रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण भाग में प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 1986/फाल्गुन 10, 1907
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 1986/PHALGUNA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1986

सूचनाएं

का. आ. 757—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री शेर सिंह कुल्हर एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे चिरावा (राजस्थान) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (9)/86—न्या०]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 7th February, 1986

NOTICES

S.O. 757.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Sher Singh Kulhar, Advocate for appointment as a Notary to practise in Chirawa (Rajasthan).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(9)/86-Judl.]

का. आ. 758—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री राम प्रसाद नैयर एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे सम्पूर्ण भारतवर्ष में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (15)/86—न्या]

S.O. 758.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Ram Prasad Nayar, Advocate for appointment as a Notary to practise in whole India.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(15)/86-Judl.]

का. आ. 759:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती हैं कि श्री मोहर सिंह धिंगरा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जालंधर (पंजाब) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5 (24)/86–न्या०]
आर० एन० पोद्दार, सक्षम प्राधिकारी

S.O. 759.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Mohar Singh Dhingra, Advocate for appointment as a Notary to practise in Jalandhar (Punjab).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(24)/86-Judl.]
R. N. PODDAR, Competent Authority

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1986

का. आ. 760:—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 225/20/78—ए. वी. डी. (2) तारीख 11-12-84 में उल्लिखित श्री जे. जी. अलीमचंदानी, अधिवक्ता की नियुक्ति का अधिक्रमण करते हुए श्री ए. बी. बेलगल, अधिवक्ता मुम्बई को, श्री वी. एम. दलाल और एम. एस. मुथाना के विरुद्ध आर. सी. 65/75–मुम्बई में विशेष न्यायाधीश, मुम्बई के न्यायालय में राज्य की ओर से उपसंजात होने और अभियोजन का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[सं० 225/25/85–ए. वी. डी.-II]

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSION

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 11th February, 1986

S.O. 760.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and in supersession of appointment of Shri J. G. Alimchandani, Advocate, mentioned in notification No. 225|20|78-AVD. II dated the 11th December, 1984, the Central Government hereby appoints Shri A. B. Belgal, Advocate, Bombay, as a Special Public Prosecutor to appear and conduct prosecution on behalf of the State in the Court of the Special Judge, Bombay in RC 65/75-Bom. against Shri V. M. Dalal and M. S. Muthanna.

[No. 225/25/85-AVD. II]

का.आ. 761:—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पी. आर. नामजोशी, अधिवक्ता मुम्बई को, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुम्बई के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना मुम्बई आर. सी. सं. 70/80–मुम्बई राज्य बनाम आदि पी. गांधी से उत्पन्न होने वाले मामले में, मुम्बई उच्च न्यायालय में उपसंजात होने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[सं. 225/21/85—ए. वी. डी.-II]
एम. एस. प्रसाद, अवर सचिव

S.O. 761.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri P. R. Namjoshi, Advocate, Bombay as Special Public Prosecutor to apear in High Court, Bombay, in the case arising out of Delhi Special Police Establishment Bombay RC No. 70/80-Bombay State Versus Adi P. Gandhi, of the Directorate of Revenue Intelligence, Bombay.

[No. 225/21/85-AVD.II]
M. S. PRASAD, Under Secy.

(पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1986

का० आ० 762:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 50 के उपनियम (1) में खण्ड (ख) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान की अन्तिम रूप से संगणित रकम, ठीक अगले रुपए तक पूर्णांकित की जाएगी"

[संख्या 7/12/85-प.० ए.ड पा०कल्या०]
हजारा सिंह, उप सचिव

पाद टिप्पण :—केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का. आ. सं. 934 के रूप में तारीख 1-4-1972 को प्रकाशित किए गए नियमों का तृतीय संस्करण (दिसम्बर, 1981 तक अद्यतन) 1982 में मुद्रित हुआ। तत्पश्चात् नियमों को का. और प्र. सु. वि. की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया :—

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	तारीख
(1)	32/4/83—पेंशन एकक	26-8-1983
(2)	29/4/83—पेंशन एकक	15-11-1984
(3)	7/3/84—पेंशन एकक	17-11-1984
(4)	38/15/85—पेंशन एकक	1-7-1985
(5)	7/4/85—पेंशन एकक	29-10-1985
(6)	1/2/85—पेंशन एकक	14-11-1985

(Department of Pension & Pensioners' Welfare)

New Delhi, the 11th February, 1986

S.O. 762.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby

makes the following rules furher to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 namely :—

1. (1) Theses rules may be called the Central Civil Services (Pension) (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 in Rule 50 in sub-rule (1), after the existing proviso to clause (b) the following proviso shall be inserted namely:—

"Provided further that the amount of death-cum-retirement gratuity as finally calculated shall be rounded off to the next higher rupee".

[No. 7(12)/85-P&PW]
HAZARA SINGH, Dy. Secy.

Foot Note:—The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 were published as S.O. 934 dated 1-4-72. The Third Edition (Corrected upto December, 1981) of the rules was printed in 1982. The rules were subsequently amended vide DP&AR Notifications given below :—

Sl. No.	Notification No.	Date
1.	32/4/83-Pension Unit	26-8-8a
2.	29/4/83-Pension Unit	15-11-84
3.	7/3/84-Pension Unit	17-11-84
4.	38/15/85-Pension Unit	1-7-85
5.	7/4/85-Pension Unit	29-10-85
6.	1/2/85-Pension Unit	14-11-85

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1986

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 763.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली द्वारा जारी किये जाने वाले केवल बाईस करोड़ बीस लाख रुपये मूल्य के "9.75% एन. सी. डी. सी. बन्ध-पत्र, 1999(XX सीरिज)" के रूप में उल्लिखित प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप के बन्ध-पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[संख्या 2/86—स्टाम्प-फा. सं. 33/10/86-वि. क.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th February, 1986

ORDER

STAMPS

S.O. 763.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory Notes described as "9.75% N.C.D.C Bonds, 1999 (XXth Series)" to the value of rupees twenty-two crores and twenty lakhs only to be issued by National Cooperative Develpoment Corporation, New Delhi are chargeable under the said Act.

[No. 2/86-Stamps-F. No. 33/10/86-ST]

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1986

आदेश

स्टाम्प

का० आ 764.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा 1 के खंड (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को छूट देती है जो आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले केवल सोलह करोड़ सत्तर लाख रुपये मूल्य के "9.75% ऋण-पत्र 1998, (XXIV सिरीज)" के रूप में उल्लिखित ऋणपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं. 1/86-स्टाम्प-फा. सं. 33/67/85—वि. क.]
बी. आर. मेहमी, अवर सचिव

New Delhi, the 7th February, 1986

ORDER

STAMPS

S.O. 764.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indiann Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Debentures described as "9.75% debentures, 1998 (XXIV Series)" to the value of Sixteen Crores and Seventy Lakhs rupees only to be issued by the Housing and Urban Development Corporation Limited,, New Delhi are chargeable under the said Act.

[No. 1/86-Stamps. F. No. 33/67/85-ST]
B. R. MEHMI, Under Secy.

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1985

शुद्धिपत्र

(आयकर)

का. आ. 765:—बोर्ड की दिनांक 30-5-85 की अधिसूचना स; 6237 (फा. स. 261/3/85—आयकर न्या०) में, आयकर आयुक्त (अपील), कालीकट के क्षेत्राधिकार के सम्मुख अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 के अन्तर्गत मद सं. 9 के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"9. आयकर सर्वेक्षण परिमंडल, त्रिचूर"

[सं. 6461 (फा. स० 261/3/85—आयकर (न्या०)]

(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 16th October, 1985

CORRIGENDUM

(INCOME-TAX)

S.O. 765.—In Board's notification No. 6237 (F. No. 261/3/85-ITJ) dated 30-5-85 aaginst the jurisdiction of Commissioner of Income-tax (Appeals), Calicut under column No. 2 of the schedule the following shall be added as item No. 9:

"9 I. T. Survey Circle, Trichur"

[No. 6461 (F. No. 261/3/85-ITJ)]

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1985

(आयकर)

का. आ. 766:—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमण्डलों, वार्डों और जिलों में आयकर अथवा अधिकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने कार्य का निर्वहण करेंगे :—

क्र. सं.	अनुसूची रेंज	आयकर परिमण्डल, वार्ड और जिले
1.	अपीलीय सहायक आयुक्त, रेंज-I आगरा	परिमण्डल I आगरा के क, ख, ग, घ, च, और छ वार्डों के आयकर कार्यालय। फतेहगढ़ परिमंडल अलीगढ़ परिमण्डल मैनपुरी परिमण्डल झांसी परिमंडल एटा परिमण्डल केन्द्रीय परिमण्डल I और II आगरा विशेष जांच परिमण्डल आगरा
2.	अपीलीय सहायक आयुक्त, रेंज-II आगरा	आयकर कार्यालय, क, ख, ग, घ, ङ और छ परिमण्डल II आगरा के वेतन वार्ड। हाथरस परिमण्डल, इटावा परिमण्डल इटावा परिमण्डल फैजाबाद परिमण्डल मथुरा परिमण्डल

यतः कोई आयकर परिमंडल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अन्तरित कर दिया जाता है, उस परिमण्डल, वार्ड अथवा जिले अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व रेंज के उस अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें जिसके अधिकार क्षेत्र से उस परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो, रेंज के उस अपीलीय, सहायक आयकर आयुक्त द्वारा निपटाई जाएगी जिसको उक्त परिमंडल वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो। यह अधिसूचना 1-1-86 से लागू होगी।

[सं. 6542 (फा. सं. 261/21/85-आ. क. न्या.)]

New Delhi, the 20th December, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 766.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling in that behalf and in partial modification of all previous notifications in this regard and the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Asstt. Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column (2) of the Schedule below shall perform their functions in respect of the persons and income assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, wards and Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof:—

SCHEDULE

Sl. No.	Schedule Range	Income-tax Circles, Wards & Districts
1	2	3
1.	A.A.C., Range-I Agra.	Income-tax Offices, A, B, C, D, F, & G, Wards of Circle-I, Agra. Fatehgarh Circle. Aligarh Circle, Mainpuri Circle, Jhansi Circle, Etah Circle, Central Circle-I & II, Agra. Special Investigation Circle, Agra.
2.	A.A.C., Range-II, Agra.	Income-tax Offices, A, B, C, D, E, & G, and Salary wards of Circle II, Agra. Hathras Circle, Etawah Circle, Firozabad Circle, Mathura Circle.

Where an Income-tax Circles, Wards or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another appeals arising out of Assessments made in that Income-tax Circles, Wards or Districts or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Asstt. Commissioner of Income-tax of the Range from whom that Income-tax Office, Circle Ward or District or part thereof is transferred to and dealt with by the Appellate Asstt. Commissioner of Income-tax of the Range to whom the said circle, ward or district or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-1-1986.

[No 6542 (F. No. 261/21/85-ITJ)]

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1985

(आयकर)

का. आ. 767:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त आयकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय को छोड़कर जिन पर क्षेत्राधिकार आयकर आयुक्त (अपील) में निहित है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमंडलों, वार्डों और जिलों में आयकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के सम्बन्ध में अपने कार्य करेंगे।

अनुसूची

क्रम सं.	रेंज	आयकर परिमंडल/वार्ड और जिले
1	2	3
1.	अपीलीय सहायक आयुक्त, नासिक रेंज-I, नासिक	1. नासिक के सभी वार्ड/परिमण्डल 2. मालेगांव के सभी वार्ड/परिमण्डल

1	2	3
		3. अहमदनगर के सभी वार्ड/परिमण्डल
		4. सहायक नियंत्रक संपदा शुल्क, नासिक
2. अपीलीय सहायक आयुक्त, नासिक रेंज-II, नासिक		
3. अपीलीय सहायक आयुक्त, औरंगाबाद रेंज, औरंगाबाद	1. औरंगाबाद के सभी वार्ड/परिमण्डल	
	2. जालना के सभी वार्ड/परिमण्डल	
	3. परभनी के सभी वार्ड/परिमंडल	
	4. बीड़ के सभी वार्ड/परिमण्डल	
	5. लातूर के सभी वार्ड/परिमण्डल	
	6. नान्देड़ के सभी वार्ड/परिमण्डल	
	7. जलगांव के सभी वार्ड/परिमण्डल	
	8. धुले के सभी वार्ड/परिमण्डल	

यतः कोई आयकर परिमण्डल, और अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अन्तरित कर दिया जाता है, उस आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिले अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली तत्काल पूर्व रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार क्षेत्र में उस आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अन्तरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो।

यह अधिसूचना दिनांक 1-12-1985 से लागू होगी।

[सं. 6543/फा. सं. 261/ 12/84—आ. क. न्या.]

ए. के. गर्ग, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

New Delhi, the 24th December, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 767.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all the previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in column (1) of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to income-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column (2) thereof excluding all persons and income assessed to Income-tax over which the jurisdiction vests in Commissioner of Income-tax (Appeal).

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Circles, Ward and Districts.
1	2	3
1.	A.A.C., N.R.-I Nashik.	1. All Wards /Circles in Nashik.
		2. All Wards/Circles in Malegaon.
		3. All Wards/Circles in Ahmednagar.
		4. A.C.E.D. Nashik.
2.	A.A.C. N.R.-II, Nashik.	—
3.	A.A.C. A.R. Aurangabad.	1. All Wards /Circles in Aurangabad.
		2. All Wards /Circles in Jalna.
		3. All Wards/Circles in Parbheni
		4. All Wards/Circles in Beed.
		5. All Wards/Circles in Latur.
		6. All Wards/Circles in Nanded.
		7. All Wards/Circles in Jalgaon.
		8. All Wards/Cirlces in Dhule.

Whereas the Income-tax Circle, and or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circles, Wards or Districts or part thereof and pending immediately before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or Districts or part thereof is transferred shall from the date of this Notification takes effect to transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward, District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-12-1985.

[No. 6543/F. No. 261/12/84-ITJ]

A. K. GARG, Under Secy.,
Central Board of Direct Taxes

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1985

(आयकर)

का.आ. 768.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 126, 121-क तथा 122 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, स्तम्भ 3, 4, 5, 6 तथा 7 में उल्लिखित अधिकारियों को नीचे स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में, क्षेत्राधिकार की शक्ति प्रदान करता है :—

क्रम सं.	व्यक्ति	आयकर अधिकारी	निरीक्षी सहायक आयुक्त	अपीलीय सहायक आयुक्त	आयकर आयुक्त (अपील)	आयकर आयुक्त
1	2	3	4	5	6	7
1	भारत में पंजीकृत कार्यालय रहित विदेशी कम्पनियां/प्रतिष्ठान तथा अथवा जिन्हें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 (1959 का 43) के अधीन गठित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उनके उप-ठेकेदार	—	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त (कर-निर्धारण) देहरादून	—	आयकर आयुक्त (अपील), मेरठ	आयकर आयुक्त, मेरठ

1	2	3	4	5	6	7
	तथा प्रतिनिधियों ने, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और ऐसी विदेशी कम्पनियों/प्रतिष्ठानों के बीच हुए करार के अनुसार, भारत के विभिन्न स्थलों पर चलने वाले कार्यों अथवा इसके अपतटीय कार्यों के सिलसिले में तकनीकी कार्य करने अथवा अन्य सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों से एकमेव तथा अनन्य रूप से लगाया हुआ है।					
2	भारत में पंजीकृत कार्यालय रहित अनिवासी कम्पनियों/प्रतिष्ठानों के कर्मचारी (जिनमें अनिवासी संबद्ध कम्पनियों/प्रतिष्ठानों के उपठेकेदार शामिल हैं) जिन्हें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 (6959 का 43) के अधीन गठित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और ऐसी अनिवासी कम्पनियों/प्रतिष्ठानों के बीच हुए करार के अनुसार, भारत के विभिन्न स्थलों पर चलने वाले कार्यों अथवा इसके अपतटीय कार्यों के सिलसिले में तकनीकी कार्य करने अथवा अन्य सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों से, एकमेव तथा अनन्य रूप से लगाया हुआ है।	आयकर अधिकारी क–वार्ड देहरादून	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त देहरादून	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त देहरादून	आयकर आयुक्त (अपील) मेरठ	आयकर आयुक्त मेरठ

यह अधिसूचना 1-12-1985 से प्रभावी होगी। [सं. 6476/फा.सं. 187/29/84-आ.क. (नि-I)]

आर.के. तिवारी, अवर सचिव
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

New Delhi, the 29th October, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 768—In exercise of the powers conferred under section 126, 121-A & 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes empowers the officers mentioned in Col. 3, 4, 5, 6 & 7 to have jurisdiction in respect of such persons as specified in Col. 2 hereunder.

Sl. No.	Persons	I.T.O.	I.A.C.	A.A.C.	C.I.T (Appeals)	C.I.T.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Foreign companies/concerns who have no registered office in India and/or solely and exclusively engaged by the Oil & Natural Gas Commission constituted under the Oil & Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959) their sub-contractors and assignees, for the purposes of rendering works technical or other services in relation to its operations at various places in India or in relation to its off-shore operations in accordance with the agreement between Oil & Natural Gas Commission and such foreign companies/concerns.	–	Inspecting Assistant Commissioner of Income, (Assessment) Dehradun.	–	Commissioner of Income-tax (Appeals) Meerut.	Commissioner of Income-tax, Meerut.
2.	Employees of non-resident companies/-concerns who have no registered offices in India including employees of non-resident affiliates and sub-contractors of such non-resident companies/concerns, and who are engaged solely and exclusively by the Oil & Natural Gas Commission, constituted under the Oil & Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959) for the purpose of rendering works technical or others services in relation to its operations at various places in India or in relation to its offshore operations in accordance with the agreement between Oil & Natural Gas Commission and such non-resident companies/concerns.	Income-tax Officer, A-Ward, Dehradun.	Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Dehradun.	Appellate Asstt. Commissioner of Income-tax Dehradun.	Commissioner of Income-tax (Appeals) Meerut.	Commissioner of Income,-tax, Meerut.

This notification shall take effect from 1-12-85.

[No. 6476 /F. No. 187/29/84-IT(A1)]
R. K. TEWARI, Under Secy.
Central Board of Direct Taxes

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1985

(आयकर)

का. आ. 769.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 की धारा 122 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बोर्ड की दिनांक 11.11.81 की अधिसूचना सं. 4306 (फा. सं. 261/13/81—आ. क. न्या.) दिनांक 11-11-1982 की अधिसूचना सं. 4448 (फा. सं. 261/6/82—आ. क. न्या.); दिनांक 7-10-82 की अधिसूचना सं. 4041 तथा दिनांक 10-11-1982 की अधिसूचना सं. 4962 (फा. सं. 261/6/82—आ. क न्या.) में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, आयकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय को छोड़कर जिन पर क्षेत्राधिकार आयकर आयुक्त (अपील) में निहित है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमंडलों, वार्डों तथा जिलों में, आयकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने कार्य करेंगे।

अनुसूची

क्र. सं.	रेंज	आयकर परिमंडल, वार्ड और जिले
1	2	3
1.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, इन्दौर रेंज, इन्दौर।	1. आ. क. अधि., केन्द्रीय परिमंडल, इन्दौर 2. आ. क. परिमंडल—I, इन्दौर 3. आ. क. परिमंडल—II, इन्दौर 4. आ. क. परिमंडल, खंडवा 5. सहायक नियंत्रक, सम्पदा शुल्क, इन्दौर 6. आ. क. अधि., विशेष सम्पदा शुल्क व आ. क. परिमंडल, इन्दौर 7. आ. क. अधि. विशेष जांच परिमंडल, इन्दौर 8. आ. क. अधि. (विशेष) जांच परिमंडल, इन्दौर 9. आ. क. अधि., विशेष जांच परिमंडल-1, इन्दौर 10. आ. क. अधि., विशेष जांच परिमंडल-II, इन्दौर 11. आ. क. अधि., विशेष जांच परिमंडल-III, इंदौर 12. आ. क. अधि., विशेष जांच IV, इन्दौर 13. आ. क. परिमंडल, धार 14. आ. क. अधि. (वसूली तथा उगाही वार्ड), परिमंडल-1, इन्दौर 15. आ. क. परिमंडल, महू 16. आ. क. अधि., विशेष सर्वेक्षण परिमंडल, इन्दौर 17. आ. क. अधि. सर्वेक्षण, इन्दौर 18. आ. क. अधि., विशेष सर्वेक्षण परिमंडल वार्ड, परिमंडल-I, इन्दौर। 19. आ. क. अधि., विशेष सर्वेक्षण वार्ड, परिमंडल 1, इन्दौर 20. आ. क. अधि., विशेष सर्वेक्षण वार्ड, परिमंडल-II, इन्दौर। 21. आ. क. परिमंडल, खारगांव।
2.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, उज्जैन रेंज, उज्जैन।	1. आ. क. परिमंडल, उज्जैन 2. आ. क. परिमंडल, रतलाम। 3. आ. क. परिमंडल, मन्दसौर। 4. आ. क. परिमंडल, नीमच। 5. आ. क. परिमंडल, देवास।
3.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, भोपाल रेंज, भोपाल	1. आ० क. परिमंडल, भोपाल। 2. आ. क. परिमंडल, इटारसी 3. आ. क. परिमंडल, बैतुल। 4. आ. क. परिमंडल, विदिशा। 5. आ. क. अधि., सिहोर, मुख्यालय भोपाल।
4.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, ग्वालियर रेंज ग्वालियर	1. आ. क. परिमंडल, ग्वालियर 2. आ. क. परिमंडल, गुना। 3. आ. क. परिमंडल, शिवपुरी। 4. आ. क. परिमंडल, मुरैना।

2. जहां कोई आयकर परिमंडल/वार्ड/जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अंतरित कर दिया गया हो, वहां उस आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व, रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार-क्षेत्र में उक्त आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अंतरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी जिसके अधिकार-क्षेत्र में उक्त परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1985 से लागू होगी।

[सं. 6518 (फा. सं. 279/143/84—आ. क. न्या.]

New Delhi, the 29th November, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 769.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of Board's Notification No. 4306 (F. No. 261/13/81-ITJ) dated 13-11-81, No. 4448 (F. No. 261/6/82-ITJ) dated 10-11-1982, No. 4041 dated 7-10-82 and 4962 (F. No. 261/6/82-ITJ) dated 10-11-1982, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column (1) of Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to income tax in the Income tax circles, wards and districts specified in the corresponding entry in column (2) thereof, excluding all persons and income assessed to Income-tax over which the jurisdiction vests in Commissioners of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Circles, Wards & Districts.
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income Tax, Indore Range, Indore.	1. ITO, Central Circle, Indore. 2. IT-Circle-I, Indore. 3. IT- Circle-II, Indore. 4. IT-Circle, Khandwa. 5. Asstt. Controller of Estate Duty, Indore. 6. ITO, Spl. Estate Duty-cum-II Circle, Indore. 7. ITO, Spl. Investigation Circle, Indore. 8. ITO (Special) Investigation Circle, Indore. 9. ITO, Special Investigation Circle-I, Indore. 10. ITO. Special Investigation Circle-II, Indore. 11. ITO, Special Investigation Circle-III, Indore. 12. ITO, Special Investigation IV Indore. 13. ITO Circle, Dhar. 14. ITO (Collection & Recovery Ward, Circle-I, Indore. 15. II Circle, Mhow. 16. ITO, Special Survey Circle, Indore. 17. ITO, Survey Circle, Indore. 18. ITO, Special & Survey Circle Ward, Circle-I, Indore. 19. ITO, Spl. & Survey Ward, Circle-I, Indore. 20. ITO, Spl., & Survey Ward, Circle-II, Indore. 21. IT Circle, Khargone.
2.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Ujjain Range, Ujjain.	1. IT Circle, Ujjain. 2. IT Circle, Ratlam. 3. IT Circle, Mandsaur. 4. IT Circle, Neemuch. 5. IT Circle, Dewas.
3.	Appellate Assistant Commissioner of Income-taxe, Bhopal Range, Bhopal.	1. IT Circle, Bhopal. 2. IT Circle, Itarsi. 3. IT Circle, Betul. 4. IT Circle, Vidisha. 5. ITO, Sehora with Hqrs, at Bhopal.
4.	Appellate Assistant Comissioner of Income-tax, Gwalior Range, Gwalior.	1. IT Circle, Gwalior. 2. IT Circle, Guna. 3. IT Circle, Shivpuri. 4. IT Circle, Morena.

2. Wherever an Income-tax Circle, ward, District of part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of the assessments made in that I.T. Circle, Ward or Districts or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appeallte Assistant Commissioner of the Range from whom that I.T. Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date of this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said circle, ward or district or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1st December, 1985.

[No. 6518 (F. No. 279/143/84-ITJ)]

का. आ. 770—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, आयकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय को छोड़कर, जिन पर क्षेत्राधिकार आयकर आयुक्त (अपील) में निहित है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमंडलों, वार्डों और जिलों में, आयकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने कार्य करेंगे।

अनुसूची

क्र.सं.	रेंज	आयकर परिमंडल वार्ड/जिले
1	2	3
1.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, क-रेंज, जयपुर	1. जयपुर स्थित सभी केन्द्रीय परिमंडल। 2. जयपुर स्थित सभी विशेष जांच परिमंडल। 3. जयपुर स्थित सभी विशेष सर्वेक्षण परिमंडल। 4. जयपुर स्थित सभी वेतन परिमंडल। 5. जयपुर स्थित आयकर अधिकारी ब स. नि. सं. शुल्क। 6. जयपुर स्थित सभी कंपनी परिमंडल। 7. जयपुर स्थित ग्यास परिमंडल। 8. जयपुर स्थित सभी जिला परिमंडल। 9. अलवर स्थित सभी वार्ड/परिमंडल। 10. भरतपुर स्थित सभी वार्ड/परिमंडल।
2.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, ख रेंज, जयपुर	1. अ.स.आ., क-रेंज, जयपुर के सामने उल्लिखित से भिन्न जयपुर स्थित सभी वार्ड/परिमंडल। 2. टोंक स्थित सभी वार्ड/परिमंडल।
3.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, कोटा रेंज, कोटा	1. कोटा में सभी वार्ड/परिमंडल। 2. बूंदी में सभी वार्ड/परिमंडल। 3. झालावाड़ में सभी वार्ड/परिमंडल। 4. सवाई माधोपुर में सभी वार्ड/परिमंडल।

1	2	3
	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, अजमेर रेंज, अजमेर	1. अजमेर में सभी वार्ड/परिमंडल । 2 सीकर में सभी वार्ड/परिमंडल । 3. झुनझुनु में सभी वार्ड/परिमंडल । 4. ब्यावर में सभी वार्ड/परिमंडल ।

2. जहां कोई आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अंतरित कर दिया गया हो, वहां उस आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व, रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार-क्षेत्र में उक्त आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अन्तरित की जाएगी और उसके द्वारा निपटाई जाएगी जिसके अधिकार-क्षेत्र में उक्त परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो ।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1985 से लागू होगी ।

[सं. 6519 (फा. सं. 279/143/84—आ. क. न्या.)]

S.O. 770.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all the previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to income-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in Column (2) thereof excluding all persons and incomes assessed to income-tax over which the jurisdiction vests in Commissioner of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Circles/Wards Districts
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-taxe, A-Range, Jaipur.	1. All Central Circles at Jaipur. 2. All Special Investigation Circles at Jaipur. 3. All Special Survey Circles at Jaipur. 4. All Salary Circles at Jaipur. 5. Income-tax Officer-cum-ACED at Jaipur. 6. All Company Circles at Jaipur. 7. Trust Circles at Jaipur. 8. All Districts Circles at Jaipur. 9. All Wards/Circles at Alwar. 10. All Wards/Circles at Bharatpur.
2.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, B. Range, Jaipur.	1. All Wards/Circles at Jaipur. other than those specified against AAC A-Range, Jaipur. 2. All Wards/Circles at Tonk.
3.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Kota Range, Kota.	1. All Wards/Circles at Kota. 2. All Wards/Circles at Bundi. 3. All Wards/Circles at Jhalawar. 4. All Wards/Circles at Sawai-Madhopur.
4.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Ajmer Range, Ajmar.	1. All Wards/Circles at Ajmer. 2. All Wards/Circles at Sikar. 3. All Wards/Circles at Jhunjhunu. 4. All Wards/Circles at Beawar.

2. Where any Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle/Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle/Ward or District or part thereof is transferred shall from the date of this notification take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle/Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1st December, 1985.

[No 6519 (F. No. 279/143/84-ITJ]

का. आ. 771.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122, की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा, दिनांक 14-12-1981 की अपनी अधिसूचना सं. 4343 (फा. सं. 261/32/81—आ. क. न्या.) में संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

"अमृतसर रेंज, अमृतसर तथा जम्मू रेंज, जम्मू के सामने स्तम्भ (1) और (2) के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न-लिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

रेंज	आयकर परिमंडल, वार्ड और जिले
अमृतसर रेंज, अमृतसर	(i) सभी आयकर परिमंडल, वार्ड और जिले जिनके मुख्यालय जिला-1, अमृतसर से भिन्न अमृतसर में स्थित थे अथवा हैं । (ii) आयकर परिमंडल, तरनतारन और बटाला ।
जम्मू रेंज, जम्मू	(i) सभी आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा, जिले जिनके मुख्यालय जम्मू, श्रीनगर, गुरदासपुर, पठानकोट और उधमपुर में थे अथवा है । (ii) आयकर जिला-1, अमृतसर ।

जहां कोई आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अंतरित कर दिया गया हो, वहां उस आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व, रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस

अपीलीय सहायक आयुक्त को अंतरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटायी जाएंगी जिसके अधिकार-क्षेत्र में उक्त परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो।

यह अधिसूचना 25-10-1985 से लागू होगी।

[सं. 6520 (फा. सं. 261/16/85—आ. क. न्या.)]

S.O. 771.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of the 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the schedule appended to its Notification No. 4343 (F. No. 261/32/81-ITJ), dated 14-12-1981.

Existing entries under column (1) and (2) against Amritsar Range, Amritsar and Jammu Range, Jammu shall be substituted by the following entries :—

Range	Income-tax Circles, Wards and District.
(1)	(2)
Amritsar Range	(i) All Income-tax Circles, Wards and Districts which had or have their headquarters at Amritsar, other than District - I, Amritsar.
	(ii) Income-tax Circle Tarn Taran Batala.
Jammu Range, Jammu.	(i) All Income-tax Circles, Wards or Districts which had or have their headquarters at Jammu, Srinagar, Gurdaspur, Pathankot and Udhampur.
	(ii) Income-tax District - I, Amritsar.

Where any Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to aonther Range appeals arising out the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or Districts or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date of this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appelalte Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 25-10-1985.

[No. 6520 (F. No. 261/16/85-ITJ)]

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1985

का. आ. 772—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रेंज के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, आयकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय को छोड़कर जिन पर क्षेत्राधिकार आयकर आयुक्त (अपील) में निहित है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमण्डलों, वार्डों और जिलों में, आयकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने कार्य करेंगे।

अनुसूची

क्रम सं.	रेंज	आयकर परिमण्डल, वार्ड और जिला
1	2	3
अहमदाबाद		
1	अपीलीय सहायक आयुक्त, अहमदाबाद, रेंज-I अहमदाबाद	परिमण्डल-I, अहमदाबाद
2	अपीलीय सहायक आयुक्त, अहमदाबाद, रेंज-II, अहमदाबाद	परिमण्डल-II, अहमदाबाद, सर्वेक्षण परिमण्डल, अहमदाबाद
3.	अपीलीय सहायक आयुक्त, अहमदाबाद रेंज-III, अहमदाबाद	परिमण्डल-III, अहमदाबाद
4.	अपीलीय सहायक आयुक्त, अहमदाबाद रेंज-IV,	परिमण्डल-I, अहमदाबाद
5	अपीलीय सहायक आयुक्त, अहमदाबाद रेंज-V, अहमदाबाद	परिमण्डल-V अहमदाबाद, पाटन परिमण्डल, महसाणा परिमण्डल तथा पालनपुर परिमण्डल
6.	अपीलीय सहायक आयुक्त, अहमदाबाद रेंज-VI, अहमदाबाद	परिमण्डल-VI अहमदाबाद, सुरेन्द्र नगर परिमण्डल, हिम्मत नगर परिमण्डल, मेहसाणा परिमण्डल
7	अपीलीय सहायक आयुक्त, रेंज- VII, अहमदाबाद	कम्पनी परिमण्डल-I, कम्पनी परिमण्डल-II कम्पनी परिमण्डल-V, कम्पनी परिमण्डल-VI, कम्पनी परिमण्डल- VII, कम्पनी परिमण्डल- VIII, कम्पनी परिमण्डल-IX, कम्पनी परिमण्डल, XV अहमदाबाद।
8.	अपीलीय सहायक आयुक्त, अहमदाबाद रेंज- VIII अहमदाबाद।	कम्पनी परिमण्डल-III, कम्पनी परिमण्डल-IV कम्पनी परिमण्डल-X कम्पनी परिमण्डल-XI कम्पनी परिमण्डल-XII कम्पनी परिमण्डल-XIII कम्पनी परिमण्डल-XVI अहमदाबाद
9	अपीलीय सहायक आयुक्त, अहमदाबाद रेंज- IX अहमदाबाद।	विशेष परिमण्डल, अहमदाबाद विशेष जांच परिमण्डल, अहमदाबाद व्यावसायिक परिमण्डल, अहमदाबाद।
10	अपीलीय सहायक आयुक्त, अहमदाबाद रेंज-X अहमदाबाद।	केन्द्रीय परिमण्डल, अहमदाबाद, सम्पदा शुल्क तथा उपहार कर परिमण्डल अहमदाबाद।
सूरत		
11.	अपीलीय सहायक आयुक्त —रेंज सूरत	परिमण्डल-I सूरत, खम्भात परिमण्डल, वापी परिमण्डल, नवसारी परिमण्डल

1	2	3
12.	अपीलीय सहायक आयुक्त रेंज, सूरत	परिमण्डल-II, सूरत, परिमण्डल-III, सूरत, विशेष जांच परिमण्डल, सूरत, केन्द्रीय परिमण्डल, सूरत विशेष सर्वेक्षण परिमण्डल, सूरत
	बड़ौदा	
13.	अपीलीय सहायक आयुक्त, क—रेंज बड़ौदा।	केन्द्रीय परिमण्डल, बड़ौदा परिमण्डल-I परिमण्डल III , बड़ौदा, गोधरा परिमण्डल, भरूच परिमण्डल
14.	अपीलीय सहायक आयुक्त, ख—रेंज बड़ौदा।	परिमण्डल II, बड़ौदा, म. शु. परिमण्डल तथा आ. क. परिमण्डल, बड़ौदा, नाडियाड परिमण्डल, नाडियाड परिमण्डल, पेटलाड परिमण्डल, आनन्द परिमण्डल, विशेष सर्वेक्षण परिमण्डल, बड़ौदा।

यतः कोई आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अंतरित कर दिया जाता है, उस आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिले अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर-निर्धारण से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिनके अधिकार-क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अन्तरित की जायेंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो।

यह अधिसूचना 1-1-1986 से लागू होगी।

[सं. 6544(फा. सं. 279/143/84-आ.क. नि.)]

सुरेन्द्र पाल, अवर सचिव
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

New Delhi, the 24th December, 1985

S.O. 772.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all the previous Notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in column (2) of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to income-tax in the Income-tax Circles, wards and districts specified in the corresponding entry in column (3) thereof, excluding all persons and income assessed to Income-tax over which the jurisdiction vests in Commissioner of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Circle, Ward & Districts.
1	2	3
	AHMEDABAD	
1.	Appellate Assistant Commissioner, Ahmedabad Range-I, Ahmedabad.	Circle I, Ahmedabad.
2.	Appellate Assistant Commissioner, Ahmedabad Range-II, Ahmedabad.	Circle II, Ahmedabad, Survey Circles, Ahmedabad.
3.	Appellate Assistant Commissioner, Ahmedabad Range-III, Ahmedabad.	Circle-III, Ahmedabad.
4.	Appellate Assistant Commissioner, Ahmedabad Range-IV, Ahmedabad.	Circle-IV, Ahmedabad.
5.	Appellate Assistant Commissioner, Ahmedabad Range V, Ahmedabad.	Circle V, Ahmedabad, Patan Circle, Mehsana Circle and Palanpur Circle.
6.	Appellate Assistant Commissioner, Ahmedabad Range VI, Ahmedabad.	Circle VI, Ahmedabad, Surendranagar Circle, Himmatnagar Circle, Modasa Circle.
7.	Appellate Assistant Commissioner, Range VII, Ahmedabad.	Com. Circle I, Com. Circle II Com. Circle V, Com. Circle VI, Com. Circle VII, Com. Circle VIII, Com. Circle IX, Com. Circle XV, Ahmedabad.
8.	Appellate Assistant Commissioner, Ahmedabad Range VIII, Ahmedabad.	Com. Circle III, Com. Circle IV, Com. Circle X, Com. Circle XI, Com. Circle XII, Com. Circle XIII, Com. Circle XVI, Ahmedabad.
9.	Appellate Assistant Commissioner, Ahmedabad Range IX, Ahmedabad.	Special Circles, Ahmedabad Special Investigation Circles, Ahmedabad, Professional Circles, Ahmedabad.
10.	Appellate Assistant Commissioner, Ahmedabad Range-X, Ahmedabad.	Central Circles, Ahmedabad Estate Duty-cum-I. T. Circle, Ahmedabad.
	SURAT	
11.	Appellate Assistant Commissioner, A-Range, Surat.	Circle I Surat. Bulsar Circle. Vapi Circle. Navsari Circle.
12.	Appellate Assistant Commissioner, B-Range Surat.	Circle II, Surat, Circle III Surat, Spl. Investigation Circles, Surat, Central Circles, Surat, Spl. Survey Circles, Surat.
	BARODA	
13.	Appellate Assistant Commissioner, A-Range, Baroda.	Central Circles, Baroda Circle I, Circle III, Baroda, Godhra Circle, Bharuch Circle.
14.	Appellate Assistant Commissioner, B-Range Baroda.	Circle -II, Baroda, E.D. Circle Cum-I.T. Circle, Baroda, Nadiad Circle, Potlad Circle, Anand Circle, Spl., Survey Circles, Baroda.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, Appeals arising out of the assess-

nents made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof, and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred, shall from the date of this Notification takes effect to be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-1-1986.

[No. 6544 (F. No. 279/143/84-ITJ)]
SURENDER PAUL, Under Secy.,
Central Board of Direct Taxes

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1986

का. आ. 773.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आशीष कुमार चन्द्र को हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा, (प. बं.) का अध्यक्ष नियुक्त करती है और 8-6-1985 से प्रारम्भ होकर तथा 30-6-1988 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री आशीष कुमार चन्द्र, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 2-5/85-आर. आर. बी.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 31st January, 1986

S.O. 773.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Ashis Kumar Chandra as the Chairman of the Howrah Gramin Bank, Howrah (WB) and specifies the period commencing on the 8th June, 1985 and ending with 30th June, 1988 as the period for which the said Shri Ashis Kumar Chandra shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2—5/85-RRB]

का. आ. 774.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री विनकर राव को जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्ति की तीन वर्ष की अवधि 30-6-1985 को समाप्त हो गई थी, 1-7-1985 से प्रारम्भ होने वाली तथा 28-10-1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रथमा बैंक, मुरादाबाद का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 2-16/85-आर. आर. बी.]

S.O. 774.—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby reappoints Shri Dinkar Rao as the Chairman of Prathma Bank, Moradabad whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of Section 11 had expired on 30th June, 1985 for a period commencing from 1st July, 1985 and ending with 28th October, 1985.

[No. F. 2—16/85-RRB]

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1986

का. आ. 775.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के उपबंध प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1076 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1980 के बाद स्थापित किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उनका सम्बन्ध 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त वर्ष के लिए उनके तुलन पत्रों और लाभ-हानि विवरण तथा उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रकाशन से है।

[सं. एफ. 8 (11)/84 आर. आर. बी.]
च. वा. मीरचन्दानी, निदेशक

New Delhi, the 7th February, 1986

S.O. 775.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of section 31 of the said Act shall not apply to the Regional Rural Banks established after 31st December, 1980 under sub-section (1) of Section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) insofar as the said Section requires the publication of their balance sheets and profit and loss accounts together with the Auditors Report thereon in respect of the year ending 31st December, 1985.

[F. 8(11)/84-RRB]
C. W. MIRCHANDANI, Director

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1986

का.आ. 776.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित खंड 3 के उपखंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री एम.जी.के. नायर को 16 फरवरी, 1986 से प्रारम्भ होने वाली और 13 नवम्बर, 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इंडियन बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[सं एफ. 9/49/85-बी.ओ. 1(1)]

New Delhi, the 10th February, 1986

S.O. 776.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby re-appoints Shri M.G.K. Nair as the Managing Director of Indian Bank for a period commencing on February 16, 1986 and ending with November 13, 1988.

[No. F. 9/49/85-BO. I(1)]

का.आ. 777.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 पठित खंड 5 के उपखंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री एम.जी.के. नायर को, जिन्हें 16 फरवरी, 1986 से इंडियन बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से इंडियन बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 9/49/85-बी.ओ. 1(2)]

S.O. 777.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India, hereby, appoints Shri M.G.K. Nair who has been re-appointed as Managing Director of Indian Bank with effect from February 16, 1986 to be the Chairman of the Board of Directors of Indian Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/49/85-BO. I(2)]

का.आ. 778.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1980 के खंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार निदेश देती है कि श्री के.पी. बस्तवार, एडवोकेट, 12वीं लाइन, बैल मार्किट के निकट, इटारसी (मध्य प्रदेश), जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 19 फरवरी, 1983 की अधिसूचना सं. एफ 9/18/81-बी.ओ.-I के तहत विजया बैंक के निदेशक नियुक्त किए गए थे, दिनांक 19 फरवरी, 1986 से निदेशक नहीं रहेंगे।

[सं. एफ. 9/31/82-बी.ओ.-I]
एस. एस. हसूरकर, निदेशक

S.O. 778.—In exercise of the powers conferred by clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government is pleased to direct that Shri K. P. Bastwar, Advocate, 12th Line, Near Block Market, Itarsi (Madhya Pradesh) appointed as Director of the Vijaya Bank under notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), No. F. 9/48/81-BO. I, dated 19th February, 1983 shall cease to hold the office of Director with effect from 19th February, 1986.

[No. F. 9/31/82-BO. I]
S. S. HASURKAR, Director

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1986

सं. 147ए/86-सीमाशुल्क

का. आ. 779.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर को भाण्डागार स्टेशन घोषित करता है।

[फा. सं. 473/609/84-सी यू VII]
संदीप जोशी, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 1986

No. 147A/86-CUSTOMS

S.O. 779.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Bhubaneshwar in the State of Orissa to be a warehousing station

[F. No. 473/609/85-CUS. VII]
SANDEEP JOSHI, Under Secy.
Central Board of Excise and Customs

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1986

आदेश

का. आ. 780.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए नाशक जीवसार तथा उनके निरूपणों की बाबत भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3310 तारीख 7 अक्तूबर, 1970 में संशोधन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 3982 तारीख 24 अगस्त, 1985 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे जिनके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 28-8-1985 को उपलब्ध करा दी गयी थीं;

और उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3310 तारीख 7 अक्तूबर, 1970 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के उपाबंध-I के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

उपाबंध-I

1. बीएचसी, तकनीकी तथा परिष्कृत।
2. बीएचसी (एचसीएच) डस्टिंग चूर्ण।
3. बीएचसी (एचसीएच) पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण।
4. डीडीटी तकनीकी।
5. डीडीटी डस्टिंग चूर्ण।
6. डीडीटी पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण।
7. मच्छर लाखानाशी तेल।
8. गामा—बीएचसी (लिंडेन) पायसीकृत दाने।
9. डीडीटी पायसीकृत दाने।
10. एथिलीन डायक्लोराईड कार्बन टेटराक्लोराईड मिश्रण।
11. गामा—बीएचसी (लिंडेन)
12. चूना गंधक घोल।
13. पायरेथम निस्सारण।
14. निकोटिन गंधक घोल।
15. जिंक फॉस्फाइड, तकनीकी।
16. एल्ड्रीन, तकनीकी।
17. एल्ड्रीन पायसीकृत दाने
18. एल्ड्रीन डस्टिंग चूर्ण।
19. एल्ड्रीन, तकनीकी।
20. एथिलीन डायब्रोमाईड।
21. मैथिल ब्रोमाइड।
22. कॉपर ऑक्सीक्लोराईड, तकनीकी।
23. 2, 4-डी सोडियम, तकनीकी।
24. गामा—बीएचसी (लिंडेन) धूंआ कारक जनित्र।
25. कॉपर ऑक्सीक्लोराईड डस्टिंग चूर्ण।
26. कॉपर ऑक्सीक्लोराईड पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण।
27. क्यूपरस ऑक्साइड पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण।
28. क्यूपरस ऑक्साइड डस्टिंग चूर्ण।
29. क्यूपरस ऑक्साइड तकनीकी (फफूंदनाशी श्रेणी)
30. जगह-जगह कीटनाशी छिड़काव।
31. 2,4-डी का तरल एमिन नमक।
32. मैलेथियन, तकनीकी।
33. डायजिनान, तकनीकी।
34. फिनाइल मर्करी एसीटेट, तकनीकी।
35. स्थायी मैथाक्सी एथिल मर्करी क्लोराईड सांद्रित।
36. पैराथियान एथिल, तकनीकी।
37. फिनाईल मर्करी क्लोराइड, तकनीकी।
38. एथिल मर्करी क्लोराईड, तकनीकी।

39. स्थायी मैथोक्सी एथिल मर्करी क्लोराइड पर आधारित निरूपण।
40. मैलेथियन पायसीकृत दाने।
41. मैलेथियन डस्टिंग चूर्ण।
42. मैलेथियन पानी में घुलनशील सान्द्रित चूर्ण।
43. मिथाइल पैरेथियन, तकनीकी।
44. क्लोरडेन पायसीकृत दाने।
45. डायजिनोन पायसीकृत दाने।
46. डायजिनोन पानी में घुलनशील सान्द्रित चूर्ण
47. क्लोरडेन, तकनीकी।
48. क्लोरडेन डस्टिंग चूर्ण।
49. मिथाइल पैराथियन पायसीकृत दाने।
50. औरगैनोमरक्यूरियल ग्राई-सीड-ड्रेसिंग निरूपण।
51. भिगोने योग्य गंधक चूर्ण।
52. जिनेब, तकनीकी।
53. जिनेब, पानी में घुलनशील चूर्ण।
54. जिरम, तकनीकी।
55. जिरम पानी में घुलनशील चूर्ण।
56. डाईमेथोट, तकनीकी।
57. डाईमेथोट पायसीकृत दाने।
58. थियोमेटोन दाने।
59. थियोमेटोन पायसीकृत दाने।
60. थाईरम, तकनीकी।
61. 2, 4-डी तकनीकी।
62. एंडोसल्फन डस्टिंग चूर्ण।
63. एंडोसल्फन पायसीकृत दाने।
64. एंडोसल्फन पानी में घुलनशील चूर्ण, दाने।
65. बिनापाक्राइल पायसीकृत दाने।
66. एंडोसल्फन, तकनीकी।
67. टोक्साफेन, तकनीकी।
68. थाईरम पानी में घुलनशील चूर्ण।
69. थाईरम सीड ड्रेसिंग पर आधारित।
70. फारियम पायसीकृत दाने।
71. डायक्लोरोवोस, तकनीकी।
72. फासफामीडन, तकनीकी।
73. डायक्लोरोवोस पायसीकृत दाने।
74. डाइकोफोल तकनीकी।
75. डाइकोफोल, पायसीकृत दाने।
76. फेनाट्रोथियन, तकनीकी।
77. फेनाट्रोथियन पायसीकृत दाने।
78. क्यूमाकयूरल तकनीकी।
79. वार्फरेन चारे के दाने।
80. वार्फरेन सोडियम, तकनीकी।
81. वार्फरेन, तकनीकी।
82. पायसीकृत लारवीसाइडल तेल पाइरेथ्रम में।
83. फासफेमीडोम पानी में घुलनशील दाने।
84. पाइरेथ्रम डस्टिंग चूर्ण।
85. हेप्टाक्लोर डस्टिंग चूर्ण।
86. हेप्टाक्लोर तकनीकी।
87. एल्यूमिनियम फास्फाइड निरूपण।
88. हेप्टाक्लोर पायसीकृत दाने।
89. सल्फर डस्टिंग चूर्ण।
90. कार्बेरियल पानी में घुलनशील दाने।
91. कार्बेरियल डस्टिंग चूर्ण।
92. फेनीट्रोथियन डस्टिंग चूर्ण।
93. आइसोबोरनियल थियोसायनोसिटेट (थानाइट) तकनीकी।
94. वार्फेरिन सोडियम नमक पानी में घुलनशील चूर्ण।
95. 2, 4-डी एथिल इस्टर।
96. कार्बोरियल तकनीकी।
97. ट्राईक्लोरोफोस डस्टिंग चूर्ण।
98. क्वीनलफास डस्टिंग चूर्ण।
99. प्रोपेनिल, तकनीकी।
100. [illegible] पायसीकृत दाने।
101. [illegible] डस्टिंग चूर्ण।
102. फेनथियान पायसीकृत दाने।
103. [illegible] पानी में घुलनशील दाने।
104. फेनथियन तकनीकी।
105. फॉरेट, तकनीकी।
106. डायसलफोटन, तकनीकी।
107. [illegible], तकनीकी।
108. फोरमेथियन तकनीकी घोल।
109. मोनोक्रोटोफॉस, तकनीकी।
110. फॉरमोथियन पायसीकृत दाने।
111. [illegible] पायसीकृत दाने।
112. [illegible] पायसीकृत दाने।
113. क्वीनलफौस डस्टिंग चूर्ण।
114. [illegible], तकनीकी।
115. [illegible], तकनीकी।
116. मोनोक्रोटोफॉस पानी में घुलनशील दाने।
117. ऑक्सीडिमेटन—मैथाइल, तकनीकी दाने।
118. ऑक्सीडेमेटन—मैथाइल पायसीकृत दाने।
119. डालापोन-सोडियम, तकनीकी।
120. डालापोन-सोडियम पानी में घुलनशील चूर्ण।
121. फैन्थोएट पायसीकृत दाने।
122. फैन्थोएट, तकनीकी।
123. एमसीपीए का तरल एमाइन नमक।
124. कार्बेन्डाज़िम (एमबीसी) तकनीकी।
125. कार्बेन्डाज़िम (एमबीसी) पानी में घुलनशील चूर्ण दाने
126. फॉसेलोन पायसीकृत दाने।
127. फॉसेलोन, तकनीकी।
128. फॉसेलोन डस्टिंग चूर्ण।
129. एमसीपीए, तकनीकी।
130. पैराक्वाट, तकनीकी।
131. पैराक्वाट डाइक्लोराइड पानी में घुलनशील दाने।
132. टेमफॉस पायसीकृत दाने।
133. टेमफॉस, तकनीकी।
134. डियूरॉन तकनीकी।
135. डियूरॉन पानी में घुलनशील चूर्ण, दाने।
136. मैनकोजेब, तकनीकी।
137. मैनकोजेब पानी में घुलनशील चूर्ण, दाने।
138. [illegible] पायसीकृत दाने।
139. एडिफेनफॉस तकनीकी।
140. एडिफेनफॉस पायसीकृत दाने।
141. नाइट्रोफेन, तकनीकी।
142. नाइट्रोफेन पायसीकृत दाने।
143. फ्लूक्लोरेलीन, तकनीकी दाने।
144. फ्लूक्लोरेलीन पायसीकृत दाने।
145. मैथाइल पैराथियान डस्टिंग चूर्ण।
146. [illegible] तकनीकी।
147. निकल क्लोराइड, हेक्साहाइड्रेट, पैस्टीसाइडल ग्रेड।
148. सोडियम [illegible] वर्ग।
149. एलाक्लोर, तकनीकी।
150. एलाक्लोर पायसीकृत दाने।
151. ब्यूटाक्लोर तकनीकी।
152. ब्यूटाक्लोर पायसीकृत दाने।

153 ट्राइस्लैट, तकनीकी
154 ट्राइस्लैट पायसीकृत दाने
155 फारेट दानेदार, संपुटित
156 कारबोफेरेन दानेदार-संपुटित
157 एलक्लोर, दानेदार
158 ब्यूटाक्लोर, दानेदार
159 फैनथियोन दानेदार
160 ट्राईक्लोरोफान दानेदार
161 फैनीट्रोथियो दानेदार
162 विधनलफोस-दानेदार
163 डायसल्फोन दानेदार, संपुटित
164 कारबोरियल दानेदार।
165 डायजिनोन दानेदार
166 लिंडेन दानेदार।
167 एल्डीकार्ब, दानेदार संपुटित।
168 मैथाइल पैराथियन, तकनीकी दाने।
169 ट्राईडेमार्फ पायसीकृत दाने।
170 प्रपोक्सर पायसीकृत दाने।
171 ट्राइडेमार्फ, तकनीकी।
172 2, 4-डी एथिल इस्टर पायसीकृत दाने।
173 2, 4-डी एथिल इस्टर पानी में घुलनशील चूर्ण।
174 एण्डोसल्फन दानेदार।
175 नाइट्रोजन दानेदार।
176 फैनथोएट दानेदार।
177 क्लोरफोनवीनफोस, तकनीकी।
178 पैराक्यूट डाइमैथाइल सल्फेट पानी में घुलनशील दाने।
179 फैनीट्रोथियन पानी में घुलनशील चूर्ण।
180 कैपटाफोल पानी में घुलनशील चूर्ण।
181 कैपटाफोल तकनीकी।
182 एथियन पायसीकृत दाने।
183 कापर एसिटोआर्सनाइट।
184 एथियन, तकनीकी।
185 निकोटीन सल्फेट
186 एल्युमिनियम फास्फाइड।

(ii) उक्त अधिसूचना के उपाबंध-(ii) के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"उपाबंध—(II)"

नाशकजीवमार तथा उनके निरूपणों के लिए विनिर्देश :—

क्र.सं.	नाशकजीवमार तथा उनके निरूपणों का नाम	*भारतीय मानक संस्थान द्वारा जारी किए गए संबद्ध विनिर्देश।
1	2	3
1.	बी एच सी तकनीकी तथा परिष्कृत	भा.मा : 560—1980
2.	बी एच सी (एच सी एच) डस्टिंग चूर्ण	भा.मा : 561—1973
3.	बी एच सी (एच सी एच) जल में घुलनशील चूर्ण दाने	भा.मा : 562—1973
4.	डी डी टी, तकनीकी	भा.मा : 563—1973
5.	डी डी टी डस्टिंग चूर्ण	भा.मा : 564—1984
6.	डी डी टी जल में घुलनशील चूर्ण, दाने	भा.मा : 565—1984
7.	मच्छर लारवानाशी तेल	भा.मा : 568—1978
8.	गामा-बी एच सी (लिंडेन) पायसीकृत दाने	भा.मा : 632—1978
9.	डी डी टी पायसीकृत दाने	भा.मा : 6[illegible]—1985
10.	एथिलीन डायक्लोराईड कार्बन टेटराक्लोराईड मिश्रण	भा.मा : 634—1965
11.	गामा—बी एच सी (लिंडेन)	भा.मा : 8[illegible]—1984
12	चूना गंधक घोल	भा.मा : 1050—1984
13	पायरेथ्रम निस्सारण	भा.मा : 1051—1980
14.	निकोटीन गंधक घोल	भा.मा : 1055—1984
15.	जिंक फास्फाइड, तकनीकी	भा.मा : 1251—1984
16.	एल्ड्रीन, तकनीकी	भा.मा : 1306—1974
17	एल्ड्रीन पायसीकृत दाने	भा.मा : 1307—1982
18.	एल्ड्रीन डस्टिंग चूर्ण	भा.मा : 1308—1984
19.	एल्ड्रीन तकनीकी	भा.मा : 1309—1974
20	एथिलिन डाइब्रोमाईड	भा.मा : 1311—1966
21.	मैथिल ब्रोमाइड	भा.मा : 1312—1980
22.	कापर आक्सीक्लोराइड, तकनीकी	भा.मा : 1486—1978
23.	2, 4-डी सोडियम, तकनीकी	भा.मा : 1488—1985
24.	गामा-बी एच सी (लिंडेन) धुम्रकारक जनित्र	भा.मा : 1505—1968
25.	कापर आक्सीक्लोराइड डस्टिंग चूर्ण	भा.मा : 1506—1977
26.	कापर आक्सीक्लोराइड पानी में घुलनशील सान्द्रित चूर्ण	भा.मा : 1507—1977
27.	क्यूपरस आक्साइड पानी में घुलनशील सान्द्रित चूर्ण	भा.मा : 1665—1977
28.	क्यूपरस आक्साइड डस्टिंग चूर्ण	भा.मा : 1669—1960
29.	क्यूपरस आक्साइड, तकनीकी (फफूंदीनाशी श्रेणी)	भा.मा : 1682—1973
30.	जलद-मातृ कीटनाशी छिड़काव	भा.मा : 1824—1978
31.	2, 4-डी का तरल एमिन नमक	भा.मा : 1827—1984
32.	मैलेथियन, तकनीकी	भा.मा : 1832—1978
33.	डायजीनोन, तकनीकी	भा.मा : 1833—1980
34.	फिनाइल मर्करी एसीटेट, तकनीकी	भा.मा : 2126—1973
35.	स्थायी मैथाक्सी एथिल मर्करी क्लोराइड दाने	भा.मा : 2127—1984
36.	पैराथिन एथिल, तकनीकी	भा.मा : 2128—1973
37.	एथिल मर्करी क्लोराइड, तकनीकी	भा.मा : 2353—1963
38.	स्थायी मैथोक्सी एथिल मर्करी क्लोराइड पर आधारित निरूपण।	भा.मा : 2354—1963
39.	स्थायी मैथोक्सी एथिल मर्करी क्लोराइड दाने	भा.मा : 2355—1964
40.	मैलथियन पायसीकृत दाने	भा.मा : 2567—1978
41.	मैलेथियन डस्टिंग चूर्ण	भा.मा : 2568—1978
42.	मैलेथियन पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण	भा.मा : 2569—1978
43.	मिथाइल पैराथियन, तकनीकी	भा.मा : 2570—1980
44.	क्लोरडेन पायसीकृत दाने	भा.मा : 2682—1984
45.	डायजीनोन पायसीकृत दाने	भा.मा : 2861—1980
46.	डायजिनोन पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण	भा.मा : 2862—1984
47.	क्लोरडेन, तकनीकी	भा.मा : 2863—1968
48.	क्लोरडेन डस्टिंग चूर्ण	भा.मा : 2864—1984
49	मिथाइल पैराथियान पायसीकृत दाने	भा.मा : 3284—1984
50.	ऑरगैनोमरक्यूरियल ड्राई-सीड-ड्रेसिंग निरूपण	भा.मा : 2865—1978
51.	भिगोने योग्य गंधक चूर्ण	भा.मा : 3383—1982
52.	जिनेब, तकनीकी	भा.मा : 3898—1981
53.	जिनेब पानी में घुलनशील चूर्ण	भा.मा : 3899—1981
54.	जिरम, तकनीकी	भा.मा : 3900—1975
55.	जिरम पानी में घुलनशील चूर्ण	भा.मा : 3901—1975
56.	डाइमिथोएट, तकनीकी	भा.मा : 3902—1975
57.	डायमिथोएट पायसीकृत दाने	भा.मा : 3903—1984
58.	थियोमिटोन दाने	भा.मा : 3904—1966
59.	थियोमिटोन पायसीकृत दाने	भा.मा : 3905—1966
60	थाइरम, तकनीकी	भा.मा : 4320—1982
61.	2, 4-डी, तकनीकी	भा.मा : 4321—1978

1	2	3
62.	एण्डोसल्फन डस्टिंग चूर्ण	भा. मा. 4322—1967
63.	एण्डोसल्फन पायसीकृत दाने, चूर्ण	भा. मा : 4323—1970
64.	एण्डोसल्फन पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण	भा. मा : 4324—1967
65.	बिनापाक्राइल पायसीकृत दाने	भा. मा : 4325—1967
66	एण्डोसल्फन, तकनीकी	भा. मा : 4344—1978
67.	टोक्सोम, तकनीकी	भा. मा : 4451—1967
68.	थाइरम पानी में घुलनशील चूर्ण	भा. मा : 4766—1982
69.	थाइरम-सी-ड्रेसिंग निरूपण	भा. मा : 4783—1982
70.	पायरेथम पायसीकृत दाने	भा. मा : 4808—1982
71.	डायक्लोरोफोस, तकनीकी	भा. मा : 4929—1978
72.	फासफामीडन, तकनीकी	भा. मा : 4958—1968
73.	डायक्लोरवस पायसीकृत दाने	भा. मा : 5277—1978
74.	डाइकोफोल, तकनीकी	भा. मा : 5278—1969
75.	डाइकोफोल पायसीकृत दाने	भा. मा : 5279—1969
76.	फैनीट्रोथियन, तकनीकी	भा. मा : 5280—1969
77.	फैनीट्रोथियन पायसीकृत दाने	भा. मा : 5281—1979
78.	क्यूमाफ्यूरन, तकनीकी	भा. मा : 5526—1969
79.	वार्फेरेन क्षारे क दाने	भा. मा : 5549—1970
80.	वार्फेरेन सोडियम, तकनीकी	भा. मा : 5551—1970
81.	वार्फेरेन, तकनीकी	भा. मा : 5552—1970
82.	पायसीकृत लार्वीनाशी तेल पाइरेथम बेस में	भा. मा : 6014—1978
83.	फासफेमीडोन पानी में घुलनशील दाने	भा. मा : 6177—1981
84.	पाइरथ्रम डस्टिंग चूर्ण	भा. मा : 6178—1982
85.	हेप्टाक्लोर डस्टिंग चूर्ण	भा. मा : 6429—1981
86.	हेप्टाक्लोर तकनीकी	भा. मा : 6432—1972
87	एल्यूमीनियम फास्फाइड निरूपण	भा. मा : 6438—1980
88.	हेप्टाक्लोर पायसीकृत दाने	भा. मा : 6439—1978
89.	सल्फर डस्टिंग चूर्ण	भा. मा : 6444—1979
90	कारबेरियल पानी में घुलनशील दाने	भा. मा : 7121—1973
91	कारबेरियल डस्टिंग चूर्ण	भा. मा : 7122—1984
92.	फैनोट्रोथियन डस्टिंग चूर्ण	भा. मा : 7126—1973
93.	डाइसोबोरनियल थियोसाइनोएसिटेट (थाईमाइट), तकनीकी	भा. मा : 7158—1973
94.	वार्फेरेन सोडियम नमक पानी में घुलनशील चूर्ण	भा. मा : 7168—1973
95.	2, 4-डी एथिल इस्टर्स	भा. मा : 7233—1985
96	कारबोरियल, तकनीकी	भा. मा : 7539—1975
97.	ट्राईक्लोरफोस डस्टिंग चूर्ण	भा. मा : 7943—1976
98.	क्वीनटोजन डस्टिंग चूर्ण	भा. मा : 7944—1976
99.	ट्राईक्लोरफोन, तकनीकी	भा. मा : 7945—1975
100	टोक्साफेन पायसीकृत दाने	भा. मा : 7946—1976
101.	टोक्साफेन डस्टिंग चूर्ण	भा. मा : 7947—1976
102	फेनथियन पायसीकृत दाने	भा. मा : 7948—1976
103.	क्वीनटोजन पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण	भा. मा : 7949—1976
104	फेनथियन, तकनीकी	भा. मा : 7960—1976
105.	फोरेट, तकनीकी	भा. मा : 7976—1976
106	डायसलफोटन, तकनीकी	भा. मा : 7977—1976
107.	क्वीनटोजन, तकनीकी	भा. मा : 7985—1976
108.	फोरेनोथियन तकनीकी घोल	भा. मा : 8024—1976
109.	मोनोक्रोटोफोस, तकनीकी	भा. मा : 8025—1983
110.	फोरमोथियन पायसीकृत दाने	भा. मा : 8026—1976
111.	प्रोपेनोल पायसीकृत दाने	भा. मा : 8027—1976
112.	क्वीनलफोस पायसीकृत दाने	भा. मा : 8028—1976
113.	क्वीनलफोस डस्टिंग चूर्ण	भा. मा : 8029—1985
114.	प्रोपेनील, तकनीकी	भा. मा : 8071—1976
115.	क्वीनलफोस, तकनीकी	भा. मा : 8072—1984
116.	मोनोक्रोटोफोस पानी में घुलनशील दाने	भा. मा : 8074—1983
117.	आक्सीडेमेटन-मैथाइल तकनीकी दाने	भा. मा : 8258—1976
118.	आक्सीडेमेटन-मैथाइल पायसीकृत दाने	भा. मा : 8259—1976
119.	डालापोन-सोडियम, तकनीकी	भा. मा : 8267—1976
120.	डालापोन-सोडियम पानी में घुलनशील चूर्ण	भा. मा : 8286—1976
121.	फैनथोएट पायसीकृत दाने	भा. मा : 8291—1976
122	फैनथोएट, तकनीकी	भा. मा : 9293—1976
123.	एम सी पी ए का सरल एमाइन नमक	भा. मा : 8294—1976
124.	कार्बेनडाइजिम (एम बी सी), तकनीकी	भा. मा : 8445—1977
125.	कार्बेनडाइजिम (एम बी सी) पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण	भा. मा : 8446—1977
126.	फोसेलोन पायसीकृत दाने	भा. मा : 8487—1977
127.	फोसेलोन, तकनीकी	भा. मा : 8488—1977
128.	फोसेलोन डस्टिंग चूर्ण	भा. मा : 8489—1977
129.	एम सी पी ए, तकनीकी	भा. मा : 8494—1977
130.	प्रोपोक्सर, तकनीकी	भा. मा : 8496—1977
131.	रैटाग्रूट डायक्लोरेड पानी में घुलनशील दाने	भा. मा : 9497—1982
132.	टेमफोम पायसीकृत दाने	भा. मा : 9498—1977
133.	टेमफोम, तकनीकी	भा. मा : 8701—1978
134.	डियूरोन, तकनीकी	भा. मा : 8702—1973
135.	डियूरोन पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण	भा. मा : 9703—1978
136.	मैनकोजेब, तकनीकी	भा. मा : 8707—1978
137.	मैनकोजेब पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण	भा. मा : 8708—1978
138.	क्लोरफीरिफोस पायसीकृत दाने	भा. मा : 8944—1978
139.	एडिफनफोस, तकनीकी	भा. मा : 8954—1978
140.	एडिफनफोस पायसीकृत दाने	भा. मा : 8955—1978
141.	नाइट्रोफन, तकनीकी	भा. मा : 8956—1978
142.	नाइट्रोफन पायसीकृत दाने	भा. मा : 8957—1978
143.	फ्लूक्लोरोलीन, तकनीकी दाने	भा. मा : 8956—1978
144.	फ्लूक्लोरोलीन पायसीकृत दाने	भा. मा : 8959—1978
145.	मैथाइल पैराथियन डस्टिंग चूर्ण	भा. मा : 8960—1978
146.	क्लोरफीरिफोस, तकनीकी	भा. मा : 8963—1978
147.	निकल क्लोराइड हैक्साहाईड्रेट, पैन्टीमाइडम ग्रेड	भा. मा : 9351—1980
148.	सोडियम, साइनाइड, कीटनाशी वर्ग	भा. मा : 9352—1980
149.	एलक्लोर, तकनीकी	भा. मा : 9353—1980
150.	एलक्लोर, पायसीकृत दाने	भा. मा : 9354—1980
151.	बूटाक्लोर, तकनीकी	भा. मा : 9355—1980
152.	बूटाक्लोर पायसीकृत दाने	भा. मा : 9356—1980
153.	ट्राईल्लेट, तकनीकी	भा. मा : 9357—1980
154.	ट्राईल्लेट पायसीकृत दाने	भा. मा : 9358—1980
155.	फोरेट दानेदार संपुटित	भा. मा : 9359—1980
156.	कारबोफरेन दानेदार-संपुटित	भा. मा : 9360—1980
157.	एलक्लोर दानेदार	भा. मा : 9361—1980
158.	बूटाक्लोर दानेदार	भा. मा : 9362—1980
159.	फैनथियोन दानेदार	भा. मा : 9363—1980
160.	ट्राईक्लोरोफन दानेदार	भा. मा : 9364—1980
161.	फैनीट्रोथियन दानेदार	भा. मा : 9365—1980

1	2	3
162.	क्विनलफॉस-दानेदार	भा.मा: 9366—1980
163.	डायसल्फोटन-दानेदार, संपुटित	भा.मा: 9367—1980
164.	कार्बेरियल-दानेदार	भा.मा: 9368—1980
165.	डायजिनोन-दानेदार	भा.मा: 9369—1980
166.	लिण्डेन दानेदार	भा.मा: 9370—1980
167.	एल्डीकार्ब दानेदार, संपुटित	भा.मा: 9371—1980
168.	मीथाइल पैराथियन, तकनीकी दाने	भा.मा: 9372—1980
169.	ट्राईडेमार्फ, पायसीकृत दाने	भा.मा: 9656—1980
170.	प्रोपार्गाइट पायसीकृत दाने	भा.मा: 9665—1981
171.	ट्राईडेमार्फ, तकनीकी	भा.मा: 9667—1981
172.	2, 4-डी एथिल इस्टर पायसीकृत दाने	भा.मा: 10243—1982
173.	2, 4-डी एथिल इस्टर पानी में घुलनशील चूर्ण	भा.मा: 10244—1982
174.	एण्डोसल्फन दानेदार	भा.मा: 10265—1982
175.	नाइट्रोफेन दानेदार	भा.मा: 10266—1982
176.	फैनथोएट दानेदार	भा.मा: 10267—1982
177.	क्लोरफेनविनफोस, तकनीकी	भा.मा: 10268—1982
178.	पैराक्वाट डाईमेथाइल सल्फेट पानी में घुलनशील दाने	भा.मा: 10294—1982
179.	फैनीट्रोथियन पानी में घुलनशील चूर्ण	भा.मा: 10295—1982
180.	कैपटाफोल पानी में घुलनशील चूर्ण	भा.मा: 10296—1982
181.	कैपटाफोल, तकनीकी	भा.मा: 10300—1982
182.	एथियन पायसीकृत दाने	भा.मा: 10319—1982
183.	कॉपर एसिटोआर्सेनाइट	भा.मा: 10355—1982
184.	एथियन, तकनीकी	भा.मा: 10269—1982"

[फाईल सं. 16(2)/84-ई आई एंड ई पी]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 1st March, 1986

ORDERS

S.O. 780.—Whereas for the development of the Export Trade of India, certain proposals for amending the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3310 dated the 7th October, 1970 regarding the Pesticides and their formulations were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules 1964 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3982 dated the 24th August, 1985, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within 45 days from the date of publication of the order in the Official Gazette;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 28th August, 1985.

And whereas objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3310 dated the 7th October 1970, namely :—

For Annexure I to the said notification, the following shall be substituted, namely :—

ANNEXURE-I

1. BHC Technical and refined
2. BHC (HCH) dusting powders
3. BHC (HCH) water dispersible powder concentrates

4. DDT technical
5. DDT dusting powders
6. DDT water dispersible powder concentrates
7. Mosquito larvicidal oil
8. Gama-BHC (Lindane) emulsifiable concentrates
9. DDT emulsifiable concentrates
10. Ethylene dichloride carbon tetrachloridemixture
11. Gama HBC (Lindane)
12. Lime sulphur solution
13. Pyrethrum extracts
14. Nicotine sulphate solution
15. Zinc phosphide, technical
16. Aldrin, technical
17. Aldrin emulsifiable concentrates
18. Aldrin dusting powders
19. Endrin, technical
20. Ethylene dibromide
21. Methyl bromide
22. Copper oxychloride, technical
23. 2, 4D sodium, technical
24. Gama-BHC (Lindane) smoke generators
25. Copper oxychloride dusting powders
26. Copper oxychloride water dispersible powder concentrates
27. Cuprous oxide water dispersible powder concentrates
28. Cuprous oxide dusting powders
29. Cuprous oxide, technical (fungicidal grade)
30. Insecticidal space spray
31. Liquid amine salts of 2, 4-D
32. Malathion, technical
33. Diazinon Technical
34. Phenyl mercury acetate, technical
35. Stabilized methoxy ethyl mercury chloride concentrates
36. Parathion ethyl, technical
37. Phenyl mercury chloride, technical
38. Ethyl mercury chloride, technical
39. Formulations based on stabilized methoxy ethyl mercury chloride concentrates
40. Malathion emulsifiable concentrates
41. Malathion dusting powders
42. Malathion water dispersible powder concentrates
43. Methyl parathion, technical
44. Chlordane emulsifiable concentrates
45. Diazinon emulsifiable concentrates
46. Diazinon water dispersible powder concentrates
47. Chlordane, technical
48. Chlordane dusting powders
49. Methyl parathion emulsifiable concentrates
50. Organo mercurial dry-seed-dressing formulations
51. Wettable sulphur powder
52. Zineb, technical
53. Zineb water dispersible powders
54. Ziram, technical
55. Ziram water dispersible powder
56. Dimethoate technical
57. Dimethoate emulsifiable concentrates
58. Thiometon concentrates
59. Thiometon emulsifiable concentrates
60. Thiram technical
61. 2, 4-D technical
62. Endosulfan dusting powders
63. Endosulfan emulsifiable concentrates
64. Endosulfan water dispersible powder concentrates
65. Binapacryl emulsifiable concentrates
66. Endosulfan, technical
67. Toxaphene, technical
68. Thiram water dispersible powder

69. Thiram seed dressing formulations
70. Pyrethrum emulsifiable concentrates
71. Dichlorves technical
72. Phosphemidon technical
73. Dichlorves emulsifiable concentrates
74. Dicofol, technical
75. Dicofol, emulsifiable concentrates
76. Fenitrothion, technical
77. Fenitrothion, emulsifiable concentrates
78. Coumafuryl, technical
79. Warfarin bait concentrates
80. Warfarin sodium, technical
81. Warfarin, technical
82. Emulsifiable larvicidal oil pyethrum based
83. Phosphamidon water soluble concentrates
84. Pyrothrum dusting powders
85. Heptachlor dusting powders
86. Heptachlor, technical
87. Aluminium phosphide formulation
88. Heptachlor emulsifiable concentrates
89. Sulphur dusting powder
90. Carbaryl water dispersible concentrates
91. Carbaryl dusting powders
92. Fenitrothion dusting powders
93. Isobornyl thiocyanoacetate (Thanite) technical
94. Warfarin sodium salt water soluble powder
95. 2, 4-D Ethyl Esters
96. Carbaryl technical
97. Trichlorfom dusting powders
98. Quintozene dusting powders
99. Trichlorfon, technical
100. Toxaphene emulsifiable concentrates
101. Toxaphene dusting powders
102. Fenthion emulsifiable concentrates
103. Quintozene water dispersible powder concentrates
104. Fenthion, technical
105. Phorate, technical
106. Disulfoton, technical
107. Quintozene, technical
108. Formothion technical solution
109. Monocrotophos, technical
110. Formothion emulsifiable concentrates
111. Propanil emulsifiable concentrates
112. Quinalphos emulsifiable concentrates
113. Quinalphos dusting powders
114. Propanil, technical
115. Quinalphos technical
116. Monocrotophos water soluble concentrates
117. Oxydemeton-methyl technical concentrates
118. Oxydemeton-methly emulsifiable concentrates
119. Dalapon-sodium technical
120. Dalapon-sodium water soluble powder
121. Phenthoate emulsifiable concentrates
122. Phenthoate, technical
123. Liquid amine salts of MCPA
124. Carbendazim (MBC) technical
125. Carbendazim (MBC) water dispersible powder concentrates
126. Phosalone emulsifiable concentrates
127. Phosalone, technical
128. Phosalene, dusting powders
129. MCPA, technical
130. Propoxur, technical
131. Paraquat dichloride water soluble concentrates
132. Temephos emulsifiable concentrates
133. Temephos technical
134. Diuron, technical
135. Diuron water dispersible concentrates
136. Mancozeb, technical
137. Mancozeb water dispersible powder concentrates
138. Chlorphyrifos emulsifiable concentrates
139. Edifenphos, technical
140. Edifenphos emulsifiable concentrates
141. Nitrofen, technical
142. Nitrofen emulsifiable concentrates
143. Fluchloralin, technical concentrates
144. Fluchloralin emulsifiable concentrates
145. Methyl parathion dusting powders
146. Chloryrifos, technical
147. Nickel chloride, hexa hydrate, pesticidal grade
148. Sodium cyanide, pesticidal grade
149. Alachlor, technical
150. Alachlor emulsifiable concentrates
151. Butachlor, technical
152. Butachlor emulsifiable concentrates
153. Triallate, technical
154. Triallate emulsifiable concentrates
155. Phorate granules, encapsulated
156. Carbofuran granules, encapsulated
157. Alachlor granules
158. Butachlor granules
159. Fenthion granules
160. Trichlorfon granules
161. Fenitrothion granules
162. Quinalphos granules
163. Disulfoton granules, encapsulated
164. Carbaryl granules
165. Diazinon granules
166. Lindane granules
167. Aldicarb granules encapsulated
168. Methyl parathion, technical concentrates
169. Tridemorph emulsifiable concentrates
170. Propoxur emulsifiable concentrates.
171. Tridemorph, technical
172. 2, 4D Ethyl ester emulsifiable concentrates
173. 2, 4D, Ethyl ester water dispersible powders
174. Endosulfan granules
175. Nitrofan granules
176. Phenthoate granules
177. Chlorfenvinphos, technical
178. Paraquate dimethyl sulphate water soluble concentrates
179. Fenitrothion water dispersible powders
180. Captafol water dispersible powders
181. Captafol technical
182. Ehtion emulsifiable concentrates
183. Copper acetoarsenite
184. Ethion technical
185. Nicotine sulphate
186. Aluminium Phosphide

(ii) For Annexure-II to the said notification, the following shall be substituted, namely:—

"ANNEXURE—II

Specifications for pesticides and their formulations

Sl. No.	Name of the pesticides and their formulations	*Relevant specification issued by the Indian Standard Institution
1	2	3
1.	BHC technical and refined	IS : 560—1980
2.	BHC (HCH) dusting powders	IS : 561—1978
3.	BHC (HCH) water dispersible powder concentrates	IS : 562—1978

1	2	3
4.	DDT technical	IS : 563—1973
5.	DDT dusting powders	IS : 564—1984
6.	DDT water dispersible powder concentrates	IS : 565—1984
7.	Mosquito larvicidal oil	IS : 588—1978
8.	Gama-BHC (Lindane) emulsifiable concentrates	IS : 632—1978
9.	DDT emulsifiable concentrates	IS : 633—1985
10.	Ethylene dichloride carbon tetrachloride mixture	IS : 634—1965
11.	Gama -BHC (Lindane)	IS : 882—1984
12.	Lime sulphur solution	IS : 1050—1984
13.	Pyrethrum extracts	IS : 1051—1980
14.	Nicotine sulphate solution	IS : 1055—1984
15.	Zinc phosphide, technical	IS : 1251—1984
16.	Aldrin, technical	IS : 1306—1974
17.	Aldrin emulsifiable concentrates	IS : 1307—1983
18.	Aldrin dusting powders	IS : 1308—1984
19.	Endrin, technical	IS : 1309—1974
20.	Ethylene dibromide	IS : 1311—1966
21.	Methyl bromide	IS : 1312—1980
22.	Copper oxychloride, technical	IS : 1486—1978
23.	2, 4-D Sodium technical	IS : 1488—1985
24.	Gama-BHC (Lindane) smoke	IS : 1505—1968
25.	Copper oxychloride dusting powders	IS : 1506—1977
26.	Copper oxychloride water dispersible powder concentrates	IS : 1507—1977
27.	Cuprous oxide water dispersible powder concentrates	IS : 1665—1977
28.	Cuprous oxide dusting powders	IS : 1669—1960
29.	Cuprous oxide, technical (fungicidal grade)	IS : 1682—1973
30.	Insecticidal space spray	IS : 1824—1978
31.	Liquid amine salts of 2, 4-D	IS : 1827—1984
32.	Malathion, technical	IS : 1832—1978
33.	Diazinon, technical	IS : 1833—1980
34.	Phenylmercury acetate, technical	IS : 2126—1973
35.	Stabilized methoxy ethyl mercury chloride concentrates	IS : 2127—1984
36.	Parathion ethyl, technical	IS : 2128—1973
37.	Ethyl mercury chloride, technical	IS : 2353—1963
38.	Formulations based on stabilised methoxy ethyl mercury chloride concentrates	IS : 2354—1963
39.	Formulations based on stabilized methoxy ethyl mercury chloride concentrates	IS : 2358—1984
40.	Malathion emulsifiable concentrates	IS : 2567—1978
41.	Malathion dusting powders	IS : 2568—1978
42.	Malathion water dispersible water concentrates	IS : 2569—1978
43.	Methyl parathion, technical	IS : 2570—1980
44.	Chlordane emulsifiable concentrates	IS : 2682—1984
45.	Dizinon emulsifiable concentrates	IS : 2861—1980
46.	Dizinon water dispersible powder, concentrates	IS : 2862—1984
47.	Chlordane, technical	IS : 2863—1968
48.	Chloridane dusting powders	IS : 2864—1984
49.	Methyl parathon emulsifiable concentrates	IS : 2865—1978
50.	Organo mercurial dry seedressing formulations	IS : 3284—1984
51.	Wettable sulphur powder	IS : 3383—1982
52.	Zineb, technical	IS : 3898—1981
53.	Zineb water dispersible powders	IS : 3899—1981
54.	Ziram, technical	IS : 3900—1975
55.	Ziram water dispersible powder	IS : 3901—1975
56.	Dimethoate technical	IS : 3902—1975
57.	Dimethoate emulsifiable concentrates	IS : 3903—1984
58.	Thiometon concentrates	IS : 3904—1966
59.	Thiometon emulsifiable concentrates	IS : 3905—1966
60.	Thiram technical	IS : 4320—1982
61.	2, 4-D technical	IS : 4321—1978
62.	Endosulfan dusting powders	IS : 4322—1967
63.	Endosulfan emulsifiable concentrates	IS : 4323—1980
64.	Endosulfan water dispersible powder concentrates	IS : 4324—1967
65.	Binapacryl emulsifiable concentrates	IS : 4325—1967
66.	Endosulfan, technical	IS : 4344—1978
67.	Toxaphene, technical	IS : 4451—1967
68.	Thiram water dispersible powder	IS : 4766—1982
69.	Thiram seed dressing formulations	IS : 4783—1982
70.	Pyrethrum emulsifieble concentrates	IS : 4808—1982
71.	Dichlorves, technical	IS : 4929—1978
72.	Phosphamidon, technical	IS : 4958—1968
73.	Dichlorves emulsifiable concentrates	IS : 5277—1978
74.	Dicofol, technical	IS : 5278—1969
75.	Dicofol emulsifiable concentrates	IS : 5279—1969
76.	Fenitrothion, technical	IS : 5280—1969
77.	Fenitrothion, emulsifiable concentrates	IS : 5281—1979
78.	Coumafuryl technical	IS : 5526—1969
79.	Warfarin bait concentrates	IS : 5549—1970
80.	Warfarin sodium technical	IS : 5551—1970
81.	Warfarin, technical	IS : 5552—1970
82.	Emulsifiable larvicidal oil pyrethrum based	IS : 6014—1978
83.	Phosphamidon water soluble concentrates	IS : 6177—1981
84.	Pyrethrum dusting powders	IS : 6178—1982
85.	Heptachlor dusting powders	IS : 6429—1981
86.	Heptachlor, technical	IS : 6432—1972
87.	Aluminium phosphide formulation	IS : 6438—1980
88.	Heptachlor emulsifiable concentrates	IS : 6439—1978
89.	Sulphur dusting powder	IS : 6444—1979
90.	Carbaryl water dispersible powder concentrates	IS : 7121—1973
91.	Carbaryl dusting powders	IS : 1122—1984
92.	Fenitrothion dusting powders	IS : 7126—1973
93.	Isobornyl thiocyanoacetate (Thanite) technical	IS : 7158—1973
94.	Warfarin sodium salt water soluble powder	IS : 7168—1973
95.	2, 4-D Ethyl esters	IS : 7233—1985
96.	Carbaryl technical	IS : 7539—1975
97.	Trichlorfon dusting powders	IS : 7943—1976
98.	Quintozene dusting powders	IS : 7944—1976
99.	Trichlorfon, technical	IS : 7945—1975
100.	Toxaphene emulsifiable concentrates	IS : 7946—1976
101.	Toxaphene dusting powders	IS : 7947—1976
102.	Fenthion emulsifiable concentrates	IS : 7948—1976
103.	Quintozene water dispersible powder concentrates	IS : 7949—1976
104.	Fenthion, technical	IS : 7950—1976
105.	Phorate, technical	IS : 7976—1976
106.	Disulfoton, technical	IS : 7977—1976
107.	Quintozene, technical	IS : 7985—1976
108.	Formothion technical solution	IS : 8024—1976
109	Monocrotophos, technical	IS : 8025—1983
110.	Formothion emulsifiable concentrates	IS : 8026—1976

1	2	2
111.	Propanil emulsifiable concentrates	IS : 8027—1976
112.	Quinalphos emulsifiable concentrates	IS : 8028—1976
113.	Quinalphos dusting powders	IS : 8029—1985
114.	Propanil, technical	IS : 8071—1976
115.	Quinalphos, technical	IS : 8072—1984
116.	Monocrotophos water soluble concentrates	IS : 8074—1983
117.	Oxydemeton-methyl technical concentrates	IS : 8258—1976
118.	Oxydemeton-methyl emulsifiable concentrates	IS : 8259—1976
119.	Dalapon-sodium technical	IS : 8267—1976
120.	Dalapon-sodium water soluble powder	IS : 8286—1976
121.	Phenthoate emulsifiable concentrates	IS : 8291—1976
122.	Phenthoate, technical	IS : 8293—1976
123.	Liquid amine salts of MCPA	IS : 8294—1976
124.	Carbendazim (MBC) technical	IS : 8445—1977
125.	Carbandazim (MBC) water dispersible powder concentrates	IS : 8446—1977
126.	Phosalone, emulsifiable concentrates	IS : 8487—1977
127.	Phosalone, technical	IS : 8488—1977
128.	Phosalone dusting powder	IS : 8489—1977
129.	MCPA, technical	IS : 8494—1977
130.	Propoxur, technical	IS : 8496—1977
131.	Paraquat dichloride water soluble concentrates	IS : 8497—1977
132.	Temephos emulsifiable concentrates	IS : 8498—1977
133.	Temephos, technical	IS : 8701—1978
134.	Diuron, technical	IS : 8702—1978
135.	Diuron water dispersible concentrates	IS : 8703—1978
136.	Mancozeb, technical	IS : 8707—1978
137.	Mancozeb water dispersible powder concentrates	IS : 8708—1978
138.	Chlorphyrifos emulsifiable concentrates	IS : 8944—1978
139.	Edifenphos, technical	IS : 8954—1978
140.	Edifenphos, emulsifiable concentrates	IS : 8955—1978
141.	Nitrofen technical	IS : 8956—1978
142.	Nitrofen emulsifiable concentrates	IS : 8957—1978
143.	Fluchloralin, technical concentrates	IS : 8956—1978
144.	Fluchloralin emulsifiable concentrates	IS : 8959—1978
145.	Methyl parathion dusting powders	IS : 8960—1978
146.	Chlorpyrifos, technical	IS : 8963—1978
147.	Nickel chloride, hexahydrate, Pesticidal grade	IS : 9351—1980
148.	Sodium, cyanide, pesticidal grade	IS : 9352—1980
149.	Alachlor, technical	IS : 9353—1980
150.	Alachlor emulsifiable concentrates	IS : 9354—1980
151.	Butachlor, technical	IS : 9355—1980
152.	Butachlor, emulsifiable concentrates	IS : 9356—1980
153.	Triallate, technical	IS : 9357—1980
154.	Triallate emulsifiable concentrates	IS : 9358—1980
155.	Phorate granules, encapsulated	IS : 9359—1980
156.	Carbofuran granules, encapsulated	IS : 9360—1980
157.	Alachlor granules	IS : 9361—1980
158.	Butachlor granules	IS : 9362—1980
159.	Fenthion granules	IS : 9363—1980
160.	Trichlorfon granules	IS : 9364—1980
161.	Fenitrothion granules	IS : 9365—1980
162.	Quinalphos granules	IS : 9366—1980
163.	Disulfoton granules, encapsulated	IS : 9367—1980
164.	Carbaryl granules	IS : 9368—1980
165.	Diazinon granules	IS : 9369—1980
166.	Lindane granules	IS : 9370—1980
167.	Aldicarb granules encapsulated	IS : 9371—1980

1	2	3
168.	Methylparathion, technical concentrates	IS : 9372—1980
169.	Tridemorph emulsifiable concentrates	IS : 9656—1980
170.	Propoxur emulsifiable concentrates	IS : 9665—1981
171.	Tridemorph technical	IS : 9668—1981
172.	2, 4-D Ethyl ester emulsifiable concentrates	IS : 10243—1982
173.	2, 4-D Ethyl ester water dispersible powders	IS : 10244—1982
174.	Endosulfan granules	IS : 10265—1982
175.	Nitrofan granules	IS : 10266—1982
176.	Phenthoate granules	IS : 10267—1982
177.	Chlorfenvinphos, technical	IS : 10268—1982
177.	Chlorfenvinphos, technical	IS : 10268—1982
178.	Paraquat dimethyl sulphate water soluble concentrates	IS : 10294—1982
179.	Fenitrothion water dispersible powders	IS : 10295—1982
180.	Captafol water dispersible powders	IS : 10296—1982
181.	Captafol technical	IS : 10300—1982
182.	Ethion emulsifiable concentrates	IS : 10319—1982
183.	Copper acetoarsenite	IS : 10355—1982
184.	Ethion technical	IS : 10369—1982

[F. No. 6(2)/84-EI&EP]

का. आ. 781.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी, नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3311 तारीख 7 अक्टूबर, 1970 के साथ संलग्नित नाशकजीवमार और उनके निरूपणों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नाशकजीवमार और उनके निरूपणों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नाशकजीवमार और उनके निरूपणों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1970 में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची"

1. बी एच सी तकनीकी तथा परिष्कृत ।
2. बी एच सी (एच सी एच) डस्टिंग चूर्ण ।
3. बी एच सी (एच सी एच) पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण ।
4. डी डी टी तकनीकी ।
5. डी डी टी डस्टिंग चूर्ण ।
6. डी डी टी पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण ।
7. मच्छर नाशकारी तेल ।
8. गामा-बी एच सी (लिण्डेन) पायसीकृत दाने ।
9. डी डी टी पायसीकृत दाने ।
10. एथिलीन डाइक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड मिश्रण ।
11. गामा-बी एच सी (लिण्डेन) ।
12. चूना गंधक घोल ।
13. पायरेथ्रम निस्सारण ।
14. निकोटीन गंधक घोल ।
15. जिंक फास्फाइड तकनीकी ।
16. एल्ड्रीन, तकनीकी ।
17. एल्ड्रीन पायसीकृत दाने ।

18. एल्ड्रीन डस्टिंग चूर्ण।
19. एल्ड्रीन, तकनीकी।
20. एथिलीन डायब्रोमाईड।
21. मैथिल ब्रोमाइड।
22. कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तकनीकी।
23. 2, 4-डी सोडियम, तकनीकी।
24. गामा-बी.एच.सी. (लिण्डेन) धुआंकारक जनित।
25. कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डस्टिंग चूर्ण।
26. कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण।
27. क्यूपरस ऑक्साइड पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण।
28. क्यूपरस ऑक्साइड डस्टिंग चूर्ण।
29. क्यूपरस ऑक्साइड, तकनीकी, (फफूंदीनाशी श्रेणी)।
30. जगह-जगह कीटनाशी छिड़काव।
31. 2, 4-डी का तरल एमिन नमक।
32. मैलेथियन, तकनीकी।
33. डायजिनॉन, तकनीकी।
34. फिनाइल मर्करी ऐसीटेट, तकनीकी।
35. स्थायी मैथोक्सी एथिल मर्करी क्लोराइड सांद्रित।
36. पैराथियन एथिल, तकनीकी।
37. फिनायल मर्करी क्लोराइड, तकनीकी।
38. एथिल मर्करी क्लोराइड, तकनीकी।
39. स्थायी मैथोक्सी एथिल मर्करी क्लोराइड पर आधारित निरूपण।
40. मैलाथियन डस्टिंग चूर्ण।
41. मैलेथियन पायसीकृत दाने।
42. मैलेथियन पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण।
43. मिथाइल पैरथियन तकनीकी।
44. क्लोरेडेन पायसीकृत दाने।
45. डायजीनोन पायसीकृत दाने।
46. डायजीनोन पानी में घुलनशील सांद्रित चूर्ण।
47. क्लोरेडेन तकनीकी।
48. क्लोरडेन डस्टिंग चूर्ण।
49. मिथाइल पैराथियन पायसीकृत दाने।
50. ओरगैनोमरक्यूरियल ड्राई-सीड-ड्रैसिंग निरूपण।
51. मिलाने योग्य गंधक चूर्ण।
52. जिनेब, तकनीकी।
53. जिनेब पानी में घुलनशील चूर्ण।
54. जिरम, तकनीकी।
55. जिरम पानी में घुलनशील चूर्ण।
56. डाइमेथोएट तकनीकी।
57. डाइमेथोएट पायसीकृत दाने।
58. थियोमेटोन दाने।
59. थियोमेटोन पायसीकृत दाने।
60. थाइरम, तकनीकी।
61. 2, 4-डी, तकनीकी।
62. एंडोसल्फन डस्टिंग चूर्ण।
63. एंडोसल्फन पायसीकृत दाने।
64. एंडोसल्फन पानी में घुलनशील चूर्ण, दाने।
65. बिनापाक्राइल पायसीकृत दाने।
66. एंडोसल्फन, तकनीकी।
67. टॉक्साफेन, तकनीकी।
68. थाइरम पानी में घुलनशील चूर्ण।
69. थाइरम-सीड-ड्रैसिंग निरूपण।
70. पायरेथ्रम पायसीकृत दाने।
71. डायक्लोरवोस, तकनीकी।
72. फासफामीडान, तकनीकी।
73. डायक्लोरवस पायसीकृत दाने।
74. डाइकोफोल, तकनीकी।
75. डाइकोफोल पायसीकृत दाने।
76. फैनीट्रोथियन, तकनीकी।
77. फैनीट्रोथियन पायसीकृत दाने।
78. कम्माफ्यूरल, तकनीकी।
79. वार्फरेन चारे के दाने।
80. वार्फरेन सोडियम, तकनीकी।
81. वार्फरेन, तकनीकी।
82. पायसीकृत पाइपरोनाइल तेल पाइरेथ्रम बेस में।
83. फासफेमीडोन पानी में घुलनशील दाने।
84. पाइरेथ्रम डस्टिंग चूर्ण।
85. हेप्टाक्लोर डस्टिंग चूर्ण।
86. हेप्टाक्लोर, तकनीकी।
87. एल्यूमीनियम फास्फाइड निरूपण।
88. हेप्टाक्लोर पायसीकृत दाने।
89. सल्फर डस्टिंग चूर्ण।
90. कारबोरिल पानी में घुलनशील दाने।
91. कारबोरिल डस्टिंग चूर्ण।
92. फैनीट्रोथियन डस्टिंग चूर्ण।
93. आइसोबोरनियल थियोसाइएनसिटेट (थाइनाइट) तकनीकी।
94. वार्फरेन सोडियम नमक पानी में घुलनशील चूर्ण।
95. 2, 4-डी एथिल इस्टर्स।
96. कारबोरिल, तकनीकी।
97. ट्राईक्लोरफोन, डस्टिंग चूर्ण।
98. क्वीनटोजन डस्टिंग चूर्ण।
99. ट्राईक्लोरफोन, तकनीकी।
100. टोक्साफेन पायसीकृत दाने।
101. टोक्साफेन डस्टिंग चूर्ण।
102. फेनथियन पायसीकृत दाने।
103. क्वीनटोजन पानी में घुलनशील दाने।
104. फेनथियन, तकनीकी।
105. फोरेट, तकनीकी।
106. ईमिलफोटन, तकनीकी।
107. क्वीनटोजन, तकनीकी।
108. फारमोथियन तकनीकी घोल।
109. मोनोक्रोटोफास, तकनीकी।
110. फारमोथियन पायसीकृत दाने।
111. प्रोपेनील पायसीकृत दाने।
112. क्वीनलफोस पायसीकृत दाने।
113. क्वीनलफोस डस्टिंग चूर्ण।
114. प्रोपेनील, तकनीकी।
115. क्वीनलफोस, तकनीकी।
116. मोनोक्रोटोफोस पानी में घुलनशील दाने।
117. ऑक्सीडेमेटन-मैथाइल तकनीकी दाने।
118. ऑक्सीडेमेटन-मैथाइल पायसीकृत दाने।
119. डालापोन-सोडियम, तकनीकी।
120. डालापोन-सोडियम पानी में घुलनशील चूर्ण।
121. फैनथोएट पायसीकृत दाने।
122. फैनथोएट, तकनीकी।
123. एम.ई.पी.ए. का तरल एमाइन नमक।
124. कार्बनडाइजिम (एम.बी.सी.) तकनीकी।
125. कार्बनडाइजिम (एम.बी.सी.) पानी में घुलनशील चूर्ण दाने।
126. फोसलोन पायसीकृत दाने।
127. फोसेलोन, तकनीकी।
128. फोसेलोन डस्टिंग चूर्ण।
129. एम.सी.पी.ए. तकनीकी।

130. प्रोपोक्सर, तकनीकी ।
131. पैराक्यूट डीक्लोराइड पानी में घुलनशील दाने ।
132. टेमफोस पायसीकृत दाने ।
133. टेमफोस तकनीकी ।
134. डियूरोन, तकनीकी ।
135. डियूरोन पानी में घुलनशील चूर्ण, दाने ।
136. मैनकोजेब, तकनीकी ।
137. मैनकोजेब पानी में घुलनशील चूर्ण, दाने ।
138. क्लोरफेनविनफोस पायसीकृत दाने ।
139. एडिफनफोस, तकनीकी ।
140. एडिफनफोस पायसीकृत दाने ।
141. नाइट्रोफन तकनीकी ।
142. नाइट्रोफन पायसीकृत दाने ।
143. फ्लूक्लोरोलीन, तकनीकी दाने ।
144. फ्लूक्लोरोलीन पायसीकृत दाने ।
145. मैथाइल पैराथियन डस्टिंग चूर्ण ।
146. क्लोरफेनविनफोस, तकनीकी ।
147. निकल क्लोराइड, हैक्साहाइड्रेट, पैस्टीसाइडल ग्रेड ।
148. सोडियम, साइनाइड, कीटनाशी ग्रेड ।
149. एलक्लोर, तकनीकी ।
150. एलक्लोर पायसीकृत दाने ।
151. बूटाक्लोर, तकनीकी ।
152. बूटाक्लोर पायसीकृत दाने ।
153. ट्राईल्लेट, तकनीकी ।
154. ट्राईल्लेट पायसीकृत दाने ।
155. फोरेट दानेदार संपुटित ।
156. कारबोफ्यूरान दानेदार संपुटित ।
157. एलक्लोर दानेदार ।
158. बूटाक्लोर दानेदार ।
159. फैनथियोन दानेदार ।
160. ट्राईक्लोरोफन दानेदार ।
161. फैनीट्रोथियोन दानेदार ।
162. क्वीनलफोस दानेदार ।
163. डायसल्फोटन दानेदार, संपुटित ।
164. कारबेरियल दानेदार ।
165. डायजिनोन दानेदार ।
166. लिण्डेन दानेदार ।
167. एल्डीकार्ब दानेदार संपुटित ।
168. मैथाइल पैराथियन, तकनीकी दाने ।
169. ट्राईडेमोर्फ पायसीकृत दाने ।
170. प्रोपोक्सर पायसीकृत दाने ।
171. ट्राईडेमोर्फ, तकनीकी ।
172. 2, 4-डी एथिल इस्टर पायसीकृत दाने ।
173. 2, 4-डी एथिल इस्टर पानी में घुलनशील चूर्ण ।
174. एण्डोसल्फन दानेदार ।
175. नाइट्रोफन दानेदार ।
176. फैनथोएट दानेदार ।
177. क्लोरफेनविनफोस, तकनीकी ।
178. पैराक्यूट डाइमैथाइल सल्फेट पानी में घुलनशील दाने ।
179. फैनीट्रोथियन पानी में घुलनशील चूर्ण ।
180. कैपटाफोल पानी में घुलनशील चूर्ण ।
181. कैपटाफोल, तकनीकी ।
182. एथियन पायसीकृत दाने ।
183. कॉपर एसिटोआर्सेनाइट ।
184. एथियन, तकनीकी ।
185. निकोटीन सल्फेट ।
186. एल्यूमिनीयम फॉसफाइड ।"

[फाईल सं. 6(2)/84-ई आई एंड ई पी]

S.O. 781.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Pesticides and their Formulations (Inspection) Rules, 1970 published with the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3311 dated the 7th October, 1970, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Pesticides and their Formulations (Inspection) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Pesticides and their Formulations (Inspection) Rules, 1970, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE

1. BHC technical and refined
2. BHC (HCH) dusting powders
3. BHC (HCH) water dispersible powder concentrates
4. DDT technical
5. DDT dusting powders
6. DDT water dispersible water concentrates
7. Mosquito larvicidal oil
8. Gama—BHC (Lindane) emulsifiable concentrates
9. DDT emulsifiable concentrates
10. Ethylene dichloride carbon tetrachloride mixture
11. Gama BHC (Lindane)
12. Lime sulphur solution
13. Pyrethrum extracts
14. Nicotine sulphate solution
15. Zinc phosphide, technical
16. Aldrin, technical
17. Aldrin emulsifiable concentrates
18. Aldrin dusting powders
19. Aldrin technical
20. Ethylene dibromide
21. Methyl bromide
22. Copper oxychloride, technical
23. 2, 4D sodium, technical
24. Gama—BHC (Lindane) smoke generators
25. Copper oxychloride dusting powders
26. Copper oxychloride water dispersible powder concentrates
27. Cuprous oxide water dispersible powder concentrates
28. Cuprous oxide dusting powders
29. Cuprous oxide, technical (fungicidal grade)
30. Insecticidal space spray
31. Liquid amine salts of 2, 4-D
32. Malathion, technical
33. Diazinon technical
34. Phenyl mercury acetate, technical
35. Stabilized methoxy ethyl mercury chloride concentrates
36. Parathion ethyl, technical
37. Phenyl mercury chloride, technical
38. Ethyl mercury chloride, technical
39. Formulations based on stabilized methoxy ethyl mercury chloride concentrates
40. Malathion dusting powders
41. Malathion emulsifiable concentrates
42. Malathion water dispersible powder concentrates
43. Methyl parathion, technical
44. Chlordane emulsifiable concentrates
45. Diazinon emulsifiable concentrates
46. Diazinon water dispersible powder concentrates
47. Chlordane, technical
48. Chlordane dusting powders

49. Methyl parathion emulsifiable concentrates
50. Organo mercurial dry-seed-dressing formulations
51. Wettable sulphur powder
52. Zineb, technical
53. Zineb water dispersible powders
54. Ziram, technical
55. Ziram water dispersible powder
56. Dimethoate technical
57. Dimethoate emulsifiable concentrates
58. Thiometon concentrates
59. Thiometon emulsifiable concentrates
60. Thiram technical
61. 2, 4-D technical
62. Endosulfan dusting powders
63. Endosulfan emulsifiable concentrates
64. Endosulfan water dispersible powder concentrates
65. Binapacryl emulsifiable concentrates
66. Endosulfan, technical
67. Toxaphene, technical
68. Thiram water dispersible powder
69. Thiram seed dressing formulations
70. Phrethrum emulsifiable concentrates
71. Dichlorves technical
72. Phosphemidon technical
73. Dichlorves emulsifiable concentrates
74. Dicofol, technical
75. Dicofol, emulsifiable concentrates
76. Fenitrothion, technical
77. Fenetrothion, emulsifiable concentrates
78. Coumafuryl, technical
79. Warfarin salt concentrates
80. Warfarin sodium technical
81. Warfarin, technical
82. Emulsifiable larvicidal oil pyrethrum based
83. Phosphamidon water soluble concentrates
84. Pyrethrum dusting powders
85. Heptachlor dusting powders
86. Heptachlor, technical
87. Aluminium phosphide formulation
88. Heptachlor emulsifiable concentrates
89. Sulphur dusting powder
90. Carbaryl water dispersible concentrates
91. Carbaryl dusting powders
92. Fenitrethion dusting powders
93. Isobornyl thiocyanoacatete (Thanite) technical
94. Warfarin sodium salt water soluble powder
95. 2, 4-D ethyl esters
96. Carbaryl technical
97. Trichlorfom dusting powders
98. Quinbozene dusting powders
99. Trichlorfon, technical
100. Toxaphene emulsifiable concentrates
101. Toxaphene dusting powders
102. Fenthion emulsifiable concentrates
103. Quintozene water dispersible powder concentrates
104. Fenthion, technical
105. Phorate, technical
106. Disulfoton, technical
107. Quintozene, technical
108. Formothion technical solution
109. Monocrotophos, technical
110. Formethion emulsifiable concentrates
111. Propanil emulsifiable concentrates
112. Quinalphos emulsifiable concentrates
113. Quinalphos dusting powders
114. Propanil, technical
115. Quinalphos technical
116. Monocrotophos water soluble concentrates
117. Oxydemeton-methyl technical concentrates
118. Oxydemeton-methyl emulsifiable concentrates
119. Dalapon-sodium technical
120. Dalapon-sodium water soluble powder
121. Phenthoate emulsifiable concentrates
122. Phenthoate, technical
123. Liquid amine salts of MCPA
124. Carbendazim (MBC) technical
125. Carbondazim (MBC) water dispersible powder concentrates
126. Phosalone emulsifiable concentrates
127. Phosalone, technical
128. Phosalone, dusting powders
129. MCPA technical
130. Propoxur, technical
131. Paraquat dischloride water soluble concentrates
132. Termephos emulsifiable concentrates
133. Temphos technical
134. Diuron, technical
135. Diuron water dispersible concentrates
136. Mancozeb technical
137. Mancozeb water dispersible powder concentrates
138. Chlorphyrifos emulsifiable concentrates
139. Edifenphos, technical
140. Edifenphos emulsifiable concentrates
141. Nitrofen, technical
142. Nitrofen emulsifiable concentrates
143. Fluchloralin, technical concentrates
144. Fluchloralin emulsifiable concentrates
145. Methyl parathion dusting powders
146. Chloryrifos, technical
147. Nickel chloride, hexa hydrate, pesticidal grade
148. Sodium cynaide, pesticidal grade
149. Alachlor, technical
150. Alachlor emulsifiable concentrates
151. Butachlor, technical
152. Butachlor emulsifiable concentrates
153. Triallate, technical
154. Triallate emulsifiable concentrates
155. Phorate granules, encapsulated
156. Carbofuran granules, encapsulated.
157. Alachlor granules
158. Butachlor granules
159. Fenthion granules
160. Trichlorfon granules
161. Fentrothion granules
162. Quinalphos granules
163. Disulfoton granules, encapsulated
164. Carbaryl granules
165. Diazinon granules
166. Lindane granules
167. Aldicarb granules encapsulated
168. Methyl parathion, technical concentrates
169. Tridemorph emulsifiable concentrates
170. Propoxur emulsifiable concentrates
171. Tridemorph, technical
172. 2, 4-D ethyl ester emulsifiable concentrates
173. 2, 4D ethyl ester water dispersible powders
174. Endosulfan granules
175. Nitrofan granules
176. Phenthoate granules

177. Chlorfenvinphos, technical
178. Paraquate dimethyl sulphate water soluble concentrates
179. Fenitrothion water dispersible powders
180. Captafol water dispersible powders
181. Captafol technical
182. Ethion emulsifiable concentrates
183. Copper acetoarsenite
184. Ethion technical
185. Nicotine sulphate
186. Aluminium phosphide."

[F. No. 6(2)/84-FI&FP]

का. आ. 782.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए काजू की गिरियां निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम II के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 3091 तारीख 6 जुलाई 1985 के अधीन भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड-(ii) तारीख 6 जुलाई 1985 में प्रकाशित किए गए थे,

और उनसे प्रभावित सभी व्यक्तियों से 13 सितम्बर, 1985 तक आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 19 जुलाई, 1985 को उपलब्ध करा दी गयी थीं;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात अपनी यह राय होने पर कि उक्त उपनियम के अनुसरण में और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का.आ. 1022 तारीख 26 मार्च, 1966 और स.का.आ. 275 तारीख 28 जनवरी, 1978 का अधिक्रमण करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है;

(1) अधिसूचित करता कि काजू की गिरियां निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी,

(2) इस आदेश की अनुसूची में दिए गए विनिर्देशों को काजू की गिरियों को मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देता है।

(3) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान काजू की गिरियों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करता जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरण द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ऐसे काजू की गिरियां मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं और निर्यात योग्य हैं।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को काजू की गिरियों के नमूनों के निर्यात पर भूमि, वायु या समुद्र मार्ग द्वारा लागू नहीं होगी परन्तु यह तब जब कि ऐसे नमूनों का पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 250 रु. से अधिक नहीं होगा।

3. परिभाषाएं: इस आदेश में "काजू की गिरियों" से सभी प्रकार की काजू की गिरियां, बिना झुलसी, झुलसी हुई, साबुत या टुकड़े तथा भुनी हुई या नमक लगाई हुई गिरियां भी अभिप्रेत है।

4. यह आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुसूची

काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश

1. सामान्य विशेषताएं. काजू की गिरियां, काजुओं को भूनकर, छिलका उतारकर और छीलकर (ऐनाकार्डियम आक्सिडेंटल लिनेअस) से प्राप्त की जाएगी

2. विनिर्दिष्ट विशेषताएं

क. काजू की गिरियां—सफेद साबुत :

श्रेणी अभिधान	व्यापारिक नाम	रंग/विशेषताएं	काउंट/453 ग्राम माप विवरण	अधिकतम आर्द्रता	टूटे हुए टुकड़े	एस एस एस जी/एल एस जी अधिकतम	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8
डब्ल्यू-180	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	120–180	5	5	5 (एस एस एस जी तथा एस डब्ल्यू के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जमे हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन या मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और आंशिक मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं।
डब्ल्यू-210	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	200–210	5	5	5 (एस एस एस जी तथा एस डब्ल्यू के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जमे हुए बीजावरण आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्ण या रहित होंगी। यदि छिलन या मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और आंशिक मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
डब्ल्यू-240	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	220–240	5	5	5 (एन एल एस जी तथा एस डब्ल्यू के साथ)	
डब्ल्यू-280	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	260–280	5	5	5 (एन एल एस जी तथा एस डब्ल्यू के साथ)	
डब्ल्यू-320	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	300–320	5	5	5 (एन एल एस जी तथा एस डब्ल्यू के साथ)	
डब्ल्यू-400	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	350–400	5	5	5 (एन एल एस जी तथा एस डब्ल्यू के साथ)	गिरियां घसन, कीट, क्षति, फफूंदी विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्ण-तया रहित होंगी। यदि छिलन या मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं।
डब्ल्यू-450	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	400–450	5	5	5 (एन एल एस जी तथा एस डब्ल्यू के साथ)	
डब्ल्यू-500	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	450–500	5	5	5 (एन एल एस जी तथा एस डब्ल्यू के साथ)	
ङ. भुलसी हुई काजू की गिरियां—साबुत							
एस डब्ल्यू-	भुलसी हुई/ साबुत	शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां भुलसी हुई/हल्की या गहरी हो सकती हैं।	—	5	5	7.5 (एन एल जी तथा एस एस डब्ल्यू के साथ)	गिरियां घसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी यदि छिलन मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं।
एस डब्ल्यू-180	भुलसी हुई/ साबुत	शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां भुलसी हुई/ हल्की या गहरी हो सकती हैं।	170–180	5	5	7.5 (एन एल जी तथा एस एस-डब्ल्यू के साथ)	
एस डब्ल्यू-210	भुलसी हुई/ साबुत	शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां भुलसी हुई/हल्की या गहरी हो सकती हैं।	200–210	5	5	7.5 (एन एल जी तथा एस एस-डब्ल्यू के साथ)	
एस डब्ल्यू-240	भुलसी हुई/ साबुत	शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां भुलसी हुई/हल्की या गहरी हो सकती हैं।	220–240	5	5	7.5 (एन एल एस जी तथा एस डब्ल्यू के साथ	गिरियां घसन, कीट, क्षति, फफूंदी विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्ण तया रहित होंगी यदि छिलन मुरझा-एपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं।
एस डब्ल्यू-280	भुलसी हुई/ साबुत	शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां भुलसी हुई/ हल्की या गहरी हो सकती हैं।	260–280	5	5	7.5 (एन एल एस जी तथा एस डब्ल्यू के साथ)	

1	2	3	4	5	6	7	8
एस डब्ल्यू-320	झुलसी हुई/ साबुत	शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां झुलसी हुई/ हल्की या गहरी हो सकती हैं।	300–320	5	5	7.5 (एन एल एस जी तथा एस एस डब्ल्यू के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी यदि छिलन, मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं।
एस डब्ल्यू-400	झुलसी हुई/ साबुत	शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां झुलसी हुई/हल्की या गहरी हो सकती है।	350–400	5	5	7.5 (एन एल एस जी तथा एस डब्ल्यू के साथ)	
एस डब्ल्यू-450	झुलसी हुई/ साबुत	शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां झुलसी हुई/ हल्की या गहरी हो सकती है।	400–450	5	5	7.5 (एन एल एस जी तथा एस एस एस डब्ल्यू के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी यदि छिलन मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है।
एस डब्ल्यू-500	झुलसी हुई/ साबुत	शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां झुलसी हुई/हल्की या गहरी हो सकती हैं।	450–500	5	5	7.5 (एस एल एस जी तथा एस एस डब्ल्यू के साथ)	
ग. डेजर्ट काजू की गिरियां—साबुत							
एस एस डब्ल्यू	भुनी हुई साबुत घटिया	गिरियां ज्यादा भुनी हुई, कच्ची, मुरझाई हुई (पीरीवल) चित्तीदार (करनोरम) रंगहीन तथा हल्की नीली हो सकती है	लागू नहीं	5	5		गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी।
डी डब्ल्यू	डेजर्ट साबुत	गिरियां अधिक भुनी हुई गहरी, भूरी, गाढ़ी नीली, चित्तीदार, रंगहीन तथा काले धब्बों वाली हो सकती है।	लागू नहीं	5	5	शून्य	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी।
घ. काजू की गिरियां (सफेद टुकड़े)							
बी	बट्स	सफेद/पीला दंत सफेद हल्का सलेटी आड़ी तिरछी टूटी हुई (समान रूप या असमान) तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई गिरियां	लागू नहीं	5	5	(एसबी)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार का प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं।
एस	टुकड़े	सफेद/पीला दंत सफेद या हल्का सलेटी/प्राकृतिक रूप में लम्बाई में टूटी हुई गिरियां	लागू नहीं	5	5	(एसएस)	गिरियां ग्रसन, कीट क्षति, फफूंदी, विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन/ मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं।

1	2		4	5	6	7	8
एल डब्ल्यू पी	सफेद बड़े टुकड़े	सफेद/पीलापन लिए सफेद या हल्का सलेटी	गिरियां दो से अधिक टुकड़ों में टूटी हुई और 4 छिद्रों वाली /16 एस डब्ल्यू जी छलनी 4.75 मि. मी. आई एस छलनी से नहीं निकल सकेंगी	5	शून्य	5 (एस पी तथा एस डब्ल्यू पी के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी । यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं ।
एस डब्ल्यू पी	छोटे सफेद टुकड़े	सफेद/पीलापन लिए सफेद या हल्का सलेटी	एस डब्ल्यू पी में वर्णित से छोटी टूटी हुई गिरियां किन्तु जो 6 छिद्रों वाली 20 एस डब्ल्यू जी छलनी/2.80 मि.मी. आई एस छलनी से न निकल सकें।	5	शून्य	5 (एस एस पी तथा बी बी के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी । यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं ।
बी बी	बेबी बिट्स	सफेद/पीलापन लिए सफेद या हल्का सलेटी	एस डब्ल्यू पी में वर्णित से छोटे टूटी हुई गिरियों और पदमूलक जो 10 छिद्रों वाली 24 छिद्रों वाली 24 एस डब्ल्यू जी छलनी/170 मि.मी. आई एस छलनी से न निकल सकें।	5	शून्य	1% (काजू का पाउडर)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी ।
ङ. काजू की गिरियों—भुने हुए टुकड़े							
एस बी	भुने हुए बट्स	आंशिक तिरछी टूटी हुई गिरियां (समान रूप तथा असमान रूप में) तथा प्राकृतिक रूप में जुड़ी हुई गिरियां/शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भुनी हुई/हल्की गहरी हो सकती हैं ।	शून्य	5	5	7.5 (डीबी)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए, बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी । यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत होंगी ।
एसएस	भुने हुए टुकड़े	प्राकृतिक रूप से लम्बाई में टूटी हुई गिरियां/शुष्कक बोरमा में भूनने सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण दौरान गिरियां	शून्य	5	5	5 (डीएस)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी । यदि छिलन/मुरझाए-

1	2	3	4	5	6	7	8
		भूनी हुई हल्की गहरी हो सकती है।					पन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत होंगी।
एसपी	भूने हुए टुकड़े	शुष्कक/बोरमा में भूनने/सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भूनी हुई हल्की/गहरी हो सकती है।	टुकड़े जो 4 छिद्रों वाली 16एस डब्ल्यूजी छलनी/4.75 मी.मि. आई एस छलनी से न निकल सकें।	5	शून्य	5 (एसपी) एस तथा एसएसपी के साथ	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। । यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत होंगी।
एस एस पी	भूने हुए छोटे टुकड़े	शुष्कक/बोरमा में भूनने सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भूनी हुई हल्की/गहरी हो सकती है।	भूने टुकड़े से छोटे टुकड़े जो 6 छिद्रों वाली/20 एसडब्ल्यूजी छलनी 2.80 मि.मी. छलनी से न निकल सकें	5	शून्य	5 (डीएसपी)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत-गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्ति-जनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत होंगी।
ब. काजू की गिरियां (खराब टुकड़े)							
एसपीएस	भूने हुए घटिया टुकड़े	शुष्कक/बोरमा में भूनने/सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भूनी हुई/हल्की गहरी हो सकती हैं।	टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां जो 4 छिद्रों वाली 16 एस डब्ल्यू जी छलनी/4.75 मि.मी. आई एस छलनी से न निकल सके।	5	शून्य	5 (डीपी तथा डीएसपी के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्ति-जनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी।
डीपी	डेजर्ट टुकड़े	गिरियां गहरी भुनी हुई गाढ़े भूरे, गाढ़े नीले, चित्तीदार, रंगहीन और काले धब्बों से युक्त हो सकती है।	टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां जो चार छिद्रों वाली/16 एस डब्ल्यू जी छलनी/4.75 मि.मी. आई एस छलनी से न निकल सकें।	5	शून्य	5 (डीएसपी)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी।
डी एस पी	डेजर्ट छोटे टुकड़े	गिरियां गहरी भुनी हुई गाढ़े, भूरे गाढ़े नीले चित्तीदार, रंगहीन और काले धब्बों से युक्त हो सकती है।	टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां जो 6 छिद्रों	5	शून्य	2 (छोटे टुकड़े)	गिरियां, ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत-गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्ति-जनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
			बाली/20 एस डब्ल्यू जी छलनी 2.80 मि. मी. आई एस छलनी से न निकल सके।				
डीबी	डेजर्ट बट्स	आड़ी तिरछी टूटी हुई गिरियां (समान रूप तथा असमान रूप में) प्राकृतिक रूप में जुड़ी हुई, चित्तीदार गाढ़े भूरे, रंगहीन तथा गाढ़े नीले तथा काले धब्बों से युक्त हो सकती है।	शून्य	5	5	7.5 (डीपी तथा डीएसपी के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत-गंधिता जुड़े हुए बीजावरण, आपत्ति-जनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी।
डीएस	डेजर्ट टुकड़े	टूटी हुई गिरियां प्राकृतिक रूप से टूटी हुई लम्बाई में गिरियां गहरी भूनी हुई, गाढ़े भूरे, नीले, चित्तीदार रंगहीन तथा काले धब्बों से युक्त हो सकती है।	शून्य	5	5	5(डीपी तथा डीएस पी के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी।

एन.एल.जी.—अगली निम्न श्रेणी का द्योतक है।

एन.एल.एस.जी.—अगली निम्न श्रेणी के आकार का द्योतक है।

छ. भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश

छ.1 कच्ची सामग्री :—

छ.1.1 काजू की गिरियां, जिनमें भुनी हुई, बिना भुनी हुई साबुत गिरियां या टुकड़े सम्मिलित हैं, भूनने तथा नमक लगाने के लिए प्रयोग की जाएंगी।

छ.1.2 ये किसी भी प्रकार के कीट ग्रसन, फफूंदी, वृद्धि, विकृत गंधिता तथा बीजावरण की उपस्थिति से पूर्णतया रहित होंगी।

छ.2 तैयार करना :—

छ.2.1 भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियां किसी भी साध्यताप्राप्त पकाने वाले बर्तन में उनको भूनकर तथा नमक लगा कर या सुखाकर तैयार की जाएगी।

छ.2.2 पकाने के लिए प्रयुक्त, बर्तन स्टैनलैस स्टील के होंगे।

छ.3 उत्पाद अपेक्षाएं :—

छ.3.1 क्रेता तथा विक्रेता के बीच की गयी संविदा में यथा अनुबंधित श्रेणी अभिधान तब तक अनुज्ञात होंगे जब तक कि वे तथ्य या दुर्व्यपदेशन न करते हों।

छ.3.2 रासायनिक विश्लेषण किए जाने पर, काजू की गिरियां भूनकर तथा नमक लगाकर तैयार करने के पश्चात् निम्नलिखित सारणी में वर्णित स्वीकृत स्तरों के अंतर्गत होंगी।

(1) मुक्त वसीय अम्ल—0.4% (ओलिक अम्ल के रूप में) निष्कर्षित वसा-भार।

(2) पैराक्साइड मूल्य—निष्कर्षित वसा का 2 एम ई क्यू/0.02 कि. ग्राम भुनी हुई और नमक लगी हुई काजू की गिरियों में मुक्त वसा अम्ल और पैराक्साइड मूल्य के प्राक्कलन की पद्धति परिशिष्ट में दी गयी निर्धारण पद्धति के अनुसार होगी।

छ.3.3 परिरक्षी और सुरुचि कर्मक उसी प्रकार अनुज्ञात होंगे जिस प्रकार वे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन अनुज्ञेय है।

छ.4 पैक करना :—

छ.4.1 भूनी हुई और नमक लगी हुई काजू की गिरियां क्रेता द्वारा यथाविनिर्दिष्ट आकार और अन्य अपेक्षाओं के उपभोक्ता आधानों में पैक की जाएंगी।

छ.4.2 गिरियां संविदा की अपेक्षानुसार पन्नी में भी पैक की जा सकेंगी।

छ.4.3 आधान, नए, साफ और जंग रहित या अन्य किसी भी प्रकार की क्षति से रहित होंगे।

छ.4.4 गिरियां वैक्यूम वाले आधानों में या अक्रिय गैस के माध्यम से पैक की जाएंगी।

छ.4.5 क्रेता की पैकिंग अपेक्षाओं के अनुसार आधान गत्ते (कार्ड बोर्ड) के डिब्बों में या विस्फमित लकड़ी की पेटियों में पैक किए जाएंगे।

छ.4.6 प्रत्येक डिब्बे या पेटियों पर निम्नलिखित दर्शाने के लिए चिन्ह लगाए जाएंगे :—

(क) उत्पाद का नाम,

(ख) विनिर्माता का नाम,

(ग) पीत परिवहन चिन्ह,

(घ) किलोग्राम में शुद्ध और कुल भार।

छ.5 मुहर बंद करना :—

छ.5.1 पैक किए जाने के पश्चात् प्रत्येक परेषण को परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में उचित रूप से मुहर बंद किया जाएगा।

[फाइल सं. 6/9/83—ई आई एण्ड ई पी]

S.O. 782.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Cashew Kernels to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 6th July, 1985 under the Order of the Government of India

in the Ministry of Commerce, S.O. 3091 dated the 6th July, 1985;

And whereas the objections and suggestions were invited till the 13th September, 1985, from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the Public on the 19th July, 1985;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council being of opinion, that, in pursuance of the said sub-rule and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce Nos. S.O. 1022 dated the 26th March, 1966 and S.O. 275 dated the 28th January, 1978, it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Cashew Kernels shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) recognises the specifications as set out in the Schedule to this order as the standard specifications for Cashew Kernels.

(3) prohibits the export, in the course of international trade of such Cashew Kernels unless the same are accompanied by a certificate issued by any of the Agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that such Cashew Kernels conform to the standard specification and are export-worthy.

2. Nothing in this Order shall apply to the export of bona fide samples of Cashew Kernels by land, sea or air to prospective buyers provided that no such samples is in excess of f.o.b. value of Rs. 250.

3. Definitions—In this order "Cashew Kernels" mean—all types of Cashew Kernels unscorched, scorched, wholes, pieces, roasted and salted kernels.

4. This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

SPECIFICATIONS FOR CASHEW KERNELS

1. General Characteristics : Cashew Kernels shall have been obtained through roasting shelling and peeling cashew nuts (Anacardium occidentale linnaeus)

2. Special Characteristics :

Grade Designation	Trade Name	Colour/characteristics	Count/454 gms size description	Max. Moisture %	Broken Max %	NLSG NLG Max. %	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
A. CASHEW KERNELS—WHITE WHOLES							
W-180	White Wholes	White pale ivory/light ash characteristic shape	170—180	5	5	5 (NLSG and SW together)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity adhering testa objectionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scraping/shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernel.
W-210	White wholes	White pale ivory/light ash characteristic shape	200—210	5	5	5 (NLSG and SW together)	
W-240	White Wholes	White pale ivory/light ash characteristic shape	220—240	5	5	5 (NLSG and SW together)	
W-280	White Wholes	White pale ivory/light ash characteristic shape	260—280	5	5	5 (NLSG and SW together)	
W-320	White Wholes	White pale/ivory/light ash characteristic shape	300—320	5	5	5 (NLSG and SW together)	
W-400	White Wholes	White pale/ivory/light ash characteristic shape	350—400	5	5	5 (NLSG and SW together)	
W-450	White Wholes	White pale ivory/light ash characteristic shape	400—450	5	5	5 (NLSG and SW together)	
W-500	White Wholes	White pale ivory/light ash characteristic shape	450—500	5	5	5 (NLSG and SW together)	
B. SCORCHED CASHEW KERNELS—WHOLES							
SW	Scorched Wholes	Kernels may be scorched/slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/borma	N.A.	5	5	7.5 (NLG & SSW together)	Kernels shall be a completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scraping/
SW-180	Scorched Wholes	Kernels may be a scorched/slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/borma	170—180	5	5	7.5 (NLG & SSW together)	

1	2	3	4	5	6	7	8
SW-210	Scorched Wholes	Kernels may be scorched/slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/borma	200—210	5	5	7.5 (NLG & SSW together)	shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernel.
SW-240	Scorched Wholes	Kernels may be scorched/slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/borma	220—240	5	5	7.5 (NLG & SSW together)	
SW-280	Scorched Wholes	Kernels may be scorched/slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/borma	260—280	5	5	7.5 (NLG & SSW together)	
SW-320	Scorched wholes	Kernels may be scorched/slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/borma	300—320	5	5	7.5 (NLG & SSW together)	
SW-400	Scorched wholes	Kernels may be scorched/slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/borma	350—400	5	5	7.5 (NLG & SSW together)	
SW—450	Scorched wholes	Kernels may be scorched/slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/borma	400—450	5	5	7.5 (NLG & SSW together)	
SW-500	Scorched wholes	Kernels may be scorched/slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/borma.	450—500	5	5	7.5 (NLG & SSW together)	
C. DESSERT CASHEW KERNELS—WHOLES							
SSW	Scorched wholes second	Kernels may be over scorched, immature, shrivelled (Pririval) speckled (Karaniram) discoloured and light blue.	N.A.	5	5	7.5	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity adhering testa and objectionable extraneous matter.
DW	Dessert Wholes	Kernels may be deep scorched, deep brown, deep blue speckled, discoloured and black spotted.	N.A.	5	5		Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter.
D. CASHEW KERNELS (WHITE PIECES)							
B	Butts	White/pale ivory or light ash. Kernels broken crosswise (evenly or unevenly) naturally attached.	N.A.	5	5	5 (SB)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scraping/ shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernels.

1	2	3	4	5	6	7	8
S	Splits	White/pale ivory or light ash, kernels, split, naturally lengthwise.	N.A.	5	5	5(S)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and obejctionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scraping/ shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernels.
LWP	Large White pieces	White/pale ivory or light ash.	Kernels broken than two pieces and not passing through 4 mesh/16 SWG sieve/4.75 mm. I.S. Sieve	5	Nil	5 (SP and SWP together)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scraping/ shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernels.
SWP	Small white pieces	White/pale ivory or light ash.	Broken kernels smaller than those described on LWP but not passing through 6 mesh 20 SWG Sieve/ 2.80 mm I.S. Sieve	5	Nil	5 (SP and SWP together)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scraping/ shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernels.
BB	Baby Bits	White/pale ivory or light ash.	Plumules and broken kernels smaller than those described as SWP but not passing through a 10 mesh 24 SWG Sieve/ 1.70 mm I. S. Sieve.	5	Nil	1% (Cashew Powder)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter.
E. CASHEW KERNELS—SCORCHED PIECES							
SB	Scorched Butts	Kernels broken crosswise (evenly or unevenly) and naturally attached. Kernels may be scorched/slightly darkened due to overheating while roasting or drying in the drier/ borma.	N.A.	5	5	7.5 (DB)	Kernels shall be c mpletely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scraping/shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernel.

1	2	3	4	5	6	7	8
SS	Scorched splits	Kernels split naturally lengthwise, kernels may be scorched slightly darkened due to over heating while roasting or drying in drier/borma	N.A.	5	5	7.5 (DS)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scrapping/shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernel.
SP	Scorched Pieces	Kernels may be scorched/slightly darkened due to over heating while roasting or drying in drier/borma.	Pieces not passing through a 4 mesh. 16 SWG sieve 4.75 mm I.S. Sieve	5	Nil	7.5 (SPS & SSP together)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scrapping/shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernel.
SSP	Scorched Small Pieces	Kernels may be scorched/slightly darkened due to over heating while roasting or drying in drier/borma.	Pieces smaller than SSP but not passing through a 6 mesh/20 SWG sieve 2.80 mm I.S. Sieve.	5	Nil	5 (DSP)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scrapping/shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernel.
F. CASHEW KERNELS (DESSERT PIECES)							
SPS	Scorched Pieces seconds	Kernels may be over scorched immature, shrivelled (Pirival) speckled (Karaniram) discoloured and light blue.	Kernels broken into pieces but not passing through a 4 mesh/16 SWG Sieve 4.75 mm I. S. Sieve	5	Nil	7.5 (DP&DSP together)	Kernels shall be completely free from infestation on insect damage, mould, rancidity adhering testa and objectionable extraneous matter.
DP	Dessert Pieces	Kernels may be deep scrorched, deep brown, deep blue, speckled discoloured and black spotted.	Kernels broken into pieces but not passing through a 4 mesh/16 SWG Sieve 4.75 mm I. S. Sieve	5	Nil	7.5 (DSP)	Kernels shall be completely free from infestation insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter.
DSP	Dessert small pieces	Kernels may be deep scorched, deep brown, deep blue, speckled discoloured and black spotted.	Kernels broken into pieces but not passing through 6 mesh/20 SWG 2.80 I. S. Sieve	5	Nil	2 (Smaller pieces)	Kernels shall be completely free from infestation insect damage, mould, rancidity adhering testa and objectionable extraneous matter.
DB	Dessert Butts	Kernels broken crosswise (evenly and unevenly) naturally attached, kernels may be deep scorched, speckled, deep brown discoloured and deep blue & black spotted.	N.A.	5	5	7.5 (DP & DSP together)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity adhering testa and objectionable extraneous matter.

1	2	3	4	5	6	7	8
DS	Dessert Splits	Kernels split naturally lengthwise kernels may be deep scorched, deep brown, deep blue, speckled discoloured & black spotted.	N.A.	5	5	5 (DP & DSP together)	Kernels shall be completely free from infestation insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter.

NLG denotes : Next lower Grade.
NLGS denotes : Next Lower Size Grade.

G. Specifications for Roasted and Salted Cashew Kernels.

G.1 Raw Materials.

G. 1.1 Cashew Kernels, which shall include scorched, unscorched whole or pieces shall be used for roasting and salting.

G. 1.2 They shall be completely free from insect infestation of any kind, fungal growth, rancidity and the presence of testa.

G. 2 Preparation :

G.2.1 Roasted and Salted Cashew Kernels shall be prepared by roasting the Cashew Kernels in any of the recognised cooking media and salting, or through the dry roasting and salting process.

G. 2.2 The cooking utensils used shall be of stainless steel.

G. 3 Product Requirements

G. 3.1 The grade designations as stipulated in the contract between the buyer and the seller shall be allowed unless they make any misrepresentation of the facts.

G. 3.2 The kernels, after the preparation through roasting and salting, on chemical analysis shall be within the acceptance levels shown below :—

1. Free fatty acid—0.4 per cent (As oleic) on the weight of extracted fat.

2. Peroxide value—2mep|0.02 kg. of extracted fat. The method of estimation of free fatty acid and peroxide value in roasted and salted Cashew Kernels shall be as per the method of determination given in the Appendix.

G. 3.3 Preservatives and flavouring agents shall be permitted as admissible under the prevention of Food Adulteration Act, 1954.

G. 4 Packing

G. 4.1 The roasted and salted Cashew Kernels shall be packed in consumer containers|bulk tin containers of the size and other requirements as may be specified by the buyer.

G. 4.2 The Kernels may also be foil packed if required in the contract.

G. 4.3 The containers shall be new, clean and free from rusting or any kind of damage.

G. 4.4 The kernels shall be packed in the containers under vacuum or in the medium of inert gas.

G. 4.5 The containers shall be packed in cardboard cartons or disinfested wooden cases according to the packing requirements of the buyer.

G. 4.6 Each carton or case shall be marked to show :
(a) name of the product
(b) name of the manufacturer
(c) shipping mark
(d) net and gross weight in kgs.

G. 5 Sealing

G. 5.1 Each consignment after packing shall be suitably sealed as may be specified by the Council.

[F. No. 6(9)|83-EI&EP]

का.आ. 783.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1023 तारीख 26 मार्च, 1966 और का.आ. 376 तारीख 28 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काजू की गिरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1986 है ;

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित कोई भी अभिकरण अभिप्रेत है ;

(घ) "काजू की गिरियां" से सभी प्रकार की काजू की गिरियां भूनसी हुई, बिना भूनसी हुई, साबुत, टुकड़े, भूनी हुई और नमक लगी हुई गिरियां अभिप्रेत हैं।

3 क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण :—निर्यात के लिए आशयित काजू की गिरियों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जाएगा कि काजू की गिरियां अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, या तो,

(क) उपाबंध I में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार परिकल्पित उत्पादन के निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर,

या

(ख) यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्पाद का प्रसंस्करण उपाबंध-II में विनिर्दिष्ट नियंत्रण के स्तरों का पालन करते हुए प्रसंस्करण के विभिन्न प्रक्रमों पर नियंत्रणों का प्रयोग करके किया गया है, किया जाएगा।

4 अपील :—(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो उपबंध—II के पैरा 2.7 के उपपैरा (4) तथा (5) के अधीन अपने एकक के अनुमोदन देने या उपबंध—II के पैरा 5 के उप-पैरा (4) या उपबंध—II के पैरा 2 के उप-पैरा 5 के अधीन निर्यात योग्यता का प्रमाण-पत्र जारी करने के अभि-करण के इंकार से व्यथित हो तो वह ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन किन्तु सात से अनधिक सदस्यों से गठित संबंधित विशेषज्ञों के पैनल के सभापति को अपील कर सकेगा

(ख) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य व्यापार मंडल के सदस्य होंगे।

(ग) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी ।

(घ) अपील प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी ।

अनुसूची

काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश

1. सामान्य विशेषताएं :—काजू की गिरियां, काजुओं को भूनकर छिलका उतारकर और छीलकर (ऐनाकार्डियम आक्सिडेंटेल लिनेअस) से प्राप्त की जाएंगी ।

2. विशिष्ट विशेषताएं :—

क. काजू की गिरियां-सफेद साबुत :—

श्रेणी अभिधान	व्यापारिक नाम	रंग/विशेषताएं	काउंट/454 ग्राम माप विवरण	अधिक-तम आर्द्रता —	टूटे हुए टुकड़े	एनएलएसजी/ एनएलजी अधिकतम %	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8
डब्ल्यू-180	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	120-180	5	5	5(एनएलएसजी तथा एस डब्ल्यू के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्ति-जनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी । यदि छिलन या मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है ।
डब्ल्यू-210	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	200-210	5	5	5(एनएलएसजी तथा एस डब्ल्यू के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्ति-जनक बाह्य पदार्थ से पूर्णतया रहित होंगी । यदि छिलन या मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं ।
डब्ल्यू-240	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	220-240	5	5	5(एन एलएस जी तथा एसडब्ल्यू के साथ)	
डब्ल्यू-280	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	260-280	5	5	5(एनएलएस जी तथा एसडब्ल्यू के साथ)	
डब्ल्यू 320	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	300-320	5	5	5(एनएलएस जी तथा एसडब्ल्यू के साथ)	

1	2	3	4	5	6	7.	8
डब्ल्यू-400	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	350-400	5	5	5 (एनएलएस जी तथा एसडब्ल्यू के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्ति-जनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी । यदि छिलन या मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं ।
डब्ल्यू-450	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	400-450	5	5	5 (एनएलएस जी तथा एसडब्ल्यू के साथ)	
डब्ल्यू-500	सफेद साबुत	दंत सफेद पीला/हल्का सलेटी विशेष आकार	450-500	5	5	5 (एनएलएस जी तथा एस डब्ल्यू के साथ)	
ख. झुलसी हुई काजू की गिरियां-साबुत :—							
एस डब्ल्यू	झुलसी हुई साबुत	शुष्कक बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां झुलसी हुई/हल्की या गहरी हो सकती है ।	—	5	5	7.5 (एन एलजी तथा एसएस डब्ल्यू के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्ति-जनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी । यदि छिलन मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है ।
एसडब्ल्यू-180	झुलसी हुई साबुत	शुष्कक बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां झुलसी हुई या गहरी हो सकती है ।	170-180	5	5	7.5 (एन एलजी तथा एस एस डब्ल्यू के साथ)	
एस डब्ल्यू-210	झुलसी हुई साबुत	शुष्कक बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां झुलसी हुई/हल्की या गहरी हो सकती है ।	200-210	5	5	7.5 (एन एल जी तथा एसएस डब्ल्यू के साथ)	
एस डब्ल्यू-240	झुलसी हुई साबुत	शुष्कक बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां झुलसी हुई/हल्की या या गहरी हो सकती है ।	220-240	5	5	7.5 (एन एल एस जी और एस एस डब्ल्यू के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृतगंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी यदि छिलन मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है ।
एस डब्ल्यू-280	झुलसी हुई साबुत	शुष्कक बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी होने के कारण गिरियां झुलसी हुई/हल्की या गहरी हो सकती है ।	260-280	5	5	7.5 (एन एल एस जी और एस एस डब्ल्यू के साथ)	
एस डब्ल्यू-320	झुलसी हुई साबुत	शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां झुलसी हुई/हल्की या गहरी हो सकती है ।	300-320	5	5	7.5 (एन एल एस जी और एस एस डब्ल्यू के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्ति-जनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी यदि छिलन मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
एस डब्ल्यू-400	झुलसी हुई साबुत	शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां झुलसी हुई/हल्की या गहरी हो सकती है ।	350-400	5	5	7.5 (एन एल एन जी तथा एस एस डब्ल्यू के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्ति जनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होगी यदि छिलन मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियों भी अनुमत है।
एस डब्ल्यू-450	झुलसी हुई साबुत	शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां झुलसी हुई/हल्की या गहरी हो सकती है ।	400-450	5	5	7.5 (एन एलएसजी तथा एस एस डब्ल्यू के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होगी यदि छिलन मुरझाएपन से गिरि के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है।
एस डब्ल्यू-500	झुलसी हुई साबुत	शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के कारण गिरियां झुलसी हुई/हल्की या गहरी हो सकती है ।	450-500	5	5	7.5 (एन. एस एस जी तथा एस एस डब्ल्यू के साथ)	गिरिया ग्रसन, कीट क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता जुड़े हुए बीजावरण, आपत्ति-जनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होगी यदि छिलन मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है।
ग. डेजर्ट काजू की गिरियां—साबुत : —							
एस एस डब्ल्यू	भुनी हुई साबुत	गिरियां ज्यादा भुनी हुई कच्ची मुरझाई हुई (पीरोवल) चित्ती-दार (करनोरम) रंगहीन तथा हल्की नीली हो सकती है ।	लागू नहीं	5	5	7.5	गिरियां ग्रसन कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होगी ।
डी डब्ल्यू	डेजर्ट साबुत	गिरियां अधिक भुनी हुई गहरी, भूरी, गाठी नीली, चित्तीदार रंगहीन तथा काले धब्बों वाली हो सकती है ।	लागू नहीं	5	5	शून्य	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होगी ।
घ. काजू की गिरियां (सफेद टुकड़े) :—							
बी	बट्स	सफेद/पीला दंत सफेद हल्का सलेटी आड़ी तिरछी टूटी हुई (समान रूप या असमान) तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई गिरियां ।	लागू नहीं	5	5	5 (एसबी)	गिरियां, ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी । यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है।
एस	टुकड़े	सफेद/पीला दंती सफेद या हल्का सलेटी/प्राकृतिक रूप में लम्बाई में टूटी हुई गिरियां	लागू नहीं	5	5	5 (एसएस)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी । यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है।

1	2	3	4	5	6	7	8
एसडब्ल्यूपी	सफेद बड़े टुकड़े	सफेद/पीला दंती सफेद या हल्का सलेटी	गिरियां दो से अधिक टुकड़ों में टूटी हुई और 4 छिद्रों वाली/16 एस डब्ल्यू जी छलनी 4.75 मि. मी. आईएस छलनी से नहीं निकल सकेगी	5	शून्य	5 (एसएसपी तथा एसडब्ल्यूपी के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छीलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं।
एस डब्ल्यूपी	छोटे सफेद टुकड़े	सफेद/पीला दंती सफेद या हल्का सलेटी	एलडब्ल्यूपी में वर्णित से छोटी टूटी हुई गिरियां किंतु जो 6 छिद्रों 20 एसडब्ल्यू जी छलनी/2.80 मि. मी. आईएस छलनी से न निकल सकें।	5	शून्य	5 (एसएसपी तथा बीबी के साथ)	गिरियां, ग्रसन कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं।
बीबी	बेबी बिट्स	सफेद/पीला दंती सफेद/हल्का सलेटी	एसडब्ल्यूपी में वर्णित से छोटी टूटी हुई गिरियाँ और फलमूलक जो 10 छिद्रों वाली 24 एसडब्ल्यूजी छलनी/1.70 मि.मी. आई एस छलनी से न निकल सकें।	5	शून्य	1% (काजू का पाउडर)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति फफूंदी, विकृत गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी।
ख. काजू की गिरियां—भुने हुए टुकड़े :—							
एसबी	भुने हुए बट्स	आड़ी तिरछी टूटी हुई गिरियां (समान रूप तथा असमान रूप में) तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई। गिरियां/शुष्कक/बोरमा में भूनने या सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भुनी हुई/हल्की भूरी हो सकती है।	लागू नहीं	5	5	7.5 (डीबी)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है।
एसएस	भुने हुए टुकड़े	प्राकृतिक रूप से लम्बाई में टूटी हुई गिरियां/शुष्कक/बोरमा में भूनने/सुखाने के समय अधिक गर्मी दौरान गिरियां भुनी हुई/हल्की गहरी हो सकती है।	लागू नहीं	5	5	5 (डीएस)	गिरियां, ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत, गंधिता जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और भागतः मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत है।

1	2	3	4	5	6	7	8
एसपी	भुने हुए टुकड़े	शुष्कक/बोरमा में भूनने/सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भूनी हुई हल्की/गहरी हो सकती हैं।	टुकड़े जो 4 छिद्रों वाली 16 एस डब्ल्यू जी छलनी/4.75 मि.मी. आईएस छलनी से न निकल सकें।	5	शून्य	5 एसपी) एस तथा एसएसपी के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत हैं।
एसएसपी	भुने हुए छोटे टुकड़े	शुष्कक/बोरमा में भूनने/सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भूनी हुई हल्की/गहरी हो सकती हैं।	भुने टुकड़ों से छोटे टुकड़े जो 6 छिद्रों वाली/20 एस डब्ल्यू जी छलनी 2.80 मि.मी. छलनी से न निकल सकें।	5	शून्य	5 (डीएसपी)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी। यदि छिलन/मुरझाएपन से गिरी के विशेष आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छिली हुई और मुरझाई हुई गिरियां भी अनुमत होंगी।
	ब. काजू की गिरियां (खराब टुकड़े)						
एसपीएस	भुने हुए घटिया टुकड़े	शुष्कक/बोरमा में भूनने/सुखाने के समय अधिक गर्मी के दौरान गिरियां भूनी हुई/हल्की गहरी हो सकती हैं।	टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां जो 4 छिद्रों वाली/16 एस डब्ल्यू जी छलनी/4.75 मि.मी. आई एस छलनी से न निकल सके।	5	शून्य	7.5 (डीपी तथा डीएसपी के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी।
डीपी	डेजर्ट टुकड़े	गिरियां गहरी भूनी हुई गाढ़े भूरे, गाढ़े नीले, चित्तीदार, रंगहीन और काले धब्बों से युक्त हो सकती हैं।	टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां जो 4 छिद्रों वाली/16 एस डब्ल्यू जी छलनी/4.75 मि.मी. आई एस छलनी से न निकल सकें।	5	शून्य	7.5 (डीपी तथा डीएसपी के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी।
डीएसपी	डेजर्ट छोटे टुकड़े	गिरियां गहरी भूनी हुई गाढ़े भूरे, गाढ़े नीले, चित्तीदार, रंगहीन और काले धब्बे से युक्त हो सकती हैं।	टुकड़ों में टूटा हुई गिरियां जो 6 छिद्रों वाली/20 एस डब्ल्यू जी छलनी 2.80 मि.मी. आईएस छलनी से न निकल सकें।	5	शून्य	2 (छोटे टुकड़े)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी।
डी बी	डेजर्ट बट्स	आड़ी तिरछी टूटी हुई गिरियां (समान रूप तथा असमान रूप में) तथा प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई, चित्तीदार, गाढ़े भूरे, रंगहीन तथा गाढ़े नीले तथा काले धब्बों से युक्त हो सकती हैं।	लागू नहीं		5	5 7.5 (डीपी तथा डीएसपी के साथ)	गिरियां ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
डी एस	डेजर्ट टुकड़े	प्राकृतिक रूप से लम्बाई में टूटी हुई गिरियां गहरी भुनी हुई, गाढ़े भूरे, मैले चित्तीदार, रंगहीन तथा काले धब्बों से युक्त हो सकती हैं।	लागू नहीं	5	5	5 (कीटों तथा डीएसपी के साथ)	गिरियां, ग्रसन, कीट, क्षति, फफूंदी, विकृत, गंधिता, जुड़े हुए बीजावरण, आपत्तिजनक, बाह्य पदार्थों से पूर्णतया रहित होंगी।

एन एल जी—अगली निम्न श्रेणी का द्योतक है।

एन एल एस जी—अगली निम्न श्रेणी के आकार का द्योतक है।

भुनी हुई तथा नमक लगी हुई काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश:

छ.1 कच्ची सामग्री :—

छ.1.1 काजू की गिरियां, जिसमें बिना भुनी हुई, भुनी हुई, साबुत गिरियां या टुकड़े सम्मिलित हैं, भूनने तथा नमक लगाने के लिए प्रयोग की जाएगी।

छ.1.2 वे किसी भी प्रकार के कीट ग्रसन, फफूंदी वृद्धि, विकृत गंधिता तथा बीजावरण की उपस्थिति से पूर्णतया रहित होंगी।

छ.2 तैयार करना :—

छ.2.1 भुनी हुई तथा नमक लगी हुई काजू की गिरियां किसी भी मान्यता प्राप्त पकाने वाले बर्तन में उनको भूनकर तथा नमक लगाकर या सुखाकर भूनकर या नमक लगाकर तैयार की जाएगी।

छ.2.2 पकाने के लिए प्रयुक्त बर्तन स्टेनलैस स्टील के होंगे।

छ.3 उत्पाद अपेक्षाएं :—

छ.3.1 क्रेता तथा विक्रेता के बीच की गयी संविदा में यथा अनुबंधित श्रेणी अभिधान तब तक अनुज्ञात होंगे जब तक कि वे तथ्यों का दुर्व्यपदेशन न करते हों।

छ.3.2 रासायनिक विश्लेषण किए जाने पर, काजू की गिरियां भूनकर तथा नमक लगाकर तैयार करने के पश्चात् नीचे दिखाए गए स्वीकृत सीमाओं के अंतर्गत होंगी :—

(1) मुक्त-वसीय अम्ल 0.4% (ओलिक अम्ल के रूप में) (निष्कर्षित वसा/भार पर)

(2) पैराक्साइड मूल्य-निष्कर्षित वसा का 2 एमईपी/0.02 किलोग्राम भुनी हुई और नमक लगी हुई काजू की गिरियों में मुक्त वसा अम्ल और पैराक्साइड मूल्य के प्राक्कलन की पद्धति परिशिष्ट में दी गयी निर्धारण पद्धति के अनुसार होगी।

छ.3.3 परिरक्षी और सुरुचिकर्मक उसी प्रकार अनुज्ञात होंगे जिस प्रकार के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन अनुरूप हैं।

छ.4 पैक करना :—

छ.4.1 भुनी हुई और नमक लगी हुई काजू की गिरियां क्रेता द्वारा यथा विनिर्दिष्ट और अन्य अपेक्षाओं के अनुसार तथा उपभोक्ता आधानों में एक ही आकार के डिब्बों में पैक की जाएंगी।

छ.4.2 गिरियां संविदा की अपेक्षानुसार पन्नी में भी पैक की जा सकेंगी।

छ.4.3 आधान नए साफ और जंग रहित या अन्य किसी भी प्रकार की क्षति से रहित होंगे।

छ.4.4 गिरियां वैक्यूम वाले आधानों में या अक्रिय गैस के माध्यम से पैक की जाएंगी।

छ.4.5 क्रेता की पैकिंग अपेक्षाओं के अनुसार आधान गत्ते (कार्ड बोर्ड) के डिब्बों में या विसंक्रामित लकड़ी की पेटियों में पैक किए जाएंगे।

छ.4.6 प्रत्येक डिब्बे या पेटियों पर निम्नलिखित दर्शाने के लिए चिन्ह लगाए जाएंगे।

(क) उत्पाद का नाम,

(ख) विनिर्माता का नाम,

(ग) पोत परिवहन चिन्ह,

(घ) किलोग्राम में शुद्ध और कुल भार,

छ.5 मुहर बंद करना :—

छ.5.1 पैक किए जाने के पश्चात् प्रत्येक परेषण को परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में उचित रूप से मुहर बंद किया जाएगा।

परिशिष्ट

1. भुनी हुई और नमक लगी हुई काजू की गिरियों में पैराक्साइड मूल के प्राक्कलन की पद्धति :

मिश्रण में 50 ग्राम काजू की गिरियां और पाउडर लें।

250 मि. लीटर के डाटदार शक्वाकार फलास्क में चूरा सामग्री लें और उसमें 150 मि. लीटर क्लोरोफार्म मिलाएं। फलास्क को रात भर हलित (शेकर) में रखें। अगले दिन दूषण के अंतर्गत मसाले को चूषर फ्लास्क में छान लें। अवशेषों को फिर 100 मि.लीटर क्लोरोफार्म में मिला दें और दो घंटे के लिए शेकर में रखें और फिर छान लें संयुक्त क्लोरोफार्म अर्क 250 मि. लीटर तक मिलाएं।

निष्कर्षण का 10 मि. लीटर या लगभग 0.5 ग्राम वसा वाला यथोचित एलिकोट भाग पूर्व सूखे और तोले गए छोटे दो बीकरों (25 मि. ली. क्षमता वाले) में निकाला जाए। डिम को जल बर्तन के ऊपर रखने से क्लोरोफार्म वाष्पित किया जाता है। फिर डेगचियों को 70° सें.ग्रे. वाले वैक्यूम ओवन में स्थानांतरित कर दिया जाए। वैक्यूम के अंतर्गत वाष्पीकरण एक घंटे के लिए किया जाएगा। डेगचियां बाहर निकाल ली जाएंगी और शोषित्र में ठंडी की जाएगी और उन्हें तोला जाएगा। डेगचियों को फिर ओवन में 30 मिनट के लिए रखा जाएगा और फिर उठा लिया जाएगा, ठंडा किया जाएगा और तोला जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि दो परिणाम बाधक तोलों का अंतर 5 मि.ग्राम से अधिक नहीं होगी।

4 ग्राम वसा वाले क्लोरोफार्म निष्कर्षण का एलिकोट 500 मि. ली. वाले डाटदार शक्वाकार फ्लास्क में डाला जाएगा और ग्लेसियल एसिड की अपेक्षित मात्रा मिलाई जाएगी। इसमें से संतृप्त पोटाशियम आयोडाईड घोल 0.5 मि.ली. निकाला जाएगा और घोल को कभी-कभी ठीक एक मिनट के लिए हिलाकर स्थिर रहने दिया जाएगा और फिर उसमें 50 मि.ली. आसुत जल मिला लिया जाएगा। 10.1 एन सोडियम थायोसल्फेट धीरे-धीरे मिलाते हुए और निरंतर तथा

बलपूर्वक हिलाते हुए इसका अनुमापन करें । अनुमापन लगातार तब तक करते रहें जब तक कि उसका पीला रंग बिल्कुल लुप्त न हो जाए, एक प्रतिशत स्टार्च सूचक का 0.5 मि.ली. मिलाएं और अनुमापन लगातार करते रहें जब तक कि नीला रंग लुप्त न हो जाए ।

टिप्पण :

(1) प्रतिदिन अधिक्रमक का पूर्ण निर्धारण करें । पूर्ण अनुमापन 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट के 0.1 मि.ली. से अधिक नहीं होगी ।

(2) अनुमापन आरम्भ करने से पूर्व यदि घोल का रंग हल्का पीला है तो उस अवस्था में स्टार्च सूचक मिलाया जा सकता है ।

(3) यदि अनुमापन 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट घोल के 0.5 मि.ली. से कम है तो 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट घोल का प्रयोग करते हुए निर्धारण को दोहराएं ।

पैराक्साइड मूल्य निम्नानुसार परिकलित किया जा सकता है । पैराक्साइड मूल्य प्रति 1000 ग्राम वसा के अनुसार पैराक्साइड के मि.ली. मूल्यों के रूप में होगा ।

$$\frac{(ए-बी) \times एन \times 1000}{डब्ल्यू}$$

जहां ए = नमूने का अनुमापन

बी = शून्य

एन = थायोसल्फेट की सांद्रणता

डब्ल्यू = परीक्षण के लिए ली गयी वसा का भार

2. मुक्त वसा अम्ल के प्राक्कलन की प्रक्रिया :

लगभग 5 ग्राम वाले क्लोरोफार्म के एक ऐलिकोट को तोलने वाले शंक्वाकार फ्लास्क में डाला जाएगा । जल तापन पर क्लोरोफार्म वाष्पित किया जाएगा । क्लोरोफार्म में अवशेष वैक्यूम ओवन में वैक्यूम के अधीन हटा दिए जाएंगे । फ्लास्क को क्लोरोफार्म रहित वसा के साथ तोला जाएगा ।

फिनोर्फथालिन का सूचक के रूप में प्रयोग करते हुए अल्कोहल (आसुत) हल्के सोडियम हाईड्रोक्साइड घोल सहित निष्प्रभावित होगा । 50 मि.ली. गर्म वसा में निष्प्रभावित अल्कोहल मिलाई जाएगी और फ्लास्क को अच्छी तरह हिलाया जाएगा । 0.1 एन सोडियम हाईड्रोक्साइड सहित अनुपालन तब तक करें जब तक कि गुलाबी रंग जो 30 सेकेंड के लिए स्थिर है प्रकट न हो ।

टिप्पण : यदि अनुमापन 0.1 एन सोडियम हाईड्रोक्साइड घोल 0.5 मि.ली. से कम हो तो 0.02 एन सोडियम हाईड्रोक्साइड घोल प्रयुक्त करते हुए निर्धारण दोहराएं ।

मुक्त वसीय अम्ल की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

नमूने के रूप में मुक्त वसीय अम्ल प्रतिशत $= \frac{ए \times एन \times 28.2}{डब्ल्यू}$

जहां ए = सोडियम हाईड्रोक्साइड घोल का मि.लीटर

एन = सोडियम हाईड्रोक्साइड घोल की सामान्यता: तथा

डब्ल्यू = परीक्षण के लिए ली गयी वसा का भार ।

उपाबंध-I

परेषणानुसार निरीक्षण की प्रक्रिया

[नियम 3(क) देखें]

1. निरीक्षण का आधार :

(1) काजू की गिरियों का निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से किया जाएगा कि वह केन्द्रीय सरकार, द्वारा निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है और समुचित श्रेणी अभिधान लेबल लगाया गया है ।

(2) काजू की गिरियों का निर्यात करने का इच्छुक व्यक्ति स्वास्थ्यकर परिसरों में काजू की गिरियों को भूनकर, छिलका उतारकर, सुखाकर/और श्रेणीकरण करके उनका परेषण इस ढंग से बनाएगा कि परेषण मान्यता प्राप्त श्रेणी विनिर्देशों में से किसी एक के अनुरूप हो ।

(3) उपरोक्त उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में काजू की गिरियां तैयार करने के पश्चात् निर्यातकर्ता भा. मा. 916 (नवीनतम प्रति) के अनुरूप उन्हें नए साफ सूखे और रिसन सह टिन आधानों में पैक करेगा । प्रत्येक टिन भली प्रकार से बंद किए जाएंगे । और ऐसी रीति से सील किए जाएंगे जो अधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) टिन इसके पश्चात् श्रेणी अभिधान लेबलों से चिन्हित किया जाएगा और नालीदार तन्तु बोर्ड डिब्बों में पैक किया जाएगा । सीलबंद टिन में पैक करने के लिए प्रयुक्त नालीदार तंतु बोर्ड दोहरी तह के नालीदार तंतु बोर्ड का होगा जो 25 कि. ग्राम अंतर्वस्तु के लिए भा.मा. -2771 भाग-1 (नवीनतम प्रति) के अनुसार उचित होगा ।

(5) श्रेणी अभिधान लेबलों का प्रयोग करने का इच्छुक निर्यातकर्ता ऐसे लेबलों की उपेक्षाओं की स्वीकृति अभिकरण के निकटतम कार्यालय से प्राप्त करेगा ।

(6) एक डिब्बे में केवल एक ही श्रेणी की काजू की गिरियों को पैक किया जाएगा ।

2. निरीक्षण की प्रक्रिया :

(1) काजू की गिरियों का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता निर्यात के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए अभिकरण को या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को आवेदन देगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन निर्यात के लिए लदान के आरम्भ की तारीख से कम से कम सात दिन पहले (भूनी हुई तथा नमक लगी हुई काजू की गिरियों की दशा में 15 दिन पहले) दिया जाएगा ।

(3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, अभिकरण निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अपना यह समाधान करने की दृष्टि से काजू की गिरियों के परेषण का निरीक्षण करेगा कि परेषण का उपरोक्त नियम 1.1 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार श्रेणीबद्ध, लेबल तथा पैक किया गया है । निर्यातकर्ता अभिकरण को ऐसा निरीक्षण करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देगा ।

(4) यदि निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात की जाने वाली काजू की गिरियों का परेषण नियम (1) में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो वह सूचना प्राप्त होने के सात दिन के (भूनी हुई तथा नमक लगी हुई काजू की गिरियों की दशा में 15 दिनों के भीतर) यह घोषित करने वाला प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण निर्यात योग्य है ।

(5) जब अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन (भूनी हुई तथा काजू नमक लगी हुई काजू की की गिरियों की दशा में 15 दिनों की) उक्त अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित लिखित रूप में निर्यातकर्ता को देगा ।

(6) प्रमाणन के पश्चात् भी अभिकरण को परेषण की क्वालिटी भंडारण के किसी स्थान पर, अभिवहन के दौरान या उसके वस्तुतः लदान से पूर्व पत्तनों पर पुनः निर्धारित करने का अधिकार होगा ।

(7) यदि इनमें से किसी भी प्रक्रम पर यह पाया जाता है कि परेषण मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है तो मूल रूप में जारी किया गया निरीक्षण प्रमाण-पत्र वापिस ले लिया जाएगा ।

3. निरीक्षण का स्थान :

इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण नियंत्रिकर्ता के उस परिसर पर किया जाएगा जहां माल निरीक्षण के लिए प्रस्थापित किया जाता है, परन्तु यह जब तक कि परिसर में निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

उपाबंध (II)

[नियम 3 (ख) देखें]

उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण के लिए प्रसंस्करण यूनिटों द्वारा अपनाए जाने वाले नियंत्रण स्तर ।

क्वालिटी नियंत्रण .

अभिकरण द्वारा अनुमोदित केवल प्रसंस्करण यूनिटें ही निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने के पात्र होंगे तथा ऐसा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक यूनिट के पास न्यूनतम विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिएं :

1. संभरक यूनिटें :

सामान्य : अभिकरण द्वारा अनुमोदित केवल संभरण यूनिटें ही निर्यात के लिए कच्ची काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करेंगी । यूनिट में विद्यमान कीट विज्ञान संबंधी पहलुओं के प्रति विशेषकर निर्देश से स्वच्छता और स्वास्थ्यकर दशाओं का न्याय निर्णयन करने और निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने के लिए उपलब्ध न्यूनतम सुविधाओं की पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए संभरक यूनिटें/शाखा कारखाने अभिकरण द्वारा मूल्यांकन किए जाने के अधीन होंगे। संभरक यूनिट के पास नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होंगी :

1.1 परिवेश और निर्माण : (1) यूनिटों का परिवेश प्रसंस्करणकर्ता के वस्तुगत नियंत्रण के अधीन है ऐसा होगा, जिससे स्वच्छता संबंधी कोई समस्या नहीं होगी ।

(2) भवन ठोस, संतोषजनक रूप से रखे जाएंगे ।

(3) कार्य करने वाले कक्षों को संदूषण के किसी भी जोखिम से बचाने के लिए अच्छी दशा में रखा जाएगा ।

1.2 प्रसंस्करण क्षेत्र : (1) कच्ची गिरी के गोदाम और प्रसंस्करण कक्ष इस प्रकार के होंगे जिसमें प्रभावशाली प्रति-पीडक तथा पीडकहरण संक्रियाएं सुविधाएं दी जा सकें ।

(2) प्रसंस्करण कक्षों में, कृन्तकों, पक्षियों तथा सजातियों का प्रवेश रोकने के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी ।

(3) सभी कार्य क्षेत्रों में अच्छी रोशनी होगी ।

(4) खाद्य उत्पादों के भंडारकरण के लिए प्रयोग किए गए क्षेत्र या कक्ष तथा डिब्बे उनमें पृथक और सुभिन्न होंगे, जो अखाद्य सामग्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं ।

(5) सभी बर्तन, ट्रे, मेज की सतह, जो सामग्री के संपर्क में आती है प्रयोग से पूर्व उसके पश्चात् और प्रयोग के अंतरालों के दौरान जब भी आवश्यक हो साफ की जाएगी ।

1.3 प्रसाधन सुविधा : (1) यूनिट में विधि के अधीन यथा अपेक्षित पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी । प्रसाधनों में साबुन तथा पर्याप्त पानी के प्रदाय का प्रबंध किया जाएगा ।

1.4 कार्मिकों का स्वास्थ्य तथा स्वच्छता : (1) संयंत्र का प्रबंध संहस यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में यह जानकारी हो कि वह संचारी रोग से पीड़ित है, यूनिट के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति न दी जाए ।

(2) प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति कार्य करने समय अपनी आवश्यक सफाई रखेंगे ।

(3) कार्यकर्ता प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात प्रसंस्करण कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व अपने हाथ धोएंगे ।

(4) प्रसंस्करण कक्ष में किसी भी रूप में तंबाकू का चबाना, थूकना तथा प्रयोग प्रतिषिद्ध होगा ।

1.5 परिवहन सुविधाएं : (1) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्व प्रसंस्कृत तथा परिरक्षित उत्पादों को पैक किए जाने वाले केन्द्रों में पालिथिन के स्तर वाले/जंगरहित धातु के डिब्बों में परिवहन किया जाएगा ।

1.6 निरीक्षण प्रक्रिया : (1) संभरक यूनिटों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नियंत्रिकर्ता परिषद् द्वारा विहित प्रोफार्मा में, संभरक यूनिटों के बारे अभिकरण को लिखित रूप में देगा ।

(2) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण के अधिकारी यूनिट में प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध स्वच्छता तथा स्वास्थ्यकर दशाओं और सुविधाओं का न्यायनिर्णयन करने के लिए संभरण यूनिटों में जाएंगे ।

(3) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में इन नियमों में यथा-विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं और स्वास्थ्यकर तथा स्वच्छता दशाएं संतोषजनक हैं और कोई संदूषण समस्या दिखाई नहीं देती है जो अभिकरण यूनिट का अनुमोदन कर देगा तथा निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने के लिए उसे अनुज्ञात कर देगा ।

(4) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यूनतम स्वच्छता संबंधी और स्वास्थ्यकर दशाएं नहीं है तो प्रसंस्करणकर्ता को उस यूनिट में निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(5) वह यूनिट जिसका अनुमोदन नहीं किया गया है या जिसका अनुमोदन वापिस ले लिया गया है, दोषों का सुधार करने के पश्चात् फिर से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नए सिरे से आवेदन दे सकता है ।

(6) यदि किसी भी समय, किसी भी कारण से उत्पाद को विनिर्देशों के अनुरूप बनाने में कठिनाई आती है या यदि अभिकरण द्वारा ऐसा निदेश दिया जाता है तो अभिकरण को सूचना देकर निर्यात के लिए उत्पाद को निलंबित कर दिया जाएगा ।

(7) निर्यात के लिए प्रसंस्करण केवल तभी पुनः आरम्भ किया जाएगा जब अभिकरण उसका लिखित अनुमोदन कर दें ।

(8) भूनना, सुखाना, छिलका उतारना, श्रेणीकरण, भंडारकरण इत्यादि जैसी प्रसंस्करण प्रक्रिया यूनिट के अनुभवी कार्मिक के पर्यवेक्षणाधीन स्वास्थ्यकर दशाओं में की जाएगी ।

(9) प्रसंस्करण संक्रियाओं, जैसे भूनना, जब भी आवश्यक समझा जाए, अभिकरण के अधिकारियों की जांच के अधीन होंगे ।

1.7 प्रसंस्करण : (1) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवश्यक प्रतिपीडक तथा पीडकहरण उपाय कालिकतः तथा जब कभी अभिकरण के अधिकारियों द्वारा सुझाव दिया जाए, किए जाते है ।

2.0 पैक करने के केन्द्र :—

सामान्य : अभिकरण द्वारा अनुमोदित पैक किए जाने वाले केन्द्र ही निर्यात के लिए काजू की गिरियों को पैक करने के पात्र होंगे ।

2.1 ऐसे अनुमोदित पैक किए जाने के केन्द्र केवल अनुमोदित संभरक यूनिटों से ही निर्यात के लिए पैक की जाने वाली गिरियों से प्राप्त करेंगे । अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पैक करने वाले केन्द्र के पास नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिएं ।

2.2 परिवेश, संनिर्माण तथा अभिन्यास:—

(1) भवन, स्थायी/अर्द्धस्थायी बनावट का होगा तथा अच्छी दशा में रखा जाएगा।

(2) उस परिसर के जो प्रसंस्करणकर्ता के वस्तुगत नियंत्रण के अधीन है, आसपास किसी भी प्रकार का दलदल, कूड़े का ढेर, या पशुगृह नहीं होगा जो किसी भी प्रकार की सफाई की समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है।

(3) काम करने वाले परिसरों को संदूषण के किसी भी जोखिम से बचाने के लिए अच्छी दशा में रखा जाएगा।

2.3 प्रसंस्करण क्षेत्र: (1) प्रसंस्करण कक्षों में कीटाणुओं, कृन्तकों, पक्षियों तथा गजातियों के प्रवेश का निरावण करने के लिए उपाय किए जाएंगे।

(2) सभी कार्य क्षेत्रों में अच्छी रोशनी होगी।

(3) खाद्य उत्पादों के भंडारकरण के लिए प्रयोग किए गए क्षेत्र या कक्ष उनसे पृथक और सुभिन्न होंगे जो अखाद्य सामग्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

(4) प्रसंस्करण क्रियाओं के दौरान काम करने के क्षेत्र में से अपशिष्ट सामग्री शीघ्र हटाई जाएगी।

(5) सभी बर्तन, ट्रे तथा मेज की सतह जो काजू की गिरियों के संपर्क में आती है प्रयोग के पूर्व, उसके पश्चात् और प्रयोग के अंतरालों के दौरान जब भी आवश्यकता हो साफ की जाएगी।

(6) क्षेत्रों को भरने के लिए प्रयुक्त सभी छोटे पात्र जैसे ट्रे, बाल्टी और बर्तन लकड़ी के अतिरिक्त संभारण सामग्री से बने होंगे तथा उनकी सतह दरारों से मुक्त होगी।

(7) प्रसंस्करण संक्रियाओं के दौरान काम करने के क्षेत्रों से अपशिष्ट सामग्री शीघ्र हटाई जाएगी।

(8) पैकिंग/भराई अनुभाग के प्रवेश पर हाथ धोने की सुविधा जैसे हाथ धोने के पात्र, तथा साबुन की सुविधा होगी।

2.4 मशीनरी: (1) पैकिंग केन्द्र के पास 26" ऊंचाई के वैक्यूम को निकालने के प्रयोजन एक विटा पैक उपकरण काम करने की अच्छी दशा में होगा। वैक्यूमीकरण के दौरान डिब्बों में से निकाली गयी वैक्यूम उपदर्शित करने के लिए मेज के साथ विटापैक लगाया जाएगा।

(2) पैकिंग केन्द्र से भराई अनुभाग में वातीय बाहरी पदार्थ पृथक्करण (पी एस एम एस) का प्रबंध किया जाएगा जो गिरियों के साथ विद्यमान बाह्य पदार्थ को पृथक करेगा। काजू की गिरियों को भरने का संपूर्ण कार्य केवल पी एस एम एस द्वारा किया जाएगा।

(3) स्वास्थ्य दशाओं के अधीन रखे गए पैकिंग केन्द्रों में गिरियों को अनुकूल रखने के लिए आवश्यक शीतलन सुविधाएं होंगी।

2.5 प्रसाधन सुविधाएं: (1) सफाई संबंधी पर्याप्त प्रसाधन सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा। प्रसाधनों में साबुन तथा पर्याप्त पानी का प्रबंध किया जाएगा।

2.6 कर्मचारियों का स्वास्थ्य और स्वच्छता. (i) संयंत्र प्रबंध मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में यह जानकारी हो कि वह संचारी रोग से पीड़ित है, यूनिट के किसी भी क्षेत्र में काम करने की अनुमति न दी जाए।

(2) प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति कार्य करते समय अपनी अत्यधिक सफाई रखेंगे।

(3) कार्यकर्ता प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात् प्रसंस्करण कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व अपने हाथ धोएंगे।

(4) प्रसंस्करण कक्ष में किसी भी रूप में तंबाकू को चबाना, थूकना तथा उसका प्रयोग करना प्रतिषिद्ध होगा।

(5) प्रसंस्करण कक्ष में खाना रखने वाले डिब्बे नहीं रखे जाएंगे।

(6) प्रबंध मंडल भराई तथा पैकिंग अनुभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्वच्छ एप्रेन तथा हैड गियर देगा।

2.7 पैक करने वाले केन्द्रों का अनुमोदन: (1) निर्यात करने के लिए काजू की गिरियों को पैक करने का इच्छुक प्रसंस्करणकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में अभिकरण द्वारा विहित प्रोफार्मा में देगा।

(2) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण के अधिकारी पैकिंग यूनिट में यह देखने के लिए जाएंगे कि यूनिट में प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(3) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यूनतम विहित सुविधाएं हैं तो यूनिट को काजू की गिरियों को निर्यात के लिए पैक करने के लिए अनुमोदित कर दिया जाएगा।

(4) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यूनतम विहित सुविधाएं नहीं हैं तो यूनिट को काजू की गिरियों को निर्यात के लिए पैक करने के लिए अनुमोदित नहीं किया जाएगा।

(5) किसी यूनिट को दिया गया अनुमोदन कम से कम दो मास की अवधि की सूचना के पश्चात् निम्नलिखित कारणों से वापिस ले लिया जाएगा:—

(i) यदि उपस्कर तथा मशीनरी अच्छी काम करने की दशा में न हों;

(ii) यदि यूनिट के स्वास्थ्यकर तथा सफाई संबंधी दशाएं संतोषजनक न हों;

(iii) यदि संभरण यूनिट की स्वच्छता तथा स्वास्थ्यकर दशा संतोषजनक नहीं है तथा अभिकरण के अधिकारियों ने कीट विज्ञान सर्वेक्षण में कीट ग्रसन के लक्षणों को देखा है;

(iv) यदि प्रसंस्करणकर्ता ने परिषद द्वारा जारी किए गए नियमों के उपबंधों का अतिक्रमण किया है या जानबूझकर अतिक्रमण करने का प्रयत्न किया हो।

(6) प्रसंस्करणकर्ता को अनुमोदन के ऐसे वापिस लेने के बारे में लिखित रूप में सूचना दी जाएगी।

(7) जब विटा पैक मशीन काम करने की विहित दशा में न हो तो यूनिट में विटा पैक कार्य नहीं किया जाएगा।

(8) वह यूनिट जिसका अनुमोदन वापिस ले लिया गया है दोषों को सुधारने के पश्चात् फिर से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नए सिरे से आवेदन-पत्र देगी।

(9) यदि किसी भी यूनिट को किसी भी समय कारण से अपेक्षाओं को अनुरूपता बनाए रखने में कोई कठिनाई हो या अभिकरण द्वारा निर्देश दिया गया हो तो अभिकरण को सूचित करते हुए निर्यात के लिए उत्पादन निलंबित कर दिया जाएगा।

(10) निर्यात के लिए प्रसंस्करण को केवल तभी पुनः आरम्भ किया जाएगा जब वह लिखित रूप में अभिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा।

2.8 काजू की गिरियों की पैकिंग तथा भराई: (1) निर्यात के लिए काजू की गिरियों को पैक करने का इच्छुक निर्यातकर्ता उत्पादन के दौरान स्थानिटी नियंत्रण के भागों के स्तरों का प्रयोग करते हुए इन नियमों में निर्दिष्ट काजू की गिरियों की प्रक्रियाओं के पश्चात् उन्हें भारतीय मानक 916 (नवीनतम प्रति) के अनुरूप नए साफ सूखे और रिसन सह आधारों में पैक करेगा। प्रत्येक टिन भली प्रकार से बंद किए जाएंगे और ऐसी रीति में सीलबंद किए जाएंगे जो अभिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए

(2) टिन इसके पश्चात श्रेणी अभिधान, लेबलों से चिन्हित किया जाएगा तथा नालीदार तंतु बोर्ड के डिब्बों में पैक किया जाएगा। संलग्न डिब्बों की पैकिंग के लिए प्रयुक्त नालीदार फाइबर बोर्ड दोहरी नालीदार फाइबर बोर्ड का होगा जो भा.मा. 2771, भाग 1 (नवीनतम प्रति) के अनुसार 25 किलोग्राम तक के भार के लिए उपयुक्त होगा।

(3) श्रेणी अभिधान लेबलों को प्रयोग करने का इच्छुक निर्यातकर्ता ऐसे लेबलों की अपेक्षाओं की स्वीकृति अभिकरण के निकटतम कार्यालय से प्राप्त करेगा।

(4) एक डिब्बे में केवल एक ही श्रेणी की काजू की गिरियों को पैक किया जाएगा।

3. संयुक्त यूनिट : (1) एक संयुक्त काजू की कारखाने में जिसमें निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने तथा पैक करने दोनों की सुविधाएं हैं, अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संभरक यूनिट तथा पैकिंग केन्द्र की निर्धारित सुविधाएं होनी चाहिएं। ऐसी यूनिटों के लिए एक संयुक्त अनुमोदन पर्याप्त होगा।

4. अभिलेखों का रखा जाना : (1) काजू की गिरियों के प्रसंस्करण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण कर्ता संबंधित परिसरों पर आवश्यक अभिलेख/रजिस्टर रखेगा और यह अभिकरण के अधिकारियों को निरीक्षण के लिए जब भी अपेक्षित हो, उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. निरीक्षण की प्रक्रिया : (1) काजू की गिरियों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता इस निमित्त विहित प्रोफार्मा में अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा और ऐसी सूचना के साथ इस आशय का घोषणा-पत्र भी देगा कि काजू की गिरियों के परेषण का अभिकरण द्वारा इस संबंध में तथा विहित उत्पादन के दौरान क्वालटी नियंत्रण उपायों के स्तरों को अपनाते हुए प्रसंस्करण किया गया है।

(2) ऐसी सूचना लदाई के लिए प्रमाण पत्र की प्राप्ति की अपेक्षित तारीख से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व, काजू की गिरियों के उस मामले में जब प्रायोगिक परीक्षण न हो तथा पांच वर्ष पूर्व जब प्रयोगशाला परीक्षण हों, दी जाएगी। भुनी हुई नमक लगी काजू की गिरियों के मामले में ऐसी सूचना अवधि दस कार्य दिवस होगी।

(3) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, यदि अभिकरण का समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाला परेषण विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है तो वह निर्यातकर्ता यह घोषणा करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा कि परेषण निर्यात योग्य है।

(4) जब अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है तो वह ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार किए जाने की सूचना उसके कारणों सहित लिखित रूप में निर्यातकर्ता को देगा।

(5) निरीक्षण के प्रयोजन के लिए अभिकरण के अधिकारी को संयुक्त अभिलेखों और उन परिसरों तक पहुंच होगी जहां काजू की गिरियों का प्रसंस्करण, पैकिंग तथा भंडारकरण किया जाता है।

(6) प्रमाणन के पश्चात भी अभिकरण को परेषण की क्वालिटी भंडारकरण के किसी स्थान पर, अभिवहन के दौरान या पत्तनों पर उसके वस्तुतः लदान से पूर्व पुनः निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(7) यदि इनमें से किसी भी प्रक्रम पर यह पाया जाता है कि परेषण मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है तो मूल रूप से जारी किया गया निरीक्षण प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जाएगा।

[फाइल सं. 6(9)/83-ई आई एंड ई पी]
एन.एस. हरिहरन, निदेशक

पाद टिप्पण :

का.आ. 1022 और 1023 तारीख 26-2-1966
का.आ. 275 तारीख 28-1-1978

S.O. 783.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce Nos. S.O. 1023, dated the 26th March, 1966 and S.O. 276 dated the 28th January, 1978 excepts as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(c) "Agency" means any one of the agencies established under section 7 of the Act at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras;

(d) "Cashew Kernels" means all type of Cashew Kernels scorched, unscorched, wholes, pieces, roasted and salted kernels.

3. Quality Control and Inspection.—The inspection of Cashew Kernels intended for export shall be carried out with a view to ensure that Cashew Kernels conform to the standard specifications recognised under section 6 of the Act and specified in the schedule appended to these rules, either,

(a) on the basis of inspection and testing of finished products as per specifications recognised for this purpose by adopting the procedure specified in Annexure-I.

OR

(b) by ensuring that the product has been processed by exercising the controls at different stages of processing by following the levels of controls as specified in Annexure-II.

4. Appeal.—(a) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to accord approval for his unit under sub-paras (4) and (5) of para 2.7 of Annexure-II or to issue a certificate of exportworthiness under sub-para (4) of para 5 of Annexure-II or sub-para (5) of para 2 of Annexure-I may within fifteen days of recipt of the communication of such refusal by it, prefer an appeal to the convener of the concerned panel of experts consisting of not less than three, but not more than seven members, appointed for the purpose by the Central Government;

(b) atleast two-thirds of the total membership of the Panel of Experts shall consist of trade members;

(c) the quorum of the Panel shall be three;

(d) the appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

SCHEDULE

SPECIFICATION FOR CASHEW KERNELS

1. General Characteristics : Cashew Kernels shall have been obtained through roasting shelling and peeling cashew nuts (Anacardium of accidental Cinneous)

2. Special characteristics

CASHEW KERNELS—WHITE WHOLES :

Grade-designation	Trade Name	Colour/characteristics	Count/454 gms size description	Max. Moisture	Broken Max%	NLSG NLG Max. %	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
W-180	White Wholes	White pale ivory/light ash characteristic	170—180	5	5	5 (NLSG & SW together)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa objectionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scrapping/shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernels.
W-210	White Wholes	White pale ivory/light ash characteristic shape	200—210	5	5	5(NLSG AND SW together)	
W-240	White wholes	White pale ivory/light ash characteristics shape	220 —240	5	5	5(NLSG & SW together)	
W-280	White wholes	White pale ivory/light ash characterties shape	260-280	5	5	5(SLSG & SW together)	
W-320	White wholes	White pale ivory/light ash characteristic shape	300—320	5	5	5(NLSG & SW together)	
W-400	White wholes	White pale/ivory/light ash characteristic shape	350—400	5	5	5(NLSG & SW together)	
W-450	White Wholes	White pale ivory/light ash characteristics shape	400—450	5	5	5(NLSG & SW together)	
W-500	White Wholes	White pale ivory/light ash characteristic shape	450—500	5	5	5(NLSG & SW together)	
B. SCORCHED CASHEW KERNELS — WHOLES							
SW	Scorched wholes	Kernels may be scorched/ slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/ borma.	N.A.	5	5	7.5(NOSG & SSW together)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering tests and objectioncable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scrapping/ shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernel.
SW-180	Scorch d wholes	Kernels may be scorched/ slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/ borma.	170—180	5	5	7.5(NLSG & SSW together)	
SW-210	Scorched wholes	Kernels may be scorched/ slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/ borma.	200—210	5	5	7.5 (NLSG & SSW together)	
SW-240	Scorched wholes	Kernels may be scorched/ slightly darkned due to over-heating while roasging of drying in drie!/ borma.	220—240	5	5	7.5 (NLSG & SSW together)	
SW-280	Scorched wholes	Kernels may be scorched/ slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/ borma.	260—280	5	5	7.5 (NLSG & SSW together)	
SW-320	Scorched wholes	Kernels may be scorched/ slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/borma.	300—320	5	5	7.5 (NLSG & SSW together)	

1	2	3	4	5	6	7	8
SW 400	Scorched wholes	Kernels may be scorched/ slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/borma.	350—400	5	5	7.5 (NLSG & SSW together)	
SW-450	Scorched wholes	Kernels may be scorched/ slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/ borma.	400—450	5	5	7.5 (NLSG & SSW together)	
SW-500	Scorched wholes	Kernels may be scorched/ slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/ borma.	450—500	5	5	7.5 (NLSG & SSW together)	
C. DESSERT CASHEW KERNELS—WHOLES							
SSW	Scorched wholes Seconds	Kernels may be over scorched, immature, shrivelled (Pirival) speckled (Karaniram) discoloured and light blue.	N.A.	5	5	7.5	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter.
DW	Dessert whole	Kernels may be deep scorched, deep brown, deep blue, speckled, discoloured and black spotted.	N.A.	5	5	N.A.	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter.
D. CASHEW KERNELS (WHITE PIECES)							
B.	Butts	White/pale ivory or light ash. kernels broken crosswise (evenly or unevently) naturally attached).	N.A.	5	5	5(SS)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scrapping/ shirvelling does not affect the characteristic shape of the kernels.
S	Splits	White/pale ivory or light ash, kernels split naturally lengthwise.	N.A.	5	5	5(SS)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scrapping/ shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernels.
LWP	Large White Pieces	White/pale ivory or light ash	Kernels broken than two pieces and not passing through 4 mesh/16 SWG sieve/ 4.75 mm. I.S. Sieve	5	Nil	5(SP & SWP together)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scrapping/ shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernels.

1	2	3	4	5	6	7	8
SWP	Small White Pieces	White/pale ivory or light ash	Broken Kernels smaller than those described on LWP but not passing through 6 mesh 20 SWG Sieve/ 2.80 mm I. S. Sieve.		5	5(SPS & BB together)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scrapping/ shrivelling does not effect the characteristic shape of the kernels.
BB	Baby bits	White/pale ivory or light ash	Plumules and broken kernels smaller than those described as SWP but not passing through a 10 mesh 24 SWG Sieve/1.70 mm. I.S. Sieve.	5	Nil	1% (Cashew powder)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity adhering testa and objectionable extraneous matter.
E. CASHEW KERNELS — SCORCHED PIECES							
SB	Scorched Butts	Kernels broken crosswise (evenly or unevenly) and naturally attached. Kernels may be scorched/slightly darkened due to over heating while roasting or drying in the drier/borma.	N.A.	5	5	7.5 (DB)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scrapping/ shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernel.
SS	Scorched splits	Kernels split naturally long thwise, kernels may be scorched/slightly darkened due to overheating while roasting or drying in drier/ borma	N.A.	5	5	7.5 (DS)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter. Scraped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scrapping/shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernel.
SP	Scorched pieces	Kernels may be scorched slightly darkened due to overheating while roasting or drying in drier/borma.	Pieces not passing through a 4 mesh 16 SWG sieve 4.75 mm. I.S. Sieve.	5	Nil	7.5 (SPS & SSP together)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scrapping/ shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernel.

1	2	3	4	5	6	7	8
SSP	Scorched small pieces	Kernels may be scorched/ slightly darkened due to over-heating while roasting or drying in drier/borma.	Pieces smaller than SSP but not passing through a 6 mesh/20 SWG Sieve 2.80 mm. I.S. Sieve.	5	Nil	5 (DSP)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity, adhering testa and objectionable extraneous matter. Scrapped and partially shrivelled kernels also permitted provided such scrapping/ shrivelling does not affect the characteristic shape of the kernel.
F. CASHEW KERNELS (DESERT PIECES)							
SPS	Scorched pieces seconds	Kernels may be over-scorched immature, shrivelled (Pirival) speckled (Karaniram) discoloured and light blue.	Kernels broken into pieces but not passing through a 4 mesh/16 SWG sieve 4.75 mm. I.S. Sieve.	5	Nil	7.5 (DP & DSP together)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity adhering testa and objectionable extraneous matter.
DP	Dessert pieces	Kernels may be deep scorched, deepbrown deep blue, speckled, discoloured and black spotted.	Kernels broken into pieces but not passing through a 4 mesh/16 SWG sieve 4.75 mm. I.S. Sieve.	5	Nil	7.5 (DP & DSP together)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity adhering testa and objectionable extraneous matter.
DSP	Dessert small pieces	Kernels may be deep scorched, deep brown deep blue, speckled, discoloured and black spotted.	Kernels broken into pieces but not passing through a 6 mesh/20 SWG 2.80 mm. I.S. Sieve	5	Nil	2 (smaller pieces)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity adhering testa and objectionable extraneous matter.
DB	Dessert Butts	Kernels broken crosswise (evenly and unevenly) naturally attached kernels may be deep scorched, speckled deep brown, discoloured and deep blue and black spotted.	N.A.	5	5	7.5 (DP & DSP together)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity adhering testa and objectionable extraneous matter.
DS	Dessert splits	Kernels split naturally lengthwise kernels may be deep scorched, deep brown, deep blue, speckled, discoloured and black spotted.	N.A.	5	5	5(DP & DSP together)	Kernels shall be completely free from infestation, insect damage, mould, rancidity adhering testa and objectionable extraneous matter.

NLG denotes : Next Lower Grades
NLSG denotes : Next Lower Size Grade.

G. Specifications for Roaster and Salted Cashew Kernels.

G. 1 Raw Materials.

G. 1.1 Cashew Kernels, which shall include scorched unscorched whole or pieces shall be used for roasting and salting.

G. 1.2 They shall be completely free from insect infestation of any kind, fungal growth, rancidity and the presence of testa.

G. 2 Preparation :

G. 2.1 Roasted and Salted Cashew Kernels shall be prepared by roasting and Cashew Kernels in any of the recognised cooking media and salting, or through the dry roasting and salting process.

G. 2.2 The cooking utensils used shall be of stainless steel.

G. 3 Product Requirements

G. 3.1 The grade designations as stipulated in the contract between the buyer and the seller shall be allowed unless they make any misrepresentation of the facts,

G. 3.2 The Kernels, after the preparation through roasting and salting, on chemical analysis shall be within the acceptance levels shown below :—

1. Free fatty acid—0.4 per cent (As oleic) on the weight of extracted fat.

2. Peroxide Value—2 m.e.p./0.02 kg of extracted fat. The method of estimation of free fatty acid and peroxide value in roasted and salted Cashew Kernels shall be as per the method of determination given in the Appendix.

G. 3.3 Preservatives and flavouring agents shall be permitted as admissible under the prevention of Food Adulteration Act, 1954.

G. 4 Packing

G. 4.1 The roasted and salted Cashew Kernels shall be packed in consumer containers, bulk tin containers of the size and other requirements as may be specified by the buyer.

G. 4.2 The Kernels may also be foil packed if required in the contract.

G. 4.3 The containers shall be new, clean and free from rusting or any kind of damage.

G. 4.4 The Kernels shall be packed in the containers under vacuum or in the medium of inert gas.

G. 4.5 The containers shall be packed in cardboard cartons or disinfected wooden cases according to the packing requirements of the buyer.

G. 4.6 Each carton or case shall be marked to show :—

(a) name of the product

(b) name of the manufacturer

(c) shipping mark

(d) net and gross weight in kgs.

G. 5 Sealing

G. 5.1 Each consignment after packing shall be suitably sealed as may be specified by the Council.

APPENDIX

1. Procedure for estimation of peroxide value in Roasted and Salted Cashew Kernels.

Weigh 50 gms. of Cashew Kernels and Powder in Grinder.

Take the powdered material in 250 ml. stopered conical flask and add 150 ml. of chloroform, keep the flask in shakar over night. Next day the slurry is filtered in a Buchaner flask under suction. The residue is then mixed with 100 ml. of chloroform and kept in a shaker for two hours and filtered. The volume of the combined chloroform extracts is than made upto 250 ml.

10 ml. each of the extract or suitable aliquot portion containing about 0.5 gm. fat is pipetted out into two previously dried and weight smaller beakers (25 ml. capacity), chloroform is evaporated off by keeping the dishes on water bath. Then the dishes are transferred to a vacuum oven maintained at 70°C. Evaporation under vacuum is carried out for one hour. Dishes are taken out, cooled in a desicator and weighed. The dishes are again kept in the oven for 30 minutes, then taken out, cooled and weighed. This process is repeated until the difference between the two consecutive weighings is not more than 5 mg.

Aliquot of the chloroform extract containing about 4 gm. of fat is taken in a 600 ml. stoppered conical flask and required quantity of glacial acetic acid 0.5 ml of saturated potassium iodide solution is pipetted out into this and the solution is allowed to stand with occasional shaking for exactly one minute and then 50 ml. distilled water is added. Titrate this with 0.1N Sodium thiosulphate adding it gradually and with constant and vigorous shaking. Titration is continued until the yellow colour has almost disappeared, 0.5 ml. of 1 per cent starch indicator is added and the titration continued until the blue colour just disappears.

NOTE :

(1) Conduct Blank determination of the reagent daily. Blank titration should not exceed 0.1 ml. of 0.1N Sodium thiosulphate.

(2) If the colour of the solution is light yellow before the start of titration, starch indicator may be added at that stage.

(3) If the titration is less than 0.5 ml. of 0.1N Sodium thiosulphate solution repeat the determination using 0.01N Sodium thiosulphate solution.

The peroxide value may be calculated as under :—

Peroxide value as milli equivalent of peroxide per 1000 g. fat $= \frac{(A-B) \times N \times 1000}{W}$

Where : A = Titration of samples

B = Blank

N = Normality of thiosulphate

W = Weight of fat taken for test

2. Procedure for estimation of Free Fatty Acid.—An aliquot of the chloroform containing about 5 g. of fat is taken in a weighed conical flask. Chloroform is evaporated off on a water bath. Traces of chloroform is removed under vacuum in the vacuum oven. Flask is weighed with chloroform free fat.

Absolute alcohol (Distilled) is neutralised with dilute Sodium hydroxide solution using phenolpthalein as indicator. To the fat 50 ml. of hot neutralised alcohol is added and the flask is shaken well. Titrate with 0.1 N Sodium hydroxide till a pink colour which is stable for 30 seconds appeared.

NOTE

If the titration is less than 0.5 ml. of 0.1 N Sodium hydroxide solution, repeat the determination using 0.02N Sodium hydroxide solution.

The free fatty acid may be calculated as under :

Free fatty acid as oleic, percentage $= \frac{A \times N \times 28.2}{W}$

Where : A = ml. of the sodium hydroxide solution solution

N = Normality of the sodium hydroxide solution; and

W = Weight in gms. of fat taken for test.

ANNEXURE—I

[See Rule 3(a)]

PROCEDURE FOR CONSIGNMENTWISE INSPECTION

1. Basis of inspection. (1) Inspection of Cashew Kernels shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Export (Quality Control and Insnection) Act, 1963 (22 of 1963) and that the proper grade designation label has been affixed.

(2) Any person desiring to export Cashew Kernels shall prepare a consignment of Cashew Kernels by roasting, peeling, drying and grading in hygienic premises so as to make the consignment conform to any one of the recognised grade specifications.

(3) After preparing the cashew kernels in the manner specified in sub-rule (2) above, the exporter shall pack the same in new, clean, dry and leak-proof tin container conforming to IS:916 (latest version). Each tin shall be securely closed and sealed in such manner as may be specified by the Agency from time to time.

(4) The tin shall thereafter be marked with grade designation lable and packed in corrugated fibre board cartons. The corrugated fibre board used for packing sealed tins shall be of double wall corrugated fibre board suitable for a mass content of 25 kgs. as per S:2771 Part-I (latest version).

(5) Exporters intending to use grade designation labels shall contain their requirements of such labels from nearest office of the Agency.

(6) Cashew Kernels of only one grade shall be packed in a carton.

2. Procedure for inspection: (1) Any exporter intending to export Cashew Kernels shall submit an application to the Agency or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be made out not less than seven days (15 days in the case of roasted and salted Cashew Kernels) before the date of commencement of loading for export.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2) the Agency shall inspect the consignment of Cashew Kernels as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfying itself that the consignment has been graded, labelled and packed in accordance with the rules referred to in rule 1.1 above. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Cashew Kernels to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 1, it shall, within seven days (15 days in the case of roasted and salted cashew kernels) of the receipt of intimation, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days (15 days in the case of roasted and salted Cashew Kernels) refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing along with the reasons therefor.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place of storage, in transit, or at the ports before its actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

3. Place of Inspection:—Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection, provided adequate facilities exist therein for inspection.

ANNEXURE-II

[See rule 3 (b)]

CONTROL LEVELS FOR INPROCESS QUALITY CONTROL TO BE ADOPTED BY THE PROCESSING UNITS

Quality Control.

Only processing units, approved by the Agency shall be eligible for processing Cashew Kernels for export and submit to qualify for such approval, shall have the following minimum facilities :—

1. Feeder Units :—General—Only feeder units approved by the Agency shall process raw cashewnuts for export. In order to adjudge the sanitary and hygienic conditions with special reference to entomological aspects prevailing in the unit and assess the adequacy of the minimum facilities available to process Cashew Kernels for export, the feeder units/branch factories shall be subjected to an evaluation by the Agency. A feeder unit shall have the minimum facilities as specified below :—

1.1 Surroundings and construction.—(1) The surroundings of units, which are under the physical control of the processor, shall be such as not to pose any sanitary problems.

(2) The building shed shall be maintained satisfactorily.

(3) The working rooms shall be maintained in good repair to prevent any risk of infestation.

1.2 Processing Areas.—(1) The rawnut godowns and the processing rooms shall be such as to permit effective anti-infestation, and dis-infestation operation.

(2) Arrangements shall be available to prevent entry of rodents birds and the like into the processing room.

(3) All the working areas shall be well lighted.

(4) Areas of compartments and the containers used for the storage of edible products shall be separated and distinct from those used for inedible materials.

(5) All the utensils, trays and table surface which come into contact with material shall be cleaned before, after and during intervals of use as often as necessary.

1.3 Toilet Facility.—(1) Adequate toilet facilities as required under the law shall be provided in the unit. Soap and plentiful supply of water shall be provided at the toilet.

1.4 Personnel health and Hygiene.—(1) Plant management shall take care to ensure that no person while known to be affected with a communicable disease is permitted to work in any area of the unit.

(2) All persons working in the processing areas shall maintain a high degree of personal cleanliness while on duty.

(3) The workers shall wash their hands before entering the processing room after each absence.

(4) Chewing, spilling and use of tobacco in any form shall be prohibited in the processing rooms.

1.5 Transportation facilities.—(1) It shall be ensured that pre-processed and finished products are transported to the packing centres only in polythene laminated/non-rusting metallic container.

1.6 Procedure of Inspection.—(1) For the purpose of assessment of feeder units, the exporter shall inform the Agency in writing, in the proforma prescribed by the Council, the details of the feeder units.

(2) On receipt of such information, the Agency officers, shall visit the feeder units in order to adjudge the sanitary and hygienic conditions and facilities for processing available in the unit.

(3) If the unit is found to have the minimum facilities as specified in these rules and the hygienic and sanitary conditions are satisfactory and no infestation problems noticed, the Agency shall approve the unit and permit it to carry out processing of Cashew Kernels for export.

(4) If the unit is found not have the minimum sanitary and hygienic conditions, the processor shall not be allowed to process Cashew Kernels for export in that unit.

(5) A unit which is not approved or whose approval has been withdrawn may after rectifying the defects, make fresh application to the Agency for getting fresh approval.

(6) If, at any time, there is any difficulty in maintaining the conformity of the product to the specification for any reason or if so directed by the Agency, production for export shall be suspended under intimation to the Agency.

(7) The processing for export shall be resumed only after the same is approved by the Agency in writing.

(8) The processing operations such as roasting, drying, peeling, grading, storage etc. shall be carried out in hygienic conditions under the supervision of experienced personnel of the unit.

(9) The processing operations such as roasting shall be subjected to check by the Agency officers as often as found necessary.

1.7 Processing.—(1) It shall be ensured that necessary anti-infestation and dis-infestation measures are carried out periodically and, as and when suggested by the Agency officers.

2.0 Packing Centre:—General . Only packing centres approved by the Agency shall be eligible for packing Cashew Kernels for export.

2.1 Such approved packing centres shall obtain kernels for packing for export from approved feeder units only. A packing centre to qualify for approval shall have minimum facilities as specified below:

2.2 Surroundings, Construction and layout:—(1) The building shall be of permanent/semi-permanent construction and kept in good repair.

(2) The surroundings which are under the physical control of the processor shall not have any swamps, dumps or animal housing nearby which might pose any sanitary problems.

(3) The working premises shall be kept in good repair to prevent any risk of infestation.

2.3 Processing areas.—(1) Measures shall be adopted to protect against entry of insects, rodents, birds and the like into the processing rooms.

(2) All the working areas shall be well lighted.

(3) Areas or compartments used for the storage of edible products shall be separate and distinct from those used for inedible materials.

(4) Waste material shall be frequently removed from the working areas during processing operations.

(5) All the utensils, trays and table surface which come in contact with Cashew Kernels shall be cleaned before, after and during intervals of use as often as necessary.

(6) All small receptables like trays, bowls, and utensils used in filling areas shall be of non-corrodible materials other than wood, and shall also have smooth surface from crevices.

(7) Rejected materials shall be frequently removed from the working areas during processing operation.

(8) Hand washing facility such as wash basin and soap shall be provided at the entrance to the packing/filling section.

2.4 Machinary.—(1) The packing centre shall have a vitapack equipment in good working condition capable of drawing a vacuum of 26″ Hg. The vitapack shall be fitted with a guage to indicate the vacuum drawn from the tins during vacuumisation.

(2) The packing centre shall be provided with a pneumatic foreign matter segregator (PFMS) in the filling section to segregate any foreign matter that may be present with the kernels. The entire filling operations of Cashew Kernels shall be done only through PFMS.

(3) The packing centre shall have necessary cooling facilities for conditioning the kernels, maintained under hygienic conditions.

2.5 Toilet Facility.—(1) Adequate toilet facilities of sanitary type shall be provided. Soap and plentiful supply of water shall be provided at the toilets.

2.6 Personnel Health and Hygiene.—(1) Plant management shall take care to ensure that no person while known to be affected with a communicable disease is permitted to work in any area of the unit.

(2) All persons working in the processing area shall maintain a high degree of personal cleanliness while on duty.

(3) The workers shall wash their hands before entering the processing rooms after each absence.

(4) Chewing, spitting and use of tobacco in any form shall be prohibited in the processing rooms.

(5) Lunch boxes shall not be kept in the processing rooms.

(6) The management shall provide clean approns and head gears to the employee working in the filling and packing section.

2.7 Approval of packing centre.—(1) A processor intending to pack Cashew Kernels for export shall inform his intention to do so in writing, in the proforma prescribed by the Agency in this behalf.

(2) On receipt of such information, the Agency officers shall visit the packing unit in order to adjudge the facilities for processing available in the unit.

(3) If the unit is found to have the minimum prescribed facilities, the unit shall be approved to pack Cashew Kernels for export.

(4) If the unit is found not to have the minimum prescribed facilities, the unit shall not be approved to pack Cashew Kernels for export.

(5) The approval so accorded shall be withdrawn in respect of unit for the following reasons, after giving a notice of minimum period of two months.

(i) If the equipments and machinery are not in good working condition;

(ii) If the sanitary and hygienic conditions of the unit are not satisfactory;

(iii) If the sanitary and hygienic conditions of the feeder unit are not satisfactory and cases of infestation have been reported in the entomological survey by the Agency officers;

(iv) If the processor has voilated or deliberately attempted to violate the provision of the rules issued by the Council.

(6) Such withdrawal of approval shall be intimated in writing to the processor.

(7) No vitapacking work shall be undertaken in the unit, when the vitapack machine is not in the prescribed working condition.

(8) A unit, whose approval has been withdrawn, may, after rectifying the defects, take a fresh application to the Agency for obtaining fresh approval.

(9) If at any time, there is any difficulty for unit in maintaining the conformity to the requirements for any reason or if directed by the Agency, production for export shall be suspended under intimation to the Agency.

(10) The processing for export shall be resumed only after the same is approved by the Agency in writing.

2.8 Filling and packing Cashew Kernels.—(1) An exporter intending to pack Cashew Kernels for export shall after preparing the Cashew Kernels in this behalf specified in these rules exercising the levels of inprocess quality control measures shall pack the same in new, clean, dry and leakproof tin containers conforming to IS.916 (Latest version). Each tin shall be securely closed and sealed in such manner as may be specified by the Agency from time to time.

(2) The tins shall, thereafter, be marked with grade designation labels and packed in corrugated fibre board cartons. The corrugated fibre board used for packing sealed tins shall be double wall corrugated fibre board suitable for mass content of 25 kgs. as per IS:2771-Part-I (Latest Version).

(3) Exporters intending to use grade designation labels shall obtain their requirements of such labels from the nearest office of the Agency.

(4) Cashew Kernels of only one grade shall be packed in a carton.

3. Composite Unit.—(1) A composite Cashew factory having facilities for both processing and packing of Cashew Kernels for export shall have the prescribed facilities of the feeder units and the packing centre to be eligible for approval. For such units, a composite approval will be sufficient.

4. Maintenance of records.—(1) Necessary records|registers shall be maintained by the processor at the respective premises in order to ensure effective control of the processing of Cashew Kernels and these shall be made available to the Agency officers for inspection as and when required.

5. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export a consignment of Cashew Kernels shall give intimation to the Agency in writing in the proforma prescribed in this behalf and submit alongwith such intimation a declaration to the effect that the consignment of Cashew Kernels has been processed adopting the levels of in-process quality control measures as prescribed by the Agency in this regard.

(2) Such intimation shall reach the Agency office not less than three working days prior to the required date of receipt of certificate for shipments in the case of Cashew Kernels involving no laboratory tests and five working days when laboratory tests are involved. In the case of roasted| salted Cashew Kernels such notice period shall be ten working days.

(3) On receipt of such intimation, if the Agency is satisfied that the consignment to be exported complies with the specified standards, it shall issue a certificate to the exporter declaring the consignment exportworthy.

(4) When the Agency is not so satisfied, it shall refuse to issue such certificate and communicate such refusal in writing to the exporter alongwith the reasons therefor.

(5) For the purpose of inspection, the Agency officer shall have access to relevant records and 'premises where processing, packing and storage of Cashew Kernels are carried out'.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place of storage, while in transit or at the ports before its actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

[F. No. 6(9)|83-EI&EP]
N. S. HARIHARAN, Director

Foot Note :

S.O. 1022 and 1023 dated 26-2-1966.

S.O. 275 dated 28-1-1978.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1986

आदेश

का. आ. 784.—मै. इन्टरनेशनल कम्प्यूटर नेटवर्क्स (इन्डिया) प्रा. लि., एफ-43, साउथ एक्सटेन्शन, नई दिल्ली-49 को लागत बीमा भाड़ा मूल्य की संलग्न सूची के अनुसार अमरीका से आवेदक की अपनी विदेशी मुद्रा बचत के अंतर्गत पंजीगत माल का आयात करने के लिए 24,14,200/रुपए (चौबीस लाख चौदह हजार दो सौ रु. मात्र) (अमरीका डालर 247689) मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं. पी./सी जी/2086340, दिनांक 23-3-83 दिया गया था ।

2 फर्म ने अब उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति जारी करने का इस आधार पर आवेदन किया है कि यह सी डब्ल्यू सी, पालम के पास पंजीकृत करवाने के बाद तथा आंशिक रूप से 17,22,184/-रु. मूल्य का उपयोग करने के बाद, खो गई है ।

3 अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने 1985—88 की आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक के अध्याय-2, पैरा 86 में यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं, तदनुसार, संतुष्ट हूं कि पार्टी द्वारा आयात लाइसेंस सं. पी/सी जी/2086340 दिनांक 23-3-83 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है । यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की उप धारा (9 सी) सी के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै. इन्टरनेशनल कम्प्यूटर नेटवर्क्स (इन्डिया) प्रा. लि., नई दिल्ली को जारी की गई आयात लाइसेंस सं. पी./सी जी/2086340 दिनांक 23-3-83 की उक्त मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

4. फर्म को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति को अलग से जारी किया जा रहा है ।

[मि. सं. 1960/82/6/आई एन एस ए/सी जी.-4]

पाल बैक, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 24th January, 1986

ORDER

S.O. 784.—M/s. International Computer Networks (India) Pvt. Ltd., F-43, South Extension, New Delhi-49 were granted an import licence No. P|CG|2086340 dated 23-3-83 for import of C.G. as per list attached for c.i.f. value of Rs. 24,14,200 (Rupees Twenty four Lakhs fourteen thousand and two hundred only) (US $ 247689) from USA under applicant's own foreign exchange savings abroad.

2. The firm has applied for issue of Duplicate Customs purposes copy of above mentioned licence on the ground that the same has been lost after having been registered with CWC, Palam and utilized partly i.e. Rs. 17,22,184.

3. In support of the contention, the licensee has filed an affidavit as required in para 86 of Chapter II of Hand Book of Import-Export Procedures 1958—88. I am accordingly satisfied that the original customs purposes copy of Import Licence No. P|CG|2086340 dt. 23-3-83 has been lost by the party. In exercise of the power conferred under sub-clause 9(cc) of the Import Control Order, 1955 dt. 7-12-1985 as amended the said original customs purposes copy of Import licence No. P|CG|2086340 dated 23-3-83 issued to M/s. International Computer Networks (India) Pvt. Ltd., New Delhi is here by cancelled.

4. A duplicate customs purposes copy of the said licence is being issued to the firm separately.

[F. No. 1960|82|6|INSA|CG. IV]
PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports & Exports

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1986

आदेश

का. आ. 785.—श्रीमती मनोरमा भटनागर, एस-54, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 को इसुजु जैमिनी आर-कार 4 डोर सेडान 4 सिलिन्डर डीजल 1500 आर एच डी डीलक्स मॉडल कार के आयात करने के लिए केवल 66,500/- रुपए के मूल्य का एक सीमा शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3052070, दिनांक 15-7-1985 दिया गया था। आवेदक ने सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट स्थानाभ्रष्ट/गुम हो गई है। आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट को किसी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और इस तरह से सीमा शुल्क निकासी परमिट के मूल्य का बिल्कुल भी सदुपयोजन नहीं किया गया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने उपर्युक्त न्यायिक प्राधिकारी के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि सीमा शुल्क निकासी परमिट सं. पी./जे/3052070, दिनांक 15-7-85 की मूल प्रति आवेदक द्वारा खो गई है। समय-समय पर यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 के उप खंड 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती मनोरमा भटनागर को दिए गए उक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट सं. पी. जे/3052070 दिनांक 15-7-85 की मूल प्रति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. पार्टी को सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति को अलग से जारी किया जा रहा है।

[फाइल सं. ए/बी-21/85-86/बी एल एस/3115]

एन. एस. कृष्णामूर्ति, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात कार्यालय)

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1985

(निरस्तीकरण आदेश)

का. आ. 786.—सर्वश्री नीहारिका इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड बी-76 से 79 और बी-35, सेक्टर-VI नोएडा काम्पलेक्स (जिला गाजियाबाद) यू.पी. को एक आयात लाइसेंस सं. पी/एस/1960266 दिनांक 2-7-84 का 6,23,376/- रु. के लिए आयात नीति 1984-85 के परिशिष्ट 3ए और 4ए की मदों के आयात हेतु प्रदान किया गया है।

आवेदक फर्म ने उस कथन के समर्थन में एक शपथ-पत्र आयात-निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1985-88 के पैरा 86 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि उक्त लाइसेंस की कस्टम प्रयोजन कापी सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता, नई दिल्ली के पास पंजीकृत कराने के पश्चात और आंशिक रूप से 3,76,830/- रु. की शेष राशि उपयोग करने के पश्चात कहीं खो गई है।

डुप्लीकेट कस्टम प्रयोजन कापी बकाया राशि रु. 3,76,830/- को कवर करने के लिए अपेक्षित है।

अब आयात-व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दि. 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9 (डी) में प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए मैं उपर्युक्त लाइसेंस सं. पी एस. 1960266 दि. 2-7-84 की मूल कस्टम प्रयोजन कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूं।

आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्य विधि पुस्तिका 1985-88 के पैरा 86 के अनुसार उक्त लाइसेंस सं. पी/एस 1960266 दि. 2-7-84 की कस्टम प्रयोजन कापी की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जायेगा।

[सं. यू-पी/अदर्स/प्रोप/5/ए एम-85/एयू-1/सी एल ए/2541-50]

एस. एल. चौहान, उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

New Delhi, the 11th February, 1986

ORDER

S.O. 785.—Mrs. Manorama Bhatnagar, S-54, Greater Kailash-I, New Delhi-110048, was granted a Customs Clearance Permit No. P/J/3052070 dated 15th July, 1985 for Rs. 66,500 only for import of Isuzu Gemini R-Car 4 door Sedan 4 Cylinder Diesel 1500 RHD Deluxe Model Car. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced lost. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs authority and such the value of the CCP has not been utilised at all.

2. In support of her contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/3052070 dated 15th July, 1985 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7th December, 1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/3052070 dated 15th July, 1985 issued to Mrs. Manorma Bhatnagar.

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[F. No. A/B-21/85-86/BLS/3115]

N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

for Chief Controller of Imports & Exports.

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 5th November, 1985

CANCELLATION ORDER

S.O. 786.—M/s. Niharika Electronics Pvt., Ltd. B-76 to 79 and B-35, Sector VI, Noida Complex, (Distt. Ghaziabad) UP, was granted an import licence No. P|S|1960266 dated 2-7-84 for Rs. 6,27,376 for import of items of Appendix 3-A and 4-A of Import Policy for 1984-85, required for manufacture of Colour Television sets.

The applicant has filed an affidavit as required under para 86 of Hand Book of Import & Export Procedure, 1985-88 wherein they have stated that the Custom Purpose Copy of the above licence has been lost after having been registered with the Asstt. Collector of Customs, New Delhi and utilised partly leaving a balance of Rs. 3,76,830.

A duplicate Custom Purpose Copy is required by the firm to cover the balance value of Rs. 3,76,830.

In exercise of the powers conferred on me under sub-clause 9(d) in the Import Trade Control Order, 1955 dated 7-12 55 as amended upto date, I cancel the Customs Purpose of the above licence.

The applicant (licencee) is now being issued duplicate Customs Purpose Copy of import licence No. P|S|1960266 dt. 2-7-84 for Rs. 6,23,376 in accordance with the provision of paragraph 86 of Hand Book of Import Export Procedure. 1985—88.

[No. UP/others/Prop./5|AM-85|AU.I|CLA|2541 to 50

S. L. CHOHAN, Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

for Jt. Chief Controller of Imports & Exports

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1986

का.आ. 787.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम (7) के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वनस्पति की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिये गये ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है। यह फीस 1985-10-01 से लागू होगी :

अनुसूची

क्रम सं.	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	प्रति इकाई	मुहर लगाने की फीस
1	2	3	4	5
1.	वनस्पति	IS : 10633-1983 वनस्पति की विशिष्टि	एक टन	20.00 रु.

[सं. सी एम डी/13 : 10]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 3rd February, 1986

S.O. 787.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee per unit for Vanaspati details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1985-10-01.

THE SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking fee per unit
1	2	3	4	5
1.	Vanaspati	IS : 10633-1983 Specification for Vanaspati.	One Tonne	Rs. 20.00

[No. CMD/13 : 10]

का.आ. 788.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के नियम 4 के उपनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जो मानक चिन्ह उसके डिजाइन, शाब्दिक विवरण तथा तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिया गया है, वह निर्धारित कर दिया गया है।

यह भारतीय मानक संस्था/प्रमाणन चिन्ह/अधिनियम 1952 और इसके अधीन बने नियमों तथा विनियमों के निमित्त 1985-10-01 से लागू होगा :

अनुसूची

क्रम सं.	मानक चिन्ह का डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक चिन्ह की डिजाइन और शाब्दिक विवरण
1	2	3	4	5
1	IS:10633 ISI VANASPATI	वनस्पति	IS : 10633-1983 वनस्पति की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम, जिसमें "ISI" अक्षर होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई निश्चित शैली और परस्पर सम्बद्ध अनुपात में तैयार किया गया है। डिजाइन में निर्देशन के अनुसार उसके ऊपर भारतीय मानक संस्था तथा नीचे "वनस्पति" शब्द अंकित है।

[संख्या सी एम डी/13:9]

बी. एन. सिंह, अपर महानिदेशक

S O. 788.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark, design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule here to annexed, has been specified.

This standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed the reunder, shall come into force with effect from 1985-10-10:

THE SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS : 10633	Vanaspati	IS : 10633,1983 –Specification for Vanaspati.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side and the words 'VANASPATI' being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]
B. N. SINGH, Addl. Director General

का. आ. 789.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 496 लाइसेंसों के ब्यौरे नीचे की अनुसूची में दिए गए हैं, उनका अप्रैल, 1985 में नवीकरण किया जाता है।

अनुसूची

क्रम संख्या	सी एम/एल संख्या	वैध : तक
(1)	(2)	(3)
1.	0000707	1986-03-31
2.	0015013	1986-04-30
3.	0017017	1986-03-31
4.	0017118	1986-03-31
5.	0017219	1986-03-31
6.	0017421	1986-03-31
7.	0039128	1986-03-31
8.	0039229	1986-03-31
9.	0039330	1986-03-31
10.	0039635	1986-03-31
11.	0039835	1986-03-31
12.	0042117	1986-03-31
13.	0042218	1986-03-31
14.	0051522	1986-03-31
15.	0057534	1986-03-31
16.	0057635	1986-03-31
17.	0060826	1986-03-31
18.	0060927	1986-03-31
19.	0061929	1986-03-31
20.	0062527	1986-03-31
21.	0067133	1986-03-31
22.	0077843	1986-03-31
23.	0102109	1986-03-31
24.	0102210	1986-03-31
25.	0102311	1986-03-31
26.	0102412	1986-03-31
27.	0102816	1986-03-31
26.	0103111	1986-03-31
29.	0103212	1986-03-31
30.	0103313	1986-03-31
31.	0103414	1986-03-31
32.	0103515	1986-03-31
33.	0113316	1986-03-31
34.	0115623	1986-03-31
35.	0122721	1986-03-15
36.	0123420	1986-03-31
37.	0133928	1986-03-31
38.	0140824	1986-03-31
39.	0153833	1986-04-15
40.	0158540	1985-06-30
41.	0165941	1986-03-31
42.	0166034	1986-03-31
43.	0166943	1986-04-15
44.	0178041	1986-04-15
45.	0187244	1986-03-31
46.	0187648	1986-03-15
47.	0187749	1985-03-31
48.	0191538	1986-03-31
49.	0193441	1985-03-31
50.	0194342	1986-03-31
51.	0194544	1986-03-31
52.	0194645	1986-03-31
53.	0195243	1986-03-31
54.	0195748	1986-04-30
55.	0200311	1986-01-31
56.	0210011	1985-04-30
57.	0225226	1986-02-15
58.	0228939	1986-03-15
59.	0230522	1986-03-31
60.	0231726	1986-03-31
61.	0233528	1986-03-31
62.	0241628	1986-03-31
63.	0246335	1986-03-31
64.	0247539	1986-03-31
65.	0251126	1986-04-15
66.	0262030	1986-03-31
67.	0262131	1986-03-31
68.	0263133	1986-03-31

(1)	(2)	(3)
69.	0263234	1986 03 31
70.	0270635	1985-10-31
71.	0276849	1986-03-31
72.	0276950	1986-03-31
73.	0277447	1986-03-31
74.	0296552	1986-03-31
75.	0300416	1986-03-31
76.	0301418	1986-03-31
77.	0308533	1986-03-31
78.	0312019	1986-03-31
79.	0324329	1986-03-31
80.	0334433	1986-03-31
81.	0335738	1986-03-15
82.	0336336	1986-03-15
83.	0336042	1986-03-31
84.	0338138	1986-04-15
85.	0340630	1986-03-31
86.	0344436	1986-02-15
87.	0349345	1986-03-31
88.	0349446	1986-03-31
89.	0359146	1986-03-31
90.	0371742	1986-03-31
91.	0373039	1986-02-28
92.	0373645	1986-03-15
93.	0374647	1986-03-15
94.	0375245	1986-03-31
95.	0376449	1986-03-31
96.	0376550	1986-03-31
97.	0376954	1986-03-31
98.	0377148	1986-03-31
99.	0377350	1986-03-31
100.	0377451	1986-03-31
101.	0377552	1986-03-31
102.	0377956	1986-03-31
103.	0382242	1986-04-30
104.	0382343	1986-04-30
105.	0382545	1986-04-30
106.	0387959	1986-04-15
107.	0394855	1986-03-31
108.	0403729	1985-09-30
109.	0419845	1986-03-31
110.	0422733	1986-02-28
111.	0425032	1986-04-30
112.	0426741	1986-03-31
113.	0428644	1986-03-31
114.	0428947	1986-03-31
115.	0429646	1986-04-15
116.	0430025	1986-04-15
117.	0430328	1986-04-15
118.	0431128	1986-04-15
119.	0431734	1986-04-15
120.	0436441	1986-05-15
121.	0457247	1986-03-31
122.	0457954	1986-04-15
123	0486456	1986 04 15
124.	0490147	1986 02-28
125.	0490548	1986-02-28
126.	0490649	1986-02-28
127.	0492350	1985-12-31
128.	0493554	1986-04-30
129.	0498059	1986-03-31
130.	0504432	1986-04-30
131.	0509644	1986-04-15
132.	0509745	1986-03-31
133.	0510023	1986-04-15
134.	0510124	1986-04-15
135.	0510679	1986-03-15
136.	0513534	1986-03-31
137.	0514536	1986-04-15
138.	0517138	1986 04-15
139.	0522030	1986-03-31
140.	0522131	1986-03-31
141.	0522232	1986-03-31
142.	0522333	1986-03-31
143.	0522434	1986-03-31
144.	0526139	1986-03-31
145.	0536344	1986-03-31
146.	0537045	1986-03-31
147.	0546044	1986-03-31
148.	0559558	1986-03-31
149.	0569258	1986-02-15
150.	0580347	1986-04-15
151.	0584557	1985-10-31
152.	0589163	1986-02-15
153.	0590552	1986-02-15
154.	0590653	1986-02-15
155.	0591655	1986-02-28
156.	0593659	1986-02-28
157.	0597465	1986-03-31
158.	0597970	1986-03-31
159.	0599570	1986-03-15
160.	0599671	1986-03-15
161.	0599772	1986-03-15
162.	0600731	1986-03-15
163.	0601430	1986-03-31
164.	0602028	1986-03-31
165.	0602533	1986-04-30
166.	0602634	1986-04-30
167.	0602836	1986-03-31
168.	0603131	1986-03-31
169.	0603535	1986-06-30
170.	0603939	1986-04-15
171.	0604052	1986-04-15
172.	0604436	1986-04-30
173.	0604638	1986-03-31
174.	0606137	1986-04-30
175.	0607240	1986-04 30
176.	0611736	1986-04-30
177.	0613235	1986-03-31
178.	0651243	1986-04-30
179.	0672554	1986-01-31
180.	0675560	1986-03-31
181.	0680654	1986-03-15
182.	0682153	1986-03-15
183.	0682254	1986-03-31
184.	0683256	1986-03-15
185.	0683860	1986-03-15
186.	0683862	1986-03-15
187.	0684965	1986-03-15
188.	0685765	1986-03-31
189.	0696969	1986-03-31
190.	0687264	1986-03-31
191.	0687486	1986-03-31
192.	0688286	1986-03-31
193.	0689268	1986-03-31
194.	0689571	1986-04-30
195.	0689672	1986-03-31
196.	0689773	1986-04-15
197.	0690859	1986-04-30
198.	0690960	1986-04-30
199.	0691053	1986-04-30
200.	0692156	1986-03-31
201.	0693562	1986-04-15

(1)	(2)	(3)
202.	0694867	1986-04-15
203.	0697368	1986-04-15
204.	0708953	1986-03-31
205.	0711134	1986-04-15
206.	0716750	1986-03-31
207.	0736958	1986-04-15
208.	0737455	1985-11-30
209.	0741850	1986-03-31
210.	0750649	1986-02-15
211.	0752249	1986-02-28
212.	0752855	1986-02-15
213.	0758459	1986-02-28
214.	0758059	1986-02-28
215.	0758968	1986-03-31
216.	0763759	1986-03-31
217.	0765157	1986-03-31
218.	0765864	1986-04-30
219.	0766462	1986-03-31
220.	0766664	1986-03-31
221.	0768668	1986-04-15
222.	0768769	1986-04-15
223.	0769770	1986-04-15
224.	0772053	1986-04-30
225.	0772457	1986-04-30
226.	0774158	1986-05-15
227.	0779370	1086-01-31
228.	0794164	1986-08-31
229.	0739568	1986-01-31
230.	0795166	1985-08-31
231.	0820341	1986-04-15
232.	0821444	1986-04-15
233.	0827456	1986-04-30
234.	0836861	1986-02-28
235.	0840549	1986-08-31
236.	0842351	1986-03-15
237.	0842654	1986-03-15
238.	0846460	1986-03-31
239.	0846864	1986-04-15
240.	0848060	1986-03-31
241.	0848464	1986-03-31
242.	0849365	1986-03-31
243.	0849769	1986-03-31
244.	0850146	1986-03-31
245.	0850249	1986-03-15
246.	0851150	1986-03-31
247.	0851251	1986-03-31
248.	0851352	1986-03-31
249.	0851655	1986-03-31
250.	0852657	1986-04-15
251.	0852359	1986-04-15
252.	0853558	1986-03-31
253.	0853659	1986-04-15
254	0853661	1986-04-15
255.	0853962	1986-03-31
256.	0856261	1986-04-15
257.	0856362	1986-04-15
258.	0859772	1986-04-15
259.	0859873	1986-04-15
260.	0860454	1986-04-15
261.	0860555	1986-04-15
262.	0860656	1986-04-15
263.	0660858	1986-04-15
264.	0861961	1986-04-15
265.	0862256	1986-04-15
266.	0862862	1986-04-15
267.	0863056	1986-04-15
268.	0863258	1986-04-15
269.	0863460	1986-04-15
270.	0864563	1985-04-30
271.	0866365	1986-04-30
272.	0867771	1986-03-31
273.	0670255	1986-03-31
274.	0895473	1986-03-31
275.	0896879	1986-01-15
276.	0897477	1986-01-15
277.	0909963	1985-11-15
278.	0912750	1986-03-31
279.	0926155	1985-08-15
280.	0927561	1986-03-15
281.	0930954	1986-01-15
282.	0947163	1986-02-28
283.	0948872	1986-03-15
284.	0950657	1986-03-15
285.	0953562	1986-03-31
286.	0953865	1986-03-31
287.	0954160	1986-03-31
288.	0954665	1986-03-31
289.	0954766	1986-03-31
290.	0954968	1986-03-31
291.	0955061	1986-03-31
292.	0955263	1986-03-31
293.	0955364	1986-03-31
294.	0956366	198y-03-31
295.	0956467	1986-03-31
296.	0957873	1986-03-31
297.	0957974	1986-03-31
298.	0958168	1986-03-31
299.	0960054	1986-04-15
300.	0960660	1986-08-31
301.	0961056	1986-04-15
302.	0961258	1986-03-31
303.	0961359	1986-03-31
304.	0961460	1986-04-15
305.	0961965	1986-04-15
306.	0962260	1986-08-31
307.	0962361	1986-04-15
308.	0962563	1986-04-15
309.	0963565	1986-04-30
310.	0964163	1986-04-30
311.	0971059	1985-05-31
312.	0979883	1986-07-15
313.	1001512	1986-03-31
314.	1026831	1986-03-31
315.	1039941	1986-02-28
316.	1040017	1985-09-30
317.	1040118	1986-03-15
318.	1041019	1986-03-15
319.	1041221	1986-03-15
320.	1041827	1986-03-15
321.	1042930	1986-03-15
322.	1045027	1986-03-15
323.	1046635	1986-03-15
324.	1047536	1986-03-15
325.	1048437	1985-04-15
326.	1050424	1986-03-15
327.	1050525	1986-03-15
328.	1051850	1986-03-31
329.	1054634	1986-03-31
330.	1055151	1986-03-31
331.	1056840	1986-03-15
332.	1057034	1986-03-15
333.	1057236	1986-03-15
334.	0157436	1986-03-15
335.	1058541	1986-03-31
336.	1059341	1983-04-15

(1)	(2)	(3)
337.	1060025	1986-03-31
338.	1060124	1986-03-31
339.	1060225	1986-03-31
340.	1060326	1986-03-31
341.	1060427	1986-03-31
342.	1060528	1986-03-31
345.	1060730	1986-03-31
344.	1062330	1986-04-15
345.	1062653	9186-04-15
346.	1063029	1986-03-15
347.	1063332	1986-04-15
348.	1063938	1986-04-15
349.	1064334	1986-04-15
350.	1064538	1986-04-15
351.	1065033	1986-04-15
352.	1068140	1986-04-15
353.	1071432	1986-03-31
354.	1071533	1986-04-30
355.	1072737	1986-04-30
356.	1074135	1086-03-31
357.	1083136	1986-04-30
358.	1085039	1986-05-31
359.	1088550	1985-06-15
360.	1119434	1986-04-15
361	1119838	1985-09-30
362.	1132729	1985-11-30
363.	1133428	1985-11-30
364.	1134834	1985-11-30
365.	1133432	1985-11-30
366.	1150630	1986-01-31
367.	1150731	1986-01-31
368.	1153333	1986-02-15
369.	1155842	1986-02-15
370.	1156137	1986-03-31
371.	1156339	1986-02-15
372.	1156541	1986-02-15
373.	1156642	1986-02-15
374.	1156844	1986-02-15
375.	1161130	1986-02-15
376.	1161837	1986-02-28
377.	1163033	1986-02-28
378.	1163740	1986-02-28
379.	1163942	1986-02-28
380.	1165744	1986-02-28
381.	1166342	1986-02-28
382.	1166443	1986-02-28
383.	1167041	1986-02-28
384.	1168043	1986-03-15
385.	1168144	1986-03-15
386.	1168851	1986-03-15
387.	1171739	1986-03-15
388.	1172842	1986-03-31
389.	1174139	1986-03-15
390.	1174442	1986-03-31
391.	1174644	1986-03-31
392.	1175141	1986-03-31
393.	1175343	1986-05-15
394.	1175646	1986-03-31
395.	1175747	1986-03-31
396.	1175949	1986-09-30
397.	1176244	1986-04-15
398.	1176446	1986-03-15
399.	1176749	1986-04-15
400.	1177044	1986-04-15
401.	1180437	1986-04-15
402.	1180639	1986-04-30
403.	1181338	1986-04-30
404.	1181439	1986-04-30
405.	1181742	1986-04-30
406.	1181944	1986-04-30
407.	1187350	1985-05-15
408.	1235537	1985-09-15
409.	1255543	1985-12-31
410.	1263946	1986-01-15
411.	1264645	1986-01-15
412.	1266144	1986-01-15
413.	1267550	1986-01-31
414.	1276854	1986-02-15
415.	1279355	1986-02-28
416.	1279557	1986-02-28
417.	1279658	1986-02-28
418.	1281544	1986-02-28
419.	1283952	1986-02-28
420.	1284045	1986-02-28
421.	1284247	1986-03-15
422.	1284651	1986-03-15
423.	1285249	1986-03-15
424.	1285451	1986-03-15
425.	1285552	1986-03-15
426.	1285855	1986-03-15
427.	1286352	1986-03-15
428.	1287455	1986-03-15
429.	1290949	1986-03-15
430.	1291042	1986-03-31
431.	1291143	1986-03-31
432.	1291648	1986-03-31
433.	1291749	1986-03-31
434.	1291850	1986-03-31
435.	1292044	1986-03-31
436.	1292145	1986-03-31
437.	1292549	1986-03-31
438.	1292650	1986-03-31
439.	1292751	1986-03-31
440.	1293147	1986-03-31
441.	1293450	1986-03-31
442.	1293753	1986-03-31
443.	1294048	1986-03-31
444.	1294250	1986-03-31
445.	1294553	1986-03-15
446.	1295555	1986-03-31
447.	1295656	1986-03-31
448.	1296052	1986-06-30
449.	1296355	1986-03-31
450.	1296658	1986-03-31
451.	1296759	1986-03-31
452.	1296860	1986-03-31
453.	1296961	1986-03-31
454.	1297155	1986-03-31
455.	1297256	1986-03-31
456.	1297357	1986-03-31
457.	1297458	1986-03-31
458.	1297559	1986-03-31
459.	1297660	1986-03-31
460.	1298157	1986-03-31
461.	1298359	1986-03-31
462.	1298561	1986-03-31
463.	1298965	1986-03-31
464.	1299058	1286-03-31
465.	1299664	1986-03-31
466.	1299967	1986-03-15
467.	1300017	1986-03-15
468.	1300926	1986-04-15
469.	1301019	1986-04-15

(1)	(2)	(3)
470.	1301120	1986-04-51
471.	1301322	1986-04-15
472.	1301423	1986-04-15
473.	1301524	1986-04-15
474.	1301625	1986-04-15
475.	1301827	1986-04-15
476.	1301928	1986-04-15
477.	1302021	1986-04-15
478.	1302625	1986-04-15
479.	1302627	1986-04-15
480.	1302930	1986-09-15
481.	1303023	1986-04-15
482.	1303225	1986-04-15
483.	1303730	1986-04-31
484.	1303831	1986-04-15
485.	1304025	1986-04-15
486.	1304126	1986-03-31
487.	1304227	1986-04-15
488.	1304530	1986-09-30
489.	1334631	1986-04-15
490.	1304833	1986-04-15
491.	1305229	1986-04-15
492.	1305936	1986-04-30
493.	1306433	1986-04-30
494.	1307132	1986-04-30
495.	1307334	1986-04-30
496.	1309035	1986-08-31

[सं. सी. एम. डी. / 13 : 12]
बी. एन. सिंह, अपर महानिदेशक

S O. 789 :—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that 496 licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been renewed during the month of April 1985 :

SCHEDULE

Sl. No.	CM/L No.	Valid upto
(1)	(2)	(3)
1.	0000707	1986-03-31
2.	0015013	1986-04-30
3.	0017017	1986-03-31
4.	0017118	1086-03-31
5.	0017219	1986-03-31
6.	0017421	1086-03-31
7.	0039128	1986-03-31
8.	0039229	1986-03-31
9.	0039330	1986-03-31
10.	0039633	1986-03-31
11.	0039835	1986-03-31
12.	0042117	1986-03-31
13.	0042218	1986-03-31
14.	0051522	1986-03-31
15.	0057534	1986-03-31
16.	0057635	1986-03-31
17.	0060826	1986-03-31
18.	0060927	1986-03-31
19.	0061929	1986-03-31
20.	0062527	1986-03-31
21.	0067133	1986-03-31
22.	0077843	1986-03-31
23.	0102109	1986-03-31
24.	0102210	1986-03-31
25.	0102311	1986-03-31
26.	0102412	1986-03-31
27.	0102816	1986-03-31
28.	0103111	1986-03-31
29.	0103212	1986-03-31
30.	0103313	1986-03-31
31.	0103414	1986-03-31
32.	0103515	1986-03-31
33.	0113316	1986-03-31
34.	0115623	1986-03-31
35.	0122721	1986-03-15
36.	0123420	1986-03-31
37.	0133928	1986-03-31
38.	0140824	1986-03-31
39.	0153833	1986-04-15
40.	0158540	1985-06-30
41.	0165941	1986-03-31
42.	0166034	1986-03-31
43.	0166943	1986-04-15
44.	0178041	1986-04-15
45.	0187244	1986-03-31
46.	0187648	1986-03-15
47.	0187749	1985-03-31
48.	0191538	1986-03-31
49.	0193441	1986-03-31
50.	0194342	1986-03-31
51.	0194544	1986-03-31
52.	0194645	1986-03-31
53.	0195243	1986-03-31
54.	0195748	1986-04-30
55.	0200311	1986-01-31
55.	0200311	1986-01-31
56.	0210011	1985-04-30
57.	0225226	1986-02-15
58.	0228939	1986-03-15
59.	0230522	1986-03-31
60.	0231726	1986-03-31
61.	0233528	1986-03-31
62.	0241628	1986-03-31
63.	0246335	1986-03-31
64.	0247539	1986-03-31
65.	0251126	1986-04-15
66.	0262030	1986-03-31
67.	0262131	1986-03-31
68.	0263133	1986-03-31
69.	0263234	1986-03-31
70.	0270635	1985-10-31
71.	0276849	1986-03-31
72.	0276950	1986-03-31
73.	0277447	1986-03-31
74.	0296552	1986-03-31
75.	0300416	1986-03-31
76.	0301418	1986-03-31
77.	0308533	1986-03-31
78.	0312019	1986-03-31
79.	0324329	1986-03-31
80.	0334433	1986-03-31
81.	0335738	1986-03-15
82.	0336336	1986-03-15
83.	0336942	1986-03-31
84.	0338138	1986-04-15
85.	0340630	1986-03-31
86.	0344436	1986-02-15
87.	0349345	1986-03-31

(1)	(2)	(3)
88.	0349446	1986-03-31
89.	0359146	1986-03-31
90.	0371742	1986-03-31
91.	0373039	1986-02-28
92.	0373645	1986-03-15
93.	0374647	1986-03-15
94.	0375245	1986-03-31
95.	0376449	1986-03-31
96.	0376550	1986-03-31
97.	0376954	1986-03-31
98.	0377148	1986-03-31
99.	0377350	1986-03-31
100.	0377451	1986-03-31
101.	0377552	1986-03-31
102.	0377956	1986-03-31
103.	0382242	1986-04-30
104.	0382343	1986-04-30
105.	0382545	1986-04-30
106.	0387959	1986-04-15
107.	0394855	1986-03-31
108.	0403729	1985-09-30
109.	0419845	1986-03-31
110.	0422733	1986-02-28
111.	0425032	1986-04-30
112.	0426741	1986-03-31
113.	0428644	1986-03-31
114.	0428947	1986-03-31
115.	0429646	1986-04-15
116.	0430025	1986-04-15
117.	0430328	1986-04-15
118.	0431128	1986-04-15
119.	0431734	1986-04-15
120.	0436441	1986-05-15
121.	0457247	1986-03-31
122.	0457954	1986-04-15
123.	0486456	1986-04-15
124.	0490447	1986-02-28
125.	0490548	1986-02-28
126.	0490649	1986-02-28
127.	0492350	1985-12-31
128.	0493554	1986-04-30
129.	0498059	1986-03-31
130.	0504432	1986-04-30
131.	0509644	1986-04-15
132.	0509745	1986-03-31
133.	0510023	1986-04-15
134.	0510124	1986-04-15
135.	0510629	1986-03-15
136.	0513534	1986-03-31
137.	0514536	1986-04-15
138.	0517138	1986-04-15
139.	0522030	1986-03-31
140.	0522131	1986-03-31
141.	0522232	1986-03-31
142.	0522333	1986-03-31
143.	0522434	1986-03-31
144.	0526139	1986-03-31
145.	0536344	1986-03-31
146.	0537043	1986-03-31
147.	0546044	1986-03-31
148.	0559558	1986-03-31
149.	0569258	1986-02-15
150.	0580347	1986-04-15
151.	0584557	1985-10-31
152.	0589163	1986-02-15
153.	0590552	1986-02-15
154.	0590653	1986-02-15
155.	0591655	1986-02-28
156.	0593659	1986-02-28
157.	0597465	1986-03-31
158.	0597970	1986-03-31
159.	0599570	1986-03-15
160.	0599671	1986-03-15
161.	0599772	1986-03-15
162.	0600731	1986-03-15
163.	0601430	1986-03-31
164.	0602028	1986-03-31
165.	0602533	1986-04-30
166.	0602634	1986-04-30
167.	0602836	1986-03-31
168.	0603131	1986-03-31
169.	0603535	1986-06-30
170.	0603939	1986-04-15
171.	0604032	1986-04-15
172.	0604436	1986-04-30
173.	0604638	1986-03-31
174.	0606137	1986-04-30
175.	0607240	1986-04-30
176.	0611736	1986-04-30
177.	0613235	1986-03-31
178.	0651243	1986-04-30
179.	0672554	1986-01-31
180.	0675560	1986-03-31
181.	0680654	1986-03-15
182.	0682153	1986-03-15
183.	0682254	1986-03-31
184.	0683256	1986-03-15
185.	0683660	1986-03-15
186.	0683862	1986-03-15
187.	0684965	1986-03-15
188.	0685765	1986-03-31
189.	0686969	1986-03-31
190.	0687264	1986-03-31
191.	0687466	1986-03-31
192.	0688266	1986-03-31
193.	0689268	1986-03-31
194.	0689571	1986-04-30
195.	0689672	1986-03-31
196.	0689773	1986-04-15
197.	0690859	1986-04-30
198.	0690960	1986-04-30
199.	0691053	1986-04-30
200.	0692156	1986-03-31
201.	0693562	1986-04-15
202.	0694867	1986-04-15
203.	0697368	1986-04-15
204.	0708953	1986-03-31
205.	0711134	1986-04-15
206.	0716750	1986-03-31
207.	0736958	1986-04-15
208.	0737455	1985-11-30
209.	0741850	1986-03-31
210.	0750649	1986-02-15
211.	0752249	1986-02-28
212.	0752855	1986-02-15
213.	0756459	1986-02-28
214.	0758059	1986-02-28
215.	0758968	1986-03-31
216.	0763759	1986-03-31
217.	0765157	1986-03-31
218.	0765864	1986-04-30
219.	0766462	1986-03-31

(1)	(2)	(3)
220.	0766664	1986-03-31
221.	0768668	1986-04-15
222.	0768769	1986-04-15
223.	0769670	1986-04-15
224.	0772053	1986-04-30
225.	0772457	1986-04-30
226.	0774158	1986-05-15
227.	0779370	1986-01-31
228.	0794164	1986-08-31
229.	0794568	1986-01-31
230.	0795166	1986-08-31
231.	0820341	1986-04-15
232.	0821444	1986-04-15
233.	0827456	1986-04-30
234.	0836861	1986-02-28
235.	0840549	1986-08-31
236.	0842351	1986-03-15
237.	0842654	1986-03-15
238.	0846460	1986-03-31
239.	0846864	1986-04-15
240.	0848060	1986-03-31
241.	0848464	1986-03-31
242.	0849365	1986-03-31
243.	0849769	1986-03-31
244.	0850148	1986-03-31
245.	0850249	1986-03-15
246.	0851150	1986-03-31
247.	0851251	1986-03-31
248.	0851352	1986-03-31
249.	0851655	1986-03-31
250.	0852657	1986-04-15
251.	0852859	1986 04-15
252.	0853558	1986-03-31
253.	0853659	1986-04-15
254.	0853861	1986-04-15
255.	0853962	1986-03-31
256.	0856261	1986-04-15
257.	0856362	1986-04-15
258.	0859772	1986-04-15
259.	0859873	1986-04-15
260.	0860454	1986-04-15
261.	0860555	1986-04-15
262.	0860656	1986-04-15
263.	0860858	1986-04-15
264.	0861961	1986-04-15
265.	0862256	1986-04-15
266.	0862862	1986-04-15
267.	0863056	1986-04-15
268.	0863258	1986-04-15
269.	0863460	1986-04-15
270.	0864563	1986-04-30
271.	0866365	1986-04-30
272.	0867771	1986-03-31
273.	0870255	1986-03-31
274.	0895473	1986-03-31
275.	0896879	1986-01-15
276.	0897477	1986-01-15
277.	0909963	1985-11-15
278.	0912750	1986-03-31
279.	0926155	1985-08-15
280.	0927561	1986-03-15
281.	0930954	1986-01-15
282.	0947163	1986-02-28
283.	0948872	1986-03-15
284.	0950657	1986-03-15
285.	0953562	1986-03-31
286.	0953865	1986-03-31
287.	0954160	1986-03-31
288.	0954665	1986-03-31
289.	0954766	1986-03-31
290.	0954968	1986-03-31
291.	0955061	1986-03-31
292.	0955263	1986-03-31
293.	0955364	1986-03-31
294.	0955366	1986-03-31
295.	0956467	1986-03-31
296.	0957873	1986-03-31
297.	0957974	1986-03-31
298.	0958168	1986-03-31
299.	0960054	1986-04-15
300.	0960660	1986-08-31
301.	0961056	1986-04-15
302.	0961258	1986-03-31
303.	0961359	1986-03-31
304.	0961460	1986-04-15
305.	0961965	1986 04-15
306.	0962260	1986-08-31
307.	0962361	1986-04-15
308.	0962563	1986-04-15
309.	0963565	1986-04-30
310.	0964163	1986-04-30
311.	0971059	1985-05-31
312.	0979883	1985-07-15
313.	1001512	1986-03-31
314.	1026831	1986-03-31
315.	1039941	1986-02-28
316.	1040017	1985-09-30
317.	1040118	1986-03-15
318.	1041019	1986-03-15
319.	1041221	1986-03-15
320.	1041827	1986-03-15
321.	1042930	1986-03-15
322.	1045027	1986-03-15
323.	1046635	1986-03-15
324.	1047536	1986-03-15
325.	1048437	1986-04-15
326.	1050424	1986-03-15
327.	1050525	1986-03-15
328.	1051830	1986-03-31
329.	1054634	1986-03-31
330.	1055131	1986-03-31
331.	1056840	1986-03-15
332.	1057034	1986-03-15
333.	1057236	1986-03-15
334.	1057438	1986-03-15
335.	1058541	1986-03-31
336.	1059341	1984-04-15
337.	1060023	1986-03-31
338.	1060124	1986-03-31
339.	1060225	1986-03-31
340.	1060326	1986-03-31
341.	1060427	1986-03-31
342.	1060528	1986-03-31
343.	1060730	1986-03-31
344.	1062330	1986-04-15
345.	1062633	1986-04-15
346.	1063029	1986-03-15
347.	1063332	1986-04-15
348.	1063938	1986-04-15
349.	1064334	1986-04-15
350.	1064536	1986-04-15
351.	1065033	1986-04-15
352.	1068140	1986-04-15

(1)	(2)	(3)
353.	1071432	1986-03-31
354.	1071533	1986-04-30
355.	1072737	1986-04-30
356.	1074135	1986-03-31
357.	1083136	1986-04-30
358.	1085039	1986-05-31
359.	1088550	1985-06-15
360.	1119434	1986-04-15
361.	1119838	1985-09-30
362.	1132729	1985-11-30
363.	1133428	1985-11-30
364.	1134834	1985-11-30
365.	1135432	1985-11-30
366.	1150630	1986-01-31
367.	1150731	1986-01-31
368.	1153333	1986-02-15
369.	1155842	1986-02-15
370.	1156137	1986-03-31
371.	1156339	1986-02-15
372.	1156541	1986-02-15
373.	1156642	1986-02-15
374.	1156844	1986-02-15
375.	1161130	1986-02-15
376.	1161837	1986-02-28
377.	1163033	1986-02-28
378.	1163740	1986-02-28
379.	1163942	1986-02-28
380.	1165744	1986-02-28
381.	1166342	1986-02-28
382.	1166443	1986-02-28
383.	1167041	1986-02-28
384.	1168043	1986-03-15
385.	1168144	1986-03-15
386.	1168851	1986-03-15
387.	1171739	1986-03-15
388.	1172842	1986-03-31
389.	1174139	1986-03-15
390.	1174442	1986-03-31
391.	1174644	1986-03-31
392.	1175141	1986-03-31
393.	1175343	1986-05-31
394.	1175646	1986-03-31
395.	1175747	1986-03-31
396.	1175949	1986-09-30
397.	1176244	1986-04-15
398.	1176446	1986-03-15
399.	1176749	1986-04-15
400.	1177044	1986-04-15
401.	1180437	1986-04-15
402.	1180639	1986-04-30
403.	1181338	1986-04-30
404.	1181439	1986-04-30
405.	1181742	1986-04-30
406.	1181944	1986-04-30
407.	1187350	1985-05-15
408.	1235537	1985-09-15
409.	1255543	1985-12-31
410.	1263946	1986-01-15
411.	1264645	1986-01-15
412.	1266144	1986-01-15
413.	1267550	1986-01-31
414.	1276854	1986-02-15
415.	1279355	1986-02-28
416.	1279557	1986-02-28
417.	1279658	1986-02-28
418.	1281544	1986-02-28
419.	1283952	1986-02-28
420.	1284045	1986-02-28
421.	1284247	1986-03-15
422.	1284651	1986-03-15
423.	1285249	1986-03-15
424.	1285451	1986-03-15
425.	1285552	1986-03-15
426.	1285855	1986-03-15
427.	1286352	1986-03-15
428.	1287455	1986-03-15
429.	1290949	1986-03-15
430.	1291042	1986-03-31
431.	1291143	1986-03-31
432.	1291648	1986-03-31
433.	1291749	1986-03-31
434.	1291850	1986-03-31
435.	1292044	1986-03-31
436.	1292145	1986-03-31
437.	1292549	1986-03-31
438.	1292650	1986-03-31
439.	1292751	1986-03-31
440.	1293147	1986-03-31
441.	1293450	1986-03-31
442.	1293753	1986-03-31
443.	1294048	1986-03-31
444.	1294250	1986-03-31
445.	1294553	1986-03-15
446.	1295555	1986-03-31
447.	1295656	1986-03-31
448.	1296052	1986-06-30
449.	1296355	1986-03-31
450.	1296658	1986-03-31
451.	1296759	1986-03-31
452.	1296860	1986-03-31
453.	1296961	1986-03-31
454.	1297155	1986-03-31
455.	1297256	1986-03-31
456.	1297357	1986-03-31
457.	1297458	1986-03-31
458.	1287559	1986-03-31
459.	1297660	1986-03-31
460.	1298157	1986-03-31
461.	1298359	1986-03-31
462.	1298561	1986-03-31
463.	1298965	1986-03-31
464.	1299058	1986-03-31
465.	1299664	1986-03-31
466.	1299967	1986-03-31
467.	1300017	1986-03-15
468.	1300926	1986-04-15
469.	1301019	1986-04-15
470.	1301120	1986-04-15
471.	1301322	1986-04-15
472.	1301423	1986-04-15
473.	1301524	1986-04-15
474.	1301625	1986-04-15
475.	1301827	1986-04-15
476.	1301928	1986-04-15
477.	130 021	1986-04-15
478.	1302526	1986-04-15
479.	1302627	1986-04-15
480.	1302930	1986-09-15
481.	1303023	1986-04-15
482.	1303225	1986-04-15
483.	1303730	1986-04-15
484.	1303831	1986-04-15

(1)	(2)	(3)
485.	1304075	1986-04-15
486.	1304126	1986-03-31
487.	1304227	1986-04-15
488.	1304530	1986-09-30
489.	1304631	1986-04-15
490.	1304833	1986-04-15
491.	1305279	1986-04-15
492.	1305936	1986-04-30
493.	1306433	1986-04-30
494.	1307132	1986-04-30
495.	1307334	1986-04-30
496.	1309035	1986-08-31

[No. CMD/13 : 12]

B.N. SINGH, Add. Director General

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1986

का. आ. 790.—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के खंड (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार इसके द्वारा, मेदान स्थित भारत के प्रधान कौंसलावास में सहायक श्री जे. एन. गुलाटी को 17-1-86 से कौंसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[संख्या टी— 4330/1/85]

आर. दयाकर, उप सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th February, 1986

S.O. 790.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri J. N. Gulati, Assistant in the Consulate General of India, Medan, Indonesia to perform the duties of Consular Agent with effect from 17th January, 1986.

[No. T. 4330/1/85]

R. DAYAKAR, Dy. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1986

शुद्धि-पत्र

का. आ. 791:—जबकि, कोयला धारी क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में पृष्ठ सं. 1 से 8 तक प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 21 (अ) दिनांक 15 जनवरी, 1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में उल्लिखित जमीनों के अधिग्रहण के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और जबकि केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में मुद्रण की कुछ अशुद्धियां रह गई हैं ;

इसलिए, अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस संबंध में अन्य सभी क्षमता प्रदायक शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

पृष्ठ 2 पर—अधिसूचना की अनुसूची में—

(1) "1बी रिवर कोलफील्स" के स्थान पर "ईब रवहर कोलफील्ड्स" पढ़िए और "जिला साम्बलपुर (उड़ीसा)" के स्थान पर "जिला सम्बलपुर (उड़ीसा)" पढ़िए और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त हुआ हों वहां सम्बलपुर पढ़िए ।

(2) क्रम सं. 7 में ग्राम स्तंभ के नीचे "खन्तामहल" के स्थान पर "खुण्टमहल" पढ़िए और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त हुआ हो वहां "खुण्टमहल" पढ़िए ।

(3) कुडालोई ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं. में—"2348 (भाग)" के स्थान पर "2348" पढ़िए ।

(4) "लखमपुर ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं. यह शब्द "2350/3420 (भाग)......." के स्थान पर "1352 (भाग)" ...." के पहले पढ़िए ।

(5) सोल्दीया ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं; में "9395" के स्थान पर ("93 से 95" पढ़िए और "104 (भाग), 107 (भाग)" के स्थान पर "104 (भाग) से 107 (भाग)" पढ़िए।

(6) कुसुरालोई ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं. में "1044, 1046" के स्थान पर "1044 से 1046" पढ़िए।

पृष्ठ 3 पर—"368/1831" के स्थान पर 368/1931" पढ़िए ।

(7) खालिआपाली ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं. में "1 414" के स्थान पर "1 से 414" पढ़िए और "46/427" के स्थान पर "48/427" पढ़िए और "355, 455 1" के स्थान पर "355/455" पढ़िए ।

(8) कारलाजोरी ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या में—"1 331," के स्थान पर "1 से 331" पढ़िए और "61/36," के स्थान पर "61/356" पढ़िए और "18/376" के स्थान पर "19/376" पढ़िए ।

(9) "उल्का" ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या में—के स्थान पर "उबका" पढ़िए और "281 (भाग), 284 (भाग)" के स्थान पर "281 (भाग) से 284 (भाग)" पढ़िए और "313 (भाग), 316 (भाग)" के स्थान पर "313 (भाग) से 316 (भाग)" पढ़िए और "599 (भाग) 602 (भाग)" के स्थान पर "599 (भाग) से 602 (भाग)" पढ़िए और "775/1402" के स्थान पर "775/1502" पढ़िए।

(10) टमगोस्माल ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या में—के स्थान पर "टिंगिस्माल" पढ़िए और "301 (भाग), 304 (भाग)" के स्थान पर "301 (भाग) से 304 (भाग)" पढ़िए और "24/1186" के स्थान पर "124/1186" पढ़िए।

पृष्ठ 4 पर—"606/105" के स्थान पर "606/1205" पढ़िए और
"599/1208" के स्थान पर "594/1208" पढ़िए और
"469/227" के स्थान पर "469/1227" पढ़िए और
"988/127" के स्थान पर "988/1271" पढ़िए और
"378/1 17" के स्थान पर "378/1317" पढ़िए और
"4 9/1 325" के स्थान पर "469/1325" पढ़िए और
"478/132" के स्थान पर "478/1329" पढ़िए और
"543/1 31" के स्थान पर "543/1331" पढ़िए और

"563/1833" के स्थान पर "563/1333" पढ़िए और "180/1342" के स्थान पर "189/1342" पढ़िए और "291/1345" के स्थान पर "293/1345" पढ़िए ।

(11) "खैराकुनी" ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या मे-- के स्थान पर "खैराकुनी" पढ़िए और "562/1551" के स्थान पर "362/1551" पढ़िए और "43/16/18" के स्थान पर "43/1618" पढ़िए और "1037/1711" के स्थान पर "1039/1711" पढ़िए ।

(12) सीमा वर्णन में :—

रेखा "ब5–ब6–ब7–ब8–ब9–ब9–ब10" के स्थान पर "ब5–ब6–ब7–ब8–ब9" पढ़िए ।

(13) "ब16–ब17" रेखा में "हिन्गीस्मल" के स्थान पर "टिंग-स्माल" पढ़िए । और "982" के स्थान पर "2982" पढ़िए और "2385, 2387" के स्थान पर "2385, 2388, 2387" लिखें और "सेराकुनी" के स्थान पर "खैराकुनी" पढ़िए।

(14) रेखा ख-ग 12 में "2841, 283" के स्थान पर "284, 282, 283" लिखें ।

(15) रेखा ग 12-ग 11 में "1340, 1362" के स्थान पर "1340, 1363, 1362" लिखें ।

जिन जमीनों के लिए उपयुक्त शुद्धि-पत्र जारी किया गया है उनमें से किसी जमीन से हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी होने के तीस दिन के भीतर, कोयला धारी क्षेत्र (अर्जन और विकास)) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 की उप-धारा (1) के अनुसार, प्रस्तुत पूरी भूमि अथवा उसके किसी भाग के अधिग्रहण के संबंध में अथवा ऐसी भूमि में अथवा उस पर किन्हीं अधिकारों के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

[सं. 19/37/83–सी एल/सी ए]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 7th February, 1986

CORRIGENDUM

S.O. 791.—Whereas, by the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal) No. S.O. 21(E) dated the 15th January, 1985 published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), at pages 1 to 8, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands described in the Schedule appended to that notification;

And whereas, it has been brought to the notice of the Central Government that certain errors of printing nature have occurred in the publication of the said notification in the Gazette.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby amends the Schedule appended to the said notification as follows :—

In the Schedule—

at page—6,

(1) plot numbers to be acquired in village Kudloi—

for '2981 (Part) to 2985 (Part)' read "2981 (Part) to 2984 (Part)";

(2) plot numbers to be acquired in village Soldia—

for "144|855" read "44|855",

(3) plot numbers to be acquired in village Kusuraloi—

(a) for "123|1811" read "125|1811";

(b) for "321|1826" read "321|1836";

(c) for "397|184", read "397|1844";

at page-7,—

(1) plot numbers to be acquired in village Ubda—

for "1348 to 1363" read "1340 to 1363";

(2) plot numbers to be acquired in village Tingismal—

(a) for "Tinoismal" read "Tingismal";

(b) for "368 (Part)" read "336 (Part)";

(c) for "528|1233" read "529|1233";

(d) for "977|1251" read "877|1251";

(e) for "11|1256" read "117|1256";

(f) for "111|30, 38|1281, 86|1282, 98|1293"; read "111|1280, 88|1281, 88|1282, 88|1283";

(g) for "1068|1290" read "1060|1290";

(h) for '923|1303" read "923|1308";

(i) for "874|39" read "874|1339";

(3) plot numbers to be acquired in village Khairakuni—

(a) for "1561" read "62|1561";

(b) for "3|1579" read "6|1578";;

(c) for "966|1590" read "956|1590";

(d) for "397|1635" read "397|1636";

at page—8,

in Boundary Description—,

(a) in line C2-D-D1-D2-3D for "3D" read "D3".;

(b) in line D15-D16—for "835" read "838" and for "Soldiand" read "Soldia and".

Any person interested in any land in respect of which the above corrigendum has been issued may, within thirty days of the issue of this notification object to the acquisition of the whole or any part of the said land, or of any rights in or over such land in terms of sub-section (1) of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957).

[No. 19|37|83-CL|CA]

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1986

का.आ. 792.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की सम्भावना है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी-1(ई) III/ईआर/303-1085 तारीख 11 अक्तूबर, 1985 का निरीक्षण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व अनुभाग), कोयला एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001 के कार्यालय में या कलक्टर, शहडोल (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में— अथवा कोयला नियंत्रक, 1-काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोयला एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001 को भेजेगा।

अनुसूची

बटुरा ब्लाक

सोहागपुर कोयला क्षेत्र

जिला शहडोल (मध्य प्रदेश)

(पूर्वेक्षण के लिए वर्णित भूमि)

क्रम सं.	ग्राम	साधारण सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1.	साको	963	सोहागपुर	शहडोल	54.348	भाग
2.	बकहो	369	सोहागपुर	शहडोल	177.021	भाग
3.	बकही	639	अनुपपुर	शहडोल	556.290	भाग
4.	चाका	289	सोहागपुर	शहडोल	240.474	भाग
5.	खमरौंध	179	सोहागपुर	शहडोल	53.995	भाग
6.	बटुरा	649	सोहागपुर	शहडोल	446.408	भाग
7.	बिछिया	716	सोहागपुर	शहडोल	404.057	भाग

कुल क्षेत्र : 1932.593 हैक्टर (लगभग)
या 4775.54 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :

क–ख रेखा बिन्दु "क" से आरम्भ होती है और साको ग्राम से होकर गुजरती है, फिर नदी को पार करती है और चाका, खमरौ बिछिया ग्रामों से होकर जाती है और खैरबाना और बिछिया ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख–ग रेखा बिछीया ग्राम से होकर जाती है फिर बटुरा और रामपुर ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग–घ रेखा बटुरा ग्राम से होकर जाती है, सोन नदी को पार करती है, फिर बकही, बकहो ग्रामों से होकर जाती है और बकहो ग्राम में बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ–क रेखा बकहो ग्राम से होकर जाती है, फिर साको ग्राम से होकर जाती है और उसी ग्राम में आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं. 43015/29/85-सी.ए.]

टी.सी.ए. श्रीनिवासन, निदेशक

New Delhi, the 12th February, 1986

S.O. 792.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan bearing No. C-1(E) III/ER/303-1085 dated the 11th October, 1985 of the area covered/by this notification can be inspected at the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 or at the Office of the Collector, Shabdol (Madhya Pradesh) or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited, Coal Estate Civil Lines, Nagpur-440001 within ninety days from the date of publication of this notification.

THE SCHEDULE

BATURA BLOCK

SOHAGPUR COALFIELD

DISTRICT SHAHDOL (MADHYA PRADESH)

(Lands notified for prospecting)

Serial Number	Village	General Number	Tehsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Sako	963	Sohagpur	Shahdol	54.348	Part
2.	Bakho	369	Sohagpur	Shahdol	177.021	Part
3.	Bakhi	639	Anuppur	Shahdol	556.290	Part
4.	Chaka	289	Sohagpur	Shahdol	240.474	Part
5.	Khamraudh	179	Sohagpur	Shahdol	53.995	Part
6.	Batura	649	Sohagpur	Shahdol	446.408	Part
7.	Bichhia	716	Sohagpur	Shahdol	404.057	Part

Total Area : 1932.593 hectares (approximately)
or 4775.54 acres (approximately)

Boundary description :

A-B lines starts point 'A' and passes through village Sabo, then crosses Sone River and proceeds through villages Chaka, Khamraudh, Bichhia and meets on the common boundary of villages Khairbana and Bichhia at point 'B'.

B-C Line passes through village Bichhia, then proceeds along the common boundary of villages Batura and Rampur and meets at point 'C'.

C-D Line passes through villages Batura, crosses Sone River, then proceeds through villages Bakhi, Bakho and meets in village Bakho at point 'D'.

D-A Line passes through village Bakho then proceeds through village Sabo and meets in the same village at starting point 'A'.

[No. 43015|29|85-CA]

T. C. A. SRINIVASAN, Director

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1986

का.आ. 793—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में		विवरण
झांसी	मोठ	मोठ	सरेगा	238	0	02	
				327	0	20	

[सं. O-14016/5/84-जी पी]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 19th February, 1986

S.O. 793.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplementary Notification u/s 3(1) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Sarsa	238	0 02	
				327	0 20	

[No. O-14016/5/84-GP]

का.आ. 794—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में		विवरण
झांसी	मोठ	कोंच	खेड़ा बेड़ा	3	0	03	

[सं. O-14016/32/84-जी पी]

S.O. 794.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplimentry notification u/s 3(1) H.B.J. Pipe Line

Distt.	Tahsil	Pargana	Village	Plot no.	Area in acres	Remarks
Jhalaun	Konch	Konch	Khembera	3	0-03	

[No. O-14016/32/84-GP]

का.आ. 795.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में	विवरण
झांसी	झांसी	झांसी	डंगर-वाहा	932	0-12	
				949	0-03	
				1148	0-10	
				1461	0-04	

[सं. O-14016/37/84-जी पी]

S.O. .—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplimentry Notification U/s 3(1) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Dangirwahi	932	0-12	
				949	0-03	
				1148	0-10	
				1461	0-04	

[No. O-14016/37/84-GP]

का.आ. 796.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226 020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा सं	लिया गया रकबा	विवरण
इटावा	औरैय्या	औरैय्या	अनेपुर	260	0-20	

[सं. G-14016/49/84-जीपी]

S.O. 796.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Barreily-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Pargana	Tahsil	Village	Plot No.	Area in acquired	Remarks
Etawah	Auriya	Auriya	Ane Pur	260	0—20	

[No O-14016/49/84-GP]

का.आ. 797.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में	विवरण
झांसी	मोठ	मोठ	एरा	316	0.02	

[सं. O-14016/63/84-जी पी]

S.O. 797.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplementary Notification u/s 3(1) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Aira	316	09 02	

[No. O-14016/63/84-GP]

का.आ. 798.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	झांसी	झांसी	रकबा	123	0.20	
				150	0.22	
				155	0.11	
				684	0.29	
				124	0.02	
				379	0.02	
				522	0.62	

[सं. O-14016/66/84-जी पी]

S.O. 798.—Whereas its appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareilly to Jugdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project, B-58|B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplimentary Notification u/s 3(1) M.B.J. Gas Pip Line Project

District	Tahsil	pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Rakra	123	0—20	
				150	0—22	
				155	0—11	
				684	0—29	
				124	0—02	
				379	0—02	
				522	0—62	

[No. O-14016/66/84-GP]

का.आ. 799.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत. अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में	विवरण
झांसी	झांसी	झांसी	राजापुर	484	0 19	

[सं. O-14016/67/84-जीपी]

S.O. 799.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplimentary Notification u/s 3(1) M.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Rajapur	484	0.19	

[No. O-14016/67/84-GP]

का. आ. 800.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में	विवरण
झांसी	मोंठ	मोंठ	इमलिया रहेट	121	0-02	

[सं. O-14016/68/84-जी पी]

S.O. 800.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplementary notification u/s 3(1) H.B.J. Gas Pipe Line

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
Jhansi	Moth	Moth	Imaliya Estate	121	0—02	

[No. O-14016/68/84-GP]

का. आ. 801 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1662 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं. संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्र एकड़ में	विवरण
झांसी	कोंच	कोंच	गोरा कानपुर	1	0 —03	

[सं. O-14016/82/84-जी.पी]

S.O. 801.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may; within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplementary notification u/s 3(1) H.B.J. Gas Pipe Lines.

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
Jhansi	Konch	Konch	Gora Karanpur	1	0-03	

[No. O-14016/82/84-GP]

का०आ० 802 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम, 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्र (एकड़ में) गाटा सं	विवरण
झांसी	झांसी	झांसी	मिझौना	395 0—04	

[सं० O-14016/175/84-जी०पी०]

S.O. 802.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplementary Notification u/s 3(1) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	area in acres	Remarks
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Mihauna	395	0—04	

[No. O-14016/175/84-GP]

का०आ० 803.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की अपनी आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में	विवरण
जालौन	कोंच	कोंच	खकसीस	709	0-01	
				892	0-01	
				925	0-02	
				239	0-01	
				910	0-12	

[सं० O-14016/177/84-जी०पी०]

S.O. 803.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of htis notifiaction, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplementary notification u/s 3(1) H.B.J. Pipe Line

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhalaun	Konch	Konch	Khaksees	709	0 01	
				892	0 01	
				925	0 02	
				239	0 01	
				910	0 12	

[No. O-14016/177/84-GP]

का०आ० 804.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	अर्जित रकबा (एकड़ में) गाटा सं	विवरण
जालौन	जालौन	जालौन	तातारपुर	117 0–02	

[सं. O-14016/183/84-जी० पी०]

S.O. 804.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplimentarry Notification u/s 3(1) H.B.J. Gas pipe Linep roject

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acers.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Tatarpur	117	0 02	

[No. O-14016/183/84-GP]

का०आ० 805.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेपा करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत. यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	अर्जित रकबा (एकड़ में) गाटा सं	विवरण
जालौन	जालौन	जालौन	गोरा राठौर	245 0–09	

[सं० O-14016/187/84-जी० पी०]

S.O. 805.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government

hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplementary Notification u/s 3(1) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acres	Remarks
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Gora Rathour	245	0—09	

[No. O-14016/187/84-GP]

का०आ० 806.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि०, बी०-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में	विवरण
जालौन	कोंच	कोंच	कियोलारी	253	0-35	
				112	0-03	
				229	0-02	

[फा० O-14016/288/84-जी० पी०]

S.O. 806.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Barcily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project, B-58|B, Aliganj; Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplimentary Notification u/s 3(1) H.B.J. Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acres	Remarks
Jalaun	Konch	Konch	Keonlari	253	0—35	
				112	0—03	
				292	0—02	

[No.O-14016/288/84-GP]

का० आ० 807.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि०, बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में	विवरण
जालौन	कोंच	कोंच	अटा	258	0-01	

[सं०-14016/306/84-जी०पी०]

S.O. 807.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplimentry Notification u/s 3(1) H.B.J. Pipe Line Project

District	Tahsil	Pergana	Village	Plot No.	Area in Acres	Remarks
Jalaun	Konch	Konch	Ata	258	0—01	

[No. O-14016/306/84-GP]

का. आ. 808.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., बी.-58/बी, अलीगंज, लखनऊ 226020,उ. प्र. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा, एकड़ में		विवरण
जालौन	कोंच	कोंच	रैपुरा	31	0	12	—

[सं. O-14016 / 308 /84-जी पी]

S.O. 808.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd; H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplimentory Notification u/s 3(1) H.B.J. Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acres	Remarks
Jalaun	Konch	Konch	Raipura	31	0—12	

[No. O-14016/308/84-GP]

का. आ. 809.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा (एकड़ में)	विवरण
जालौन	कोंच	कोंच	तितरा-परस राम	58	38	

[संख्या O—14016/310/84-जी पी]

S.O. 809.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd.; H.B.J. Pipeline Project, B-58|B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplementry Notification u/s 3(1) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acres	Remarks
Jalaun	Konch	Konch	Titraparsram	58	38	

[No. O-14016/310/84-GP]

का. आ. 810—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजीरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा (एकड़ में)	विवरण
जालौन	जलौन	जालौन	रोमई-मुस्त-किल	754	0—08	

[सं. O-14016/313/84-जी.पी.]

S.O. 810.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd; H.B.J. Pipeline Project, B-58|B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplementary Notification u/s 3(1) H.B.J. Gas Pipe Line

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Romomustkil	754	0-08

[No. O-14016/313/84-GP]

का. आ. 811:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हाजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी. 58/बी, अलीगंज लखनऊ-226020, यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भीकथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा सं.	लिया गया रकबा	अन्य विवरण
इटावा	औरेय्या	औरेय्या	जमुहा	149	0-63	

[स. O-14016/336/84-जी पी]

S.O. 811.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd; H.B.J. Pipeline Project, B-58|B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Barejlly-Jagdesh Pur Pipe Line Project

District	Pargana	Tahsil	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
Etawah	Auriya	Auriya	Jumha	149	0—63	

[No. O-14016/336/84-GP]

का. आ. 812:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: प्रतीत होता है कि लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., बी 58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा (एकड़ में)	विवरण
जालौन	जालौन	जालौन	बघावली विचारा	23	1-02	

[सं. O-14016/410/84-जी. पी.]

S.O. 812.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the

Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplementary Notification u/s 3(1) H.B.J. Pipeline Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Baghawali Divera 23		1—02	

[No. O-14016/410/84-GP

का. आ. 813.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत : पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58 /बी, अलीगंज, लखनऊ 226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	चक नं.	गाटासंख्या	अर्जित रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	4	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	चचकी	594	1182 1169	0 59

[सं.-O 14016-432 / 84 / जी .पी.]

S.O. 813.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Cimpetent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplementry Notification u/s 3(1) H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distlict	Tahsil	Pargana	Village Chuck No.	Plot No.	Area in acres	Remarks
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Chaki Chuck No. 594	1182 1169	0—59	

[No. O-14016/432/84-GP]

का.आ. 814.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच.बी.जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर सोबेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम पायगा; तहसील पिछोर; जिला शिवपुरी; राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	480	0.140
2	479	0.240
3	455	0.030
4	456	0.030
5	478	0.360
6	473	0.070
7	474	0.080
8	475	0.080
9	476	0.110
10	467	0.010
11	468	0.040
12	483	0.030
13	434	0.010
14	600	0.180
15	601	0.010
16	603	0.150
17	604	0.140
18	605	0.030
19	607	0.030
20	608	0.020
21	606	0.030
22	610	0.200
23	615	0.330
24	616	0.030
25	618	0.160
26	620	0.100
27	621	0.440
28	659	0.030
29	943	0.330
30	944	0.010
31	945	0.010
32	629	0.020
33	946	0.170
34	950	0.080
35	951	0.040
36	964	0.240
37	965	0.030
38	956	0.020
39	957	0.030
40	963	0.130
41	1039	0.050
42	962	0.150
43	958	0.020
44	977	0.010
45	917	0.080
46	916	0.030
47	918	0.130
48	919	0.140
49	1010	0.020
50	1011	0.021
51	1012	0.010
52	1013	0.020
53	1015	0.010
54	1071	0.040
55	1072	0.010
56	1040	0.060
57	1041	0.020
58	1044	0.030
59	1045	0.080
60	906	0.010
61	1034	0.030
62	1046	0.080
63	1047	0.020
64	1048	0.060
65	905	0.020
66	907	0.010
67	908	0.073
68	894	0.050
69	896	0.030
70	1066	0.010
71	1067	0.060
72	1068	0.030
73	1069	0.010
74	1070	0.073
75	1163	0.040
76	1164	0.030
77	1101	0.060
78	1102	0.030
79	1103	0.040
80	1093	0.020
81	1094	0.080
82	1095	0.010
83	1097	0.130

1	2	3
84	891	0.010
85	892	0.010
86	893	0.010
87	872	0.070
88	890	0.060
89	1117	0.030
90	1096	0.080
योग कुल क्षेत्रफल		6.427

[सं. O-14016/534/86—ज.पी.]

S.O. 814.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HRJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GASPIPELINE PROJECT

Village Payga, Tehsil : Pichhore, District : Shivpuri (M.P.)

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectares
1	2	3
1.	480	0.140
2.	479	0.240
3.	455	0.030
4.	456	0.030
5.	478	0.360
6.	473	0.070
7.	474	0.080
8.	475	0.080
9.	476	0.110
10.	467	0.010
11.	468	0.040
12.	483	0.030
13.	434	0.010
14.	600	0.180
15.	601	0.010
16.	603	0.150
17.	604	0.140
18.	605	0.030
19.	607	0.030
20.	608	0.020
21.	606	0.030
22.	610	0.200
23.	615	0.303
24.	616	0.030
25.	618	0.160
26.	620	0.100
27.	621	0.440
28.	659	0.030
29.	943	0.330
30.	944	0.010
31.	945	0.010
32.	629	0.070
33.	946	0.170
34.	950	0.080
35.	951	0.040
36.	964	0.240
37.	965	0.030
38.	956	0.020
39.	957	0.030
40.	963	0.130
41.	1039	0.050
42.	962	0.150
43.	958	0.070
44.	977	0.010
45.	917	0.080
46.	916	0.030
47.	918	0.130
48.	919	0.140
49.	1010	0.070
50.	1011	0.071
51.	1012	0.010
52.	1013	0.020
53.	1015	0.010
54.	1071	0.040
55.	1072	0.010
56.	1040	0.060
57.	1041	0.020
58.	1044	0.030
59.	1045	0.080
60.	906	0.010
61.	1034	0.030
62.	1046	0.080
63.	1047	0.070
64.	1048	0.060
65.	905	0.070
66.	907	0.010
67.	908	0.073
68.	894	0.050
69.	896	0.030
70.	1066	0.010
71.	1067	0.060
72.	1068	0.030
73.	1069	0.010
74.	1070	0.073
75.	1163	0.040
76.	1164	0.030
77.	1101	0.060
78.	1102	0.020
79.	1103	0.070
80.	1093	0.020
81.	1094	0.080
82.	1095	0.010
83.	1097	0.130
84.	891	0.010
85.	892	0.010
86.	893	0.010
87.	872	0.070
88.	890	0.060
89.	1117	0.030
90.	1096	0.080
Total Area		6.427

[No. O-14016/534/86-GP]

का.आ. 815—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिय पाइप लाइन गैस अथारिटि आफ इंडिया द्वारा बिछाई जानी चाहिय।

और, यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिय एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) क धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने क लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच० बी० जे० पाईप लाईन 45, सुभाष नगर, सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख स 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत।

अनुसूची

एच.बी.जे.गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : बेलाखेड़ा; तहसील : महिदपूर; जिला : उज्जैन; राज्य : (मध्य प्रदेश

अनुक्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1	83	0.160
2	94	0.180
3	85	0.200
4	86	0.080
5	87/1	0.120
6	71	0.110
7	73	0.020
8	74	0.440
9	90	0.180
10	91	0.020
11	95	0.005
12	96	0.500
13	103	0.170
14	103/2	0.100
15	—108/5	0.230
16	—108/6	0.280
17	—108/3	0.240
18	—107/3	0.140
19	—109	0.020
20	—115/1	0.300
21	—168/1	0.240
22	—116	0.150
23	—167/4	0.240
24	—167/5	0.280
25	—167/1/1/2	0.180
26	—167/1/1	0.200
27	167/2	0.060
28	167/3	—
29	164	0.010
30	165	0.010
31	175	0.060
32	176	0.050
33	177	0.130
34	178	0.040
35	179	0.320
36	188	0.010
37	189	0.240
38	190	0.330
39	186/2	0.010
40	191	0.010
41	192	0.450
42	197	0.005
43	107/1	0.100
44	72/1	0.250
45	72/2	0.160
46	108/4/2	0.050
योग : कुल क्षेत्रफल		7.090

[सं.O-14016/535/86-जीप.]

S.O. 815.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village : Belakheda Tehsil : Mahidpur District : Ujjain State M.P.

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectares
1	2	3
1.	83	0.160
2.	84	0.180
3.	85	0.200
4.	86	0.080
5.	87/1	0.120
6.	71	0.110
7.	73	0.020

1	2	3
8.	74	0.440
9.	90	0.180
10.	91	0.020
11.	95	0.005
12.	96	0.500
13.	103	0.170
14.	—102/2	0.100
15.	—108/5	0.230
16.	—108/6	0.280
17.	—108/3	0.240
18.	—107/3	0.140
19.	—109	0.0 0
20.	—115/1	0.300
21.	—168/1	0.240
22.	—116/	0.150
23.	—167/4	0.240
24.	—167/5	0.280
25.	—167/1/1/2	0.180
26.	—167/1/1	0.200
27.	167/2	0.060
28.	167/3	—
29.	164	0.020
30.	165	0.020
31.	175	0.060
32.	176	0 050
33.	177	0.1 0
34.	178	0.040
35.	179	0.370
36.	188	0 010
37.	189	0.240
38.	190	0.330
39.	186/2	0.010
40.	191	0 010
41.	19?	0.450
42.	197	0 005
43.	107/1	0.100
44.	7?/1	0.250
45.	7?/2	0.160
46.	108/4/2	0.050
	Total Area	7.090

[No. O-14016/535/86-GP]

का.आ. 816.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच.बी.जे. पाइप लाइन 45, सुभाषनगर सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 जो इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत।

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : केसर बड़ी; तहसील : पेटलावद; जिला : झाबुआ; राज्य : (मध्यप्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	560	0.010
2.	562	0.010
3.	684	3.320
4.	680	0.110
5.	670	0.100
6.	675	0.218
7.	677	0.520
8.	731	0.130
योग : कुल क्षेत्रफल		4.418

[सं. O-14016/536/86-जी पी]

S.O. 816.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in teh land described in the Schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village : Kesar Bardi Tehsil : Petlawad Distt. : Jhabua State M.P.

SCHEDULE

S. No.	Khasra No.	Area to be acquired for R.O.U. (In Hectares)
1.	560	0 010
2.	562	0.010
3.	684	3.320
4.	680	0.110
5.	679	0 100
6.	675	0.218
7.	677	0 5 0
8.	731	0 130
	Total Area	4.418

[No. O-14016/536/86-GP]

का.आ. 817.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में उमेराट से हजीरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, हजीरा प्रोजेक्ट, 60, सुभाष नगर सोसायटी, घोडदोड रोड, सूरत को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

उमराट से हजीरा तक पाइप-लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात; जिला : सूरत; तालुक : चोरासी

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
भाटपोर	333	0	68	80

[सं. ओ-14016/543/86-जीपी]

S.O. 817.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ubharat to Hazira in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Hazira Project, 'Prahar" 60, Subhash Nagar Society, Ghod-Dod Road, Surat.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM UBHARAT TO HAZIRA

State : Gujarat District : Surat Taluka : Chorasi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Bhatpore	333	0	68	80

[No. O-14016/543/86-GP

का. आ. 818.— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी–58 बी, अलीगंज लखनऊ–226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकम एकड़ में	विवरण
झांसी	झांसी	झांसी	बछौनी	502	0–22	
				553/2	0–12	
				1106	0–01	

[सं. O–12016/96/84–ओ एन जी–डी 4]

S.O. 818.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bariely to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplementary Notification U/S. 3(i)H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Bachauni	502	0—22	
				553/2	0—12	
				1106	0—01	

[No. O-12 016/96/84-ONG-D 4]

का.आ. 819:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि उत्तर-प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) 1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58 बी अलीगंज लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में	विवरण
झांसी	झांसी	झांसी	पनावली कला	2510	0-07	
				2598	0-11	
				2566	0-04	
				2617	0-02	
				2618	0-50	

[सं. O-12016/96/84- ओ एन जी- डी4)

S.O. 819.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroluem from Hajra-Bariely to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Supplementary Notification U/s 3(i) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Punavali Kala	2566	0—04	
				2617	0—02	
				2618	0—50	
				2510	0—07	
				2598	0—11	

[No. O-12016/96/84-ONG-D4]

का.आ. 820:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58 बी अलीगंज लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा – बरेली- जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा एकड़ में	विवरण
जालौन	कोंच	कोंच	भदेवरा	329	0-01	
				99	0-02	
				100	0-03	
				405	0-03	
				335	0-03	
				49	0-02	
				380	0-72	

[सं. O-14016/113/114/85-जी पी]

S.O. 820.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroluem from Hajra-Bariely to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucgknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Supplementary Notification U/S 3(1) H.B.J. Pipe Line

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhaluan	Konch	Konch	Bhadowara	329	0—01	
				99	0—02	
				100	0—03	
				405	0—03	
				335	0—03	
				49	0—02	
				380	0—72	

[No. O-14016/113/114/85-GP]

का. आ. 821:—यत: भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खंड 6 के उपखंड (1) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यपन स्थल सं. उभराट से हजीरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 31-8-85 से समाप्त कर दिया गया है।

अत: अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम 1963 के नियम 4 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समापन की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

उभराट से हजीरा तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का.आ.सं.	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम	भ.मपोर, तह० चोरासी जिला० सूरत	94	224.4.84	31.8.85

प्र. टा. खेंगार, गुजरात सूरत और वलसाड जिला के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

[सं. O-12016/116/83 प्रोड/जी. पी]

एम०एस० श्रीनिवासन, निदेशक/(एन जी)

S.O. 821.—Wehreas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from Ubhrat to Hazira in Gujarat State.

And whreas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 31-8-1985.

Now therefore under Rule 4 of Petroleum Pipelines (Acquisaition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Pipeline from Ubhrat to Hazira

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum	Bhimpore Tal : Chorasi Dist : Surat	942	24-4-84	31-8-85

(P.T. KHENGAR)
Competent Authority under the act for Surat & Varsad Districts in Gujarat State.

[No. 12016/116/83-PROD/GP]
M.S. SRINIVASAN, Director (NG)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17, फरवरी, 1980

का.आ 822:—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची के भाग 1 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से संबंधित क्रम संख्या 24ग के सामने कालम 2,3 और 4 के अधीन मौजूदा प्रविष्टियों के बाद क्रमश: निम्नलिखित और प्रविष्टियां रखी जाए, अर्थात् :—

1	2	3	4
1.	"आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	केवल अगस्त 1985 में हुई परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्राप्त की गई डिग्री।"

[सं. आर -12015/18/85- ए. ई.]
आर. एस. माथुर, अवर सचिव

नोट : भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की द्वितीय अनुसूची को बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया है :—

1. का. आ. सं. 4068 दिनांक 30 नवम्बर, 1979
2. का. आ. सं. 2635 दिनांक 18 सितम्बर, 1980

3. का. आ. सं. 2313 दिनांक 20 अगस्त, 1981
4. का. आ. सं. 2134 दिनांक 22 अगस्त, 1981
5. का. आ. सं. 137 दिनांक 24 दिसम्बर, 1981
6. का. आ. सं. 638 दिनांक 25 जनवरी, 1982
7. का. आ. सं. 661 दिनांक 2 फरवरी, 1982
8. का. आ. सं. 973 दिनांक 20 फरवरी, 1982
9. का. आ. सं. 354(ई) दिनांक 6 मई, 1983
10. का. आ. सं. 3550 दिनांक 5 सितम्बर, 1983
11. का. आ. सं. 804(ई) दिनांक 11 नवम्बर, 1983
12. का. आ. सं. 462(ई) दिनांक 23 जून, 1984
13. का. आ. सं. 1911 दिनांक 17 अप्रैल, 1985
14. का. आ. सं. 2745 दिनांक 29 मई, 1985
15. का. आ. सं. 3404 दिनांक 5 जुलाई, 1985
16. का. आ. सं. 4057 दिनांक 14 अगस्त, 1985
17. का. आ. स. 5603 दिनांक 2 दिसम्बर, 1985
18. का. आ. सं. 5671 दिनांक 5 दिसम्बर, 1985

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th February, 1986

S.O. 822.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In Part I of the said Schedule against serial number 24C relating to the Himachal Pradesh University, Simla, under columns 2, 3 and 4, after the existing entries, the following further entries shall respectively be inserted, namely :—

1	2	3	4
	"Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery	B.A.M.S.	Degree obtained by passing examination held in August 1985 only"

[No. R-12015/18/85-AE]
R. S. MATHUR, Under Secy.

NOTE : The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) has been subsequently amended vide:—

1. S.O. No. 4068, dated the 30th November, 1979.
2. S.O. No. 2635, dated the 18th September, 1980.
3. S.O. No. 2313, dated the 20th August, 1981.
4. S.O. No. 2314, dated the 22nd August, 1981.
5. S.O. No. 137, dated the 24th December, 1981.
6. S.O. No. 638, dated the 25th January, 1982.
7. S.O. No. 661, dated the 2nd February, 1982.
8. S.O. No. 973, dated the 20th February, 1982.
9. S.O. No. 354(E), dated the 6th May, 1983.
10. S.O. No. 3550, dated the 5th September, 1983.
11. S.O. No. 804(E), dated the 11th November, 1983.
12. S.O. No. 462(E), dated the 23rd June, 1984.
13. S.O. No. 1911, dated the 17th April, 1985.
14. S.O. No. 2745, dated the 29th May, 1985.
15. S.O. No. 3404, dated the 5th July, 1985.
16. S.O. No. 4057, dated the 14th August, 1985.
17. S.O. No. 5603, dated the 2nd December, 1985.
18. S.O. No. 5671, dated the 5th December, 1985.

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1986

का. आ. 823.—अतः केन्द्रीय सरकार का नीचे लिखे क्षेत्रों के बारे में दिल्ली की बृहत योजना में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार दिनांक 8-9-84 को नोटिस संख्या एफ. 20(5)/83 एम. पी. के साथ प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) में अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव मांगे गए थे ।

और यतः उक्त संशोधन के बारे में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा दिल्ली की बृहत योजना में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन :

"गांव जफरपुर के समीप और गांव उजवा को जाने वाली सड़क के उत्तर में स्थित लगभग 7.9 हैक्ट. (19.5 एकड़) क्षेत्र का भूमि उपयोग ग्रामीण उपयोग जोन/'कृषि हरित' पट्टी से बदलकर 'सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं' (अस्पताल) में किया जाता है ।"

[संख्या के 13011/12/78-डी. डी. 1 (ए)/IIए]
एच. के. घोष, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 6th February, 1986

S.O. 823.—Whereas cectarin modification, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 20(5)/83-MP dated 8th September, 1984 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice ;

And whereas no objections or suggestions have been received with regard to the aforesaid modifications ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely :—

MODIFICATIONS

"The land use of an area measuring about 7.9 Hectares (19.5 acres) located near village Zaffarpur and situated on the north of road leading to village Ujwa, is changed from 'Rural Use' Zone/'Agricultural Green Belt' to 'Public and Semi-public facilties' (Hospital)."

[No. K-13011/12/78-DDI(A)/IIA]
H. K. GHOSH. Desk Officer

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1986

का. आ. 824.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, इलाहाबाद बैंक लखनऊ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है ।

MINISTRY OF LABOUR

(Department of Labour)

New Delhi, the 3rd February, 1986

S.O. 824.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Allahabad Bank, Lucknow and their workmen.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, KANPUR

I.D. No. 211/84

Reference No. L-12012/94/D-II(A)

Dated 15th November, 1984

In the matter of dispute between

Shri Shitla Prasad C/o General Secretary U.P. Bank Employees Union, 165, Sobatiabagh, Allahabad.

AND

The Deputy General Manager, Allahabad Bank Hazaratganj, Lucknow.

APPEARANCE :

Shri V. N. Sekhari—for the workman.

Shri M. K. Verma—for the management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/94/84/D. II(A) dated 15th November, 1984, has referred the following dispute for adjudication :

> Whether the action of the management of Allahabad Bank Lucknow in relation to their Baraundha branch District Mirzapur in terminating the services of Shri Shitla Prasad Ex-peon-cum-Farrash with effect from 30th April, 1982 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

2. The case of the workman is that he worked for 373 days as temporary peon-cum-farrash at Baraundha branch of the management bank in District Mirzapur and was terminated w.e.f. 30th April, 1982 without assigning any reason in utter disregard of the provisions of the I.D. Act. It is further alleged that the workman belongs to scheduled caste and was sponsored b ythe employment exchange Mirzapur in clear vacancy of full time peon-cum-farrash at Baraundha branch of the bank in response to the banks letter dated 10th January, 1981. The workman has completed 373 days of work during the period from 12th January, 1981 to 30th April, 1982 out of which he has completed 294 in 12 consequtive months on or before his termination w.e.f. 30th April, 1982. That the workman was not given any appointment letter under para 495 of the Sastri Award and that he was also not given any termination letter under para 522(5) of the Sastri Award. It is further alleged that the workman was retrenched with effect from 30th April, 1982 and no retrenchment compensation was paid to the workman. It is further alleged by the workman that the bank has adopted unfair labour practice and denied the genuine claim of the workman for permanent employment in subordinate cadre i.e. peon because of their policy of hire and fire. In the end the workman has requested for his reinstatement in service with full back wages.

3. The bank management has contested the claim of the workman on the ground that the workman has never raised any demand what so ever with the bank and as such there was no occasion for the management of the bank to turn down the demand; that the reference order is bad in law as the subject matter of dispute does not come within the meaning of industrial dispute and that the rest of the paras of the claim statement of the workman have been denied by the management and in the end the management has requested to reject the claim of the workman.

4. Rejoinder to the written statement has been filed by the workman. The workman has averred that according to the banks own certificate dated 8th July, 1982 the workman worked for 300 days in 1981 and 73 days in 1982 i.e. total 373 days as full time peon-cum-farrash at Baraundha branch of the bank management.

5. Affidavit of Shri M. K. Verma dated 24th September, 1985 is on record on behalf of the bank management and 24th October, 1985 was fixed for cross of the management witness in this case. On 24th October, 1985 counsel for the parties were present. Management representative moved an application for filing a settlement in this case hence the case was adjourned to 25th November, 1985 for filing settlement. On 25th November, 1985 parties filed settlement duly verified by the representative for the workman Shri V. .N. Sekhar and Shri Rajiv for the management. The settlement is dated 25th November, 1985 and reads as follows :

1. It is agreed that the workman concerned Sri Shitla Prasad will be absorbed with prospective date here after in the permanent vacancy of peon-cum-farrash in terms of settlement dated 13th May, 1982 arrived at between the management of Allahabad Bank and All India Allahabad Bank Employees Coordination Committee.
2. It is further agreed that the workman concerned said Shri Shitla Prasad voluntary relinquishes his claim of back wages, dues of past services or any right or claim or any benefits connected with past services under this reference.
3. It is further agreed that Shri Shitla Prasad will submit bank's printed application from duly completed seeking permanent employment in the banks service in the cadre of peon-cum-farrash within a week of this settlement.
4. It is further agreed that Shri Shitla Prasad will be absorbed as aforesaid within 20 days of submission of duly completed banks printed application.
5. Thus this fully and finally resolves the entire dispute, in reference No. 211/84.

It is also prayed by the parties in the terms of settlement that the award be given in the light of the terms of setlement.

As the parties have filed settlement in the instant case and the management has agreed to absorb the workman in service according to the terms of settlement, hence there remains no dispute between the parties.

7. I, therefore, give my award in the light of terms of settlement holding that the workman will be absorbed in the service within 20 days after submitting application to the management.

8. I, therefore, give my award accordingly.

9. Let six copies of this award be sent to the government for publication.

Dated : 16-1-1986.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012/94/84-D.II(A)]

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1986

का. आ. 825.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, इलाहाबाद बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-2-86 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 18th February, 1986

S.O. 825.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Allahabad Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th February, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Reference No. L-12012|26|84-D-II(A) dt. 19-7-84

Industrial Dispute No. 193|1984.

In the matter of Dispute between :

Shri Manoj Kumar C|o Shri P. N. Tewari 165 Sobbatia Bagh Allahabad.

AND

The Dy. General Manager, Allahabad Bank, Hazaratganj, Lucknow.

APPEARANCE :

Shri V. N. Sekhari and Shri P. N. Tewari for the workman.

Shri Rajeev and Shri M. K. Verma—for the Management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012|26|84-D-II(A) dt. 19-7-84 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal;

Whether the action of the management of Allahabad Bank in relation to their Hindi Sahitya Samellan Branch, Allahabad interminating the services of Shri Manoj Kumar, Peon-cum-Farrash w.e.f. 24-12-82 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

2. The case of the workman is that he was appointed in the bank management on 27th January, 1982 and was terminated by the bank on 24th December, 1982 and during the span the workman has completed more than 240 days work. It is further averred by the applicant that he was neither given appointment letter nor termination letter. At the time of termination the applicant was also not given notice, notice pay or retrenchment compensation. The workman has further averred that the bank management has not maintained the register of casual workman, thus the bank management has violated the provisions of section 25 FG and H and also the provisions of Sastri Award and in the end the workman has prayed for his reinstatement with full back wages.

3. The bank management has contested the claim of the workman on the ground that he never raised any demand with the bank and as such there was no occasion for the management to turn down the demand of the workman. That the workman was engaged as casual labour on daily basis, therefore section 25F of the ID Act has no relevancy in this case and it is consequently prayed the claim of the applicant be dismissed.

3. The workman has filed rejoinder to this written statement of the bank management and has reiterated his earlier contention as is alleged in the claim statement.

4. In the instant case after the close of the cross of the management witness the case was fixed for affidavit evidence of the workman on 25-11-1985 and on that date parties to the case filed settlement in this case and requested that the case be decided in terms of settlement. The settlement is dated 25-11-85 and is duly verified by the parties representatives which run down as under;

1. It is agreed that the workman concerned Shri Manoj Kumar will be absorbed with perspective date hereafter in the permanent vacancy of peon-cum-farrash in terms of settlement dated 13-5-82 arrived at between the management of Allahabad Bank and All India Bank Employees Co-ordination Committee.

2. It is further agreed that the workman concerned Shri Manoj Kumar voluntarily relinquishes his claim of back wages dues of past services or any right or claim or any benefits connected with past services under this reference.

3. It is further agreed that Shri Manoj Kumar will submit bank's printed application form duly completed seeking permanent employment in the bank's service in the cadre of peon-cum-farrash within a week of this settlement.

4. It is further agreed that Shri Manoj Kumar will be absorbed as aforesaid within 20 days of submission of duly completed banks printed application.

5. Thus this fully and finally resolves the entire dispute, in reference No. 193|84.

6. Taking into consideration, the terms of settlement dated 25-11-85, duly verified by the parties and also considering their request to decide the case in terms of the settlement, I therefore, give my award holding that the concerned workman will be absorbed in the service of the bank management on the terms laid down in settlement.

7. I, therefore, give my award accordingly.

Dated : 28th January, 1986

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012(26)|84-D.II(A)]

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1986

का. आ. 826.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती, जो केन्द्रीय सरकार को 4-2-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 19th February, 1986

S.O. 826.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th February, 1986.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL-TRIBUNAL-CUM-

LABOUR COURT, KANPUR

Reference No. L-12012|122|81-D-II(A) dt. 2nd Dec. 1981

Industrial Dispute No. 184 of 1981

Name of the workman.—Shri Uma Shanker.

Name of the Industry.—Union Bank of India.

STATE : UTTAR PRADESH

APPEARANCE :

Shri V. N. Sekhari — for the workman, 36|1 Kailash Mandir, Kanpur.

Shri Satya Pal—for the management, AGM, Union Bank of India, Zonal Office, Clark Awadh Hotel Hazaratganj, Lucknow.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour Vide its notification no. L-12012|133|81. D-II(A) dt. 2nd December, 1981 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication;

Whether the action of the Management of Union Bank Of India, in not absorbing Shri Uma Shanker on the post of sub staff and terminating his services from 19-7-80 (AM) is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

2. The case on behalf of workman Shri Uma Shanker is that he entered in the management bank as sub staff on 10-11-79 and continued to work till 19-7-80 with artificial breaks when his services were terminated. Thus the actual service rendered by him as follows;

10-11-79 to 1-2-80	-84 days
3-7-80 to 31-5-80	-90 days
5-6-80 to 15-6-80	-11 days
23-6-80 to 19-7-80	-27 days

Thus the workman in all had worked for 212 days. It is averred that he worked against a permanent vacancy, that the workman was not given any appointment letter or termination letter violating the provisions of paras 495 and 522 of Sastri Award. As regards payment for the services rendered by the workman it is averred that the workman was paid at the rate of basic wage of Rs. 116 per month for the period 10-11-79 to 1-2-80 and from 3-3-80 to 1-5-80 but for the remaining period it is alleged that from 5-6-80 to 15-6-80 and again from 23-6-80 to 19-7-80 he was paid at the rate of Rs. 5 per day as daily rated workman. It is further averred that on retrenchment of the workman fresh hands were appointed by the bank management thus violating the provisions of section 25 of the I.D. Act and that persons appointed after the termination of workman were regularised and absorbed in permanent service of the bank management and in this way the workman was discriminated and denied permanent absorption. In the circumstances the termination of the workman illegal, unreasonable and the workman be reinstated in service with full back wages.

3. The management admits that the workman worked for 83 days from 10-11-79 to 31-1-80 and not till 1-2-80 and from 3-3-80 to 31-5-80 for 90 days but for the rest of the period it is alleged that the workman was water boy on daily wages for 38 days for which he was paid at the rate of Rs. 5 per day. The management, however, admits that concerned workman was appointed purely on temporary basis for 173 days against temporary vacancy and not against permanent vacancy as alleged. The management has denied that any provision of paras 495 and 522 of Sastri Award was violated and it is further alleged that no violation of section 25 G and H is being committed and thus the termination of the workman has been legal and justified

4. In the rejoinder it was urged on behalf of the workman that deliberate artificial breaks to the workman were given in the service to deprive him benefits of continuous service. It was further averred that the work of water boy is also a work of sub staff and hence continue that period also service rendered as sub staff is valid and justified. It is further averred that it was the practice of the respondent bank to appoint a person for a short duration terminating his services without any reason and appoint another person. It has been pleased that after the termination of the workman on 1-2-80 one Kare Deen was appointed who continued to work till 2-3-80 and then again that Kare Deen was terminated and Uma Shanker was appointed on 3-3-80 and continued till 31-5-80 and on termination of the workman on 31-5-80 one Jagat Chaterjee was engaged on daily rate for four days i.e. 1-6-80 to 4-6-80 and from 5-6-80 workman was appointed who continued till 15-6-80 and from 16-6-80 to 22-6-80 one Rajendra Kumar was appointed and from 26-6-80 to 19-7-80 the workman was again appointed who continued till 19-7-80 and thereafter in place of workman Shri Uma Shanker several other persons were appointed and that junior to the workman were continued in service of the bank management even after his termination. In the end it is averred that there was a need of permanent sub staff and after the termination of the workman Shri Uma Shanker fresh hands were recruited and who eventually absorbed in the services of the bank and thus the bank has violated the provision of section 25 G and H of the I.D.. Act.

5. In support of its contention the management has filed affidavit evidence of Shri S. L. Verma Manager Personnel and Industrial Relation of the bank's Zonal Office at Lucknow. He admitted that the temporary appointment of the workman for 173 days in two spells was on the basis of joint appointment and termination letter and again admits that the workman worked for 38 days as daily rated worker at the rate of Rs. 5 per day. In cross examination the witness admits that one Shri Ajit Singh temporary workman was taken in banks service through regular process of recruitment as fresh hand and that he has no knowledge if he is working with the workman. He further admits that there is no test for recruitment of sub staff only their names have to be sponsored from the local employment exchange and they are interviewed on that basis. He has denied to have any knowledge as to who was appointed after the termination of the workman. He has no knowledge if one Tapeshwari Yadav temporary peon appointed on 1-7-80 and was allowed to continue even after the service of the workman was continued. He has denied that the workman was doing other duties of banks peon. He has expressed his ignorance that Kare Deen, Shesh Narain and others who were junior to the workman were regularised. The witness further admits that the bank had opened new branches after the termination of the workman and that persons who have worked more than 90 days and 240 days were regularised. He has no knowledge if any register of temporary employee was mainatined in the branch or any service book is maintained for them.

6. On the other hand, the workman has given his affidavit evidence and testified his case of the claim statement and rejoinder. He denied that the appointment letter for the entire period was given to him and also that no termination letter was given to him for the period and that he did not work in any leave vacancy. He has named one Jagat Chaterjee and several others who were temporary like him and later they were made permanent. The workman has further averred that in view of agreement dt. 19-12-78 that temporary workman who have worked between 90 to 240 days will be considered on merits of each case, were absorbed in permanent service of the bank management. He has averred that beside working as water boy he also performed other duties of sub staff and that dispite opening of new branches and his application subsequent to his termination he was not given appointment hence he raised industrial dispute.

7. In cross examination he deposes that he was given appointment letter few days after his appointment and in all he got one appointment letter. He admits that his initial appointment was temporary. He further admits that during his tensure no one was appointment as permanent. In the end he has admitted that after July 80 he is working privately and getting Rs. 300 per month.

8. The workman has admitted having received the first appointment letter which has been proved by the management witness and is Annexure B of the management's affidavit. In this letter it is specifically written that he was appointed for one month and after 9-12-79 his services will stand automatically terminated without given notice for 14 days. As regards the other appointment letter Ext. Annexure A of the management affidavit, there is oath against oath and nothing has been filed to show that it was really delivered to the workman, thus after the termination of the service of the workman on 31-5-80 he should have been given a termination letter, 14 days notice or notice pay as required under para 522 (4) of the Sastri Award. It is not disputed that the name of the workman was not sponsored from the Employment Exchange. Reference has been made to Banks circular no. 2018 dated 16-11-78, whereby it was notified by the DGM of the bank management that recruitment in sub staff cadre in public sector bank irrespective of the nature and duration of vacancy has to be made only through the employment exchange. Thus it is clear that the workmans appointment could be made only through employment exchange. It has not come in evidence that the appointment of the workman was temporary on any permanent

vacancy. The management should have given 14 days notice on 31-5-80 to the workman before his termination or notice pay when Shri Jagat Chaterjee was engaged at his place. The management has not denied that the Jagat Chaterjee was not appointed after the termination of the workman, if the managemen required temporary hand it should have continued the workman even after 15-6-80 and not appointed Rajendra Kumar from 16-6-80 as averred by the workman in rejoinder's paragraph 4. After having appointed the workman again on 23-6-80 his services could be terminated on 19-7-80 after giving him notice and notice pay but instead of the same management appointed a number of persons junior to him mentioned from Serial B to J in the said paragraph 4 of the rejoinder of the workman and thus contravening the provisions of section 25H of the I.D. Act and retaining Tapeshwari Yadav who was junior to him having appointed him on 1-7-80 and allowing him to continue till 29-7-80, thus the provision of section 25G was also contravened on this count.

9. The work of water boy in the banking industry is one of the job of the sub staff and engaging such sub staff on daily wages of Rs. 5 and not giving them scale rate is also illegal when the work of water boy is a work of continuing nature in the banking industry. Thus in any view of the matter, the appointment of the workman in the first two spells as well as in the later two spells was temporary appointment in the banking industry, his services were terminated without notice or notice pay as required under para 522(4) of the Sastri Award and without complying the provision of section 25G and H of the I.D. Act is illegal.

10. The result is that the workman is entitled to reinstatement in service with full back wages subject to adjustment of earning admittedly made by him during the period.

11. I, therefore, hold that the action of the management of Union of Bank of India, in not absorbing Shri Uma Shanker on the post of sub staff and terminating his services from 19-7-80 (A.M.) is not justified, and is entitled to be reinstated in service as temporary with full back wages.

12. I, therefore, give my award accordingly.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012(133)/81-D-II(B)]

का.आ. 827.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-2-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 827.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th February, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Reference No. L-12012/76/80-D.II(A) dt. 6-11-81.

Industrial Dispute No. 171/1981.

In the matter of dispute between;

Smt. Kamla C/o The Secretary, UP Bank Employees Union 36/1 Kailash Mandir, Kanpur, Uttar Pradesh.

AND

The Assistant General Manager, Union Bank of India, Hotel Clarks Awadh, Hazaratganj, Lucknow.

APPEARANCES :

Shri V. N. Sekhari—for the workman.

Shri Satya Pal—for the Management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/76/80.D-II(A) dt. 6th November, 81, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal;

> Whether the action of Union Bank of India Management, in relation to its Branch at Birhana Road Kanpur in offering only full sleaves woolen sweater worth Rs. 60 by way of winter uniform to Smt. Kamala, full time sweepress since November, 1977 is justified? If not to what relief is the workman concerned entitled?

2. It is common ground that Smt. Kamla is full time sweepress at the management Birhana Road Branch and that till 1977 she was given winter uniform on the same scale as was supplied to the male sweeper of the establishment. That thereafter, the management decided to give only a full sleaves woolen sweater worth Rs. 60 to the full time female sweeper while full winter uniform worth Rs. 210 was given to the other male sweeper of the management bank. Later the limit was raised from Rs. 210 to 275 in the year 77 but the ceiling limit for the female sweepers was fixed at Rs. 60 which discrimination is illegal and obviously affects the service condition of the female sweepers, hence prayer to bring her at par.

3. It is admitted by the management that till January, 1976 the male and female sweepers were supplied uniform worth Rs. 210. That in view of para 17.1 of the Bipartite Settlement it is only laid down that one set of woolen uniform once in three years will be given to sub staff of the management. It was with this view that the management vide its circular dated 4-11-77 decided that the female members of the sub staff will be supplied woolen sweater of full sleaves upto maximum cost of Rs. 60 per sweater and later that limit of Rs. 60 has been raised to Rs. 100. That the management has not made any change in the prices of woolen uniform to the disadvantage of female employees hence there is no question of any notice under section 9A of the ID Act. That in view of para 17.7 of the bipartite settlement no discrimination has been made.

4. In the rejoinder the workman has submitted that at par with the male sub staff who are provided a pair of pant coat and trousers and a cap, the fenate sub staff are also entitled to woollen coat sari blouse and cap or scarf. Further fixing a limit of Rs. 60 for purposes of sweater was illegal and unjustified and there should not be discrimination on that account i.e. on the account of sex.

5. The management has filed six documents i.e. staff circulars of different dates of the bank management regarding uniform ranging from 1960 to February, 1985. The circular dated 14-11-77 prescribed woolen uniform for male comprising of a coat trousers wherein in the case of female only woolen sweater with full sleaves are prescribed. It was also laid down that the cost of the uniform of male may go maximum upto Rs. 275 and in the case of female maximum upto Rs. 60. In circular No. 2787 dated 25-2-75, the rate of woolen uniform for female employee was raised from 100 to 150.

6. The management witness Shri S. L. Verma admitted in cross examination that upto 1976, the amount for uniform for female was Rs. 210 and it was Rs. 210 in the case of male also. It was later in the year 1977, the amount of female uniform was reduced to Rs. 100 whereas the uniform allowance for male members was not reduced. He further admits that in case of male uniform allowance was raised from Rs. 210 to Rs. 275 and he further states that w.e.f. 14-11-77 the limit for winter uniform has been raised to Rs. 300 and in the case of female its maximum limit is Rs. 150. In the end he has admitted that except cost of uniform, the male and female sub staff are allowed same allowances and this discrimination in cost of woolen uniform for female is because of certain tradition in our Indian Society for uniform meant for male and female.

7. After this evidence the workman choose not to lead any evidence and stressed that he should not be indiscriminated no account of sex as laid down in our constitution. If male uniform is provided to male and female both they should be allowed same maximum limit for purpose of winter uniform and in the case of female it should not be indiscriminated that they should only put on full sleaves sweater to a limit of half of that of the male members of their category. This discrimination of the management on the face appears to be unjust. The female members are entitled to purchase proper winter clothings in that maximum limit to save them from incliment weather. If male members of the sub staff are allowed to put on coat trousers and cap as part of the dress the female also can spent that much limit in purchasing proper dress for themselves which comprises of woolen salwar, kammeez, and full sleaves coats or sweater within that amount.

8. In these circumstances, I hold that the action of the management bank in relation to its branch at Birhana Road Kanpur in offering only full sleaves woolen sweater worth Rs. 60 by way of winter uniform to the workman since November, 1977 is not justified. The result is that the management will reimburse her to bring her at par with the male sub staff as regards the amount spent on winter uniform.

9. I, therefore, give my award accordingly.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012(76)|80-D.II(A)]

Dated : 27th January, 1986

का. आ. 828.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-2-86 प्राप्त हुआ था।

S.O. 828.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur and shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th February, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT KANPUR.

Reference No. L-12012|278|82-D.II(A) dt. 6-12-84

Industrial Dispute No. 220 of 1984

In the matter of dispute between :

Shri Mahendra Prakash Clerk Puranpur Branch, C|o The General Secretary, State Bank of India Staff Association (Kanpur Circle) Commercial Exchange Building, 24 Mahatma Gandhi Marg, Hazaratganj, Lucknow.

AND

The Chief General Manager, State Bank of India (Law Department) Halwasiaya Palace, 24, Mahatma Gandhi Marg, Hazaratganj, Lucknow.

APPEARANCE :

Shri V. N. Sekhari, representative—for the workman.
Shri Mahesh Chandra, representative—for the Management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012|278|82-D.II(A), dated 6th November, 1984, has referred the following dispute to this tribunal for adjudication;

Whether the action of the management of State Bank of India, LHO, Lucknow, in terminating the services of Shri Mahendra Prakash Clerk, Puranpur Branch, W.e.f. November, 1979 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?

2. The case of the workman Shri Mahendra Prakash is that he joined the management bank's service on 27-7-68 and was posted at Puranpur Branch (Pilibhit) Branch of the management bank. He was later on confirmed and drew his regular increments till July, 1978. He was later on issued a memo on 22-6-78 by Branch Manager Puranpur. Branch charging him that two bogus entries for Rs. 60 each have been made by him under his authentication when he was officiating as relief sub accountant, resulting an increase of Rs. 120 in the recurring deposit account No. 97 of Shri Sakhawat Ali Khan and afterwards the entire balance was paid by closing the account by himself and thereafter the account of Rs. 120 was credited in the aforesaid account to adjust the irregularity.

3. The workman replied the memo and stated that due to rush of work he failed to recollect as to how the entries in question were authenticated by him. That despite reply the workman was chargesheeted on 13-7-79 to which the workman submitted his reply. The management did not replied that explanation and communicated the workman that one Shri R. P. Sharma was appointed as Enquiry Officer to hold an enquiry in the matter on 20-8-79. Enquiry officer Shri R. P. Sharma visited the bank on 20-8-79 and the branch manager obtained a statement of workman to the effect that the enquiry would be defended by him personally. The E.O. completed the enquiry on the same day i.e. 20-8-79 without affording proper and reasonable opportunity of defence to the workman. E.O. gave his finding on 31-8-79, according to which charges against the workman were said to have been proved. The Bank's Regional Manager vide letter dated 22-9-79 communicated the punishment to the workman as under;

Upon consideration of the enquiry proceedings and the findings of the enquiry officer, I have tentatively decided that you be dismissed from the bank's service without notice. Before, however, I taken a final decision, I give you an opportunity to make further submission within one week of receipt by you of this letter failing which I will conclude that you have nothing to say further in the matter.

The workman replied the Regional Manager but the Regional Manager did not revise the punishment of dismissal and communicated his orders vide letter dated 16-11-79, that the workman preferred an appeal against the dismissal order which was dismissed on 13-3-80. The workman again represented against the dismissal to the Cheif General Manager but the same was not considered, he consequently raised an Industrial Dispute before ALC (Central) and failure of conciliation, the present reference was made by the Government for adjudication.

4. It is alleged that the termination of the workman is illegal and unjust and is liable to be set aside on the following grounds namely; (i) mistake inrouting work can not be treated as misconduct and if it is conceded for the sake of arguments it would be a minor misconduct (ii) workman was not given reasonable opportunity to make defence and enquiry was concluded in hurry in a preplaned and biose manner which enquiry can not be called fair and reasonable; (iii) that the enquiry officer was not properly appointed, (iv) that the explanations of the workman to the charge sheet was not considered and the enquiry was expedited in a preplaned decision to dismiss the workman, (v) that the enquiry officer acted as prosecuting officer and not as independent enquiry officer, (vi) that the enquiry officer himself put questions by way of cross examination and that the relevant material evidence was shut out to the workman and relevant pass book was not produced, (vii) that the findings of the enquiry officer is not based on legal evidence and is simply based on punishment, (viii) that the enquiry officer nor punishing authority nor appellate authority and banks management including Chief General Manager applied their mind and did not consider the submissions made by the workman, hence the punishment of dismissal is illegal. Lastly it is prayed that the enquiry be set aside and he be reinstated in service.

5. The management has admitted his appointment, confirmation and that he was served with a memo and ultimately enquiry officer was appointed who communicated about holding of enquiry but the management, however, denied that the branch manager obtained statement from the workman that he would defend the enquiry personally rather the workman of his own accord opted to defend his enquiry that he was given full opportunity to cross examination the witness and defend his case and as no further time was sought for any further defence, the enquiry was completed on that very day. The management thereafter, admits that the workman after the findings of the enquiry officer punishment of dismissal of service was given to him against which he filed an appeal and the same was rejected.

6. In the rejoinder it was reiterated by the workman that he was not given full and proper opportunity to defend his case.

7. In support of its case, management filed affidavit evidence of Shri V. K. Agrawal an officer of the management bank and dealing with staff matters. He has averred that the workman while working as clerk at material branch received from one Sakhawat Ali Khan a sum of Rs. 60 twice in the year 1978 for deposit in R.D.A|c. No. 97, which amount he embazelled after making fictitious entry in the account of the customers on 2nd May and 7th June, 1978. He also authenticated said entries though he was not empowered to do so. These fictitious entries being recorded in the customers account on maturity on 19th July 1978, he was paid total amount. This act of the workman amounted to gross misconduct for which he was chargesheeted on 13th July, 1979 and in the departmental enquiry charges were fully proved against the workman. On these charges the workman was dismissed by the disciplinary authority on 22nd September, 1979. The workman opted to defend his enquiry himself and was efforded full opportunity to submit his defence. The enquiry proceedings completed the same day after recording the proceedings of the enquiry. The management witness has admitted that the pass book was not produced by the workman through his witness Shri Sakhawat Ali.

8. The management has filed the photo copy of the ledger sheet of Shri Sakhawat Ali to show that in the ledger sheet of Sakhawat Ali two entries of Rs. 60 each were made on 2nd May and 7th June, 1978. It is paper No. Ext-M-1. The management has further filed memo Ext. M-2 whereby workman was informed that during the course of balancing two bogus entries of Rs. 60 which were made under your authentication and that the entire balance including the forged entries were paid to the account holder Shri Sakhawat Ali by closing the account by yourself thereafter amount of Rs. 120 was credited in the aforesaid account to adjust irregularity. The above intention clearly shows your fraudulent intention, please clarify your position. During the enquiry, the workman told the enquiry officer that when he balanced ledger in the month of June this two entries dated 2-5-78 and 7-6-78 were not there in the ledger. On being questioned that as to who made the entries in the ledger by enquiry officer, the workman told him that he made the entries in the ledger with the help of pass book of the account holder. The workman however admitted before the E.O. that he did not officiate as officer Grade II on 2-5-78 and 7-6-78. On being questioned as to why he authenticated these fictitious entries in the relevant dates in the ledger, workman stated that these entries were authenticated by him on 10-7-78 when the account was closed and balance was paid to the account holder. He admitted that these two entries were made by him in the ledger on 10-7-78 as they were appearing in the pass book and that he did not refer the voucher and the day book. On being questioned by E. Officer as to whether he altered the date 12-5-78 to 2-5-78 knowingly and authenticated the cutting when he admits the balancing on 10th July, 1978 the witness stated that it was done in hurry to dispose of party. The workman had taken the plea that he had made entries with the permission of passing officer Shri R. U. Siddiqi. Before the enquiry officer when the workman questioned Shri R. U. Siddiqui suggesting that he made entries with his permission Shri Siddiqi replied that it was totally wrong and as responsible officer he could have allowed such entries with the help of pass book in the ledger. Shri Sakhawat Ali had told before the enquiry officer that he always use to tender the pass book at the counter when ever he deposit the money but some times he used to get money deposited through workman and hand over pass book because transaction at the bank were carried out with great delay.

9. In this case no preliminary issue was pressed and framed hence the question that it was not fair proper stands waived rather the proceedings before the enquiry officer are admitted. It is the case of the workman that at the time of final payments to the account holder Shri Sakhawat Ali on 10-7-78, the entries of 2nd May and 7th July 78 each of Rs. 60 were not in the ledger though those entries were in the pass book and it was on the basis of pass book entry that he scored out 12th and made it to read as 2 so as to read the entry of 2nd May and July when he made entry of 7th June and drew final balance and adding the interest of that day. According to the workman he consulted the branch Manager Mr. Siddiqi who signed the closing voucher and signed the ledger on 10-7-78. On the date of closing balance i.e. 10-7-78 cash was not paid to the account holder Shri Sakhawat Ali but the whole amount was transferred to his saving bank account No. 2895 on 10th July 78 as is evident from the extract of saving bank account Ext. W-1. It was at the time of tallying the ledger on 14-8-78 that the mistake was deducted and the amount of Rs. 120 admittedly not deposited on 2-5-78 and 7-6-78 was paid to the party concerned on 16-8-78 to make good the deficiency which deposite is mentioned in the copy of ledger Ext. M-1.

The workman stated in cross examination that when pass book was brought to him on 10-7-78 the entries of 2-5-78 and 7-6-78 were already authenticated in the pass book by Shri R. U. Siddiqi. The workman has not mentioned this fact in his reply to the memo that the matter was referred for payment on the instruction of branch manager. This was a very material fact which should have been mentioned there. He admits that he is not able to give any reason why he did not mention this fact in the reply. He denied the suggestion that branch manager had not given him any suggestion/instruction. When suggested in cross examination that branch manager had not gave any suggestion to post such a entries the workman stated that it was wrong to say so. He denied the suggestion that he himself had made fictitious entries in the ledger and the pass book and embazelled the amount. Though the account holder Shri Sakhawat Ali appeared before the enquiry Officer he was not produced in this court. The pass book in which the entries of 2-5-78 and 7-6-78 were made and admittedly authenticated under signatures of Shri Siddiqi branch manager has not been produced. Had that been produced it would have been clear as to who authenticated their deposit. The workman says that he summoned the vouchers to verify deposit of Rs. 60 each of 2nd May and 7th June but they were not produced as it was in the strong room. The workman has not shown his bonafide by summoning the register. Be it as it may the fact remains that he made entries in the ledger without any orders in writing of the branch manager and authenticated the entries in the ledger himself instead of branch manager. It is not disputed that at all relevant time the workman was the clerk on recurring deposit counter.

10. The statement of Shri Sakhawat Ali account holder before the enquiry officer that at times he used to leave the money and pass book with the workman and collected it after some times lend support that the entry in the pass book must have been made by him. Had the same been produced showing that it was authenticated by the branch manager Shri Siddiqi it could be said that he is absorbed and the branch manager must have signed the deposit entry after having seen payment voucher. In the absence of payment voucher and the pass book it is difficult to believe the contention of the workman that in the pass book entries were already there duly authenticated and it was on the basis of that and that the verbal permission of branch manager Mr. Siddiqi without referring to the original voucher of payment made entries of dated 2-5-78 and 7-6-78 in the ledger of Rs. 60 each on 10-7-78. It leads to one and only one inference that the workman himself received the money on the relevant dated as per deposition of Shri Sakhawat Ali account holder and the entry was made in the pass book by himself without actual depositing the amount in

the bank by vouchers and when the workman pressed for payment he made fictitous entries in the ledger by scoring out entry of 12th may and taken shelter under the verbal sanction given by branch manager Shri Siddiqi regarding making entries in the ledger of the above two dates and finalising the payments.

11. The workman has failed to show that how prejudice was caused to him during the enquiry, when question of facts are not disputed there is no question of prejudice.

12. The workman has further failed to show that the finding of the enquiry officer is perverse. The test of perversity is that the finding may not be supported by legal evidence. Yet another case of perversity is that when the findings are such which no reasonable person could have arrived on the basis of materials before him. In the instant case it being admitted that the workman was manning the recurring deposit counter on the relevant dates including 2-5-78 and 7-6-78. Further the pass book is not forth coming to show that the entries of 2-5-78 and 7-6-78 were authenticated by branch manager, no voucher of the relevant dates have been summoned to show that actually no amount was deposited by the account holder that day. The account holder Shri Sakhawat Ali in his statement stated that he used to leave money and pass book with the workman and collected it later. The workman's admission that he found the entries of relevant dates i.e. 2-5-78 and 7-6-78 in the pass book and on the basis of same made entries in the ledger himself, after making certain correction in the ledger on 10- -78 under verbal instructions of the branch manager Shri Siddiqi who has denied having given any instruction before the enquiry officer lends to only one and one inference that it was the workman who pocketed the two amounts given by the account holder on 2-5-78 and 7-6-78 about which the entries was there in the pass book and made entries in the ledger on 10-7-78 without verifying the vouchers or without written order from the branch manager or from the passing officer, to my mind, only workman has drawn that entries on the relevant dates and no one else, and received the amount from the account holder on the two relevant dates referred above. It is amply clear that only workman has passed entries of the two amounts and none else as on the relevant time workman was handling the recurring deposit counter.

13. Under these circumstances, it is crystal clear that the workman has pocketed the two amounts of Rs. 60 each on the relevant dates i.e. 2-5-78 and 7-6-78 by making false entries in the ledger without depositing the same. Further the workman himself has closed the account of the account holder Shri Sakhawat Ali on 10-7-78 under his signature after authenticating the entries for which he was not empowered to do so. Thus the workman has failed to prove his case and the management has substantiated his case by cogent and reliable evidence.

14. Thus for the reasons discussed above, I accordingly hold that the action of the management having been terminated the services of the workman on the basis of above enquiry in which there was no question of prejudice is fair and proper and justified.

15. I, therefore, hold that the action of the bank management of State Bank of India LHO Lucknow, in terminating the services of Shri Mahendra Prakash Clerk Puranpur Branch w.e.f. November, 1979, is justified. The result is that the workman is not entitled to get any relief.

16. I, therefore, give my award accordingly.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012(278)/82-D.II (A)]

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1986

का. आ. 829.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-2-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 20th February, 1986

S.O. 829.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure A in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th February, 1986.

ANNEXURE 'A'

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT KANPUR

Reference No. L-12012|129|84-D.II(A) dt. 17-10-1984

Industrial Dispute No. 208 of 1984

In the matter of dispute.

BETWEEN

Shri O. P. Gupta C|o Shri J. C. Dhavan, 8|75 Arya Nagar, Kanpur;

AND

The Regional Manager, Bank of Baroda, Lucknow Region 19 Way Road, Laxmi Tractor Building, Lucknow.

APPEARANCE :

Shri J. C. Dhavan—for the workman.

Shri A. N. Verma—for the management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012|129|84-D.II-A dated 17th October, 1984, has referred the following dispute for adjudication to this tribunal;

> "Whether the action of the management of Bank of Baroda, Lucknow in relation to their Govindganj Branch, Shahjahanpur in terminating the services of Shri O. P. Gupta Accounts-cum-Cash Clerk with effect from 25-1-1984 is justified? If not to what relief is the workman concerned entitled?"

2. It is common ground that the workman applied for appointment as clerk in the management bank while working in Regional Rural Bank Fatehpur. On the basis of interview etc. he was selected for appointment and appointment letter dated 12-3-83 Ext. M-1 was issued to the workman. It was mentioned therein that on accepting the appointment he will be on probation for a period of six months and that it may be extended on its discretion and in the end it was mentioned that if the above terms are acceptable to him he please signify in writing and report for duty at Govindganj branch, Shahjahanpur as early as possible but in case not later than 22 March, 1983. It was further mentioned that please note to bring with you your original certificate of education and character certificate of two respectable persons known to the bank alongwith two copies of each and the relieving certificate of the present employer if employed at present. In consequence of this the workman accepted the offer and joined the management bank on 7-4-83 and submitted the desired certificate as per Ext. M-2. He submitted two character certificates and relieving certificate from the previous employer. It transpires that during his probation period the workman remained absent from duty initially for 9 days for which he was granted leave without pay and he also remained absent for 12 days according to the management this leave was unauthorise, whereas according to the workman he applied for leave as he has to appear in P.C.S. Examination.

3. The management replied that telegram by which workman has extended his leave, on the local address on 10-10-83 per enclosure 6, photo copy of the documents filed with the rejoinder which was to intimate the workman that with reference to his telegram dated 1st and 5th October, sent from Lko., regarding extension of leave upto 12th October,

83, the same will be treated as unauthorised absence and since you have not contacted us we are unable to grant the same.

4. The management vide letter dated 29-9-83 intimated the workman that the relieving certificate required under appointment letter dt. 12-3-1983, by you, was not the one which was submitted on 7-4-83 by you. He was consequently asked to submit a clear relieving certificate after having obtained the same from previous employer positively by 5th October, 1985 failing which your service would be liable to be terminated.

5. Admittedly the workman was on leave from 26-9-83 to 5-10-83 i.e. 9 days leave on loss of pay and also remained unauthorise absent for a further period of 12 days as is admitted in para 5 of the written statement. This letter was sent to the workman at his Kanpur address while there is nothing on record to indicate that he received the same. The management vide letter dated 12-10-83 extended the probation period of the workman for 21 days w.e.f. 7-10-83. It was further mentioned therein that you have not submitted the relieving certificate of previous employer inspite of being given several opportunity vide letter dated 29-9-83 and please submit the same latest by 5-10-83. It was further mentioned that as the submission of the relieving certificate from the post previous employer is one of the terms of the appointment which has not been complied with, it has been decided to extend your probation period for a further period of three months from 28-10-83. It was further mentioned therein that during the extended period of probation your services are liable to be terminated in terms of appointment letter referred above.

6. It appears that the workman joined duties thereafter and worked when vide letter dated 24-1-84, his services were terminated with effect from 25-1-84 admittedly within the probation period and on payment of one month's pay in lieu of notice.

7. It has been aruged that under terms of appointment letter dated 12-3-83, the workman was required to submit relieving certificate from the present employer if employed at present. The workman was not employed when he joined the bank management on 7-4-83. The relieving certificate if employed at present is obtained when a man may not remain in employment at two places on the date of joining the new employment. So there should be a clear indication on the date of joining that he has been relieved by previous employer and the relieving certificate asking the same is produced at the time of joining new assignment. The workman had left the service of the previous employer i.e. Fatehpur Chetriya Gramin Bank w.e.f. 2-4-83 and submitted a certificate to that effect dated, 4-4-83 to the management on the date of joining the service at the management's end i.e. on 7-4-83. This in fact was a relieving certificate of the past employer and nothing more was to be given by the workman. After having joined the services of the management on 7-4-83 his probation was to close on 6-10-83 after completion of six months service. His probation should have been extended or his services should have been terminated within probation period and after completion of six months i.e. probation period, if neither the workman is terminated nor probation period is extended he will be deemed to have been confirmed employee after the expiry of the probation period. Thus the management has no right to extend the probation on 12-10-83 vide Ext. M-3 which is beyond expiry of six months.

8. As observed earlier, the applicant had filed the certificate that he was no more in service of the employer where he is working on 12-3-83, who was his present employer on that date. As on the date of joining his services had been terminated and the certificate filed, that was enough relieving certificate. If the management wanted to treat unauthorised absence as misconduct he should have been served a charge sheet before completion of six months probation and on that count extended the period of probation. No disciplinary action was taken against him. Under para 522(1) the services of a probationer may be terminated by one month's notice or on payment of one month's pay and allowances in lieu of notice. The management was within its right to terminate the service of the workman before completion of six months by giving one month's notice or paying one month pay and this having been done beyond completion of probation period and the same having been not extended within six months of probations he stood confirmed after expiry of the same.

In support of this I may refer Central Bank of India Vs State of Jammu & Kashmir JILLJ 1968 page 646 wherein it was observed thus :

> Dismissal of a probationer bank employee without charge sheet or enquiry before the expiry of probation period. No adverse remark communicated to the employee, Award of Industrial Tribunal holding termination invalid, award held justified.

10. Thus in view of the observation made above and law discussed I hold that the action of the management of Bank of Baroda, Lucknow in relation ot their Govindganj Branch, Shahjahanpur in terminating the services of Shri O. P. Gupta, accounts-cum-cash clerk with effect from 25-1-1984 is not justified.

11. The result is that the workman is entitled to be reinstated in service with full back wages.

12. I, therefore, give my award accordingly.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012(129)|84-D. II(A)]

का.आ. 830.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, इलाहाबाद बैंक, लखनऊ, के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर, के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को, 4-2-86 प्राप्त हुआ था।

S.O. 830.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Allahabad Bank, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th February, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 212/84

In the matter of dispute between :

Shri Vinod Kumar C/o The General Secretary, UP Bank Employees Union 165 Sohbatia Bagh, Allahabad.

AND

The Dy. General Manager, Allahabad Bank, Hazaratganj, Lucknow.

APPEARANCES :

Shri V. N. Sekhari and Shri P. N. Tewari—for the workman.

Shri Rajeev and Shri M. K. Verma—for the Management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/108/84.D-II(A) dt. 19-11-84 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal ;

> Whether the action of the management of Allahabad Bank Lucknow, in relation to their Jasra Branch.

Distt. Allahabad in terminating the services of Shri Vinod Kumar sub-staff with effect from 18-11-82 is justified ? If not to what relief is the workman concerned entitled ?

2. The case of the workman is that he had worked for 262 day under the bank management in twelve consecutive months as temporary peon in Jasra Branch of the management and his services were terminated w.e.f. 18th November, 1982 without assigning any reason in utter disregard of the provisions of industrial laws. It is further averred that the workman was not given any appointment letter or termination letter violating the provisions of para 522(4) of the Sastri Award. The bank has not maintained any record of such employees as regard para 516 of the Sastri Award. That the services of the workman were retrenched on 18-11-82 without any notice and without paying retrenchment compensation as required under section 25F of the I. D. Act. In the end it is averred that the bank has knowingly violated the provisions of Industrial Disputes Act as well as provisions of Sastri Award and it is prayed that the workman be reinstated in banks service with full benefits.

3. The bank management contested the claim of the workman on the ground that the matter of dispute referred to this tribunal is not a dispute much less an industrial dispute inter alia on account that the workman never raised any demand whatsoever with the bank and as such there was no occasion for the management to turn down the demand on or before the workman raised industrial dispute. The bank management has further denied all the contents of the workman made in his claim statement on different counts and prayed that the claim of the workman be rejected.

4. The workman has filed rejoinder reiterating the statements made in his claim statement.

5. Shri L. B. Singh has filed his affidavit evidence in support of management's contention. Witness was also cross-examined on his affidavit. In his cross-examination he has supported the averments of the workman that the provisions of the Sastri Award and bipartite settlement have not been followed in the case of workman. This very fact is clear from his statement wherein he has stated that no register of the temporary employee was kept in the management bank.

6. In this case after the cross of the management witness the case was fixed for affidavit evidence of the workman concerned. On 25th November, 1985 parties filed settlement in this case and the same is as under :—

1. It is agreed that the workman concerned Shri Vinod Kumar will be absorbed with prospective date here after in the permanent vacancy of peon-cum-farrash in terms of settlement dated 13-5-82 arrived at between the management of Allahabad Bank and All India Allahabad Bank Employees Co-ordination Committee.

2. It is further agreed that the workman concerned Shri Vinod Kumar voluntarily relinquishes his claim of back wages, dues of past services or any right or claim of any benefits connected with past services under this reference.

3. It is further agreed that Shri Vinod Kumar will submit banks printed application form duly completed seeking permanent employment in the banks service in the cadre of peon-cum-farrash within a week of this settlement.

4. It is further agreed that Shri Vinod Kumar will be absorbed as aforesaid within 20 days of submission of duly completed banks printed application.

5. Thus this fully and finally resolves the entire dispute. in reference No. 212/84.

6. The settlement which was filed was duly verified by the representatives of the parties concerned and they requested that the dispute be decided in terms of the settlement.

7. I, therefore, taking into consideration the terms of the settlement give my award accordingly.

8. Reference is therefore answered accordingly.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012(108)/84-D-II(A)]

का.आ. 831.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-2-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 831.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th February, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 23 of 1983

In the matter of dispute between :

Shri Jamal Ahmad, C/o The Assistant General Secretary UBBEU, 36/1 Kailash Mandir, Kanpur.

AND

The Assistant General Manager, Union Bank of India Hotel Clarks Awadh, Hazaratganj, Lucknow.

APPEARANCES :

Shri V. N. Sekhari—for the workman.

Shri Satpal—for the management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/390/81-D.II(A), dated 12-10-1982 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the action of the Management of Union Bank of India, in relation to their Civil Line Branch Allahabad in depriving Shri Jamal Ahmad, Ex-Subordinate staff of permanent employment inspite of his having been rated in the select list of such candidates drawn in 1978 is justified ? If not to what relief the said workman is entitled ?

2. The case of the workman is that he first entered in the service of the management bank on leave vacancies and worked there from 74 to 78 in different branches in different spans and thus he completed in all about 495 days work that period i.e. 1974 to 1978. It is further averred that from 17-8-78, 24-6-78 the workman worked continuously 100 days at management's civil line branch. The workman appeared for test by way of interview in 1976 and his name figured in the list of successful candidates and except the workman quite number of successful candidates were absorbed in the service of the bank management. It is further averred that a meeting was held in February 1980 regarding the absorption of the workman who have completed 240/90 days service in the bank. The workman having been completed 100 days continuous service in the management bank was not absorbed by management, thus the bank has violated the provisions of para 20.7 and 20.8 of the bipartite settlement. It is further averred that after the termination of the workman fresh new hands were appointed by the management bank and thus the workman was deprived of by the management in seeking permanent employment inspite of having completed less than 495 days service and that the name of the workman was listed in the successful candidates after their interview. Thus the action of the bank management in not absorbing the workman in service is unreason-

able and illegal. In the end it is prayed that the workman be absorbed in the banks service with full back wages.

3. The management contested the claim of the workman alleging that the matter of dispute has not been spoused by substantial number of workman of the union of the management and that the workman has served the demand notice to the bank management. It is further alleged that the concerned workman has not put in 240 days continuous service under the bank management in the preceding 12 months from the date of his termination. It is further averred that he was occasionaly employed in the service of the bank for a limited period for work which was essentially of a temporary nature and that he was employed temporarily as an additional hand due to temporary increase in work and that he was never appointed against the permanent vacancy. It is further alleged by the management that the name of the concerned workman appeared in the penal of appointment of temporary employees in temporary vacancies and he had never been placed on selected list for appointment or absorption as minimum qualification revised w.e.f. 23-7-76 for class IV i.e. sub-staff cadre came to be 7th standard pass whereas the applicant passed only 5th Class. In the last it is averred that in view of the judgment of S. K. Verma judgment of Supreme Court, the temporary employees can never be at par with permanent employees and they continued to be temporary and liable to be retrenched even if they are reinstated and also that no violation of section 25 G. H. was made as the workman did not passes minimum qualification. Referring to Sudder Workshop of Jorhaut Tea Company of 1980 Supreme Court it is averred that 25G may not be followed if there is valid reason for daviation.

4. I have heard the learned counsel for the parties and have also gone carefully through the records of the case.

5. The workman has substantiated by certificates filed alongwith affidavit and that from 74 to 78 in all he worked for 643 days in three different branches in one unit of Allahabad. He further substantiated that lastly he worked for 113 days in management's civil lines branch in the year 1978. From the above statement and also admissions it is clear that the workman did not complete 240 days in any span of one year though he completed more than 90 days. It is admitted that after interview etc., the workman was placed in the selected list for being appointed as sub-staff in the year 1976. It is admitted that interview was taken for sub-staff on 12-7-76 and the educational qualification for all selected candidates was class V pass. Annexure A to the rejoinder of the workman shows that list of selected candidates was drawn up and put up on notice board on 13-10-76 in which the name of the workman appeared at serial No. 33. It may be mentioned here that mere empanelment will not give the workman any right of being appointed permanently in the bank. Mean while the norms were changed with effect from 23-7-76 as stated by management witness Shri S. L. Verma vide circular No 2018 dated 16-11-78 whereby the qualification for appointment as sub-staff in different branches of the bank was raised to class VIIth pass. The workman did not correspond to this qualification hence he was left out and one Shri Kishan Chandra junior to him whose name appeared at serial no 34 in that list was appointed who satisfied the norms of educational qualification. This circular was issued under the advice of Union Ministry of Finance Department of Foreign Affairs Banking Division.

6. Thus in view of the law laid down in Jorhaut Tea Company Versus Management 1980 Lab I. C. page 742 wherein it was held :

> That section 25-G of the I.D. Act may not be followed if there is a valid reason for daviation.

In the instant case there was justifying reason from daviating from the list of the approved candidates and appointing Shri Kishan Chandra junior to him and ignoring his case on the point of educational qualification.

7. On the point of workman's working in clear permanent vacancy for more than 90 days there should have been a clear pleadings to that effect and specific evidence as to the vacancy was existing showing the permanent strength and that one of such permanent post was lying vacant on which the workman was engaged as temporary hand without reservation. In view of Shanker Chakravorti Versus Britania Biscuits Company 1979 SC LIC page 1192 wherein it was held thus :

> Contention to substantiate which evidence is necessary has to be pleaded.

The burden lay on the workman to show as to where was the permanent vacancy. It is not disputed that the workman was employed for all those period as temporary workman and as an additional hand due to temporary increase in work. Thus merely because of pleading that the workman had put in more than 90 days work, he will not be ome permanent in view of provision of 20.8 of the Bipartite Settlement. As pleaded by the workman his case was considered in the meeting between the Union representatives and the management at banks Central Officer Bombay in May 1980 and the case of the workman was specifically figured and the management agreed to examine his case on the basis of long temporary work ranging from more than 240 days work. As temporary the workman has not worked for more than 240 days in one span of year, he is not entitled to benefit of sec. 25F of the I. D. Act. The workman Kishan Chandra junior to him in the penal had to be given regular appointment as he satisfied the norms and discrimination on that account was proper and there was no question of infringment of section 25G on the point.

8. As regards the averments that four persons namely S/Shri Ram Badan Himmat Ram Bansi Lal and Vijai Prakash Tondon mentioned in annexure B of the rejoinder were appointed who had the same educational qualification and had not completed 240 days of work. The management witness has deposed that they must have been appointed before 23-7-76 when the bar of qualification of 7th pass was not there.

9. The workman has failed to substantiate the date as to when the persons namely Shri Radhika Prasad, Mohd. Aslam. Shrikant and Bhuvanchandra mentioned in para 4 of the workmans rejoinder were appointed and they all were senior to the workman in the penal prepared and if they satisfied the norms and were appointed earlier though their initial appointment later to the workman. The empenalment give them a right of appointment first in clear vanacy so long they responded to the educational qualification and bar has not come, if they were of the same qualification as that of workman. Thus it can not be said that junior to workman were appointed as empenalment placed them on better position for regular absorption.

10. The only infringment to my mind is that the workman was not given notice for termination as required under para 522(4) of the Sastri Award which was mandatory and which makes the termination illegal. Further admittedly so many new branches were opened and if the management had maintained a list of retrenched temporary employees as records under Sastri Award the workman would have get an appointment and as this was not done, the management has infringed the provision of section 25H of the I. D. Act which infringment is also illegal.

11. Thus in view of these circumstances and for the reasons and law discussed above, I hold that the action of the management of Union Bank of India, in relation to their Civil Lines Branch Allahabad indepriving Shri Jamal Ahmad, ex-subordinate staff of permanent employment inspite of his having been rated in the select list of such candidates drawn in 1978 is justified, but his termination as temporary employee in 1978 from the said branch without notice and notice pay being illegal, he has to be reinstated with full back wages.

12. The result is that the workman is reinstated with full back wages as observed in para 11 of this award.

13. I, therefore, give my award accordingly.

[No. L-12012/390/81-D II(A)]

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

का.आ. 8[illegible]—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, एण्ड जयपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच-

अनुबंध में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-2-86 प्राप्त हुआ था।

S.O. 832.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Bikaner & Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th February, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 190 of 1981

BETWEEN

In the matter of dispute

Shri Vishnu Dayal C/o The President U.P. Bank's Karamchari Sangh 26/104 Birhana Road, Kanpur

AND

The Manager, State Bank of Bikaner and Jaipur, 58/45 Birhana Road, Kanpur.

APPEARANCE :

Shri V. N. Sekhari—representative for the workman.

Shri T. N. Tondon—representative for the management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour and Rehabilitation, vide its notification no. L-12012/183/81-D-II (A), dated 18th December, 1981, has referred the following dispute for adjudiaction:

> Whether the action of the Sate Bank of Bikaner and Jaipur Birhana Road, Kanpur, in not absorbing Shri Vishnu Dayal, suboridnate staff in the Bank's service and terminating his services from January, 1979 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entiled?

2. The case of the workman Shri Vishnu Dayal is that he was apopinted as peon in the management bank on 24th January, 1978, and worked in all 245 days upto 2nd January, 1979 when his services were retrenched without any notice and retrenchment compensation. The management did not allow him to work till 24-3-79 when ne was allowed to work as peon for 80 days i.e. 24-3-79 to 11-6-79 and despite the provision of modified award and settlement, the petitioner was not paid regular wages but was paid Rs. 6/- per day as daily rated peon. At the time of alleged retrenchment on 2nd January, 1979, the workman was not paid retrenchment compensation and the mandatory provision of section 25F, G and H of the I.D. Act read with its rules were violated and hence termination is void abinitio. It is further averred by the applicant that after termination of his services fresh hands were employed in the bank. It is also averred that he was doing work of regular permanent nature.

3. The mangement bank has contested the claim of the applicant/workman on the ground that the workman had not completed one years completed service within the meaning of section 25B of the I.D. Act of 1947 and is not entitled to any relief of reinstatement as prayed. The management has emphatically denied that the workman had worked for 245 days in one span of year and that he was legally retrenched without any notice or reterenchment compensation and that as a matter of fact he was on dailv rated workman. At there was no contravention of section 25 of the I.D. Act there was no quesion of paying notice pay or notice and provision of section 25G and H are not attracted. It is further averred that the workman was not entitled to 14 days notice in view of para 522(4) of the Sastri Award in the alternative it is averred that if the claim of the workman is accepted this will violative of the provision of article 14 and 16 of the Indian Constitution in as much as petitioner would get a march over those employees who are seeking employment through prescribed procedure and the very fact that a person works for some time in temporary capacity against a permanent post would not convert into employment in permanent way and that the petitioner was never appointed to fill any permanent post.

4. In the rejoinnder the workman averred that he was entitled to be regularised in service in terms of provision of para 20.8 of the Bipartite Settlement read with para 20.7 and 20.12 of the same.

5. The parties have filed joint inspection note dated 16-5-85 showing that the workman worked for those particular days of 1978 mentioned therein and received payment from the bank management on vouchers or through petty cash register.

6. The management later filed photo copy of voucher showing charges paid to workman concerned for the work done on those particular days mentioned therein. This shows that he worked in August and September, 1977 and then from 30th January, 1978 till 29-8-78 with breaks possibly of Sundays and Holidays and was paid Rs. 6/- per day. The management has also filed circular dated 9-8-76 on the subject of temporary employees considering the Supreme Court's Judgment in Sunder Money's Case wherein it was observed that fresh opportunity will however, be given to all candidates who have so far have not qualified themselves. Such employees should, therefore, specifically be informed before being reappointed or before being granted extension in their temporary services that their continuous in the bank's service will depend on their being found suitable in a written test and interview.

7. Circular dated 28-2-76 annexure 146 lays down that on expiry of present term no further extension should be granted to any of them and further that no employee should permited to serve as temporay employee for more than 80 days and in this way there are further direction in annexure 146 to 152 regarding temporary employees.

8. On other hand workman has filed 15 documents, first three of which are proceedings before ALC (Central). paper no. 4 is the reply of the bank management to he Secretary U.P. Bank Karamchari Sangh dated 15-7-80 to the effect that interview for sub staff is going to take place, paper no. 5 is letter of Secretary of the Union in which he has initimated the management bank that before appointing fresh hands in the sub staff cadre those who are already worked should be given a chance. Subsequenly the present U.P. Bank Karamchari Sangh vide letter dated 4-4-82, intimated the Manager, Transport Nagar Branch of the management bank that the retrenched employees are not being considered when appointing fresh hands and it was specifically mentioned that Shri Vishnu Daval and others should be considered before appointing fresh new hands. A similar letter was written to the General Manager of the bank management at Jaipur and lastly in 1984, the President of the U.P. Bank Karamchari Sangh wrote to the General Manager to give chance to the retrenched employees including workman Shri Vishnu Daval, workman himself gave letter dated 11-4-84 to the bank management that he be given a chance for appointment as sub staff when new hands are being appointed in the bank. He get himself registered in the Employment Exchange and get renewal card of the year 1981. the workman has further filed paper no. 11, photo copy of the certificate of the bank management issued on 22-9-79 certifying that the workman had worked as temporary peon from 24-3-79 to 11-6-79, from 12-6-79 to 9-8-79 for two months, another temporary peon namely Deen Singh was engaged for 60 days and was paid total salary of Rs. 406.50p per month.

9. Shri K. S Baghel has filed his affidavit evidence on behalf of the management and was examined of justify the reference. He is the manager industrial relation in the bank management's head office at Jaipur and is fully conversant with the facts. He denied that the workman actually worked for 245 days and is not entitled to benefit of section 25F and similarly he is not entitled to notice under para 522(4) of the Sastry award and that he has no legal right to be absorbed in the bank.

10. In cross examination he has however, admitted that in view of circular Per/115/83 some employees who have worked for 270 days were regularised in bank's service. He pleaded his ignorance to the photo copies filed by the workman as paper no. 11 and further stated that he does not know if two peons were appointed on 11-6-79 when services of the workman were terminated. He states rather the workman was daily rated workman and there was no question of termination. He admits that after workman ceased to work other temporary workman were employed in the bank. He further admitted tha leave vacancy temporary appointments were made in different branches of the bank. He further states that he has no knowledge if the workman was appointed on leave vacancy or in excegency of work. He has further no knowledge if the workman worked in different department of the management bank's Birhana Road Branch, at Kanpur as peon and further has shown his ignorance about working of the workman at Kanpur. He admits that there is no written test for the appointment in sub staff cadre and their selection is based only on the basis of interview. He has further stated that he has no knowledge that if the name of the workman was sponsored from the employment exchange Kanpur. He further admits that there is no seniority list of temporary workman and no register was there of temporary employees and simply a file is maintained in which biodata of the temporary workmen are maintained.

11. On the other hand, workman examined himself on the basis of two affidavit given one earlier and the other subsequent to the examination of the management witness testifying his case. In his cross examination he stated that at times he worked on Sundays also and for work of Sunday voucher was prepared on Monday. He admits that every day he worked, he used to get Rs. 6/- per day for the days work. He admits that for the appointment in the bank there are set rules and for which names are called from employment exchange. He voluntarily stated that his name was also sponsored from the employment exchange alongwith the names of other candidates in the month of July or June 78. He admits that he was never called for interview by the bank management.

12. From the documents filed by the management annexure 1 to 143 and averments of workman coupled with joint inspection notes dated 16-5-85 it is ample clear that the workman worked in the management bank for 240 days counting from 24th January 78 to 31st December, 78, which working would be within a span of one year and in view of provision of section 25B(2)(a)(ii) he will be deemed to be in continuous service as he actually worked for not less than 240 days. The question would be in what capacity he worked. It is not the case of the management that he was in any leave vacancy on those days. The workman has averred that he was doing the duties of a sub staff of a regular peon which fact is not denied by the bank management. As no specific casual work not connected for banking industry is shown to have been given to him during the period, the natural collilery is that he worked as peon for 240 days in one span of year as a temporary workman and thus provision of para 20.7 of the Bipartite Settlement will come into play and the workman will be deemed to be temporary workman. Day to day appointment will be for a limited period of a work but if the same man is appointed day to day for a span of more thann 240 days in a year, he will be deemed to be a workman employed in the industry which employment would be temporary if the workman was not working on the perament vacancy post. For termination of such an employee the provision u/s 25F of the I.D. Act, 1947 that he should be given retrenchment compensation are mandatory and which admittedly not done in this case. In view of the oft quoted judgment in Sundermoney case any retrenchment of an employee would be illegal and he will be deemed to be in continuing in service. The workman after his first termination was again appointed for a period of 80 days from 24-3-79 to 11-6-79. Even if that be so that period will stand covered in his continuous service and may have effect on the point of wages if he was paid wages at the scale rate for that period. The termination is further illegal as admittedly new hands were appointed after termination of workman on 2-1-79. It was the duty of the management to have given a chance to the retrenched workman in view of provision of sec. 25-H of the I.D. Act and non compliance of this section would also made termination illegal.

13. Thus in view of the admitted position of working and law discussed above, I hold that the action of the State Bank of Bikaner and Jaipur Birhana Road Kanpur in not absorbing Shri Vishnu Dayal, subordinate staff in the Bank's service and terminating his services from January, 1979, is not justified, the result is that the workman is reinstated in service with full back wages.

14. I, therefore, give my award accordingly.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012/183//81-D-II(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1986

का. आ. 833.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (4) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4088 दिनांक 16 अगस्त, 1985 द्वारा फास्फोराइट खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 23 अगस्त, 1985 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 23 फरवरी, 1986 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. संख्या एल-11017/4/85 डी-1(ए)]
स. ह. सु. अय्यर, अवर सचिव

New Delhi, the 12th February, 1986

S.O. 833.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 4088 dated the 16th August, 1985 the Phosphat Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 23rd August, 1985 ;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest required the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 23rd February, 1986.

[No. S-11017/4/85-D.I(A)]
S. H. S. IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1986

का. आ. 834.—केन्द्रीय सरकार, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972 का 62) की धारा 10 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान उक्त अधिनियम के अधीन वित्त पोषित अपने क्रियाकलापों का वृत्त देते हुए उस वर्ष के लेखा विवरण के साथ निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती है :

सामान्य :

चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972

का 62) के अधीन गठित की गई थी, जिसमें चूना पत्थर और डोलोमाइट खान में नियोजित कर्मचारियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए किसी खान में उत्पादित उतने चूना पत्थर और डोलोमाइट पर जितना :

(i) किसी कारखाने के अधिष्ठाता को विक्रय किया जाता है या अन्यथा व्ययन किया जाता है ; या

(ii) ऐसी खान के स्वामी द्वारा सीमेंट, लोहा या इस्पात के निर्माण में किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है।

एक रुपया प्रति मीट्रिक टन से अनधिक दर से उत्पादन शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था की गई है। इस समय उद्ग्रहण की वास्तविक दर बीस पैसे प्रति मीटरी टन है। उपस्कर के आगम मुख्यतः लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था, आवास और पोषण, कार्यकर्पों, आदि के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

2. प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, उन्नीस राज्यों और संघ शासित क्षेत्र गोवा और दिल्ली को जिनमें देश की चूना पत्थर और डोलोमाइट खान हैं, नौ क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र को कल्याण आयुक्त के अधिकार में रखा गया है। इन क्षेत्रों के कल्याण आयुक्तों को इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए कल्याण और उपकर आयुक्तों के रूप में नियुक्त किया गया है। क्षेत्रों का आबटन इस प्रकार किया गया है :

क्रमांक	अधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्य का नाम
1.	2	3	4
1.	कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, जबलपुर	जबलपुर	मध्य प्रदेश
2.	कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, भुवनेश्वर।	भुवनेश्वर	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम मेघालय, मणीपुर और नागालैंड
3.	कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, इलाहाबाद।	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और चण्डीगढ़
4.	कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा
5.	कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय भारत सरकार, बंगलौर।	बंगलौर	कर्नाटक और केरल
6.	कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, हैदराबाद।	हैदराबाद	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और संघ शासित क्षेत्र और पांडिचेरी
7.	कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नागपुर।	नागपुर	महाराष्ट्र
8.	कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, कर्मा, बिहार	कर्मा	बिहार
9.	कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, गोवा।	गोवा	गोवा

3. चूना पत्थर और डोलोमाइट श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 के अधीन एक केन्द्रीय सलाहकार समिति और आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश राज्यों में 10 राज्य सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों की आवधिक बैठकें होती हैं और यह सरकार को इस अधिनियम के प्रशासन के बारे में नियमित रूप से सलाह देती है।

4. चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों के श्रमिकों के लिए निम्नलिखित कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था की गई है :

क : स्वास्थ्य

पिछले वर्षों के दौरान कल्याण निधि संगठन द्वारा खोले गए 13 आयुर्वेदिक औषधालयों, 18 एलोपैथिक औषधालयों और एक प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र द्वारा चूना पत्थर और डोलोमाइट खान कर्मकारों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा दी जाती रही। 1984-85 के दौरान दो और स्थिर व चलते फिरते औषधालयों के लिए मंजूरी दी गई है। 1984-85 के दौरान खान प्रबन्धतंत्र द्वारा 6 एम्बुलेंस वाहन खरीदने हेतु सहायता अनुदान की 2.75 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। अस्पताल उपस्करों के खरीदने के लिए 5,500/- रुपये की सहायता अनुदान राशि भी मंजूर की गई है। क्षयरोग अस्पताल में क्षयरोग से ग्रस्त कर्मकारों की चिकित्सा के लिए 29 पलंग आरक्षित किए गए हैं। घातक और गम्भीर दुर्घटना लाभ योजना के अधीन 9 मामलों में लाभ दिए गए हैं। स्वास्थ्य के अन्तर्गत 1984-85 के दौरान हुआ कुल व्यय 27,45,531.19 रुपये था।

ख : शिक्षा

छात्रवृत्तियां देने संबंधी योजना के अधीन चूना पत्थर और डोलोमाइट खान के ऐसे नियमित श्रमिकों के पुत्र और पुत्रियों को छात्रवृत्तियां दी दी जाती हैं, जिनकी मासिक आय 1250/- रुपये प्रति माह से अधिक न हो। इस योजना में पांचवी कक्षा से लेकर तकनीकी शिक्षा तक डिग्री पाठ्यक्रम चिकित्सकीय और इंजीनियरी पाठ्यक्रम के लिए प्रति विद्यार्थी 15/- रुपये प्रति माह से 125/- रुपये प्रति माह तक छात्र वृत्तियां देने की व्यवस्था है। 1984-85 के दौरान इन कार्यकलापों के अन्तर्गत 6,17,436.55 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। जिसमें से 5,23,643/- रुपये की राशि 1991 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां के रूप में दी गई है।

ग : मनोरंजन :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान जबलपुर क्षेत्र में दो भुवनेश्वर क्षेत्र में एक, इलाहाबाद क्षेत्र में 4 तथा बंगलोर क्षेत्र में 3 चलते फिरते सिनेमा एकक काम करते रहे। चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिकों के लिए उड़ीसा में पुरी में एक अवकाश गृह भी स्थापित किया गया है। विभिन्न खान प्रबन्धकों को 16 मि.मीटर के 28 प्रोजेक्टर सहायक उपकरणों के साथ दिए गए हैं। फिल्मों के किराए के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए खान प्रबन्धकों को सहायता अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा, कुछ खान प्रबन्धकों को रेडियो सेट भी दिए गए हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 7.51 लाख रु. की राशि मनोरंजन सुविधाओं पर खर्च की गई है।

घ : जल आपूर्ति

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 9,43,095 रु० की राशि जल आपूर्ति के निम्नलिखित प्रबन्धतन्त्रों को मंजूर की गई है।

1. मे० जयपुर उद्योग लिमिटेड, कालोदी क्वारी को उनकी बी.बी.एल. चूना पत्थर खान में एक ओवरहेड वाटर टैंक के निर्माण और कुआं खोदने के लिए दिया गया सहायता अनुदान;

(62,195/- रुपये) भीलवाड़ा क्षेत्र

2. पोलापल्ली चूना पत्थर माइंस के.सी. प्राइवेट लिमिटेड मचेरला में बोर वैल की खोदाई के लिए।

(46,500 रु०) हैदराबाद क्षेत्र

3. मै०सी०सी०आई० लिमिटेड की डिल्लाई पर्वत चूना पत्थर क्वारी, बोकाजन असम में जल आपूर्ति योजना के लिए।

(6,47,400/ रु०) भुवनेश्वर क्षेत्र

4. एस.ए.आई.एल. की पुर्नापानी चूना पत्थर और डोलोमाइट क्वारी में जल आपूर्ति में सुधार योजना के घन्तांस एक अतिरिक्त हौज के निर्माण के लिए।

(1,87,000/-रुपये) भुवनेश्वर क्षेत्र

(ङ) आवास :

चूना पत्थर और डोलोमाइट श्रमिकों के लिए मकान देने की व्यवस्था करना संगठन के मुख्य कार्यकलापों में से एक कार्य है। इस समय तीन योजनाएं चल रही हैं।

(i) टाइप-I आवास योजना

(ii) टाइप-II आवास योजना

(iii) अपना घर, स्वयं बनाओ ।

(क) टाइप-I आवास योजना के अन्तर्गत मानक अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत या 7,500/- रु. इनमें से जो भी कम हो, की आर्थिक सहायता देय है। इसके अतिरिक्त काली कपास या उभरी हुई भूमि वाले क्षेत्रों में 2000/- रु. या वास्तविक लागत, उनमें से जो भी कम हो का 50 प्रतिशत विकास व्यय देय है। विकास व्यय में अन्य बातों के साथ-साथ बाहरी और भीतरी जलपूर्ति, सफाई तथा साथ जोड़ने वाली सड़कों का भी व्यय शामिल होगा। वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान टाइप-I आवास योजना के अन्तर्गत चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिकों के लिए 318 घरों को मंजूरी दी गई।

(ख) टाइप-II आवास योजना के अन्तर्गत, देय आर्थिक सहायता की दर 1500/- रु. या निर्माण लागत का 75 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो देय है। इसके अतिरिक्त, साधारण क्षेत्रों में प्रति मकान 1500/- रु. और काली कपास या उभरी हुई भूमि क्षेत्रों में 2,250 रु. की दर से या विकास की वास्तविक लागत, इनमें से जो भी कम हो, आर्थिक सहायता देय है। 1984-85 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 366 घरों को मंजूरी दी गई।

(ग) अपना मकान स्वयं बनाओ योजना के अधीन पात्र कर्मकार को 1000/- रु. की दर से आर्थिक सहायता और इसके अतिरिक्त 4000/-रु. का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, जो कि 9 वर्ष से अनधिक अवधि में मासिक किस्तों में वसूल किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अधीन 173 कर्मकारों को लाभ मिला।

1984-85 वर्ष के लिए लेखा विवरण :—

पहली अप्रैल, 1984 को अथशेष	2,73,19,295.06 रुपये
1984-85 के दौरान प्राप्तियां	1,24,26,350.10 रुपये
1984-85 के दौरान व्यय	80,28,926.17 रुपये
31-3-1985 को अंतशेष	3,17,16,718.99 रुपये

[सं. जैड-12015/3/85-डब्ल्यू-II]

आर. डी. मिश्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 14th February, 1986

S.O. 834.—In pursuance of Section 10 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, (62 of 1972), the Central Government hereby publishes the following report giving an account of its activities financed under the said Act during the financial year 1984-85 together with the statement of accounts of that year :—

General :

The Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund was constituted under the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972) which provides for the levy and collection of cess at a rate not exceeding one rupee per metric tonne on so much of Limestone and Dolomite produced in any mine—

(i) as is sold or otherwise disposed to the occupier of any factory; or

(ii) as is used by the owner of such mine for any purpose in connection with manufacture of cement, iron or steel,

to promote the welfare of the persons employed in Limestone and Dolomite mines. The actual rate of levy presently is twenty paise per metric tonne. The proceeds of the cess are being utilised mainly for the improvement of public health and sanitation, provision of medical facilities, subsidy on housing and programmes of nutrition etc.

2. For administrative convenience, the nineteen States and Union Territories of Goa and of Delhi which have Limestone and dolomite mines in the country, have been grouped into nine regions and each region is placed under the overall charge of a Welfare Commissioner. The Welfare Commissioners of the areas have been appointed as Welfare and Cess Commissioners for the enforcement of Act and Rules framed thereunder.

The allocation of the regions is as under :—

Sl. No.	Designation of the Officer	Head-quarters	Name of the State and their Jurisdiction
1	2	3	4
1.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Government of India, Jabalpur.	Jabalpur	Madhya Pradesh
2.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Government of India, Bhubaneswar.	Bhubaneswar.	Orrisa, West Bengal Assam, Meghalaya, Manipur and Nagaland.
3.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Government of India, Allahabad.	Allahabad	Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab and Union Territory of Delhi and Chandigarh.
4.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Government of India, Bhilwara.	Bhilwara	Rajasthan, Gujarat and Haryana.
5.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Government of India, Bangalore.	Bangalore	Karnataka and Kerala.

1	2	3	4
6.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Government of India, Hyderabad.	Hyderabad	Tamil Nadu and Andhra Pradesh and Union Territory of Pondicherry.
7.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Government of India, Nagpur.	Nagpur	Maharashtra.
8.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Government of India, Karma, Bihar.	Karma	Bihar.
9.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Government of India, Goa.	Goa	Goa.

3. A Central Advisory Committee and 10 States Advisory Committees for the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh have been constituted under the Limestone and Dolomite Labour Welfare Fund Act, 1972. The Committees meet periodically and advise the Government regarding administration of the Act.

4. The following welfare facilities have been provided to Limestone and Dolomite Mines Workers :—

A. HEALTH :

Thirteen Ayurvedic dispensaries, 18 Allopathic dispensaries and one Maternity-cum-Child Welfare Centre set up by Welfare Fund Organisation during the previous years have continued to give medical treatment to the Limestone and Dolomite Mine workers and their dependents. Two more Static-cum-Mobile dispensaries were sanctioned during 1984-85. Grants-in-aid amounting to Rs. 2.75 lakhs has been sanctioned for the purchase of 6 Ambulance Vans by mine managements during the year 1984-85. Grants-in-aid amounting to Rs. 5,500 has also been sanctioned for the purchase of Hospital equipments. 29 beds have been reserved in TB Hospitals for the treatment of workers suffering from TB. Benefits have been given in 9 cases under Fatal and Serious Accident Benefits Scheme. The total expenditure during 1984-85 under Health was Rs. 27,45,531. 19.

B. EDUCATION :

Under the Scheme for the award of scholarships, scholarships are granted to the sons and daughters of regular Limestone and dolomite mine workers whose monthly earnings do not exceed Rs. 1,250 per month. The Scheme envisages award of scholarships for Class V onwards, to technical education degree courses, medical and engineering courses at the rates varying from Rs. 15 p.m. to 125 p.m. per student. During 1984-85 Rs. 6,17,486.55 lakhs has been spent under the activity out of which an amount of Rs. 5,23,043.00 has been awarded as scholarship to 1991 students.

C. RECREATION :

Two mobile Cinema Units in Jabalpur region, one in Bhubaneswar region, 4 in Allahabad region and 3 in Bangalore region continued to function during the year under report. A Holiday Home has also been set up at Puri in Orissa for the Limestone and dolomite mine workers. Twentyeight 16 m.m. projectors with accessories have been provided to different mine managements. Grants-in-aid for re-imbursement of film-hire charges are being paid to the mine managements. Besides, radio sets have also been provided to many managements. During the year under report an amount of Rs. 7.51 lakhs has been spent on recreational facilities.

D. WATER SUPPLY :

During the year under report an amount of Rs. 9,43,095 was sanctioned for Water Supply Scheme to the following managements :—

1. Grants-in-aid for construction of an overhead water tank and sinking of well to M/s. Jaipur Udyog Limited, Phalodi Quarry at their BBL Limestone Mines.

(Rupees 62,195) Bhilwara Region

2. Sinking of bore well at Polepalli Limestone Mines K.C. Pvt. Ltd., Macherla.

(Rupees 46,500) Hyderabad Region

3. Water Supply Scheme at Dillai Parbat Limestone Quarry of M/s. CCI Ltd., Bokajan, Assam.

(Rs. 6,47,400) Bhubaneswar Region

4. Improvement to water supply scheme at Purnapani Limestone and Dolomite Quarry of SAIL construction of an additional reservoir.

(Rs. 1,87,000) Bhubaneswar Region

E. HOUSING :

Provision of housing accommodation for limestone and dolomite workers is one of the main activities of the organisation. Presently, there are three schemes in vogue, namely :—

(i) Type I Housing Scheme

(ii) Type II Housing Scheme

(iii) Build Your Own House Scheme.

(a) Under Type I Housing Scheme subsidy is payable at the rate of 75 per cent of the standard estimated cost of Rs. 7500 whichever is less. In addition, the development charges are also payable at the rate of 50 per cent of Rs. 2000 for ordinary areas and 75 per cent of Rs. 2000 for black cotton or swelly soil areas are the actual cost, whichever is lower. The development charges, will inter alia include external and internal water supply, sanitation, electricity and approach roads. During the financial year 1984-85, 318 houses were sanctioned under Type I Housing Scheme for limestone and dolomite mine Workers.

(b) Under Type II Housing Scheme the rate of subsidy payable is Rs. 1500 or 75 per cent of cost of construction whichever is lesser. In addition development charges is also payable at the rate of Rs. 1500 per house in ordinary areas and Rs. 2250 in black cotton or swelly soil areas or the actual cost of development whichever is less. Under the Scheme 366 houses have been sanctioned during the year 1984-85.

(c) Under Build Your Own House Scheme financial assistance is given to an eligible worker at the rate of Rs. 1000 as subsidy besides interest free loan of Rs. 4000, refundable in monthly instalments spread over a period of not exceeding 9 years. 173 workers have benefitted under the Scheme during the financial year.

Statement of account for year 1984-85:

Opening balance as on 1st April, 84	Rs.	27319295.06
Receipts during the year 1984-85	Rs.	12426350.10
Expenditure during the year 1984-85	Rs.	8028926.17
Closing balance as on 31-3-1985	Rs.	31716718.99

[No. Z-12015/3/85-W. II]
R. D. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1986

का. आ. 835.—मैसर्स प्रागा टूल्स लिमिटेड, 6-6-8/32, कवाडिगुड़ा, सिकन्द्राबाद (ए. पी./144) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं जो ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2713 तारीख 1-7-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 24-7-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 23-7-88 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(11)/82-एस. एस.-2]

New Delhi, the 14th February, 1986

S.O. 835.—Whereas Messrs Praga Tools Limited, 6-6-8|32, Kavadigude, Secundrabad (AP|144) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2713 dated 1-7-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 24-7-85 upto and inclusive of 23-7-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and Provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the emloyees.

5. Whereas, an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme; shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and were any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportuity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/11/82-PF.II(SS.II)]

का. आ. 836.—मैसर्स तमिलनाडु स्टील लिमिटेड, अकौनम, एन. ऐ. (टी. एन./7531) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं जो ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3717 तारीख 11-10-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 30-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 29-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(36)/82-एस.एस.-2]

S.O. 836.—Whereas Messrs Tamil Nadu Steel Limited Arkonam North Area-631004 (TN/7531) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3717 dated 11-10-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 30-10-1985 upto and inclusive of 29-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commmissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and Provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the emloyees.

5. Whereas, an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and were any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/36/82-PF.II(SS.II)]

का. आ. 837.—मैसर्स श्री शिवाकामी मिल्स लिमिटेड थेनूर, मदुराई जिला (टी. एन./1707) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3149 तारीख 19-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 3-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, ऐसे उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

1568 GI/85—14

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(44)/82-एस. एस.-II]

S.O. 837.—Whereas Messrs Sree Sivakami Mills Limited Thenur, Madurai Dist. (TN/1707) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3149 dated 19-8-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-9-1985 upto and inclusive of 3-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and Provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the emloyees.

5. Whereas, an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal hair/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim com-in all respects.

[No. S. 35014/44/82-PF. II(SS. II)]

का. आ. 838.—मैसर्स प्यूरलेटर इंडिया लिमिटेड, परवानू-173220 (एच.पी.) (पी.एन./4669) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं जो ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3544 तारीख 23-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 9-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 8-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन

किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(100)/82-एस. एस.-2]

S.O. 838.—Whereas Messrs Purolater India Limited Parwanoo-173220 (H.P.)-(PN/4689) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3544 dated 25-9-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 9-10-85 upto and inclusive of 8-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the emloyees.

5. Whereas, an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal hair/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme; shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/100/82-PF. II(SS.II)]

का. आ. 839.—मैसर्स स्ट्रा प्रोडक्टस लिमिटेड नेहरू हाऊस-4, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 (डी एल/2806) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं जो ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2947 तारीख 4-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 21-8-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-8-88 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाए। है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(188)/82-एस.एस.-2]

S.O. 839.—Whereas Messrs Straw Products Ltd, Nehru House 4-Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-10002 (DL/2806) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2947 dated 4-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-8-1985 upto and inclusive of 28-8-88.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas, an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(189)/82-PF.II(SS.II)]

का. आ. 840.—मैसर्स ई. मेरक्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, शिव सागर एस्टेट "ए" डा. ए. बी. रोड वर्ली बम्बई - 400018 (एम एच / 4843) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2948 तारीख 8-11-82 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 27-11-85 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 26-11-88 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि की हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण होने की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(228)/82-एस. एस.-2/पी. एफ.-2]

S.O. 840.—Whereas Messrs. E. Merck (India) Private Limited Shiv Sagar Estate 'A' Dr. A. B. Road, Worli, Bombay-400018. (MH|4843), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3938 dated 8-11-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 27-11-85 upto and inclusive of 26-11-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rule of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme; shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of

deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/218/82-PF. II(SS. II)]

का. आ. 841 :—मैसर्स उज्ज्वल लिमिटेड, शशी बिल्डिंग, 4/18, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 (डी एल/3255) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है कि धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3345 तारीख 30-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 18-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(204)/82-एस. एस.-2/पी. एफ.-2]

S.O. 841.—Whereas Messrs Ujjwal Limited, Shashi Building, 4/18, Asaf Ali Road, New Delhi-110002, (DL/3255), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of

India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3345 dated 30-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-9-1985 upto and inclusive of 17-5-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and Provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rule of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme; shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/204/82-PF-II/SS-III]

का. आ. 842.—मैसर्स श्री प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड एच. ए. लिमिटेड, कम्पाउंड पिम्परी पुणे-411018 (एम. एच/7513) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है कि धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 400 तारीख 9-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 18-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 14-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पुणे को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया

जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पुणे के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(285)/82-एस. एस.-2/पी. एफ.-2]

S.O. 842.—Whereas Messrs Shree Products (P) Limited H. A Limited, Compound Pimpri Pune-411018 (MH/7513), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act)

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 400 dated 9-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 15-1-1986 upto and inclusive of 14-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Poona and maintain such accounts and Provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rule of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Poona and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/285/82-PF. II (SS. II)]

का. आ. 843 :—मैसर्स फाइबरग्लास पिलकिंगटन लिमिटेड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, थाना-400602 (एम एच/7626) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है कि धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4133 तारीख 22-1-82 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 11-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 10-12-88 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थान के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(319)/82-एस.एस-2]

S.O. 843.—Whereas Messrs Fiberglass Pilkington Limited Lal Bahadur Shastri Marg Thana-400602 (MH/7626), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the

Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4133 dated 22-11-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 11-12-85 upto and inclusive of 10-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rule of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme; shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/319/82-PF. II(SS. II)]

का. आ. 844 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए. एम. सफीउल्हा एण्ड कम्पनी टेनरी-32, अमूर रोड रानीपत (एन. ए. कस्बा) तमिलनाडु और इसका 12, वेपरी हाईरोड, पेरीआमेट, मद्रास-600003 स्थित प्रशासनिक कार्यालय नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(116)/86-एस. एस-2]

S.O. 844.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. A. M. Safiullah & Co. Tannery, 32, Ammoor Road, Ranipat (N.A.D.T.) Tamil Nadu including its Adm. Office at 12, Vepery High Road, Periamet Madras-600003 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(116)/86-SS-II]

का. आ. 845.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मनिकानंदनस एल. आई. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गुइंडी, मद्रास-32 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(117)/86-एस. -2]

S.O. 845.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Manikandans L.I. Industrial Estate, Guindy, Madras-32 have agreed that the provisions of the Employees' Providnet Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(117)/86-SS-II]

का. आ. 846.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वोलंटरी हेल्थ सर्विसस थान्जेवर यूनिट, थान्जेवर टैक्सटाईल कैन्टीन वालाम्बन रोड (बिल्डिंग) थान्जेवर-613005 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मकारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(118)/86-एस.एस-2]

S.O. 846.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Voluntry Health Services, Thanjavur unit Thanjavur Textile Canteen Vallam One Road (Building), Thanjavur-613005 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(118)/86-SS-II]

का. आ. 847.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम.एच. मेहता एण्ड कं., 1-ए(1) एनीपलायम एक्सटेंशन रोड तिरीपूर-638603, और इसका बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(120)/86-एस.एस-2]

S.O. 847.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. M. H. Mehta and Co. 1-A(1) Angeripalayam Extension Road Tiruppur-638603 including Head Office at Bombay have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(120)/86-SS-II]

का. आ. 848.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स होवर्ड फाईनले कन्सलटेन्टस (आई) प्राईवेट लिमिटेड, 95, वी. एम. स्ट्रीट मैलापूर मद्रास -600004, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(121)/86-एस.एस-2]

S.O. 848.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Howard Finley Consultants (I) Private Limited, 95 V. M. Street, Mylapore, Madras-600004 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(121)/86-SS-II]

का. आ. 849.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मै. विको फार्मा, डी-25, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, विशाखापट्टनम-7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(122)/86-एस.एस-2]

S.O. 849.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Veco Pharma, D-25, Indl. Estate, Visakhapatnam-7 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(122)/86-SS-II]

का. आ. 850.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दा गारशंकर प्राइमरी कोआपरेटिव लैंड मोर्टगेज बैंक लिमिटेड, गारशंकर, पंजाब नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(123)/86-एस.एस-2]

S.O. 850.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Garshankar Primary Co-operative Land Mortgage Bank Limited, Garshankar, Punjab have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(123)/86-SS-II]

का. आ. 851.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कोनार्क डीटरजन्ट एण्ड सोपस, पि. ओ. जगतपुर, कटक (उड़ीसा) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(124)/86-एस. एस-2]

S.O. 851.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Konark Detergents and Soaps Limited, Jagatpur, Cuttack have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(124)/86-SS-II]

का. आ. 852.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एस. एस. तिवारी पी. ओ. जोड़ा-34 जि. क्योन्झार उड़ीसा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(125)/86-एस. एस-2]

S.O. 852.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. S. S. Tiwari P.O. Joda-34, Dist. Keonjhar (Orissa) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(125)/86-SS-II]

का. आ. 853.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जी. एन. चौधरी एण्ड सन्स, पी. ओ. जोरा, जि. क्योन्झार (उड़ीसा) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(126)/86-एस. एस-2]

S.O. 853.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s G. N. Chowdhury and Sons P.O. Joda District Keonjhar (Orissa) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(126)/86-SS-II]

का. आ. 854.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आसाम पोलीटैक्स लिमिटिड, आर. जी. बरुआ रोड गोहाटी-781005 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(127)/86-एस. एस-2]

S.O. 854.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Assam Polytex Limited, R. G. Baruah Road, Gawabati-781005 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(127)/86-SS-II]

का. आ. 855.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16 फरवरी, 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"आदिलाबाद जिले के निर्मल राजस्व मंडल के अधीन वेंकटापुर के राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र ।"

[संख्या एस-38013/3/86-एस. एस-1]

S.O. 855.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th day of February, 1986 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chap-

ters V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh namely:—

"The area within the revenue village of Venkatapur under Nirmal revenue mandal of Adilabad District."

[No. S-38013/3/86-SS-I]

का. आ. 856.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16 फरवरी, 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 के 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

1 "जिला बंगलौर के तालुक बंगलौर उत्तर में हुबली येला-हांका में बयाटा-रायनापुरा राजस्व ग्राम ।"

[संख्या एस-38013/4/86-एस.एस-2]

S.O. 856.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th February, 1986 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka, namely:—

"Revenue village Byatarayanapura in Hobli Yelahanka, in Taluk Bangalore North in district Bangalore."

[No. S-38013/4/86-SS-I]

का. आ. 857.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा फरवरी, 1986 के 16वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्रम संख्या	स्थान का नाम	हद बस्त संख्या
1.	गोविन्दपुरा	54
2.	किशनपुरा	55
3.	पिण्डारा	72
4.	जलालपुरा खुर्द	14
5.	जिन्द	79

जिला जिन्द में ।

[संख्या एस-38013/5/86-एस.एस.-1]

S.O. 857.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th day of February, 1986 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana namely :—

Sl. No.	Name of the area	Head Bast No.
1	2	3
1.	Gobindpura	54
2.	Kishanpura	55
3.	Pindara	72
4.	Jalalpura Khurd	14
5.	Jind	79

in the District Jind.

[No. S-38013/5/86-SS-I]

का. आ. 858.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा फरवरी 1986 के 16वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

केन्द्र टुमकुर रोड के बाहरी क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम	हुबली	तालुक	जिला
1.	दासनापुरा	दासनापुरा	नेलामंगला	बंगलौर
2.	चिक्काबेदारकल्लु	दासनापुरा	नेलामंगला	बंगलौर
3.	मकाली ग्राम	दासनापुरा	नेलामंगला	बंगलौर
4.	बागलगुण्टा	यशवन्तपुरा	बंगलौर उत्तर	बंगलौर
5.	मदवारा	वामनापुरा	नेलामंगला	बंगलौर
6.	दोड्डबेदारकल्लु	वागनापुरा	नेलामंगला	बंगलौर

[संख्या एस-38013/2/86-एस.एस-1]

ए. के. भट्टराई, अवर सचिव

S.O. 858.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th day of February, 1986 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought

into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka, namely :—

Sl. No.	Name of the revenue Village	Hobli	Taluk	Distt.
1	2	3	4	5
1.	Dasanapura	Dasanapura	Nelamangala	Bangalore
2.	Chikkabidarakallu	Dasanapura	Nelamangala	Bangalore
3.	Makali Village	Dasanapura	Nelamangala	Bangalore
4.	Bagalgunte	Yeshwanthpura	Bangalore North.	Bangalore
5.	Madavara	Dasanapura	Nelamangala	Bangalore
6.	Doddabidarakallu	Dasanapura	Nelamangala	Bangalore

[No. S-38013/2/86-SS.I]

का. आ. 859.—मैसर्स इण्डियन एक्सप्रैस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्रा. लि., एक्सप्रेस टावरस नारीमन प्वाइंट, बम्बई 400021 (एम एच/1195 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बंबई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एम-35014 (5)/86-एस. एस-2]

S.O. 859.—Whereas Messrs. Indian Express Newspapers (Bombay) Pvt. Ltd., Express Towers, Nariman Point, Bombay-400021 (MH/1195) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of Premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charge etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/ nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(5)/86-SS-II]

का. आ. 860.—मैसर्स गुजरात स्टेट को. ऑप. मार्केटिंग फैडरेशन लि., सहकार भवन रिलिफ रोड, अहमदाबाद (जी जे/4833) (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्यय का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत यथाअपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014 (6)/86-एस. एस-2]

S.O. 860.—Whereas Messrs Gujarat State Co-op. Marketing Federation Ltd., Sahakar Bhawan, Relief Road, Ahmedabad (GJ/4833) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of Premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charge etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/ nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Gujarat and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(6)/85-SS-II]

का. आ. 861.—मैसर्स इण्डियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्रा. लि., 186 बी इण्डस्ट्रीयल, एरिया चण्डीगढ़-160002 (पी एन/4931) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3 क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों पर का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन अपने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014 (8)/86-एस एस-2]

S.O. 861.—Whereas Messrs. Indian Express Newspapers (Bombay) Pvt. Ltd., 186-B Industrial Area, Chandigarh-160002 (PN/4931) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such retruns to the Regional Provdent Fund Commissioner, Chandigarh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of subsection (3A) of Section 17 of the said Act. within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insuran-e premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government, and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establshment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay ne-essary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishmen do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any teason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(8)/86-SS-II]

का. आ. 861—मैसर्स वि. एम. पी. राज्य सेतू निर्माण निगम लि., ई-5 महावीर नगर, एरेरा कालोनी) (भोपाल- 462016 (एम. पी./3439) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसी बात भारतीय प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के

अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिफर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस- 35014 (40) /86-एसएस-II]

S.O. 862.—Whereas Messrs. The M.P. Rajya Setu Nirman Nigam Limited, E-5 Mahavir Nagar Area Colony Bhopal-462016 (M.P.)(MP|3439) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of Premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir| nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(40)/86-SS-II]

का. आ. 863—कान्टीनेंटल ऑटो एनसीलरी लि., प्लॉट नं. 29-30, सैक्टर-II इन्टस्ट्रीयल एरिया, परवानू (हिमाचल प्रदेश) (पी. एन. / 5908) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014(52)/86-एस० एस-2]

S.O. 863.—Whereas Messrs Continental Auto Ancillary Limited, Plot No. 29-30, Sector-II, Industrial Area, Parwanoo (Himachal Pradesh) (PN/5908) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and,

as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner, shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(52)/86-SS-II]

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1986

का. आ. 864.—मैसर्स कर्तारका ट्रेडिंग माल्टी निवास बिल्डिंग, जी. टी. रोड, जालन्धर-144001 (पी. एन. / 5688) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में

असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(49)/86-एस. एस-2]

New Delhi, the 17th February, 1986

S.O. 864.—Whereas Messrs Kasinka Trading Lally Niwas Building, G.T. Road, Jalandhar-144001 (PN/5688) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under this Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased members entitled for it and in any case within one month from receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(49)/86-SS-II]

का. आ. 865.—मैसर्स मै. आर. ओलक एण्ड सन्स (प्रा.) लिमिटेड, 426, इन्डस्ट्रियल एरिया "ए" लुधियाना-141003 (पी. एन./259) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों को वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित बीमा रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन भूत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014 (50) /86 एस.-एस-2]

S.O. 865.—Whereas Messrs C. R. Auluck & Sons (P) Ltd., 426, Industrial Area 'A' Ludhiana-141003 (PN/259) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premiums in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of

the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(50)/86-SS-II]

का. आ. 866.—मैसर्स दी ऐन्टीफरीक्शन बीयरिंगस कार्पोरेशन लि., पंडित जवाहर लाल नेहरू मार्ग, लोनावला (महाराष्ट्र) एम.एच./(4810) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक उप प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पूना को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी खर्चों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन उप प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पूना के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उन सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन न आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

(संख्या एस-35014 (15)/86-एस. एस-2)

S.O. 866.—Whereas Messrs. The Antifriction Bearings Corpn. Ltd., Pandit Jawahar Lal Nehru Marg, Lonavla-410401 (Maharashtra) (MH/4810) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Pune maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay ne essary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Dy. Regional Provident Fund Commissioner, Pune and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his aproval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(51)/86-SS-II]

का. आ. 867.—मैसर्स कौशल स्टील रोलिंग मिल्स मलोहम गोविन्दगढ़ मण्डी गोविन्दगढ़ (पी. एन./3116) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं –

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा

जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस. 35014 (53)/86-एस. एस-2]

S.O. 867.—Whereas Messrs. Kaushal Steel Rolling Mills, Amloh Road Mandi Gobindgarh-147301 (PN/3116) (hreinafter referred to as the said estabilshment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are morefavourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(53)/86-SS-II]

का. आ. 868.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 16 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 34 (अ), तारीख 20 जनवरी, 1983 के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार के अधीन उन सभी विभागीय उपक्रमों को, जिनके कर्मचारी सरकारी नियमों के अधीन अनुज्ञेय भविष्य निधि और पेंशन के फायदे, एक वर्ग के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से 20 जनवरी, 1986 से तीन वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

[सं. एस-35014/1/86 – एस एस-II]

S.O. 868.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in continuation of the notification of the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) No. S.O. 34(E), dated he 20th January, 1983, the Central Government hereby exempts all departmental undertakings under the Central Government whose employees are in receipt of provident fund and pension benefits as admissible under the Government rules as a class, from the operation of the provisions of the said Act for a further period of three years with effect from the 20th January, 1986.

[No. S-35014/1/86-SS.II]

नई दिल्ली, 18 फरवरी 1986

का. आ. 869.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए. अब्दुल करीम सोजाटवाला, निकट पंच पीर कब्रिस्तान गीता मन्दिर, अहमदाबाद। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(81)/86-एस.एस-2]

New Delhi, the 18th February, 1986

S.O. 869.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. A. Abdul Karim Sojatwala, Near Panch Pir, Kabrastan, Gita Mandir, Ahmedabad have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(81)/86-SS-II]

का. आ. 870.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मै. कृष्णा डाईरस एण्ड कलोथ डिलर्स थीरुबावेनम कुम्बाकोणम तालुक नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(83)/86-एस.एस-2]

S.O. 870.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Krishna Dyers & Cloth Dealers, Thirubavanam, Kumbakomam Taluk, Madras have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Secion 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(83)/86-SS-II]

का. आ. 871.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री गणेश लीथो, 29, पीटरस रोड, मद्रास-14 और इसकी 55-आरकाट रोड सालीग्राम मद्रास स्थित शाखा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(88)/86-एस.एस-2]

S.O. 871.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Sri Ganesh Litho 29, Peter's Road, Madras-14, including its branch at 55 Arcot Road, Saligramam, Madras have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(88)/86-SS-II]

का. आ. 872.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम. आर. ट्रेडर्स, पीस-गुड्स मरचैन्ट्स, बाजार स्ट्रीट नागापट्टिनम, तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(89)/86-एस.एस-2]

S.O. 872.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. M. R. Traders, Piece Goods Merchants, Bazar Street, Nagapattinam, Tamil Nadu have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/89/86-SS-II]

का. आ. 873.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैफको इंजिनियर्स प्रा. लि., 122/5, पुनरी हाई रोड, अडरकुप्पम पोस्ट मद्रास-103 और इसकी, मद्रास-4 स्थित प्रशासकीय कार्यलय नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(91)/86-एस.एस-2]

S.O. 873.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. MEFCO Engineers Private Limited. 122/5. Ponneri High Road. Andaikuppam Post, Madras-183 and its administrative office at Madras-8, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(91)/86-SS-II]

का. आ. 874.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि विवेकानंदा कलर वर्क्स अंलखादु-कारूवामपालयाम, तिरूपुर-638604 तमिलनाडू। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(92)/86-एस.एस-2]

S.O. 874.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Vivekananda Colour Works Alankadu, Karuvampalayam, Thiruppur-638684, Tamil Nadu have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Secion 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(92)/86-SS-II]

का. आ. 875.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि राजा इंजिनियरिंग वर्क्स, बस रोड, 155/1, जी. आर. पालायाम (वाया) उडगंथ (एन. ए. कस्बा) तमिलनाडू। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(93)/86-एस. एस-2]

S.O. 875.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Raja Engineering Works, Bus Road, 155/1, G. R. Palayam (Via) Adugunth N.A. Dist. (Tamil Nadu) have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(93)/86-SS-II]

का. आ. 876.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुरा सिल्क सैण्टर थीरुवारूर (तमिलनाडू) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(94)/86-एस. एस-2]

S.O. 876.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Mura Silk Centre, Thiruvarur (Tamil Nadu) have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(94)/86-SS-II]

का. आ. 877.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स थोनी लालारपाल पन्नाई, अनथाडापुरम रोड मयूराम। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(95)/86-एस. एस-2]

S.O. 877.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Thozhilalar Pal Pannai, Anatthandavapuram Road. Mayuram have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(95)/86-SS-II]

का. आ. 878.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विकु एण्ड सन्स, रंगाई गोडर स्ट्रीट, कोयम्बतूर-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(96)/86-एस.एस-2]

S.O. 878.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Veeku and Sons, Rangai Gowder Street, Coimbatore-I(Tamil Nadu) have agreed that the Provision of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(96)/86-SS-II]

का. आ. 879.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रोजा मार्क कडलिया मिठाई कं. नं-5, बिरमनकोल स्ट्रीट, अरसालारू रोड, कुम्बाकोनम, तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(97)/86-एस.एस-2]

S.O. 879.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Roja Mark Kadalai Mittai Company, No. 5 Birmankoil Street Arasalaru Road, Kumbakonam, Tamil Nadu have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made appli able to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(97)/86-SS-II]

का. आ. 880.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पेड्डी प्रोसेसिंग रिसर्च सेन्टर, तिरुवारूर, तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(99)/86-एस.एस-2]

S.O. 880.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Paddy Processing Research Centre, Tiruvarur, Tamil Nadu have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(99)/86-SS-II]

का. आ. 881.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम आर टैक्सटाइल्स, बाजार स्ट्रीट नागापट्टनम, तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(100)/86-एस.एस-2]

S.O. 881.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. M. R. Textiles, Bazar Street, Nagapattinam, Tamil Nadu have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(100)/86-SS-II]

का. आ. 882.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सन्गु मार्क सिवल स्टोरस, कुम्बक्कोनम, तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(102)/86-एस.एस-2]

S.O. 882.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Sangu Mark Seeval Stores, Kumbakenam, Tamil Nadu have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Secion 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(102)/86-SS-II]

का. आ. 883.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी वेदरानयाम शालट वर्कर्स कोपरेटिव प्रोडेक्शन एण्ड सेल सोसायटी ल., वेदरानयाम पीन-614810, तन्जोर डिस्ट्रीक्ट नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या

इस बात पर राजमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(103)/86-एस.एस-2]

S.O. 883.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. The Vedaranyam Salt Worker's Co-operative Production and Sale Society Limited, Vedaranyam Pin-614818, Tanjore Distt. have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(103)/86-SS-II]

का. आ. 884.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री करतीक्गान मोडरन राईस एण्ड आयल मिल्स नथीमेडु, सलेम-2-मद्रास नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर राजमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(105)/86-एस.एस-2]

S.O. 884.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Sri Karthikoyan Modern Rice and Oil Mills, Nothimedu Salem-2 Madras have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(105)/86-SS-II]

का. आ. 885.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री वैकाटचलपथी प्रिंटरस 17/1315, साउथ मैन स्ट्रीट थान्जावर तमिल नाडु । नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर राजमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(107)/86-एस.एस-2]

S.O. 885.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Sri Venkatachalapathy Printers, 17/1315, South Main Street Thanjavur, Tamil Nadu, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(107)/86-SS-II]

का. आ. 886.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वसन्ता सौप वर्कस, पट्टुकोटटीया 614601, थान्जावर जिला तमिल नाडु । नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर राजमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(112)/86-एस.एस-2]

S.O. 886.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Vasantha Soap Works, Pattukottai, 614601 Thanjavur District Tamil Nadu have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(112)/86-SS-II]

का. आ. 887.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ट्रेडर्स, 43, विरभद्रास्वामी कोल स्ट्रीट, नागापट्टीनम मद्रास नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर राजमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[संख्या एस-35019(113)/86-एस.एस-2]

S.O. 887.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Sait Traders. 43, Veeranadraswamy Koil Street Nagapattinam, Madras. have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(113)/86-SS-II]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 888.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड-3, उप-खण्ड (2) में दिनांक 25 मई, 1985 को प्रकाशित, भारत सरकार

के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2255, दिनांक 7 मई, 1985 में लाइन 3 में "अल्पना" के स्थान पर "अलफा" पढ़ें ।

[संख्या एस-35019/170/85-एस.एस.-2]

CORRIGENDUM

S.O. 888.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 2255, dated the 7th May, 1985 published in the Gazette of India, Part II Section 3, sub-section (ii), dated the 25th May, 1985, in line 3 for "Alpna" read "Alpha".

[No. S-35019(170)/85-SS-II]

का. आ. 889.—मैसर्स तमिलनाडु गुड्स ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, लि., नं.-4, श्रीरामनगर (साऊथ) स्ट्रीट, अलवरपेट, मद्रास-600018 (टी. एन./10072) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मद्रास को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और उक्त कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का आशय, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मद्रास के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसके स्थापन पहले आना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(48)/86-एस.एस.-2]

S.O. 889.—Whereas Messrs. Tamil Nadu Goods Transport Corporation Ltd., No. 4, Sri Ram Nagar (South) Street, Alwarpet, Madras-600018, (TN/10072), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any

separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madras maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall desplay on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Emplovees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the emplover shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madras and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(48)|86-SS-II]

का. आ. 890.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मार्किट फैडरेशन लि., विराजपेट, कोडागु जि., (कर्नाटका) (के. एन./5707) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मद्रास को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के

सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मंगलौर के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(43)/86-एस.एस.-2]

S.O. 890.—Whereas Messrs The Kodagur District Co-op. Marketing Federation Ltd., Virajapet, Kodagu Distt. (Karnataka) (KN|5707), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, threfore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Mangalore maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Mangalore and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(43)/86-SS-II]

का. आ. 891.—मैसर्स दि जाम श्री रणजीतसिंहजी सीनिंग और वीविंग मिल्स कं. लि. फतेहचन्द दामनी नगर, सोलापुर-413001 (एम. एच./343) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी एकक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पूना को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की भी व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, उप प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पूना के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(44)/86-एम.एस.-2]

S.O. 891.—Whereas Messrs. The Jam Shri Ranjit Singhji Spinning and Weaving Mills, Co. Ltd., Fatehchand Damani Nagar, Solapur-413001 (Maharashtra) (MH/343), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establish-

ment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Pune maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Pune and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(44)|86-SS-II]

का. आ. 892.—मैसर्स साऊथरन स्ट्रक्चरलस लि. नं.-8, पुगज रोड, राजा आनामलीयापुरम, मद्रास-28 (टी.एन.-2475-ए) और इसकी पटाबियाराम मद्रास-72 में स्थित शाखा (टी.एन./2475) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मद्रास को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मद्रास के पूर्व अनुमोदन, के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(41)/86-एस.एस-2]

S.O. 892.—Whereas Messrs Southern Structurals Limited, No. 8 Pughs Road, Raja Annamaliapuram, Madras-28, (TN/2475A) and its Branch at Pattabiram, Madras-72 (TN/2475), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madras maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madras and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(41)/86-SS-II]

का. आ. 893.—मैसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड नं.-3, जी.टी. रोड, शेरपुर लुधियाना (पंजाब) (पी.एन./125) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को लयपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(32)/86-एस.एस.-II]

S.O. 893.—Whereas Messrs. Oswal Woollen Mills Ltd., No. 3, G. T. Road, Sherpur, Ludhiana (Punjab) (PN/125) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall desplay on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(32)|86-SS-II]

का. आ. 894.—मैसर्स हिमाचल प्रदेश एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, समर सीट, शिमला-171001 (हिमाचल प्रदेश) (पी. एन./4001) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में तत्प्रकृत रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय

होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम से, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी व्यपगत हो जाए किया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी अतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(33)/86-एस. एस.-2]

S.O. 894.—Whereas Messrs. Himachal Pradesh Agro-Industries Corporation Limited Summer Seat Simla-171001, (PN|4001), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(33)|86-SS-II]

का. आ. 895 :—मैसर्स आयसर फार्म-मशीनरी लि., प्लोट नं.—29-30, सैक्टर-11, इण्डस्ट्रीयल एरिया, परवानू हिमाचल प्रदेश, (पी. एन./6031) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरिक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चंडीगढ़ की पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है । तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(34)/86-एस.एस.-2]

S.O. 895.—Whereas Messrs. Eichier Farm Machinery Limited Plot No. 29-30, Sector-II Industrial Area, Parwanoo, (HP) (PN|6031), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(34)/86-SS-II]

का. आ. 896.—मैसर्स मपर इलोए कास्ट, प्लोट नं.-62, सैक्टर-6 फरीदाबाद (पी. एन./4884) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त फरीदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरिक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त फरीदाबाद के पूर्व अनुमोदन के

किया नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014(35)/86-एम. एस.-2]

S.O. 896.—Whereas Messrs. Super Alloy Cast, Plot No. 62, Sector-6, Faridabad (PN/4884), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Faridabad maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Faridabad and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(35)/86-SS-II]

का. आ. 897 :—मैसर्स के. डब्ल्यू. इंजिनियरिंग वर्क्स (रजि.), बी-11, फोकल प्वाइन्ट, लुधियाना-141010 (पी.एन./995) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक

अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(36)/86-एस.एस.-2]

S.O. 897.—Whereas Messrs K. W. Engg. Work (Regd.) B-11 Focal Point Ludhiana-141010 (PN/995) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall desplay on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and

when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance, Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Chandigarh and where any amendment is likely to effective adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsible for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the decreased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(36)|86-SS-II]

का. आ. 898.—मैसर्स दि एम. पी. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, अपेक्स बैंक बिल्डिंग, टी. टी. नगर, भोपाल (एम. पी./3068) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(37)/86-एस.एस.-2]

S.O. 898.—Whereas Messrs The M.P. Rajya Sahakari Sangh Maryadit Apex Bank Building T.T. Nagar Bhopal (Madhya Pradesh) (MP/3068) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the decreased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(37)/86-SS-II]

का. आ. 899.—मैसर्स ओ. डब्ल्यू. एम. वूल कोम्बर्स, जी.टी. रोड, शेरपुर, लुधियाना-3 (पी.एन./125-बी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एम-35014(38)/86-एस.एस.-2]

S.O. 899.—Whereas Messrs O.W.M. Wood Combers, G.T. Road, Sherpur, Ludhiana-3 (PN/125-B) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishmen from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favour-

able to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(38)/86-SS-II]

का. आ. 900.—मैसर्स नेशनल फास्टनर्ज प्रा. लि. डवल्पड प्लाट नं. एस-19, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गुन्डी, मद्रास-600032 (टी.एन./3579) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनीयम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3ख) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर की बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त

स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(39)/86-एस.एस.-2]

S.O. 900.—Whereas Messrs National Fasteners Private Limited, Developed Plot No. S-19, Industrial Estate Guindy, Madras-600032 (TN/3579) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such insnection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the decreased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(39)/86-SS-II]

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1986

का.आ. 901.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इटावा को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोटा, राजस्थान नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजकों और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा-1 की उपधारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(24)/86-एस.एस.-2]

New Delhi, the 19th February, 1986

S.O. 901.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Itawa Co-operative Society Limited. Kota, Rajasthan have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Secion 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(24)/86-SS-II]

का.आ. 902.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्रीअप्पा पैन्ट इंडस्ट्रीज प्लाट नं. डी-16 कुप्पालुर इन्डस्ट्रीयल स्टेट कुप्पालुर अवुरई-6, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजकों और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(110)/86-एस.एस.-2]

S.O. 902.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Ariappeo Paint Industries Plot No. D-16, Kappalur Industrial Estate, Madurai-6 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Secion 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(110)/86-SS-II]

का.आ. 903.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जैड ए 109, मंगुदी फारमर्स सर्विस को-आपरेटिव सोसायटी लि०, थेन्नावरानाडुर मंगुदी-610103 थान्जोवर डिस्ट्रिक्ट नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(111)/86-एस.एस-2]

S.O. 903.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Z. A. 189, Mangudi Farmers Service Co-operative Society Limited Thennavaranadlur Mangudi-610103 Thanjavur District have agreed that the Provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(111)/86-SS-II]

का.आ. 904.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि प्लाटीनम जुबली इन्वेस्टमेंट लि., 903-906, रहेजा चैम्बर्स 9वीं मंजिल 213, नारीमन प्वायंट बम्बई-21 और इसकी अहमदाबाद में स्थित शाखाएं नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35018(4)/86-एस.एस.-2]

S.O. 904.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Platinum Jubilee Investment Ltd., 903-906, Rahoja Chambers, 9th Floor, 213, Nariman Point Bombay-21 and its branch in Ahmedabad have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(4)|86 SS-II]

का.आ. 905.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि स्टैंडर्ड रबड़ मैन्युफैक्चरर्स 1/बी 2, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, ब्लाक-डी कल्याणी (जि० नदिया) और इसकी पी-30/बी, सी.आई.टी. रोड, कलकत्ता-14 स्थित आफिस नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35017(6)/86-एस.एस.-2]

S.O. 905.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Standard Rubber Manufacturers 1|B-2, Industrial Estate Block-D, Kalyani (Dist. Nadia) including its office at P-30/B, C.I.T. Road, Calcutta-14 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(6)/86-SS-II]

का. आ. 906.—मैसर्स एक्सप्रेस न्यूजपेपरस लि., एक्सप्रेसटेट मांऊट रोड, मद्रास-2 (टी. एन./8067) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के **अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।**

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरिक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का यहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(46)/86-एस.एस.-2]

S.O. 906.—Whereas Messrs. Express Newspapers Limited, Express Estates, Mount Road, Madras-2 (TN/8067) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2B) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the regular employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2B) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempt the regular employees of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Com-

missioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(46)/86-SS-II]

का. आ. 907.—मैसर्स प्रकाश पाइप्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि. 15, के. एम. स्टोन, दहली रोड, विलेज भत्तर, डिस्ट्रिक्ट हिसार (हरियाणा), (एच. आर./9838) और इसका पदमा टावर राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 में स्थित मुख्य कार्यालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 उप-धारा (2-क) के अधीन **छूट दिए जाने के लिये आवेदन किया है ;**

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन **कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि** की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात को होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के **बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों** के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय

तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014 (60)/86-एस. एस.-2]

S.O. 907.—Whereas Messrs. Prakash Pipes & Industries Limited 15, K. M. Stone, Delhi Road, Village Mayar Distt. Hissar (Haryana) (HR/9838) including its head office at Padma Tower, Rajender Place, New Delhi-110008, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notce Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be tha of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(60)/86-SS-II]

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1986

का.आ. 908.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम.आर. सिल्क्स तिरुवरूर (तमिलनाडु) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या: एस-35019 (84)/86-एस एस-2]

New Delhi, the 20th February, 1986

S.O. 908.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. M. R. Silks, Tiruvarur, Tamil Nadu have agreed that the Provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(84)/86-SS-II]

का. आ. 909.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इडामलूर कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई सोसायटी लि., इडामलूर मन्नारगुडी तालुक नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019 (86)/86-एस०एस.-2]

S.O. 909.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Melayur Co-operative Milk Supply Society Ltd., Edamelayur, Mannargudi Taluk have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Secion 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(86)/86-SS-II]

का.आ. 910.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि गवर्नमेंट सरवैण्ट्स को-आपरेटिव स्टोर्स लि. 2 सी 62 मन्नारगुडी नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(85)/86-एस.एस-2]

S.O. 910.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. The Government Servants Co-operative Stores Ltd. 2C, 62 Mannargudi, Madras have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(85)/86-SS-II]

का.आ. 911.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दशरथ एण्ड सन्स, आटोमोबाइल एण्ड सर्विसिंग इन्जीनियर्स नं. 37-38 नोर्थ स्ट्रीट कोम्बाकोणम नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या : एस-35019(87)/86-एस.एस.-2]

ए. के. भट्टराई, अवर सचिव

S.O. 911.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. N. Dasarathy and Sons, Automobile and Servicing Engineers No. 37-38, Nageswaran North Street, Kumbakonam-612081 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Secion 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(87)/86-SS-II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1986

शुद्धिपत्र

का. आ. 912.—श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एल–31013/6/84– डी-4(ए) दिनांक 16 जनवरी, 1986 में, अधिसूचना के अंत मे आने वाले शब्दों "केन्द्रीय सरकार को 26 दिसम्बर, 1936 को प्राप्त हुआ था" के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार को 26 दिसम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ था" पढ़ें।

[सं. एल–31013/6/84- डी-4 (ए)]

के. जे. दैव्यप्रसाद, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th February, 1986

CORRIGENDUM

S.O. 912.—In the Ministry of Labour Notification No. L-31013/6/84-D.IV(A) dated 16-1-1986, the words appearing at the end of the Notification "was received by the Central Government on 26th December, 1986" may be read as "was received by the Central Government on 26th December, 1985".

[No. L-31013/6/84-D.IV(A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1986

का.आ. 913.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, कलकत्ता पत्तन न्यास के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 फरवरी, 1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 20th February, 1986

S.O. 913.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Calcutta Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd February, 1986.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 2 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Shri D. K. Mukherjee, Industrial Relations Officer.

On behalf of Workmen—Shri A. K. Mukherjee, Office Secretary of the Union.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal.

AWARD

By Order No. L-32025/3/81-D.IV(A) dated 16th January, 1982, the Government of India, in the Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of the Calcutta Port Trust in holding a trade test afresh for the post of 25 tonnes Crane Driver by inviting applications from all the Crane Drivers and Diesel Crane Drivers overlooking the exclusive claim of Shri Lakhan Chandra Das, Diesel Crane Driver, is just and proper? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The facts leading to the dispute and the reference under consideration may be briefly summerised as follows:

There were two posts of 25 tonnes Crane Drivers under the mangaement of Calcutta Port Trust, aginst which two persons were appointed and they worked in two shifts with no one to relieve them on their weekly day of rest or to work against their casuals abence. There were a number of

Diesel Crane Drivers operating lighter cranes. In the category of Diesel and Electric Crane Drivers under the management of Calcutta Port Trust, Shri Mannalal was on the top in point of seniority and four places below him in point of seniority was Shri Lakhan Chandra Das. To solve the problem of working the 25 tonnes crane during the casual absence or weekly day of rest of regular incumbents the management decided to select only incumbents for the above purpose from amongst Diesel and Electric Crane Drivers and to pay them for the day they might be engaged as per Board's resolution No. 1127, special allowance equivalent to the difference between the presumptive pay in the higher post of 25 tonnes Crane Driver and his own pay in the scale of Diesel/Electric Crane Driver. The point of importance is that Electric and Diesel Crane Drivers were not substantatively appointed in the post of 25 tonnes Crane Drivers as there was no such further post but workmen of another type called upon to shoulder additional work-load by operating 25 tonnes crane and were additionally remunerated. Applications were invited from the workmen for appearing in a trade test. Financial benefit to attract being small there was little response from amongst Diesel and Electric Crane Drivers, particularly from those senior to Shri Lakhan Das. Perhaps they were aware of the Clause 27(q) of Dasgupta Award published in the Gazette of India on 30-1-1958 providing "Any workman declining to shoulder additional responsibility shall be passed over but his seniority for the purpose of normal promotion shall not be affected". On 31-7-1973 another notice was issued. Shri Lakhan Das made an application on 2-8-1973 in which he expressed his willingness for being trade tested. His trade test was held on 16-8-1973 by a competent body and he succeeded in the test. Be it mentioned here that Electric and Diesel Crane Drivers senior to Shri Lakhan Das did not apepar in that test. During the period of suspension of a regular incumbent of the post of 25 Tonnes Crane Drivers from 29-7-1973 to 6-11-1973. Shri Lakhan Das operated 25 tonnes crane to earn additional wages as noted earlier. During the absence of the 25 Tonnes Crane Driver on medical ground from 16-7-1979 to 13-8-1979 and again from 23-8-1979 to 26-9-1979 Shri Lakhan Das again operated 25 tonnes crane and earned additional wages. He was ordered to work on 25 tonnes crane on a temporary arrangement till the vacancy in the post of 25 Tonnes Crane Driver was filled up on 9-4-1980. It was made clear that this temporary arrangement would not give rise to any special claim to the post he was called upon to work in.

Subsequently the management decided to fill up the post of 25 Tonnes Crane Driver by promotion after holding a trade test on the basis of the principle of Seniority cum Suitability and fixed 11-8-1980 for holding the trade test. Shri Lakhan Das however protested against the holding of the trade test by a letter dated 10-9-1980. He contended that having worked in the post of 25 Tonnes Crane Driver previously he had proved and demonstrated his suiabitlity for the post and he had exclusive and irresistable claim to the post to which he could be promoted with every justification. Shri Mannalal however appeared in the trade test held on 11-9-1980 and succeeded therein. Shri Lakhan Das did not appear in the said trade test. Shri Mannalal was appointed to the regular post of 25 tonnes Crane Driver in the pay scale of Rs. 450—793 with effect from 4-10-1980. Considering the circumstances of the case and performance of Shri Das in post of 25 tonnes Crane Driver earlier Shri Das was also appointed in a Supernumeraty post of 25 tonnes Crane Driver in the pay scale earlier noted with effect from 4-10-1980 Shri Lakhan Das is still not satisfied on his behalf his union raised an industrial dispute in terms noted earlier.

3. From the narration of facts it is abandently clear that Shri Lakhan Das operated the 25 tonnes crane after proving his efficiency in a trade test but he did so only in the casual absence or absence otherwise of the regular incumbent of the post and for this he was paid additionally. He was not called upon to officiate in the post of 25 tonnes Crane Driver with an assurance of promotion to the said post. The higher wages Shri Lakhan Das earned by shouldering duties in addition to the normal duties attached to his own post did not motivate Crane Drivers senior to him to appear in the trade test held on 16-8-1973. The question is: Did Shri Lakhan Das by operating 25 tonnes Crane at various times and earning higher wages lay foundation to his exclusive claim to the regular post of 25 tonnes Crane Driver by promotion? - The question must be answered in the negative. No one held out the assurance to Shri Lakhan Das that he would be appointed to the regular post to 25 tonnes Crane Driver by promotion, whenever such post would fall vacant. In the letter dated 9-4-1980 addressed to Shri Lakhan Das the Engineer-in-Charge made it clear that the temporary arrangement persuant to which Shri Das was called upon to work on 25 tonnes crane till the vacancy was filled up would not give rise to any special claim of Shri Das to the above post. So by no stretch of imagination it can be said that the claim of Shri Lakhan Das to the post of 25 tonnes Crane Driver was overlooked by the management. It must be said that the management in the instant case acted fairly and they gave due consideration to Shri Lakhan Das's operating 25 tonnes Crane before regular filling up of the post by Mannalal on promotion, subsequent to a trade test, with effect from 4-10-1980 as the management created a supernumarary post with the same pay scale with effect from 4-10-1980 to accommodate Shri Lakhan Das. For the shake of descency, discipline and fairness, Shri Das should have appeared in the trade test held on 11-9-1980, particularly in view of the provisions of Clause 27 of Dasgupta Award. There was every possibility of his qualifying in the said test. If the authorities after holding the test found Shri Das deficient by few points in respect of seniority compared to Mannalal they could have compensated him by giving weightage on the score of suitability. He would have won appreciation of the authorities by demonstrating his sense of responsibility by operating the 25 tonnes crane during the casual absence of the regular incumbents. I believe there was every possibility of Shri Lakhan Das stealing a march over Mannalal on the test of suitabiilty. Shri Lakhan Das absented himself from the trade test and denied the management the opportunity as noted above. Mannalal cannot be deprived of the post he has been appointed in. In other words Shri Mannlal cannot be given supernumarary post and Shri Das cannot be appointed to the regular post of 25 tonnes Crane Driver although both of them were promoted to the post on an from the same date i.e. 4-10-1980. The reason is that Shri Mannlal is not a party to the present proceeding and no order can be passed to his prejudice herein.

4. In any way the issue refrered to this Tribunal must be answered in the affirmative. The action of the management of the Calcutta Port Trust was just and proper. No injustice was caused to Shri Lakhan Das and it is further to be noted that Shri Lakhan Das is not entitled to any relief.

An Award may be made and published accordingly.

Dated, Calcutta,
The 24th January, 1986.

N. G. CHOUDHURY, Presiding Officer
[No L-32025/3/81-D.IV(A)Pt.]

का.आ. 914—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, कलकत्ता पत्तन न्यास के प्रबंधतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 फरवरी, 1986 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 914.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Calcutta Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd February, 1986.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 52 of 1983

PARTIES:

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Shri D. K. Mukherjee, Industrial Relations Officer.

On behalf of Workmen—Shri A. K. Mukherjee, Office Secretary of the Union.

STATE: West Bengal. INDUSTRY: Coal.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour), by Order No. L-32012/6/83-D.IV(A) dated 30th September, 1983, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Calcutta Port Trust in relation to Chief Mechanical Engineer, in denying promotion of Tindal to Shri Tribeni Ram Ahir is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

2. There is no dispute that posts of Tindals under the Calcutta Port Trust are filled up by promotion of persons from the ranks of Rigging and Slinging Khalasies on the basis of a prescribed trade test. The basis of promotion is not only trade test but also seniority-cum-suitability. Sarboshri Sarju, Babulal Shaw, Gopi Nunia, Tribeni Ram Ahir, Sk. Rahamat and Bharat Routh were Rigging and Slinging Khalasies. In 1980 a trade test was held for selecting Rigging and Slinging Khalasies for promotion to the post of Tindal, after publishing a notice inviting desirous Khalasies to appear in trade test. In the test, amongst the 6 Rigging and Slinging Khalasies earlier named 5 appeared, only Shri Tribeni Ram Ahir did not appear in the test. It is alleged he had gone to his native village with leave sanctioned. On the basis of the result of the trade test published by means of Ext. M-3, three Rigging and Singing Khalasies, namely, Sarboshri Sarju, Babulal Shaw and Gopi Nunia were promoted to the post of Tindal. Although Bharat Routh and Sk Rahamat passed the trade test they could not be simultaneously promoted for want of vacancies, but they were kept waiting after including their names in a panel framed for the purpose. As further vacancies arose another trade test was held between July to October, 1981. In the trade test held besides Shri Bharat Routh and Sk. Rahamat Shri Tribeni Ram Ahir succeeded and in the result published [Ext. M-1 (B)] Shri Bharat Routh and Sk. Rahamat were placed above Shri Tribeni Ram Ahir in terms of the Award of Dasgupta Tribunal. In the second half of 1981 two vacancies occurred in the post of Tindal, Shri Bharat Routh and Sk. Rahamat were absorved in the said two posts on the basis of their result in the two trade tests and Shri Tribeni Ram Ahir's name was shown as waiting for promotion. Shri Ahir felt aggrieved as promotion was denied to him to the post of Tindal. The expression of grievance by Shri Tribeni Ram Ahir and espousal of his cause by Union led to the present reference being to this Tribunal.

3. To justify its giving promotion to Shri Bharat Routh and Sk. Rahamat to the post of Tindal, the management relies on clauses (f) and (g) of Dasgupta Award marked Ext. M-4. The relevant clauses are quoted below:—

(f) If at a particular test more workmen than what are required are found suitable for a job, those who could not be taken in at the time shall be placed in a waiting list in order of seniority and shall be called upon to fill up vacancies as and when they crop up in future. A list of successful candidates indicating the names of those have been taken in and of those who are in the waiting list shall be pasted on the Notice Board of the Recruiting Office.

(g) A workman once passed over shall not be debarred permanently for promotion. He may be admitted to a subsequent test and if he passes the test, he will be considered for promotion only after all the persons who had passed the previous tests as well as those who are senior to him and have qualified at the subsequent test have been absorbed.

4. There is no dispute that Shri Tribeni Ram Ahir did not appear in the trade test held in May 1980 wherein three Rigging and Slinging Khalasies senior to him appeared and qualified, namely, Shri Sarju, Shri Babulal Shaw and Shri Gopi Nunia and they were promoted to the post of Tindal. There is again no dispute that two Rigging and Slyinging Khalasies, namely, Sk. Rahamat and Shri Bharat Routh junior to Shri Tribeni Ahir appeared in the said trade test and succeeded but for want of vacancies they could not be promoted to the post of Tindal and were as such shown in the Panel of wating khalasies. In the trade test held in 1981 all the three Rigging and Slinging Khalasies, namely, Shri Tribeni Ram Ahir, Sk. Rahamat and Shri Bharat Routh succeeded, yet Sk. Rahamat and Shri Bharat Routh were promoted to the posts of Tindal, vacancies being immediately available, but Sri Tribeni Ram Ahir was shown as waiting for promotion. Clause (g) of the Dasgupta Award quoted above first of all lays down that a workman once passed over shall not be debarred permanently for promotion. This sentence does not apply to the facts of the present case. Shri Tribeni Ahir was not passed over in as much as Shri Bharat Routh and Sk. Rahamat were not appointed to the posts of Tindal on the basis of trade test held in May 1980. Assuming for argument's shake that Shri Ahir was passed over, the subsequent sentence in clause (g) provides that he may be admitted to the subsequent test and if he passes the test he will be considered for promotion. Clause (g) adds that he will be considered for promotion only after all the persons who had passed previous tests as well as those who are senior to him have qualified at the subsequent test have been absorbed.

Reading the entire clause (g) with care we gather that (1) a senior workman in order to reap the benefit of clause (g) must have been passed over once only and not for more than once; (2) workmen fit for appointment to promotion posts, passing over a senior workman, are required to qualify in two trade tests, the previous one in which the senior workman did not appear and the immediately subsequent trade test in which along with them the senior workman appeared and qualified; (3) if the workmen who succeeded in the previous test and the subsequent test are senior to the passed over workman (in the sense that he did not appear in the previous trade test) they will be absorbed first in the promotion post; if they are not senior to the passed over workman no question of their being absorbed in any promotion post earlier than the passed over workman would arise and (4) if a workman junior to the passed over senior workman qualified in the previous test and vacancy in the promotion post occurred necessitating his appointment to the promotion post prior to holding a subsequent test, the junior workman will not acquire a vested right to the promotion post; for the period he worked in the higher post, he will temporarily receive pay attached to the post.

5. If we apply this part of the above clause to the three Rigging and Slinging Khalasies, namely, Shri Tribeni Ram Ahir, Shri Bharat Routh and Sk. Rahamat, we reach the conclusion that to have an edge over Shri Ahir in the matter of promotion to the post of Tindal they were required to fulfil two qualifications, namely, (i) they were senior to Shri Ahir and (ii) they qualified at the two tests. Shri Bharat Routh and Sk. Rahamat do not fulfil first qualification noted above although they fulfilled second qualification. We cannot forget as deposed to by MW-1, Shri A. P. Ghosh that the basis of promotion were the passing of the trade test and also seniority-cum-suitability. In the aforesaid circumstances there is no escape from the conclusion that Shri Tribeni Ram Ahir was unjustly denied promotion to the post of Tindal wherein workmen junior to him were promoted and the action of the management of Calcutta Port Trust in denying Shri Tribeni Ram Ahir the post of Tindal is unjustified. To remedy the above wrong Shri Tribeni Ram Ahir should have relief by way of promotion to the post of Tindal from the date Shri Sk. Rahamat his immediate junior was promoted to the post of Tindal.

The Questions referred to this Tribunal are answered accordingly and an Award be made and published.

Dated, Calcutta,

The 24th January, 1986.

Sd/-

N. G. CHOWDHURY, Presiding Officer

[No. L-32012/6/83-D.IV(A)]

का.आ. 915.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, कलकत्ता पत्तन न्यास के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 फरवरी, 1986 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 915.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Calcutta Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd February, 1986.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,

AT CALCUTTA

Reference No. 15 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Shri D. K. Mukherjee, Industrial Relation Officer.

On behalf of Workmen—Shri A. K. Mukherjee, Office Secretary of the Union.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Port.

AWARD

By Order No. L-32011/17/80-D.IV(A) dated 26-3-1981 the Government of India, Ministry of Labour referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management in regard to fixation of stages for trade tests at the end of the two scales, namely, Rs.425—566 and Rs. 465—605 pertaining to skilled artisans is just and proper? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

2. I notice that the reference of the dispute has been made by the Central Government to this Tribunal under section 10(i)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947. Such a dispute must relate to any matter appearing to be connected with or relevant to a matter specified in the Second Schedule or the Third Schedule to the aforesaid Act. To my mind the subject matter of reference has no connection with nor relevant to any of the matters mentioned in the second or Third Schedule of the Act. The reference therefore is incompetent and the entertainment of the reference by this Tribunal would be without jurisdiction. Such a situation could be avoided if the officers of the Central Government had applied their mind to the subject matter of the reference and read the items mentioned in the Second and Third Schedules of the Act. However, on this preliminary ground I am not rejecting the reference since the reference is pending for quite a long time; further in view of the definition of industrial dispute given in section 2(k) of the Industrial Disputes Act, words used in section 10(d) and items mentioned in Second and Third Schedules to the Act it is possible to take a broad view that reference of the dispute to this Tribunal is justified.

1565 GI/85—21

3. The undisputed fact is that the skilled artisans holding posts coming under the scheme of skilled scales under the Calcutta Port Trust have been enjoying three short scales as noted in Annexure 'C' to the employers written statement. What was the earlier and what is the present scale according to the recommendation of Wage Revision Committee have been given in the said annexure. The three scales have always been integrated, they could be enjoyed by an artisan in course of his carrier under the Calcutta Port Trust. Original three scales are as follows : (i) Rs. 150-4-170-5-190, (ii) Rs. 166-4-170-6-225 and (iii) Rs. 190-8-254. Wage Revision Committee recommended revision of these scales as follows (i) Rs. 400-7-435-EB-8-515-EB-10-565, (ii) Rs. 420-7-455-EB-9-545-10-595 and (iii) Rs. 425-8-465-EB-10-535-12-655. It was further modified w.e.f. 1-8-1977 as (i) Rs. 425-11-436-EB-13-566, (ii) Rs. 465-13-530-EB-15-605 and (iii) Rs. 535-15-655.

From Annexure 'A' to the written statement of the employer it seems that to traverse the three time scales an artisan had to serve for at least 19 years formerly. At present he will require only 17 years time to cover the scales. Be that it may the important point is that even earlier workmen had to undergo a trade test at the end of the first stage of the time scale to get the benefit of the second stage of the time scale and he had to appear in a further trade test at the end of the time scale of the second stage to reach the third stage of the time scale. Consequent to the revision of the pay scale by the Wage Revision Committee from 1-8-1977 the management has decided that workmen will have to appear in the trade tests at the end of the first stage of the time scale, namely, Rs. 425—566 and at the end of second stage of the time scale, namely, Rs. 465—605. Such trade tests were held at the end of the first and second stage of the time scale even before modification of the pay scale by the Wage Revision Committee. So there is nothing unfair, unjust or new in prescribing holding of trade tests at the end of the time scale of the two stages.

But on behalf of the union it is contended that if a workman is trade tested at the stage he reaches Rs. 566 he will be fitted in the second stage at Rs. 575 and he will continue to get a benefit of Rs. 9 per month by way of usual annual increment in the second stage although during the first stage of the time scale he was enjoying annual increment of Rs. 13 p.m. It is further argued that when a worker having qualified at the trade test at the end of the second stage of the time scale reaches the the third scale and gets benefit of Rs. 5 p.m losing, as Rs. 10 his usual annual increment at the initial stage of third scale and at the second stage his annual increment is Rs. 15 per month. On behalf of the union it is contended because of this loss to the workmen the fixation of the trade tests at the end of the two scales as noted in the schedule by the management is unjust and improper. Such a plea has no merit. Such trade tests were held at the end of the two stages of the time scale even before revision of the pay scale. Further I have indicated that some benefit has been conferred on the workmen by enabling them to traverse the entire pay scale within a shorter period than they used to do prior to revision. Further I may note that at the initial stage of the time scale annual increments are higher to inspire workmen to acquire skills and aptitude. At the second and third stages of the time scales the workers become experienced and habituated worker anxious to reach the top of the scale as early as they can and to reach the top of the scale they may forego enhanced annual increment at the two subsequent stages of the scale.

4. I am therefore to hold that the management did not act unjustly or improperly in fixing stages for trade test as the end of the two scales as noted in the order of reference. The question referred to the Tribunal is framed in the affirmative the workmen concerned is not entitled to any relief.

An award accordingly may be made and published.

Dated, Calcutta,

The 21st January, 1986.

N. G. CHOWDHURY, Presiding Officer

[No. L-32011/17/80-D-IV(A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1986

का. आ. 916.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, दुर्ग (मध्य प्रदेश) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-2-86 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 18th February, 1986

S.O. 916.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bhilai Steel Plant, Bhilai, Durg (MP) and their workmen, which was received by the Central Government on the 5-2-1986.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(65)/1984.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhilai Steel Plant, Bhilai, Distt. Durg (M.P.) and their workman, Shri P. K. Chaki, H. S. Machinist (S-6) represented through the Sanyukta Khadan Mazdoor Sangh (INTUC) P.O. Dallirajhara District Durg (M.P.)

APPEARANCES :

For Union.—Shri C. R. Bakshi.

For Management.—Shri D. C. Henri, Senior Law Officer.

INDUSTRY : Iron Ore Mine DISTRICT : Durg (M.P.)

AWARD

Dated, January 23rd, 1985

This is a reference made by the Government of India to the Ministry of Labour for adjudication of the following dispute vide its Notification No. L-26012(1)/84-D.III.B dated August 10, 1984:—

"Whether the action of the management of Bhilai Steel Plant in superseding Shri P. K. Chaki, H. S. Machinist (S-6) making Shri G. N. Dixit, Material Chaser (S-5) senior to him for promotion to the post of Chargeman (Mech), is justified? If not, to what relief is Shri P. K. Chaki entitled?"

2. Facts leading to the present reference are that as on 31-8-1970 Shri P. K. Chaki and Shri G. N. Dixit were respectively in the pay scale of Rs. 156-221. Consequent upon the general wage revise both the workmen were allowed the then S-5 grade as on 1-9-1970. That in the year 1974 Shri P. K. Chaki was promoted as highly skilled Fitter in the revised pay scale of S-6 while Shri G. N. Dixit who was junior to him remained in S-5. According to line of promotion existing prior to 26-2-1980 the following categories of workmen employed in N-5 grade were eligible for promotion to the post of either highly skilled Craft Category or Chargeman Grade III i.e. S-6 in the grade of Rs. 530-894:—

Category		Grade
1		2
1. Fitter (Mech.)		
2. Welder/Gas Cutter		
3. Rigger	}	S-5 (Rs. 490-777)
4. Machinist/Turner		
5. Blacksmith		

Whereas for promotion to the post of Chargeman passing of prescribed trade test was necessary and promotion to the highly skilled category was made subject to passing the skill evaluation test. While the other two categories of workmen having S-5 grade viz. HSA & Material Chaser were eligible for promotion to S-6 grade. In other words whereas the Craft Category had the avenue of promotion both to the post of Chargeman as well as highly skilled category S-6 grade the isolated category of H.S.A. and Material Chaser had only one avenue of promotion to the Chargeman post Grade III.

3. In the year 1974, 17 workmen employed in different Craft Category in S-5 were called for trade test in the month of July, 1974 for the purpose of testing suitability for the post of Chargeman Gr. III (S-6). Seniority position of Shri Chaki was seventeenth. According to available vacancies of senior post five persons were promoted as Chargeman Gr. III who were senior to Mr. Chaki. In the month of December, 1974 some vacancies were available at S-6 grade on highly skilled Craft Category. Shri Chaki was offered S-6 grade, he appeared in the skilled evaluation test and passed. Accordingly he was promoted in highly skilled Mechanic Grade in S-6 and he accepted the same with effect from 31-12-1974.

4. That an element of supervision was involved in the post of Chargeman S-6. While the post of highly skilled Fitter (S-6) was non-supervisory. In view of this, a supervision clash was foreseen due to the fact that the senior workman was likely to be supervised by the Chargeman, a junior person. Therefore to remove this ridiculous and anamolous position a dispute was raised by the said recognised Union and an Agreement was arrived before the Conciliation Officer under Sec. 12(3) of the I.D. Act between the S. K. M. Sangh, hereinafter referred to the Union, and the management of Bhilai Steel Plant, hereinafter referred to as the management, on 26-2-1980, extract of which is being reproduced below:—

(1) "It is agreed that in the event of a post of Chargeman S-6 falling vacant in any discipline where the posts of Highly Skilled artisans also exists, the highly skilled workmen in S-6 will be considered first, for redesignation as Chargeman in the same grade in S-6 after fulfilling the necessary conditions of Trade Test etc., before the workmen in S-5 categories are considered for the same.

(2) It is agreed that the L.O.P. will stand modified as above.

(3) It is agreed that this agreement will come into force with immediate effect.

(4) It is agreed that the settlement will be implemented on or before 31-8-80.

(5) It is agreed that the implementation report will be sent to the A.L.C. (c) Raipur on or before 15-4-1980, failing which it shall be presumed that the settlement has been fully implemented."

The above agreement was to come into effect immediately as per Clause 3 of the Agreement or was to be implemented on or before 31-3-1980.

5. It appears that some difficulty cropped up and as a result of discussion held by the management and the said Union on 29-4-1980 and 14-5-1980 a note of discussion was recorded to the following effect:—

"Whereas certain clarification are required for implementing the said agreement, the matter was discussed between the parties at Bhilai on 29-4-80 and on 14-5-80 and it is agreed as follows:—

(1) Seniority :

Any Highly Skilled workman, who opts for redesignation as Chargeman would count his seniority in the cadre only from the date of such redesignation, as per rules.

(2) LOP :

The Material Chaser and HSA in S-5 grade are already eligible for the post of Chargeman (S-6)

as per the existing LOP. It is hereby agreed that Material Chaser, HSA or any such other isolated posts would be considered for promotion to the post of Chargeman at a time when they would have otherwise become eligible for promotion to this post had the agreement of 26-2-1980 have not come in vogue. At the time when his turn in the LOP come, a post of Chargeman would be notionally made available from amongst the total number of Chargeman|HS workmen for his promotion."

6. Shri Chaki who was holding S-6 grade as highly skilled Machinist was given an option of redesignation as Chargeman along with the other workmen. He accepted the above option vide his application dated 17-8-80 stating that he has already passed the trade test and he is willing to accept the terms and conditions i.e. his seniority in the cadre of Chargeman (S-6) will be counted from the date they are so redesignated. The previous service in the same grade will not be counted towards seniority for further promotion in S-7 grade etc.

7. The crucial question as per the above narration cropped up at this stage. According to the workman, Shri Chaki, the management did not put the conciliation settlement in operation knowingly and deliverately and his option was not considered by the management deliberately till 31-10-1981. In the meantime the junior workman, Shri G. N. Dixit, who was in S-5 grade till 19-12-1980 was promoted to S-6 grade as Chargeman with effect from 20-12-1980. As per the settlement dated 26-2-1980 Shri Chaki should have been considered for redesignation as Chargeman as on 17-8-1980 instead of waiting till Shri Dixit was promoted on 20-12-1980. He was redesignated after ten months only on 21-10-1981.

8. That service condition and the right confirmation of the workman through conciliation settlement on 26-2-1980 should not have been brushed aside on the mere record note of discussion since the parties to record note of discussion had no right or jurisdiction to give clarification or interpretation of the same and the management had no privilege to take shelter of record note of discussion on 14-5-1980 in preference over the conciliation settlement dated 26-2-1980 and discriminate not only him but also 52 other workers who have been superseded by Shri G. N. Dixit.

9. On the other hand, the case of the management is that the conciliation settlement dated 26-2-1980 was modified by the parties to the agreement and signed by them on 14-5-1980 to the effect that on vacancy of Chargeman Gr. III (N-6) became available, highly skilled workman in S-6 grade were to be first considered for redesignation as Chargeman in Gr. 6 and those of highly skilled workmen who may opt for redesignation as Charge Gr. 6 was to count his seniority on such redesignation.

10. Thus the bone of contention is narrowed down in brief compass to the Conciliation Settlement dated 26-2-1980 and the record note of discussion dated 14-5-1980 and their validity inter se.

11. I have already reproduced the Settlement in Conciliation dated 26-2-1980 that in the event of post of Chargeman falling vacant in any discipline where any post of highly skilled Artisans also exist the highly skilled workmen in S-6 will be considered first for redesignation for highly skilled post as Chargemen after fulfilling the necessary condition of trade test before the workmen S-5 categories are considered for the same.

12. This is crystal clear and it requires no interpretation that Chargemen of S-5 category like Mr. Dixit are to be considered for promotion after the highly skilled workmen in C-6 like Mr. Chaki are redesignated as Chargemen in the same grade. It is to be further noted that this Agreement was to come into effect immediately as per Clause 3 of the said Agreement and it was to be implemented on or before 31-3-1980. The workman, Shri Chaki had passed his trade test according to the pleadings of the management on 14|15-1-1980 as he has also stated in his option application Ex. M|7 dated 17-8-1980. This happened before Mr. Dixit's promotion became due on 20-12-1980. The contention of the management in this regard is that the seniority position of Mr. Naki was seventeenth in his grade so he could not have been promoted when there were no vacancy for him. To my mind, this is no excuse. Once the Conciliation Settlement had arrived at it is not only binding as a Settlement between the employer and the workmen under Sub-section (1) of Sec. 18 but it is binding on all the parties to Industrial Dispute as has been laid down in Sub-section (3) of Sec. 18 of the Industrial Disputes Act. This view of mine is also fortified from the pronouncement made in the case of M|s. Tata Chemicals Ltd. Vs. Workmen (AIR 1978 SC 828).

13. The second limb of the contention of the management is that the parties to the conciliation settlement had clarified the interpretation of the Settlement dated 26-2-1980 vide record note of discussion dated 14-5-1980. Therefore it is also binding between the parties since Shri C. R. Bakshi representative of the workmen who was a party to the said Settlement dated 26-2-1980 was also a party to the clarification. I am unable to agree that the Settlement in conciliation will over-ride any subsequent private settlement between the parties either by way of interpretation or by way of modification.

14. However, assuming for the sake of arguments that the record note of discussion is only a clarification (which it is not, since it is a modification). Even then to my mind the position in the instant case ought not to have differed. The modification under the line of seniority (LOP) is that highly skilled workman who opts for redesignation is Chargeman could count his seniority in the cadre from the date of such redesignation as per rules. I have already pointed out that Shri Chaki had passed his trade test on 14|15-1-1980. He was given the option along with the others on 8th August 1980 (Ex. M|6). He accepted the option vide his letter dated 17-8-1980 (Ex. M|7). Now as already pointed out at this stage question of promotion of Shri G. N. Dixit had not arisen. He became eligible for promotion only on 20-12-1980 i.e. nearly after four months of the offer and acceptance of the redesignation by Shri Chaki. If he was redesignated at that stage even according to the record note of discussion he would have got seniority from that date i.e. before Mr. Dixit. Therefore this part of the so called interpretation would not have adversely affected his case. The LOP i.e. Line of Promotion given in the record of note of discussion dated 14-5-1980 says that the Material Chaser and H.S.A. in Gr. 5 are already eligible for the post of Chargeman Gr. S-6. Therefore they will become eligible for promotion in this post inspite of the Agreement dated 26-2-1980 when their turn comes for promotion. Relying on this, the contention of the management is that in view of the above clarification Shri Dixit was promoted as if the Agreement dated 26-2-1980 had not come into vogue. I have already discussed the legal aspect of two agreements. But inspite of their diversity as pointed out it does not materially affect the case of Shri Chaki because this very Agreement dated 14-5-1980 under the heading LOP further says that when Material Chaser and H.S.A. in Gr. 5 are promoted, a post of Chargeman would notionally be made available from amongst the total number of Chargemen H.S.A. workmen for promotion. This shatters the very bone of contention raised by the management that for want of vacancies Shri Chaki could not have been promoted because he was ranking Seventeenth. To my mind even if he was ranking Seventeenth Shri Dixit could have been only promoted as Chargeman Gr. 6 on a post notionally created for him and not in the regular cadre. In such cases when people are taken from outside in a particular grade they are generally placed at the bottom of that cadre. In the instant case, if Shri Chaki was redesignated on the due date he would have been senior and Shri Dixit ought to have been promoted on the post created notionally and placed at the bottom of the persons allowed to be redesignated as Chargeman as per the Settlement dated 26-2-1980 and even as per record note of Settlement dated 14-5-1980. I am, therefore, of the opinion that on such an interpretation even of the said clarification dated 14-5-1980 Shri Chaki ought to have been redesignated senior to Shri G. N. Dixit.

15. Lastly I will briefly take up the prayer of the Union for the workmen that the cases of 52 other workmen who have also been superseded by Shri Dixit should be consi-

dered. I am afraid, I am unable to do so for want of reference in this regard. The reference in question relates to only Shri P. K. Chaky and not to 52 other workmen.

16. Consequently I hold that the action of the management of Bhilai Steel Plant in superseding Shri P. K. Chaky, H. S. Machinist (S-6) and making Shri G. N. Dixit Material Chaser (S-5) senior to him for promotion to the post of Chargeman (Mech) is unjustified. Shri P. K. Chaky is therefore entitled to be placed senior to Shri G. N. Dixit as if he is being redesignated as Chargeman on 17-8-1980. The management will pay Rs. 250 as costs to the workman. I answer the reference accordingly.

V. S. YADAV, Presiding Officer.

Dated . 3-1-1986.

[No. L-26012(1)|84-D.III(B)]
SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1986

का.आ. 917.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ब रामनागोर कोलियरी, टाक कुल्टी जिला बर्दवान के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-2-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 18th February, 1986

S.O. 917.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ramnagore Colliery, P.O. Kulti (Burdwan) and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd February, 1986.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 21 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the management Ramnagore Colliery, P.O. Kulti (Burdwan).

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri Justice N. G. Chowdhury.—Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Shri Nilay Ghosh, Advocate.

On behalf of Workmen.—Shri Gautam Som, Advocate.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal

AWARD

By Order No. L-19012(66)|83-D.IV (B) dated 8th June, 1984, the Government of India, Ministry of Labour & Rehabilitation (Department of Labour) referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Ramnagore Colliery P.O. Kulti (Burdwan) not to regularise Shri Lajnath Singh as Head Peon in the Technical and Supervisory Grade-F with effect from 20-8-80 is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. The case was called out for hearing on 22-1-1986 but the parties filed a Compromise Petition and submitted that an Award be passed in terms of the Compromise petition. Accordingly I have gone through the Compromise petition and find it reasonable and for the benefit of the parties. I therefore, accept the same and pass an 'Award' in terms of the said Compromise Petition which will form part of this Award as Annexure-'A'.

Dated, Calcutta,

The 24th January, 1986.

N. G. CHOWDHURY, Presiding Officer
[No. L-19012(66)|83-D. IV(B)]

ANNEXURE-'A'

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-LABOUR COURT IN WEST BENGAL AT CALCUTTA

Reference Number 21 of 1984

PARTIES

Employers in relation to the Management of Ramnagore Colliery of M|s. IISCO Limited,

AND

Sri Rajnath Singh, Workman, represented by Colliery Mazdoor Sabha of India (CITU), Asansol (Burdwan).

PETITION OF COMPROMISE

In the matter of adjudication of above dispute, both the parties have agreed to settle their difference amicably and after a number of discussions, it has been agreed as follows :—

1. It is agreed to promote Sri Rajnath Singh, P. No. 14030, Office Peon, to the post of Head Peon in the Tech. & Supv. grade 'F' in the pay scale of Rs. 605-18-857 from the date of signing of the settlement. Next date of annual increment shall fall due on 1st March.

2. It is also agreed that the post will remain personal to Sri Rajnath Singh and deemed to be deleted from the date the post falls vacant for whatsoever reason may be.

3. It is agreed that no arrear wages or any other benefit whatsoever may be, shall either be claimed or payable to Sri Rajnath Singh.

4. It is agreed that this settlement will resolve|settle this dispute fully and finally.

That since the above terms of settlement forming the position of compromise are fair and reasonable and both the parties have jointly agreed and accepted the same, the compromise position is filed before the Hon'ble Tribunal.

That both the parties, therefore, pray that the Hon'ble Tribunal will be pleased to record the compromise petition and give its Award in terms thereof and a copy of this compromise petition may be made a part of the Award.

For & on behalf of the Employer

Sd|-
1-3-85

1. Sri P. K. Mukherjee, Agent, Ramnagore Colliery.

Sd|-
1-3-85

2. Sri Mohit Mukherjee, Manager (PL).

Witness :

For & on behalf of the Union.

Sd|-
1-3-85.

1. Sri Rabin Mondal, President, Colliery Mazdoor Sabha of India (CITU) Ramnagore Branch.

Sd|-
1-3-85

2. Sri Sukumar Paul, Org. Secy. Colliery Mazdoor Sabha of India (CITU).

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1986

का.आ. 918.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ब रामनागौर कोलियरी मैसर्स इसको, डा. कुल्टी, जि. बर्दवान के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-2-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 19th February, 1986

S.O. 918.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ramnagore Colliery of M/s. IISCO, P.O. Kulti, Distt. Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd February, 1986.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 17 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of Ramnagore Colliery of IISCO, P.O. Kulti, Distt. Burdwan,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Shri Nilay Ghosh, Advocate.

On behalf of Workmen.—Shri Gautam Som, Advocate.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal

AWARD

By Order No. L-19012(67)/83-D.IV (B) dated 16th May, 1984, the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Ramnagore Colliery of HSCO, P.O. Kulti, Distt. Burdwan in not regularising Shri Kalo Mallik as Mechanical Fitter category IV with effect from 20-2-83 is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. At the time of hearing on 22-1-1986 the parties filed a Compromise Petition and submitted that an Award be passed in terms of the Compromise Petition. Accordingly, I have gone through the Compromise Petition and find it reasonable and for the benefit of the parties. I therefore, accept the same and pass an 'Award' in terms of the said Compromise Petition which will form part of this Award as Annexure—'A'.

Dated, Calcutta,

The 24th January, 1986.

N. G. CHOWDHURY, Presiding Officer

[No. L-19012(67)/83-D.IV (B)]

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL/LABOUR COURT IN WEST BENGAL AT CALCUTTA

Reference Number 17 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Ramnagore Colliery of M/s. IISCO Limited,

AND

Shri Kalo Mallick, Workman, represented by Colliery Mazdoor Sabha of India, Asansol (Burdwan).

PETITION OF COMPROMISE

In the matter of adjudication of above dispute, both the parties have agreed to settle their difference amicably and after a number of discussions, it has been agreed as follows :—

(1) It is agreed to promote Sri Kalo Mallick, P. No. 10157, Mazdoor Category II to the post of Fitter, Category IV in the pay scale of Rs. 24.10-0.80-35.30 from the date of signing of the settlement.

(2) It is agreed that no appear wages or any other benefit whatsoever may be, shall be claimed by and payable to Sri Kalo Mallick.

(3) It is agreed that this settlement will resolve/settle all disputes fully and finally.

That since the above terms of settlement forming the petition of compromise are fair reasonable and both the parties have jointly agreed and accepted the same, the compromise petition is filed before the Hon'ble Tribunal.

That both the parties, therefore, pray that the Hon'ble Tribunal will be pleased to record this compromise petition and give its Award in terms thereof and a copy of this compromise petition may be made a part of the Award.

For and on behalf of the Employer :

(1) Sri P. K. Mukherjee, Agent, Ramnagore Colliery

(2) Sri Mohit Mukherjee, Manager (PL)

witness :

For and on behalf of the Union :

1. Sri Rabin Mondal, President, Colliery Mazdoor Sabha of India (CITU), Ramnagore Branch,

2. Sri Sukumar Paul, Org. Secy. Colliery Mazdoor Sabha of India (CITU), Ramnagore Branch.

का.आ. 919.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ब कुमारडीह 'बी' कोलियरी, डाक उखरा, जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-2-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 919.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kumardihi 'B' Colliery, P.O. Ukhra, Distt. Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th February, 1986.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 20 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kumardihi 'B' Colliery, P.O. Ukhra, Distt. Burdwan.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Shri S. N. Saigal, Deputy Personnel Manager.

On behalf of Workmen.—Shri C. S. Banerjee, General Secretary of the Union.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal

AWARD

The following dispute was sent by the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) to this Tribunal for adjudication by Order No. L-19012(72)/83-D.IV (B) dated 18th May, 1984 :

"Whether the action of the management of Kumardihi 'B' Colliery, P.O. Ukhra, Distt. Burdwan in dismissing Shri Chandra Majhi, No. 2 with effect from 15-3-1981 is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. The case was fixed for hearing today. The parties appeared and filed a Compromise Petition and prayed for an award in terms of the said petition. I have gone through the Compromise Petition and find it reasonable and for the benefit of the parties. I, therefore, accept the same and pass an 'Award' in terms of the said Compromise Petition which will form part of this Award as Annexure—'A'.

Dated, Calcutta,

The 28th January, 1986.

N. G. CHOWDHURY, Presiding Officer
[No. L-19012(72)/83-D.IV (B)]

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

In the matter of Reference No. 20 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Kumardihi Colliery of Eastern Coalfields Limited.

AND

Their workmen.

JOINT PETITION OF COMPROMISE :

Both the parties herein concerned most respectfully showeth :—

1. That the above matter is pending adjudication before this Hon'ble Tribunal and the matter has not been heard as yet.

2. That, in the meantime, the workman connected with the instant matter expired.

3. That, both the parties discussed the instant matter mutually and have come to an amicable settlement of the instant matter on the following terms :—

TERMS OF SETTLEMENT

(a) That, the Union herein concerned is no longer interested in the instant matter in view of the death of the workman concerned with the instant matter and submits that the instant matter may be disposed off. If the Management agrees to pay the amount of gratuity as per the Payment of Gratuity Act, 1972 payable to the deceased workman, Chandra Majhi No. 2 connected with the instant matter together with his legal outstanding dues, if any, to the widow of the deceased workman after identification in the presence of the General Secretary of this Union within two months.

(b) That, the Management agrees to make the payment as stated in paragraph (a) above, within two months from the date this settlement is accepted by the Hon'ble Tribunal.

(c) That, both the parties agree that by this settlement the instant matter and any matter arising out of the instant reference stands fully and finally resolved.

4. That, both the parties pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept the settlement as fair and proper and may be further pleased to pass an Award in terms of the settlement.

And for this act of kindness, both the parties, as in duty bound, shall ever pray.

Dated this the 28th day of January, 1986.

Sd/-
For and on behalf of the Employers :

Sd/-
For and on behalf of the Workman :
General Secretary,
C.M.U. (I.N.T.U.C.)

Dy. Personnel Manager

का.आ. 920.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ब चोरा कोलियरी मैसर्स ई.सी. एल के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद के केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-2-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 920.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chora Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited, P.O. Bahula, Distt. Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th February, 1986.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 32 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of Chora Colliery of M/s. E.C. Ltd., P.O. Bahula (Burdwan).

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Shri Nikhilesh Das, Advocate with Shri I. P. Singh, Personnel Manager.

On behalf of Workmen—Shri S. Yar Mohammed, Vice President of the Union.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour), by Order No. L-19012(2)/84-D.IV(B) dated 27th July, 1984 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Chora Colliery of E.C. Ltd., P.O. Bahula, District Burdwan (W.B.) in superannuating their workman Shri Tribeni Maharaj, Havildar with effect from 10th August, 1982, is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?

2. The dispute as noted above between the management of Chora Colliery of E.C. Ltd. and their workmen arose in the facts and circumstances stated below. M/s. K. C. Thapper and Brother Pvt. Ltd. were owners of the colliery aforesaid before its nationalisation and it is alleged that the workman Shri Tribeni Maharaj joined the said colliery as Havildar on 1st August, 1962. In Form-B Register of employees maintained under the relevant rules the age of the workman on the date of commencement of his employment was noted to be 43 years. The workman alleged that his date of birth was recorded in the 'B' Form Register in the year 1977 to be 43 years According to the workman the management, however started tempering with the age recorded in the Register and the workman protested against the alteration made

in the 'B' Form Register. According to the workman, he was wrongly superannuated on 11th August, 1982. The management, however, contends that after the nationalisation of the colliery, disputes often arose in course of which workmen challenged the correctness of the entries regarding their age made in the 'B' Form Register and in order to avoid such disputes, the management issued a letter bearing No. ECL/CMD/C. 6D/77/4872 dated 13th September, 1977 (Ext. M-3), which laid down :

(1) Normally we should accept the age as recorded in the 'B' Form Register.

(2) In case there is any difference in the recording of age in Form 'B' Register and in the C.M.P.F. Register the age recorded in the C.M.P.F. Register, if free from all doubts regards interpolation etc., should be accepted.

(3) If the C.M.P.F. records is not specifically clear and keeps a doubt the correctness, the age of the workman should be assessed by the "Age Determination Committee" of the Area concerned which is already existing.

After receipt of the circular the age of all the workmen recorded in Form 'B' Register were scrutinised and compared with the age recorded in a book maintained by the erstwhile management of the colliery, prepared on the basis of Declarations made by the workmen in Form 'A' of Coal Mines Provident Fund. After such examination of the records noted above it was noticed that the year of birth of the workman concerned should have been 1919 but the workman was given the benefit of the circular dated 13th September, 1977 (Ext. M-3) and his date of birth was corrected as 10th August, 1922, in the 'B' Form Register. The management contends that he was accordingly rightly superannuated on 10th August, 1982.

3. Before the arguments were heard Shri N. Das on behalf of the management submitted that as a matter of fact the workman was superannuated on 11th August, 1982 and not on 10th August, 1982 as noted in the schedule to the order of reference. According to Shri Das the difference between the actual date of superannuation and the date thereof given in the schedule to the order of reference is one day only. As the date of retirement has been noted to be 10th August, 1982 in the order of reference I proceed on the assumption that, that is the correct date of Shri Tribeni Maharaj's superannuation. I have little power to travel beyond the order of reference.

4. From the narration of facts given above it is abundantly clear that the point in dispute is what is the correct date of birth of Shri Tribeni Maharaj, the workman concerned in this reference. Ext. M-2, the entry in the 'B' Form Register proved on behalf of the management shows that in the column 'Age' 43 years was originally noted and it was subsequently noted through and the date 10th August, 1922 was inserted. Shri S. Yar Mohammad representing the union espousing the cause of the workman contends that the register produced does not appear to have been maintained in the regular course of business. To drive home his point he points out that names of workmen employed subsequent to Shri Tribeni Maharaj were entered in the register earlier than the name of the workman concerned. He points out that serial number assigned to each workman in column-1 of the register has no relation to the date of his commencement of his service. He accordingly contends that the register is a fabricated one, manufactured for the purposes of this case and unworthy of reliance. This argument appears to be forceful, but I cannot overlook that in the last but one column of this register the workman Shri Maharaj's signature in Devnagri script bearing dated 11th August, 1982 is there. If the register was fabricated Shri Maharaj would not have subscribed his signature; further the date of commencement of his service is noted in the register to be 1st August, 1962 and against that date his age was earlier noted to be 43 years, subsequently corrected by giving date of birth as 10th August, 1922. This date was noted in the 'B' Form Register according to the management on the basis of the entries marked Ext. M-4 prepared on the basis of Declaration in Form 'A' regarding the workman's contribution to Coal Mines Provident Fund; the prescribed form with the Declaration signed by the workman was sent to the Provident Fund Commissioner according to the rules. An extract relating to the age and other details of each workman was recorded in Ext. M-4. The date of birth of Shri Tribeni Maharaj has been noted to be 10th August, 1922 on the basis of such declaration in the extract noted above and corrections have been made in the 'B' Form Register subsequently. I see nothing wrong in the 'B' Form Register. It further appears that account number of Provident Fund of Shri Tribeni Maharaj is noted in this abstract register as B/494583. It is not Shri Tribeni Maharaj's case that his account number has been wrongly given there. From all these I feel satisfied that Shri Tribeni Maharaj's date of birth was correctly noted as 10th August, 1922 and on the basis thereof he has been correctly superannuated in 1982. It will be noticed that Shri Tribeni Maharaj did not examine himself as a witness before this Tribunal, he did not produce before the Tribunal any document worthy of reliance to prove that he was born after 10th August, 1922. He has not produced any evidence supporting his contention that entries in the 'B' Form Register were made in the year 1977 and in that year (1977) he was 42/43 years old. It is again worthy of note that Shri Tribeni Maharaj does not produce his identity card which generally records the age of date of birth of a workman. It appears that on the basis of Ext. M-3, Shri Tribeni Maharaj got the benefit of 3 years continued service, in stead of retiring in 1979 on the footing that he was born in the year 1919, he was made to retire on 10th August, 1982 on the basis of Ext. M-4. It is no use arguing that Ext. M-4 does not appear to have been properly maintained. We have already seen that Ext. M-4 is an extract prepared on the basis of Coal Mines Provident Fund Declaration made in Form 'A' and sent to the relevant authorities. If Shri Tribeni Maharaj was sure that in the Declaration Form his date of birth as furnished to the Provident Fund Authority was different from 10th August, 1922, he could have called for the same from the relevant authorities but Shri Tribeni Maharaj did not do that.

5. From a consideration of the case from different angles as discussed above I arrive at the conclusion that the action of the management of Chora Colliery of E.C. Ltd., P.O. Bahula (Burdwan), West Bengal, in superannuating their workman Shri Tribeni Maharaj, Havildar with effect from 10th August, 1982 is justified. Shri Tribeni Maharaj is not entitled to any relief.

An award accordingly be made and published.

Dated, Calcutta,

The 29th January, 1986.

N. G. CHOUDHURY, Presiding Officer
[No. L-19012(2)/84-D. IV(B)]
R. K. GUPTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1986

का.आ. 921.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3(ii) दिनांक 6 अगस्त, 1984 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 567(अ) तारीख 21 मई, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रमांक (5) में उल्लिखित नाम के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(5) श्री आर.एस. चुघ, संयुक्त निदेशक, मैकेनिकल इंजीनियरी (ईंधन) परिवहन मंत्रालय, रेल विभाग (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली।"	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि

[फा. संख्या : एस-32019/4/83-डब्ल्यू.सी. (एम.डब्ल्यू.)]
पी. राघवन, निदेशक

New Delhi, the 20th February, 1986

S.O. 921.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of the second 5 of the Minimum

Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation, (Department of Labour) No. S.O. 567(E) dated the 21st May, 1984 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3(ii) dated the 6th August, 1984, namely :—

In the said notification the name mentioned at serial number (5) shall be substituted as under :—

"(5) Shri R. S. Chugh, Employer's representative
Joint Director,
Mechanical Engineering (Fuel),
Ministry of Transport,
Deptt. of Railways,
(Railway Board),
New Delhi."

[F. No. S-32019/4/83-WC(MW)]
P. RAGHAVAN, Director

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1986

का. आ. 922.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बियास प्रोजेक्ट, तलवाड़ा टाउनशिप, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर (प.) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-2-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 21st February, 1986

S.O. 922.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Beas Project, Talwara Township, District Hoshiarpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th February, 1986.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 74/83(CHD)

I.D. 119/83 (DELHI)

PARTIES :

Employers in relation to the Management Beas Construction Board and Bhakra Beas Management Board.

AND

Their Workmen : Surat Singh and Others.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri J. M. Sharma and Shri N. S. Bawa.

For the Workmen—Shri D. S. Chohan.

ACTIVITY : Bhakra Beas Management Board.

STATE : Punjab

AWARD

Dated, the 29th January, 1986

The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act, per their Order No. L-42011(1)/82-D II(B) dated the 11th December, 1982 read with S.O. No. S-11025(2)/83 dated the 8th June, 1983 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication :

"(1) Whether the action of the management of Bhakra Beas Management Board in lowering down the position and the pay scale of S/Shri Shamsher Singh and 18 others (as given in annexure) is justified ? If not, to what relief the workmen are entitled ?"

(2) Whether the action of the management of Bhakra Beas Management Board in terminating the services of Shri Shiv Lal Singh Carpenter with effect from 7th September, 1981 when there was pendency of conciliation proceedings before the ALC(C), Chandigarh is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

Sl. No.	Name	Designation
1.	S/Shri Surat Singh	F.M.Spy.
2.	Mohinder Singh Kohli	F.M.Ppl.
3.	Harbans Singh	F.M.Spl.
4.	Tarsem Singh	A.F.Spl.
5	Hans Raj	A.F.Spl.
6.	Skander Paul	A.F.Spl.
7.	Ranbir Singh	A.F.Spl.
8.	Sanesh Thakur	Ch. Man Spl.
9.	Bishan Dass	-do-
10.	Rajesh Kumar	-do-
11.	Hari Singh	-do-
12.	Kirpal Singh	-do-
13.	Amar Singh	-do-
14.	Mohinder Singh	-do-
15.	Ram Dhan	Welder
16.	Shadi Lal	Canteen Manager
17.	Shiv Pal	Carpenter
18.	Jagat Ram	Fitter

2. The gist of the matter is that petitioner Shamsher Singh and 18 others, as mentioned in the above quoted annexure were employed in work-charge capacity in the Power Wing of the B.C.B. at Talwara Township. On the completion of the Works at the Project they were retrenched in accordance to Law. However later on they were re-employed by the BBMB for the maintenance and operational purposes of the Project. But in the process they were reduced in rank and deprived of their original pay scales. It was avered that at an earlier stage also a dispute had arisen between the employees and the management of the BCB (Irrigation Wing) regarding the working conditions of the employees and the matter was referred to my ld. predecessor per Reference No. 8-C of 1973. In resultant Award dated 27th June, 1974 the Tribunal had directed the management not only to give preference to the retrenched workers in the matter of re-employment but also to protect their pay scales. The petitioners, therefore, felt having been wronged at the hands of the management and raised an industrial dispute.

3. However when the matter was still being thrashed in the conciliation proceedings before the A.L.C.(C) Chandigarh, one of them viz. Shiv Pal Singh Carpenter was disengaged w.e.f. 7th September, 1981 which, perhaps, aggravated the controversy and that was how that a failure report was submitted to the Appropriate Government who then referred the dispute to this Tribunal, as indicated above.

4. In the proceedings before me, BCB pleaded indifference on the pretext that since on the completion of the Works, they had duly retrenched the petitioners, therefore, they had nothing to do with the case for want of any stakes, whereas Respondent No. 2 i.e. BBMB disowned any liability for want of privity of contract and avered that since it was not a party to the proceedings in Reference No. 8-C of 1973, therefore, it was not bound by any observations made therein or directions given by the Tribunal, it was further pleaded that in the very nature of things, it required an efficient and qualified staff for the maintenance and operational responsibilities of the Project and that in view thereof recruitment was made after screening of candidates by a high powered Selection Committee. It was explained that the petitioners were recruited for the particular posts for which they were found suitable and were thus granted the relevant pay scales. Elaborating its version the BBMB averred that since the petitioners were employed only in work-charge capacity at the BCB but recruited by it in the regular cadre, therefore,

they had no moral or legal right to protect their earlier salary.

5. Even though the answering Respondent No. 2 questioned the maintainability of the reference on a number of technical grounds also giving rise to two preliminary issues framed over and above the terms of reference, yet in all fairness to it, instead of wasting its steam on meaningless technicalities, it contested the case on merits.

6. In support of their respective versions, parties adduced verbal as well as documentary evidence which I have carefully perused and heard them.

7. There is no gain saying the BBMB was neither a party to the proceedings in Reference No. 8-C of 1973 nor was summoned to join the same at any stage. Of course in the relevant Award Ex. W17 dated 27th June, 1974 my learned predecessor was pleased to observe that as and when the Project Works were completed and any other Agency was to take over the same for operational and maintenance purposes it would endeavour to employ, seniority wise, the entire retrenched Work-charge staff who had put in a certain length of service but all the same neither the parties to the proceedings nor even the Tribunal was sure about the identity of the prospective Agency who was sought to be fastend with the responsibility and obligation to re-employ the petitioners.

8. In the same sequence it may also be worth while to note that according to the common case of the parties BCB was concerned only with the constructional aspect of the Project and on the completion thereof, had become, "funtus-officio". Obviously all the employees engaged on the Project, including the Work-charge staff like the petitioners, were retrenched on payment of terminal benefits envisaged under the Industrial Law. It was only then that the BBMB took over the Project for maintenance and operation. In a manner of speaking it was an entirely different venture by a different Organisation.

9. Otherwise too, from the scheme of Sections 78, 79 and 80 of the Punjab Re-organisation Act, as interpreted by the apex Court in the matter of Jaswant Singh Vs. Union of India AIR 1980 S.C. 115 (Para No. 31, 32, 37 and 39), there should be no manner of doubt about their distinct identities to rule out the feasibility of casting responsibilities of an "heir", "successor" or "assignee", as envisaged under Section 18(3)(c) of the Act, on the BBMB. And it was perhaps, in its realisation that almost all the petitioners, who appeared in the witness-box in the proceedings before me, conceded in their cross-examination that the BCB and BBMB were entirely two distinct and separate Employers.

10. In my considered opinion against such a back drop any direction to the contrary, as issued by my learned predecessor could, at its best, be suggestive of compassion rather than of binding legal obligation on the BBMB on whose behalf it was argued in all seriousness that precisely for this very reason it had called and presented the retrenched Work-charge employees before a high powered Selection Committee but keeping in view the enormous responsibility of maintenance and Operation it could not possibly compromise with quality and that was how that only the best available talent was selected and recruited by it.

11. There is yet another important angle to lend credence to the Management's view point in the sense that on their own admission the petitioners were recruited and discharged by the BCB in Work-charge capacity. In the very nature of things they could not be taken on the regular cadre because the Employer itself had a limited goal in completing the Project. On the other hand after taking over the completed Works, the contesting Respondent i.e. BBMB recruited the required staff on its regular cadre. It was, therefore, deemed proper to go in for the best available stuff. And it hardly requires any emphasis that for the obvious reason, the management could not be expected to convert each and every Work-charge employee into a regular one. After all on the values of employment the former fall into an inferior category of employees as compared to the regulars even in accordance to the Supreme Court observations in para No. 43 of the aforesaid matter of Jaswant Singh.

12. I, thus, find no impropriety in the impugned action of the management in picking up the petitioners for the lower category jobs for which they were found suitable; and because on their retrenchment by the Beas Construction Board they had already drawn all the terminal benefits as admissible under the Law, therefore their employment by the BBMB did not entitle them for the protection of their previous status or wages particularly when no such assurance was ever given by the BBMB. For my views I draw support from the distum in the case of Workmen of Punjab State Electricity Board, Vs. Haryana State Electricity Board Chandigarh 1981 Labour Industrial Cases 1586 wherein reliance was also placed on the Supreme Court observations in the matter of Ana-kapalle Co-operative Agricultural and Industrial Society AIR 1963 S.C. 1489 (at page No. 1496).

13. Similarly there is no merit in the petitioners' grouse on the point of disengagement of Shiv Pal Singh Carpenter during the conciliation proceedings before the A.L.C(C). At the risk of repetition it may be pointed out that the conciliation proceedings related to the joint demand raised by a number of employees, including Shiv Lal Singh, regarding the protection of their status and wages enjoyed by them at BCB. The question of his disengagement had no relevance with the controversy under consideration before the A.L.C., though otherwise also the tenure of his employment had come to an end even by afflux of time in the terms of employment. All the same, on behalf of the management an assurance was given during the course of hearing before me to make an earnest endeavour to find out some alternative avenue of his re-employment in the near future. It is besides the point that the concerned workman may also have second thoughts on the proposition because on his own showing, within a few months of his disengagement by the contesting Respondent, he was employed at Mukerian Hydel Project in the same grade.

14. Be that as it may for the reasons recorded above, for want of merit in their case, the petitioners fall in their bid and as such I return my Award against them.

Chandigarh.
29-1-1986.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer
[No. L-42011/(1)/82-D. II(B)]

का. आ. 923.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जनरल मैनेजर बियास डैम प्रोजेक्ट, तलवाड़ा टाउनशिप, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर (प.) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-2-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 923.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of General Manager, Beas Dam Project, Talwara Township, District Hoshiarpur (Pb.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th February, 1986.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 72/83 CHD.

I.D. 111 of 1983 (DELHI)

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Beas Construction Board and Bhakra Beas Management Board.

AND

Their Workmen : Yog Raj and Others.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri J. M. Sharma and Shri N. S. Bawa.

For the Workmen—Shri D. S. Chohan.

ACTIVITY : Bhakra Beas Management Board.

STATE : Punjab

AWARD

Dated the 28th of January, 1986

The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act, per their Order No. L-42011(2)/82-D.II(B) dated the 17th of September, 1982 read with S.O. No. S-11025(2)/83 dated the 8th of June, 1983 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Bhakra Beas Management Board in not absorbing S/Shri Yog Raj, (2) Gurmit Singh (3) Pritam Singh (4) Ajit Singh (5) Dev Raj (6) Narain Dass (7) Tarsim Lal (8) Mela Ram (9) Surinder Kumar (10) Narinder Singh (11) Parshotam (12) Baldev Singh (13) Prithavi Raj (14) Des Raj and (15) Piara Singh Senior workmen for the work of maintenance and operation and instead absorbing their juniors as detailed in the Annexure is justified particularly in view of the direction of the Central Government Industrial Tribunal that in the matter of absorption, offer shall first be made to the work-charge employees in order of seniority in reference No. 8/C of 1973 ? If not, to what relief the workmen are entitled ?"

Sl. No.	Name	Designation	Division
1.	S/Shri Durga Dass	T.M. Mate	Projection & Cabling
2.	Baldev Singh	-do-	-do-
3.	Tarsem Lal	-do-	-do-
4.	Jai Singh	-do-	-do-
5.	Tarsee Lal S/o Shri Gurdass Ram	-do-	-do-
6.	Kewal Singh	-do-	-do-
7.	Gurbachan Singh	-do-	-do-
8.	Kaiser Singh	-do-	-do-
9.	Ram Singh	-do-	-do-
10.	Vas Dev	-do-	-do-
11.	Kishori Lal	-do-	-do-
12.	Siri Gopal	-do-	-do-
13.	Ramesh Kumar	-do-	-do-
14.	Kashmer Singh	-do-	-do-
15.	Saroop Singh	-do-	-do-
16.	Amrit Lal	-do-	-do-
17.	Om Parkash	Chargeman	A & C Division
18.	Khazan Singh	-do-	-do-
19.	Prem Chand	-do-	-do-
20.	Mehar Chand	-do-	-do-
21.	Gurbachan Singh	T.M. Mate	Turbine Division
22.	Rattan Chand	-do-	-do-
23.	Ram Chand	-do-	-do-
24.	Puran Chand	-do-	-do-
25.	Baldev Singh	-do-	-do-
26.	Kartar Nath	-do-	-do-
27.	Om Parkash	-do-	-do-
28.	Bishan Dass	-do-	-do-
29.	Basakhi Ram	-do-	-do-
30.	Partap Singh	-do-	-do-
31.	Kishan Chand	-do-	-do-

2. To trace a short history of the matter, the petitioners Yog Raj and 14 others were employed either as T. Mate or Safai Sewak in the Pong Power Plant Circle under Respondent No. 1 Beas Construction Board in Work-charge capacity and were posted at Talwara. They were duly retrenched on completion of the Project-works but during the meanwhile there arose some dispute between number of workers employed in the Irrigation Wing and the management regarding the regularisation of their services. The said dispute was referred by the Appropriate Government to my Ld. predecessor who, per his Award dated 27th June, 1974 in Reference No. 8-C of 1973, passed a direction that such of the Work Charge employees who had put in continuous service of 10 years or more at the Project will be given seniority wise preference over all others at the time of re-employment.

3. It was the common case of the parties that on the completion of the works, Respondent No. 1 transferred the same to Respondent No. 2 i.e. BBMB for maintenance and operational effects; obviously, the latter required some limited staff for that purpose. The petitioners complained that even though they were eligible for re-employment in the light of Tribunal's Award in the aforesaid reference No. 8-C of 1973 yet Respondent No. 2, in violation thereof, engaged their juniors Durga Dass and 30 others as mentioned in the Annexure. They, therefore, assailed the action of Respondent No. 2 and claimed recruitment on priority basis in order of their seniority at the B.C.B. Project i.e. Respondent No. 1.

4. In the proceedings before me, B.C.B. pleaded indifference on the pretext that since on the completion of the Works they had duly retrenched the petitioners, therefore, they had nothing to do with the case for want of any stakes, whereas Respondent No. 2 i.e. BBMB disowned any liability for want of privity of contract and avered that since it were not a party to the proceedings in Reference No. 8-C of 1973 therefore, it was not bound by any observations made therein or directions given by the Tribunal. It, however, pleaded that in the very nature of things, it required an efficient staff for the maintenance and operational responsibilities of the Project and that in view thereof it recruited the required number of employees by presenting them before a high-powered Selection Committee. It was explained that even the petitioners were afforded due opportunity of selection and were actually examined by the Selection Committee which, however, did not find them suitable for the job.

5. Even though the answering Respondent questioned the maintainability of the reference on a number of technical grounds giving rise to two preliminary issues, framed over and above the terms of reference, yet in all fairness to it instead of wasting its steam on meaningless technicalities it contested the case on merits. In support of their respective versions the parties adduced verbal as well as documentary evidence which I have carefully perused and heard them.

6. There is no gain saying that BBMB was neither a party to the proceedings in Reference No. 8-C of 1973 nor was summoned to join the same at any stage. Of course in the relevant Award Ex. W5 dated 27th June, 1974 my learned predecessor was pleased to observe that as and when the Project Works were completed and any other Agency was to take over the same for operational and maintenance purposes it would endeavour to employ, seniority wise, the entire retrenched Work-charge staff who had put in a certain length of service; but all the same neither the parties to the proceedings nor even the Tribunal was sure about the identity of the prospective Agency who was sought to be bound with the responsibility and obligation to re-employ the petitioners.

7. In the same sequence it may also be worth while to note that according to the common case of the parties B.C.B. was concerned only with the constructional aspect of the Project and on the completion thereof, had become "funtus-officio". Obviously all the employees engaged on the Project, including the Work-charge staff like the petitioners, were retrenched on payment of terminal benefits envisaged under the Industrial Law. It was only then that the BBMB took over the Project for maintenance and operation. In a manner of speaking it was an entirely different venture by a different Organisation.

8. Otherwise too, from the scheme of Sections 78, 79 and 80 of the Punjab Re-organisation Act as interpreted by the apex Court in the matter of Jaswant Singh Vs. Union of

India AIR 1980 S.C. 115 (Para No. 21, 32, 37 and 39) there should be no manner of doubt about their distinct identities to rule out the feasibility of casting responsibilities of an "heir", "successor" or "assignee", as envisaged under Section 18(3)(c) of the Act on the BBMB. And it was, perhaps, in its realisation that the petitioners Narain Dass WW1, Mela Ram WW2 and Daldev Raj WW3 conceded in their cross-examination that the BCB and BBMB were entirely two distinct and separate Employers.

9. In my considered opinion against such a back drop any direction to the contrary, as issued by my learned predecessor could at it best, be suggestive of compassion rather than of binding legal obligation on the BBMB on whose behalf it was argued in all seriousness that precisely for this very reason it had called and presented the retrenched Work-charge employees before a high power Selection Committee, but keeping in view the enormous responsibility of Maintenance and Operation it could not possibly compromise with quality and that was how that only the best available talent was selected and recruited by it.

10. There is yet another important angle to lend credence to the Managements view point in the sense that on their own admission the petitioners were recruited and discharged by the BCB in the Work charge category. In the very nature of things they could not be taken on the regular cadre because the Employer itself had a limited goal in completing the Project. On the other hand after taking over the completed works, the contesting Respondent i.e. BBMB recruited the required staff of its regular cadre. It was, therefore, deemed proper to go in for the best available stuff. And it hardly requires any emphasis that for the obvious reason the management could not be expected to convert each and every Work-charge employee in to a regular one. After all, on the values of employment the former fall into an inferior category of employees as compared to the regulars even in accordance to the Supreme Court observations in para No. 43 of the aforesaid matter of Jaswant Singh.

11. I, therefore, find no impropriety in the impugned action of the management. However in all fairness to him, during the course of hearing before me the learned representative of the BBMB was fair enough to give an undertaking that as and when any future vacancy arises at the Project the petitioners would be re-considered for employment and every sincere endeavour would be made to provide them some succour.

12. Hence for the reasons recorded above, for want of merit in their cause, the petitioners fail in their bid and, as such, I return my Award against them.

Chandigarh.
28-1-1986.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer
[No. L-42011(2)/82-D. II(B)]

का. आ. 924.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर उत्तरी रेलवे, लखनऊ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-2-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 924.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Divisional Railway Manager, Northern Railway Lucknow and their workmen which was received by the Central Government on the 4th February, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, KANPUR

Reference No. L-41012/16/82-D.II(B) dt. 16-5-1983
Industrial Dispute No. 190 of 1983

In the matter of dispute between :

Shri Ram Shanker C/o The Zonal Working President, Uttar Railway Karamchari Union, 96/196 Roshanlal Bajaj Lane, Lucknow

AND

The Divisional Railway Manager, Northern Railway, Lucknow.

APPEARANCE :

Shri B. D. Tewari—for the workman.

Shri Shameed Quereshi—for management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-41012/16/82-D.II(B) dt. 16-5-1983, has referred the following dispute to this tribunal for adjudication :

> Whether the action of the Railway Administration Northern Railway, Lucknow Division in terminating the services of Shri Ram Shanker son of Shri Kaledin Khalasi with effect from 29-4-78 is justified ? If not to what relief is the concerned workman entitled?

2. The case of the workman is that he was casual labour working under P.W.I. Northern Railway since 24-12-72 and continued service in broken period upto 20-1-74, thereafter his services were terminated on 21-1-74 without any notice or retrenchment compensation. Thereafter workman was taken on roll of works said by inspector of works Bandariabagh Lucknow on 23-3-74 and he was given authorised scale rate in the year 1978 though it was due on 24-9-74. He continued to work upto 28-4-78, when on 29-4-78 he was again retrenched by IOW Bandariabagh, Lucknow. He submitted application to the Civil Engineer (Senior) Northern Railway, Lucknow on 8-5-82 but to no avail, hence this claim statement with request to order reinstatement of the workman with effect from 29-4-78 with all benefits and wages for retrospective effect.

3. The union filed written statement of the workman on 24-9-84, and despite sufficient notice none appeared for the management and then on 4-1-85 the case was ordered to proceed exparte against the management and 30-1-85 was fixed for workman's affidavit evidence and arguments. It was for the first time that on 16-3-85 the management moved an application to set aside the order to proceed exparte and the application was allowed on cost of Rs. 25. On the date fixed i.e. 6-4-85, for filing written statement the management again moved an application for time which was allowed on cost Rs. 50 fixing 16-4-85 for written statement. Management again applied for time on 16-4-85 which was again allowed on cost Rs. 50 fixing 16-5-85 and ordering that total cost be paid and thus allowing one months time. On 16-5-85 the management again moved an application which was allowed again on cost Rs. 50 fixing 28-6-85 for written statement and the entire total cost was ordered to be paid on the date fixed i.e. Rs. 225 failing which the right of defence will stand struck off. On 28-6-85 the management did not file written statement and again applied time to file written statement. In view of the previous order that the right of defence will stand struck off, hence the application was rejected and the arguments of the workman were heard and the case was reserved for orders. On 8-7-85 the management representative moved an application to recall the order without tendering cost, as there was no justifying cause for recall of the order, the application of the management was rejected.

4. It appears that the management had no case i.e. why they were seeking adjournments after adjournments without paying cost. Under railway boards circular even a casual labour becomes a temporary workman and becomes entitle to scale rate after completing continuous 120 days. It was probably on that account that the workman was given scale rate in 1978. For termination even a temporary workman if he has completed more than 240 days he should have given notice or notice pay and retrenchment compensation as required u/s 25F of the I.D. Act of 1947. The workman had given affidavit to substantiate his statement of claim that he worked continuously from 23-3-74 without break to 28-4-78. Thus the termination of the workman

concerned is void ab initio and the workman is entitled to be reinstated in service with full back wages w.e.f. 29-4-78.

5. I, accordingly hold that the action of the Railway Administration Northern Railway, Lucknow Division in terminating the services of Shri Ram Shanker son of Shri Kaledin Khalasi w.e.f. 29-4-78 is not justified and the result is that the workman is entitled to be reinstated with full back wages.

6. I, therefore, give my award accordingly.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-41012(16)/82-D.II(B)]

का. आ. 925.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कन्ट्रोलर आफ एयरोड्रोम्स नागपुर एयरपोर्ट के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-2-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 925.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur (M.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Controller of Aerodromes, Nagpur Airport and their workmen which was received by the Central Government on the 4th February, 1986.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER,

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)
Case No. CGIT/LC(R)(31)/1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of Controller of Aerodromes, Nagpur Airport and their workman, Ku. Supriya M. Sikday, Telephone Operator, (Nagpur-5 (M.S).

APPEARANCES :

For workman—Shri K. K. Ghosh.

For management—Shri S. K. Jain.

INDUSTRY : Aviation DISTRICT : Nagpur (M.S.)

AWARD

Dated : January 27, 1985

The Central Government in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred by Clause 10(1)(d)(2A) referred the following dispute, for adjudication, vide Notification No L-11011(7)/84-D.II(B) Dated 20th April, 1985: —

"Whether the action of the management of the Controller of Aerodromes, Nagpur Airport, Nagpur in terminating the services of Ku. Supriya M. Sikday, Telephone Operator w.e.f. 16-8-84 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. Non-controversial facts of the case are that the workman concerned Ku. Supriya M. Sikday was sponsored by the Employment Exchange, Nagpur, for the post of Telephone Operator at Nagpur Airport Nagpur. She was interviewed and taken in service on 13-4-1983 on daily wages of Rs. 11 for 12 hours per day and she worked with the Controller of Aerodromes, Nagpur Airport, Nagpur till 15-8-1984, when finally she was restrained from attending duties with effect from 16th August, 1984. She worked there for a total period of 490 days without a day's break in service.

3. The case of the workwomen is that she has passed Telephone Operators Course conducted by the Government of Maharashtra in First Division and obtained advance Vocational Certificate in Telex Operation'. She started working with the Controller of Aerodromes, Nagpur, but no appointment letter illustrating her salary, terms and service conditions etc. was communicated to her. Manager assured vide letter dated 23rd August, 1982 for further communication. She was asked to assist the Telephone Department for installation of PBX Board and was formally allowed to join duties from 13th April, 1983. She has further contended that all of a sudden, without any ryhme or reason; her services were terminated by the Controller of Aerodromes, Nagpur Airport, Nagpur vide his letter No. NP/EB-2/Genl/3852 59 dated 25th July, 1984. This was to be effective from 31-7-1984. Subsequently vide Memorandum No. NB-EB/2/Genl./3970-74 dated 31-7-1984 the termination of her services was withdrawn and she was allowed to work till 15-8-84. The management has issued a certificate dated 10th September, 1984 which is reproduced below :—

"This is certify that Ku. Supriya Sikdar has worked as Telephone Operator in this office from 13-4-1983 to 15-8-1984."

She is a Schedule Caste and in terms of Govt. of India directives issued from time to time, to safe guard the future, she deserves a compenssionate treatment from the Controller of Aerodrome, Nagpur Airport, Nagpur, but the same has been denied.

4. The case of the workwomen in short therefore is that she has neither been supplied with any appointment letter containing terms of service nor any reason for terminating her employment which amounts to unfair labour practice. She has not been given either one month's notice or salary in lieu thereof or the retrenchment compensation in accordance with Sec. 25F of the I.D. Act. Her termination amounts to retrenchment within the meaning of Sec. 2(oo) of the I.D. Act.

4. The management has raised a preliminary point that the Civil Aviation of the Government of India is not an industry as per the Judgment of the Central Government Industrial Tribunal, No. II, Bombay (Case No. CGIT/2/1 of 1983). Therefore this Tribunal has no jurisdiction to decide the present reference.

5. On merits, in the brief the case of the management is that the management wanted to appoint trained Aerodrome Assistants to man their T-43 Board. Since at the relevant time trained personnels were not available for posting at Nagpur the management called candidates from the local Employment Exchange for the four posts of Telephone Operators on daily wages and Ku. Supriya M. Sikdar was one of the candidates sponsored by the Employment Exchange. She was interview and was considered for appointment as Telephone Operator on purely temporary daily wages of Rs. 11 per day. Her appointment was on stop gap arrangement till qualified Aerodromes Assistants were not posted. Therefore when the qualified persons were available her services were treminated. As such the workwomen is not entitled to any relief.

6. The points for consideration are whether the management of Controller of Aerodromes, Nagpur Airport, Nagpur under the Civil Aviation Department is not an industry and if it is an industry whether the action of the Controller of Aerodromes, Nagpur Airport, Nagpur in terminating the services of Ku. Supriya M. Sikdar, Telephone Operator with effect from 16-8-1984 is justified.

7. I will first take up the preliminary points raised by the management that the Civil Aviation of the Government of India is not an industry. As such this Tribunal has no jurisdiction to try the present reference.

8. The word 'industry' is defined under Sec. 2(j) of the Industrial Disputes Act, 1947 and its relevant portion are reproduced below:—

"(j) "industry" means any systematic activity carried on by co-operation between an employer and his workmen (whether such workmen are employed by such employer directly or by or through any agency,

including a contractor) for the production, supply or distribution of goods or services with a view to satisfy human wants or wishes (not being wants or wishes which are merely spiritual or religious in nature), whether or not—

(i) any capital has been invested for the purpose of carrying on such activity; or

(ii) such activity is carried on with a motive to make any gain or profit".

The test whether a particular department of the Government or public sector undertaking is an 'industry' or not has been considered in the case of Bangalore Water Supply and Sewerage Board Vs. R. Rajappa and others 1978-I-LLJ-349). It has been held therein:—

"I. (a) where (i) systematic activity; (ii) organised by co-operation between employer and employees (the direct and substantial element is commercial); (iii) for the production and/or distribution of goods and services calculated to satisfy human wants and wishes not spiritual or religious but inclusive of material things or services geared to celestial bliss i.e. making on a large-scale of (prasad or food) prima facie, there is an industry in that enterprise.

(b) Absence of profit-motive or gainful objective is irrelevant, be the venture in the public, joint or private or other sector.

(c) The true focus is functional and the decisive test is the nature of the activity with special emphasis on the employer-employee relations.

(d) If the organisation is a trade or business, it does not cease to be one because of philanthropy animating the undertaking."

It was further held that the soevereign functions strictly understood alone quality for exemption, not the welfare activities or economic adventure undertaken by the Government or statutory bodies. It was also held that even in such departments if there are units which are industries and they are substantially severable, then they can be considered to come within the meaning of Sec. 2(j). While laying down dominant nature test their Lordships of the Hon'ble Supreme Court further observed that where complex activities carried on, some of which may qualify for exemption, other not, involves employees of the total undertaking, the predominant nature of the services and the integrated nature of the departments will be the true test. I will examine the activities carried on by the management in the instant case in the light of the above observations of the Hon'ble Supreme Court.

9. Both parties filed documents and adduced no oral evidence. On behalf of the management only a copy of Award delivered by the Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Bombay in Case No. CGIT-2/4 of 1983 has been filed and it has been argued that the Civil Aviation Department is a purely Government Department. Therefore the Controller of Aerodromes, Nagpur Airport, Nagpur, which is under the Civil Aviation Department cannot come under the definition of industry. The Controller of Aerodrome Nagpur of the Civil Aviation Department are governed by the Allocation of Busines Rules of 1961. These Rules of 1961 are published by the Government of India in which the activities of the Civil Aviation Department are narrated. My learned brother of the C.G.I.T. No. 2 Bombay in the case of Management of International Airport Authority of India and the Directorate Central, Civil Aviation Department, New Delhi Vs Their workmen (Case No. CGIT-2/4 of 1983) in his award dated 17th July, 1984 has reproduced the activities of Civil Aviation Department as follows :—

1. Meteorological Organisation.

2. Aircraft and air navigation; Provision of Aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes excepting sanitary control of air navigation.

3. Beacons and other provision for the safety of aircraft.

4. Carriage of passengers and goods by air.

4A. International Civil Aviation Organisation (CAO)

4B. International Air Transport Association (IATA)

4C. Commonwealth Air Transport (CATC)

4D. Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council.

5. Corporation established under the Air Corporation Act, 1963.

6. Chief Commissioner of Railway Safety.

On the other hand on behalf of the workman it has been argued that the Aerodrome Nagpur under the Civil Aviation Department is carrying on systematized activity by cooperation of employer and employee for services calculated to satisfy human wants and wishes. The management has not produced any documentary evidence or adduced oral evidence to the contrary.

10. In view of the activities of the Civil Aviation Department as laid down under Rules 1961 I am of the opinion that there is a systematized activity by cooperation of employer and employee for services calculated to satisfy human wants and wishes and not spiritual etc. Its functions are not sovereign simply because Civil Aviation Department of which the Aerodromes Nagpur Airport is part and pracel carries on welfare activities under the Government. It cannot be said to be beyond the wide definition of industry within the meaning of Sec. 2(j) of the I.D. Act. It is the dominant nature of activity carried on by the employer and employee which is relevant. The dominant nature of the work of the Civil Aviation Department including the Aerodromes, Nagpur Airport, Nagpur is to render service to the public through the cooperation of employer and employee. In the case of Bangalore Water Supply and Sewerage case (supra) it was held that in view of Government entering into large fields of industries therefore only those service which are governed by separate rules and constitutional provisions such as Article 310 and 311 should strictly speaking be excluded from the sphere of industry by necessary implication. It is not shown that Civil Aviation Department are governed by separate rules or by constitutional provisions. Their business is only defined by Allocation of Business Rules, 1961 and not their service condition (at least no such rule has been shown to me).

11. For the reasons disposed above, I hold that the Civil Aviation Department is an industrial within the meaning of Sec. 2(j) of the Industrial Disputes Act and this Tribunal has jurisdiction to try the present dispute. The Award of other Central Industrial Tribunal is not binding on this Tribunal.

12. Coming to the merits of the case, it is not disputed before me that Ku. Supriya M. Sikdar was employed as a Telephone Operator with effect from 13-4-1983 and her services were terminated with effect 15-8-1984. Thus she worked for 490 days with the management.

13. Section 25B of the I.D. Act defines 'continuous service'. If she has worked for a period of 12 calender months preceding the date with reference to which calculation is made has actually worked under the employer for not less than 240 days. The present workmen has worked for more than 240 days in the preceding year.

14. Section 25F of the I.D. Act lays down that no workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year unless one month's notice or wages in lieu of notice and retrenchment compensation is paid, shall be retrenched.

15. The 'retrenchment' has been defined under Sec. 2(oo) of the Industrial Disputes Act as under :—

"Retrenchment" means the termination by the employer of the service of a workman for any reason what-

soever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include:—

(a) voluntary retirement of the workman; or

(b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf; or

(c) termination of the service of a workman on the ground of continuous ill-health."

16. The case of the management is that she was employed on a purely temporary and on daily wages as Telephone Operator and specifically stating that she was employed on a stop gap arrangement till the time a trained and qualified Aerodrome Assistant was not posted to M-43 Board. She and other candidates sponsored by the Employment Exchange were fully given to understand the facts and circumstances of the case. Therefore she is stopped from challenging the same. This contention stands repelled by the pronouncement of the Supreme Court in the case of State Bank of India Vs. N. Sundermoney (AIR 1976 SC. 1111) wherein it has been held that 'termination for any reason whatsoever in Sec. 2(oo) are the key words. Whatever the reason, every termination spells retrenchment otherwise than by way of punishment inflicted by the disciplinary action. It has been further held that if the workman swims into the harbour of Section 25F she cannot be retrenched without payment, at the time of retrenchment, compensation computed as prescribed therein read with Section 25B(2). Same view was expressed in the case of Hindustan Steel Ltd. Vs. State of Orissa and others (1977—I-LLJ-p. 1).

17. Casual and seasonal labour once they acquired the status of temporary servant they are governed by the condition of service as has been held in the case of L. Robert D'Souza Vs. Executive Engineer (AIR 1982 SC 854). Even in cases where according to terms of service the same terminates by aflux of time, even then it will amount to retrenchment as has been held in the case of State Bank of India Vs. N. S. Money (supra).

18. In view of the above authorities the plea of the management regarding the terms of her service do not help them. The workwoman has stated that her services were terminated without any notice or wages in lieu of notice and without paying the retrenchment compensation and on her termination some other person was taken in service. This is also admitted by the management. Therefore termination of her services amounts to unfair labour practice. In any case termination of Ku. Sikdar for reason whatsoever amounts to retrenchment and failure to give notice or wages in lieu thereof and failure to pay retrenchment compensation renders retrenchment void as has been held in the case of Factory Manager Central India Machinery Mfg. Co. Ltd. Gwalior and another Vs. Naresh Chandra Saxena (1985 LIC p. 941).

19. For the reasons discussed above, I find that the action of the management of the Controller of Aerodromes, Nagpur Airport, Nagpur in terminating the services of Ku. Supriya M. Sikdar, Telephone Operator with effect from 16-8-1984 is unjustified.

20. As a normal rule in such cases she is entitled to reinstatement from the date of termination i.e. 16-8-1984 with full back wages and all other ancillary reliefs including seniority. The reference is answered accordingly. No order as to costs.

V. S. YADAV, Presiding Officer
[No. L-41011(7)/84-D.II(B)]

का. आ. 926.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिस्ट्रिक्ट मैनजर टेलीफोन्स, डाक तार विभाग, नागपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 4-2-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 926.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur (M.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of District Manager Telephones, P & T Department, Nagpur, and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th Feb., 1986.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(94)/1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of District Manager Telephones, P & T Deptt. Nagpur and their workman Shri V. P. Deshmukh, Casual Mazdoor, represented through the All India P & T Employees Federation, H.Q. No. 52, Telecom Colony Pratapnagar, Nagpur-22.

APPEARANCES :

For Union—Shri V. N. Bagale, Advocate.

For Management—Shri Dardar and Shri Nand, Advocates

INDUSTRY : P & T DISTRICT : Nagpur (M.S.)

AWARD

Dated : January 24, 1986

In exercise of the powers conferred by Clause 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government in the Ministry of Labour referred the following dispute, for adjudication, vide Notification No. L-40012(8)/84-D.II(B) dated 20-11-1984:—

"Whether the action of the management of Telephones, Nagpur in not regularising Shri V. P. Deshmukh Casual Mazdoor in group 'D' post with effect from 24-6-1982 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. Non-controversial facts of the case are that the workman concerned, Shri V. P. Deshmukh, was employed by the management with effect from 30-12-1972 and since then he put in 12 years service. His total attendance during this period exceeds 2400 days. Initially he was paid Rs. 9.32 per day which was subsequently raised to Rs. 15 per day. He was doing the same work as the other regular employees were doing.

3. The case of the workman is that he was employed as Casual Mazdoor on 30-12-1972 and is working continuously since last 12 years. He was paid Rs. 9.32 per day, subsequently it was raised to Rs. 15 per day. He was doing the same work as the other regular employees. The work of the casual mazdoor is of perennial nature and in view of the provisions of Section 25B of I.D. Act he had a right over a post of regular Group D workman as he had completed 240 days service within 12 months of a calendar year from 30-12-1972 to 29-12-1973. He has also attained the status of the regular U/s. 25B of I.D. Act. It is stated that since the workman has completed 240 days service within twelve calendar months he is required to be regularised automatically by the appointing authority as has been held in the case of Bangalore Water and Sewage Board Vs. Rajappa. In view of the above Supreme Court judgment the Government of India issued fresh orders for regularisation of daily wages casual workmen. These orders were circulated vide No. 45/19/79-SPB-I dated 6-4-1979, according to which the casual mazdoor who fulfilled the condition of (i) 240 days service (ii) VIII Standard educational qualification and (iii) 31 years age limit become eligible for regularisation in Group D automatically. These orders therefore, supersede all the prior P & T Rules in this regard. It is nowhere stated that the literacy test to be held for determining the suitability towards regularisation.

4. The workman has further stated that he is protected under the purview of category handicapped for which the Government Medical Authority has certified. The Government

of India also promulgated reservation in recruitment for handicapped in Government services. As per this provision the workman should have been regularised.

5. The management on 19-6-1982 conducted a farce literacy test to determine suitability towards regularisation in Group D post. The management has intentionally done this with an intention to cause exploitation of casual mazdoor and ignoring the senior, workman concerned. Juniors S/Shri Gajanan Pande, D. M. Sondawale, P. R. Pardhi, M. G. Khandekar, S. A. Khokale and S. K. Madav have been regularised. This regularisation of services of juniors by ignoring the senior amounts to discrimination. The total injuries caused to the workman in comparison to his juniors amounts to Rs. 4550 upto 30-11-1984 and which is likely to be increased by the same ratio till the decision of the case. The workman is therefore entitled for the following reliefs:—

1. To regularise the service of the workman as Group D in permanent capacity after completion of 240 days service.

2. Back wages from 30-12-1973 till the date of his regularisation.

3. Compensation Rs. 4550 and cost Rs. 500.

6. The case of the management is that as per the award dated 6-10-1980 passed by this Tribunal in case No. CGIT/LC(R)(40)/78 the claim of Shri V. P. Deshmukh Casual Mazdoor for regularisation and payment at par to the regular employees is under process and that he will be benefitted accordingly.

7. It is contended that the manageemnt is strictly following recruitment rules applicable in regard to Group 'D' post. It is also contended that casual mazdoor fulfilling the prescribed conditions is regularised in Group 'D' post provided Group 'D' post is available and the candidates qualifies the prescribed test and approved by the Departmental Selection Committee. Shri Deshmukh though fulfilling the prescribed condition for regularisation was in the list of eligible candidates at the time of the previous recruitment but he was not recommended by the Departmental Selection Committee for regular appointment in Group D.

8. The management denied that they made farce of conducting literacy test to determine suitability of the candidates for appointment in Group 'D' post. As per rule 7 Part I Appendix XII of P & T Manual Vol. IV literacy test was conducted for regularisation of casual mazdoors in Group D category in which the workman concerned Shri, V. P. Deshmukh, did not qualify and others junior to him qualified in the test. Therefore the workman concerned is not entitled to Rs. 4550 and other benefits as claimed.

9. However, as per claim passed in Case No. CGIT/LC(R)(40)/78 Shri V. P. Deshmukh will get all the benefits, but the prayer as made by the workman in the instant case in totally denied.

10. Neither party adduced any oral evidence. On behalf of the workman certain documents have been filled as annexures to the statement of claim, some of which have been admitted by the management. Admittedly the workman was appointed as Casual Mazdoor with effect from 30-12-1972. The workman's contention is that he worked continuously for the period which exceeds 2600 days. The management adduced no evidence to the contrary in this regard. Certainly he had completed one year's service within the meaning of Sub-section (2) of Sec. 258 of the I.D. Act as he was appointed on 30-12-1972.

11. Management has only stated that Shri V. P. Deshmukh though fulfilling the prescribed condition for regularisation was in the list of eligible candidates at the time of the previous recruitment but he was not recommended by the Departmental Selection Committee for regular appointment in Group D. It is further stated that as per order passed by my learned predecessor in Case No. CGIT/LC(R)(40)/78 Shri V. P. Deshmukh will get all the benefits. Both parties relied on Ministry of Home Affairs O.M. o 49014/1/83-Estt.-(G) dated 13-10-1983. It says that those casual employees who were recruited before 31-3-1979 may be regularised in Group D post subject to the following conditions :—

1. Those who have put in at least 240 days service on the date of appointment against regular Group 'D' post.

2. Eligible in respect of minimum age limi after excluding the period spent as daily wages worker. But this condition was also relaxed provided they otherwise are eligible for regularisation.

3. Minimum educational qualification prescribed for the post (Management admitted that the present workman has the requisite qualification).

4. The condition of being sponsored through the Employment Exchange was also relaxed.

In any case now looking to the length of his service the condition of recruitment rules of 2 years service is now very much satisfied and the applicant workman is entitled to be regularised, as a handicap workman.

12. The question is as to from which date he should be regularised and what post.

13. As I have already pointed out the recruitment rules provided minimum two years service. Therefore in my opinion he should be regularised from the date he had completed two years service. I am fortified by the observations made in the case of L. Robert D'Souza Vs. Executive Engineer, S.E. Railway (AIR 1982 SC 854).

14. The management has admitted that he is qualified for Group 'D' post. Therefore, the managment is directed to regularise him on any Group D post from the date he has completed 2 years' service and pay the difference of wages from the aforesaid date. There is no question of payment of any further compensation but the applicant workman will be entitled to costs of Rs. 250. The reference is answered accordingly.

V. S. YADAV, *Presiding Officer.*

[No. L-40012(8)/84-D.II(B)]

का. आ. 927.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिस्ट्रिक्ट मैनजर टेलीफोन्स, नागपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-2-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 927.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur (M.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of District Manager, Telephones, Nagpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th February, 1986.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM
LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)
Case No. CGIT/LC(R)/(12)/1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of District Manager, Telephones, Nagpur and their workmen, named in the Annexure, represented through the General Secretary, All India P&T Employees Federation, H. Q. Kamptee Road, Near Bridge No. 10, Indore, P.O. Bezonbagh, Nagpur-440004.

APPEARANCES :

For Union.—Shri V. N. Bagale, Advocate.

For Management.—Shri Dardar, Advocate.

INDUSTRY : P & T. DISTRICT : Nagpur (M.S.)

AWARD

Dated : January, 24th 1986

In exercise of the powers conferred by Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, Central Government

in the Ministry of Labour referred the following dispute, for adjudication, vide Notification No. L-40012(29)|83-D. II(B) Dated 28th January, 1985 :—

"Whether the action of the management of District Manager, Telephones, Nagpur in not regularising the services of the workmen (listed in the Annexure), working as Casual Electrical Wiremen since last five years under Assistant Engineer, Tax (Installation) Nagpur is justified ? If not, to what relief and from which date they are entitled ?"

ANNEXURE

Sl. No.

1. Shri R. P. Kalmegh
2. Shri Ravindra Dalal
3. Shri B. S. Manwatkar
4. Shri P. G. Kawale
5. Shri H. K. Deotale
6. Shri T. G. Maske.

2. Non-controversial facts of the case are that the workmen numbering six were employed by the management some in the year 1978 and some in the year 1979.

3. The case of the workmen is that they were employed as Casual Electrical Wiremen and worked continuously since last six years and their total attendance exceeded 2100 days. Initially they were paid Rs. 9.32 per day which was subsequently raised to Rs. 16 per day. They were doing the same work as the other regular employees were doing. *Their work was of perennial nature and in view of the* provision of Section 25B of I.D. Act they hold a right over a post of regular Electrical Wireman as has also been laid down in the case of Bangalore Water & Sewerage Board Vs. Rajappa. In pursuance of the above Supreme Court judgment the Govt. of India issued fresh orders for regularisation of daily wages casual workmen. These orders were circulated vide endorsement of Director General, Posts and Telegraphs, Department, New Delhi No. 45|19|79-SPB-1, dated 6-4-1979, according to which the casual workmen who fulfilled the condition of 240 days service, requisite educational qualification of ITI Diploma etc. and 31 years upon age limit be considered for regularisation as Electrical Wiremen, automatically by the appointing authority. These orders, therefore, supersede all the prior P&T Rules in this regard. It is nowhere stated that the literacy test to be held for determining suitability towards regularisation. The management had appointed these workmen by observing all the due formalities i.e. by calling their names through Employment Exchange and holding their test, they were selected and appointed as casual Electrical Wiremen. District Manager (Telephones) cannot be permitted to introduce any innovance or make any alteration in the instructions of the Government. The same service conditions have been upheld by the Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur in his award dated 3-10-1980 in the case of Telephone Workmen Vs. Nagpur District Manager (Telephones). The same was confirmed by the High Court, Nagpur and subsequently by the Supreme Court in tis judgment dated 4-8-1983.

4. On the instructions of the District Manager (Telephones) dated 28-10-1980 five of the casual mazdoors who did not hold the requisite qualifications such as Diploma of I.T.I. etc. have been appointed as Electrical Wiremen. Their names are as under :—

1. Shri N. S. Thakkar
2. Shri D. B. Tijare
3. Shri V. K. Khandale
4. Shri B. S. Adase and
5. Shri M. S. Muley.

5. These workmen had made applications to the Central Government Labour Court Nagpur under Sec. 33-C(2) for arrears regarding difference of pay between permanent wiremen and the daily wages paid to the workmen which was allowed and they have been paid the arrears amounting to Rs. 2664. The workmen are, therefore, entitled to the following reliefs :—

(1) To regularise the service of the workmen as Electrical Wiremen in permanent capacity after completion of 240 days service.

(2) Back wages and arrears from 1978-79 onwards till they are regularised and absorbed in regular post.

(3) Compensation of Rs. 13500 and costs Rs. 500.

6. The case of the management is that they were employed as casual mazdoors and the nature of their services were essentially of casual nature to complete the project of installation of Nagpur Telephones Automatic Exchange Lines. After the completion of the work their services were to be terminated. The management sought the names of eligible candidates from Employment Exchange and the workmen were appointed, initially on daily wages of Rs. 6.12 per day which was later on revised to Rs. 15 per day.

7. There is no cadre as Regular Electrical Wiremen in the Nagpur Telephone District, Selection and appointment of Wiremen are made on the following basis when there are vacancies :—

(a) 75 per cent from the Departmental lower grade officials who have completed 3 years minimum service.

(b) 25 per cent from outsiders i.e. Casual Mazdoors who have passed 8th Standard and who have served Department minimum 2 years having worked 240 days in consecutive years.

If no suitable casual mazdoors are available then only candidates are sponsored through the Employment Exchange. That they should possess the necessary qualification of Wiremen.

8. The workmen have also relied on office order of Assistant Engineer, Tax, Maintenance, Nagpur dated 5th December, 1980 whereby S|Shri Thakkar, Tijare, Khandale, Adase and Muley were appointed as Wiremen. This substantiates that certain casual mazdoors were appointed as Wiremen.

9. It is the case of the management that the applicant workman did not possess the necessary qualification. But they adduced no evidence to substantiate their allegations. Admittedly these workmen were appointed as Casual Mazdoors in the year 1978 and some in the year 1979. Their contention is that they worked regularly for more than 240 days. The management adduced no evidence to the contrary. If these workmen were appointed in the year 1978 and 1979 certainly they had completed one year's service within the meaning of Sub-section (2) of Sec. 25B of the I.D. Act when the appointments vide Ex. W|3 dated 5th December, 1980 were made.

10. In fact they had the qualifications as required by the recruitment rules since they had put in 240 days service in the preceding year and atleast some of them had also completed the minimum two years service (at least those who had joined in 1978). In such circumstances only taking some select few for appointment on regular post is not justified specially in view of the order of Ministry of Home Affairs No. C.M. 49014|1|83-Estt.(G) dated 13-10-1983 (Ex. W|1). It says that those casual Employees who were recruited before 31-3-1979 may be regularised in Group 'D' post subject to the following conditions :—

(1) Those who have put in at least 240 days service on the date of appointment against regular Group 'D' post.

(2) Eligible in respect of minimum age limit after excluding the period spent as daily wages worker. But this condition was also relaxed provided they otherwise are eligible for regularisation.

(3) Minimum educational qualification prescribed for the post (Applicants workmen have filed their certificates mentioned above in this regard).

(4) The condition of being sponsored through the Employment Exchange was also relaxed.

In any case now looking to the length of their service the condition of recruitment rules of 2 years service is now very much satisfied and the applicants workmen are entitled to be regularised.

11. The question is as to from which date they should be regularised and on what post.

12. As I have pointed out the recruitment rules provided minimum two years service. Therefore in my opinion they should be regularised from the date they had completed two years service. I am fortified in this by the observations made in the case of L. Robert D'Souza Vs. Executive Engineer, S. E. Railway (AIR 1982 SC. 854).

13. It is not challenged before me that they did not work as Wiremen. At least no evidence is adduced that they did not work as such. Therefore they ought to be regularised on the post they were working from the aforesaid date. They are also entitled to difference of wages of the regular Wiremen and the wages paid to these workmen from the date they had completed two years service after deducting the amount which they have already received vide Ex. W|4, the order of the Divisional Engineer (Phones) dated 3rd December, 1985. There is no question of payment of any further amount by way of compensation but the applicant workmen will be entitled to costs of Rs. 250 each. The reference is answered accordingly.

V. S. YADAV, Presiding Officer

[No. 40012(29)|83-D. II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986